

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



फरवरी 2019

खंड 73 अंक 2

संपादन समिति

राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवडकर

संपादक

शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2018

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19

छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 1

भाषण

भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद नीतिगत मुद्दों पर चिंतन
शक्तिकांत दास 11

सूक्ष्म ऋण और कैसे कोई लोक ऋण रजिस्ट्री इसे सुदृढ़ कर सकता है
इसके संबंध में कुछ विचार
विरल वी. आचार्य 17

राष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकारी एवं वैश्विक वित्तीय चक्र
हेलेन रे 25

लेख

भारत में बैंक क्रेडिट का क्षेत्रवार विनियोजन 35

चलनिधि प्रबंधन का स्वरूप: 2018-19 के दौरान आए बदलाव 55

वर्तमान सांख्यिकी 69

हाल के प्रकाशन 113

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19

छह्वा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19

छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.5 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत किया जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.5 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

एमपीसी ने मौद्रिक नीति रुख को भी नपी-तुली सख्ती से तटस्थ में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों का वर्णन नीचे दिए गए विवरण में किया गया है।

आकलन

2. दिसंबर 2018 में अंतिम एमपीसी बैठक के समय से, वैश्विक आर्थिक गतिविधि में मंदी आई है। मुख्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में, वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में अमेरिका में आर्थिक गतिविधि में कमी आई। वर्ष 2019 की पहली तिमाही की संभावना पर आंशिक सरकारी मंदी के बादल छाए हुए हैं, हालांकि श्रम बाजार की स्थिति मजबूत बनी हुई है। यूरो क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधि

ने कमजोर औद्योगिक गतिविधि के कारण गति खो दी। जापानी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है तथा उदार मौद्रिक नीति रुख से घरेलू खर्च में मदद मिलने की संभावना है।

3. कुछ प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में भी आर्थिक गतिविधि धीमी हुई है। चीन में, वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में वृद्धि में कमी आई। रूस में आर्थिक गतिविधि ने अपनी गति खो दी जिसमें तेल की नरम कीमतें वृद्धि के लिए डाउनसाइड जोखिम हैं। ब्राजील की अर्थव्यवस्था 2018 के अंत में मजबूत प्रतीत हुई, जिसका कारण उन्नत घरेलू खर्च और निर्यात है, हालांकि औद्योगिक गतिविधि निरंतर रूप से वर्ष 2018 की पहली छमाही के उथल-पुथल से बाहर निकलने के लिए संघर्षरत है। दक्षिण अफ्रीका में, 2018 की चौथी तिमाही में आर्थिक सुधार धीमा रहा, जिसका कारण कमजोर औद्योगिक गतिविधि और मंद निर्यात रहा।

4. कच्चे तेल की कीमतों में दिसंबर के न्यून स्तर से जनवरी की शुरुआत में उत्पादन कटौती के कारण सुधार हुआ किंतु यह अक्तूबर के अपने शीर्ष स्तर से नीचे रही। मूल धातु जिनपर अमेरिका-चीन के व्यापार टकरावों के कारण लगातार अनिश्चितता की वजह से दिसंबर में बिक्री दबाव रहा, व्यापार विवाद और उत्पादन अवरोध के कम होने की उम्मीद में जनवरी में इनकी हानियों की क्षतिपूर्ति हुई। स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि हुई है जिसमें भौगोलिक-राजनीतिक अनिश्चितता तथा इक्विटी बाजारों में अस्थिरता की प्रतिक्रिया में सुरक्षित आश्रय मांग से मदद मिली। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और कई मुख्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कम बढ़ी।

5. वैश्विक वित्तीय बाजारों में दिसंबर के उथल-पुथल के बाद शांत सुर पर वर्ष की शुरुआत हुई। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच, अमेरिका के इक्विटी बाजारों में दिसंबर में तीव्र बिक्री (सेल-ऑफ) से उबरे, जो फेडरल द्वारा मौद्रिक नीति की सख्ती, व्यापार तनाव और भावी मंदी से शुरू हुई थी। ईएम स्टॉक बाजार में दिसंबर में नरम आर्थिक आंकड़ों के कारण गिरावट आई थी, उन्होंने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उदार मौद्रिक नीति के रुख की प्रत्याशा से हाल में कुछ लाभ दर्ज किया। अमेरिका में 10 वर्षीय प्रतिफल जो दिसंबर में बहुत-महीनों के निम्न स्तर तक घट गया था, वह कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और सकारात्मक जोखिम भावना के चलते जनवरी में बढ़ गया, हालांकि फेड के रुख में नरमी से लाभ प्रतिबंधित

* 07 फरवरी, 2019 को जारी किया गया।

हुए। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, यूरो क्षेत्र और जापान में बॉन्ड प्रतिफल वैश्विक वृद्धि के घटते आशावाद के कारण सहज हो गए। अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी, बॉन्ड प्रतिफलों में सहजता आई। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर दबाव में रहा, हालांकि सहज होते व्यापार तनावों ने कुछ सहायता प्रदान की। फेड द्वारा दर बढ़ोतरी चक्र में ठहराव तथा अमेरिका-चीन की व्यापार बातचीत से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में मूल्यवृद्धि हुई।

6. घरेलू अर्थव्यवस्था की ओर जाते हुए, 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) ने 2018-19 के पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) जारी किए जिसमें भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि को 2017-18 के समान स्तर 7.2 प्रतिशत पर रखा गया (पहले संशोधित अनुमान)। 2018-19 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों में सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में अभिवृद्धि और उपभोग व्यय (निजी और सरकारी दोनों) में मंदी दिखाई गई। वर्ष 2018-19 में निवल निर्यात में होने वाली गिरावट में कमी होने का अनुमान लगाया गया है।

7. निवेश मांग अर्थात् उत्पादन और पूंजीगत माल का आयात के कुछ संकेतक नवंबर/दिसंबर में संकुचित हुए। उद्योग के लिए क्रेडिट प्रवाह नियंत्रित बना रहा। उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर केंद्र का राजस्व व्यय तीसरी तिमाही में संकुचित हुआ, राज्यों के मामले में यह तेजी से बढ़ा, इस प्रकार सरकारी खर्च में कुल मिलाकर वृद्धि बनी रही।

8. आपूर्ति पक्ष पर, पहले अग्रिम अनुमानों में वास्तविक संवृद्धित सकल मूल्य 2017-18 के 6.9 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 7.0 प्रतिशत रखा गया है। अनुमानों में कृषि जीवीए वृद्धि में मंदी और औद्योगिक जीवीए वृद्धि में अभिवृद्धि सम्मिलित की गई है। व्यापार, होटलों, संचार और अन्य सेवाओं में मंद गतिविधि के चलते सेवा जीवीए वृद्धि में नरमी आना निर्धारित किया गया है। लोक प्रशासन और रक्षा सेवाओं से भी उदार होने की संभावना है।

9. अभी तक (1 फरवरी 2019 तक) रबि की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है किंतु विभिन्न फसलों में 4.0 प्रतिशत की कुल कमी इस मौसम की समाप्ति तक पूरी होने की संभावना है। रबि की कम बुआई उत्तर-पूर्वी मानसून में कमी (दीर्घावधि औसत से 44 प्रतिशत नीचे) दर्शाती है, हालांकि प्रमुख जलाशयों में जल

संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में पूर्ण जलाशय स्तर (31 जनवरी 2019 को) के 44 प्रतिशत पर थोड़ा उच्च रहा, ये रबि मौसम के दौरान सिंचाई का प्रमुख स्रोत होते हैं। इस वर्ष की सर्दियों में ठंड के मौसम की विस्तारित अवधि से गेहूं का उत्पादन बढ़ने की संभावना है जिससे बुआई क्षेत्र में कमी, यदि कोई है, आंशिक रूप से बराबर हो जाएगी।

10. अक्टूबर के त्रैमासिक माह में वृद्धि दर्शाने के बाद, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापित औद्योगिक गतिविधि नवंबर में मंदी रही। मुख्य उद्योगों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दिसंबर में घटकर 2.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई जो विद्युत और कोयले के उत्पादन में हुई मंदी तथा पेट्रोलियम परिष्करण उत्पादों, कच्चे तेल और उर्वरक उत्पादन में कमी से नीचे आ गई। विनिर्माण क्षेत्र में रिजर्व बैंक के आदेश बही, इन्वेंटरी तथा क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) द्वारा मापित क्षमता उपयोग (सीयू) पहली तिमाही के 73.8 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी तिमाही में 74.8 प्रतिशत हो गया, मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग भी 74.9 प्रतिशत से बढ़कर 75.3 प्रतिशत हो गया। जबकि वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही के लिए रिजर्व बैंक का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) का कारोबार आकलन सूचकांक विनिर्माण क्षेत्र में मांग स्थिति में कमी दर्शाता, कारोबार प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई) चौथी तिमाही में सुधार की ओर संकेत करता है। जनवरी के लिए मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) बढ़े हुए आउटपुट और नए आदेश के कारण विस्तारकारी स्तर में रहा।

11. सेवा क्षेत्र के उच्च बारंबारता सूचक गतिविधि की गति में कुछ नरमी दर्शाते हैं। मोटरसाइकलों और ट्रैक्टरों की बिक्री दिसंबर में ग्रामीण मांग में कमजोरी दर्शाती है। यात्री कारों की बिक्री जो शहरी मांग का सूचक है, संकुचित हो गई जो संभवतः ईंधन की कीमतों और अधिदेशित दीर्घावधि बीमा प्रीमियम भुगतानों में अस्थिरता दर्शाता है। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी पिछले वर्ष के उच्च आधार से दिसंबर 2018 में कम हो गई। होटलों के उप-खंड अर्थात् विदेशी पर्यटक आगंतुक और हवाई यात्री ट्रैफिक के अग्रणी संकेतक नवंबर-दिसंबर में नरमी की ओर संकेत कर रहे हैं। संचार के उप-खंड टेलीफोन उपभोक्ता आधार में अक्टूबर-नवंबर में संकुचन आया, जबकि ब्रॉडबैंड में अक्टूबर में वृद्धि जारी रही। सेवा पीएमआई में पिछले माह में कमी के बावजूद जनवरी 2019

में विस्तार जारी रहा। निर्माण क्षेत्र के सूचक अर्थात् इस्पात का उपभोग और सीमेंट के उत्पादन ने अच्छी वृद्धि दिखाना जारी रखा, हालांकि सीमेंट के उत्पादन में नवंबर 2018 में कम वृद्धि हुई जो आधार प्रभाव दिखाती है।

12. सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2018 के 3.4 प्रतिशत से घटकर दिसंबर में 2.2 प्रतिशत हो गई, जो पिछले 18 महीनों में सबसे कम स्तर पर थी। खाद्य मदों में अस्फीति जारी रही, ईंधन मुद्रास्फीति में तेज गिरावट और खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में कुछ कमी से हेडलाइन मुद्रास्फीति की कमी में योगदान मिला।

13. खाद्य समूह के पांच घटक-सब्जियां, चीनी, दलहन, अंडे तथा फल खाद्य समूह का लगभग 30 प्रतिशत हैं, दिसंबर में अस्फीति में रहे। खाद्य के अन्य प्रमुख उप-समूहों-अनाज, दूध और तेल तथा वसा में मुद्रास्फीति नियंत्रित रही। अनाजों में, चावल की कीमतें दिसंबर माह में लगातार चौथे महीने के लिए कम हुईं। मांस और मछली तथा गैर-अल्कोहॉलिक पेय पदार्थों की कीमतों की मुद्रास्फीति ने वृद्धि दिखाई जबकि तैयार खाद्य वस्तुओं के लिए यह स्थिर बनी रही।

14. ईंधन और प्रकाश समूह में मुद्रास्फीति अक्टूबर के 8.5 प्रतिशत से घटकर दिसंबर में 4.5 प्रतिशत हो गई, ऐसा तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों में तेज कमी के कारण हुआ, जो पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी दर्शाती है। केरोसिन मुद्रास्फीति में इसकी प्रशासित कीमत में नपी-तुली वृद्धि के कारण बढ़ोतरी जारी रही।

15. खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति अक्टूबर के 6.2 प्रतिशत से घटकर दिसंबर में 5.6 प्रतिशत हो गई, ऐसा मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के अनुरूप पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में नरमी आने से हुआ। आवास मुद्रास्फीति में कमी जारी रही क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आवास किराये भत्ते (एचआरए) में वृद्धि का प्रभाव समाप्त हो गया। तथापि, अनेक उप-समूहों – घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, स्वास्थ्य, मनोरंजन और आनन्द तथा शिक्षा में मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़ गई जिससे पेट्रोल, डीज़ल और आवास में कम मुद्रास्फीति का प्रभाव काफी हद तक बराबर हो गया।

16. रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के दिसंबर 2018 दौर द्वारा मापित परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं पिछले दौर से तीन महीने आगे की अवधि के लिए 80 आधार अंक तथा 12 महीने आगे की अवधि के लिए 130 आधार अंक तक कम हुईं जो खाद्य और ईंधन की कीमतों में निरंतर कमी दर्शाती हैं। इनपुट कीमतों में उत्पादकों का मुद्रास्फीति आकलन तीसरी तिमाही में सहज हो गया जैसाकि रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण में मत देने वाली विनिर्माण फर्मों द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

17. कुछ नरमी के बावजूद फार्म इनपुटों और औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही। ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि अक्टूबर में कम हो गई।

18. भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) का दिसंबर के 20 में से 12 दिवसों, जनवरी में सभी 23 दिवसों और फरवरी (6 फरवरी तक) में चार दिवसों पर नीति रेपो दर से नीचे कारोबार हुआ। डब्ल्यूएसीआर दिसंबर में औसतन रेपो दर से 4 आधार अंक और जनवरी तथा फरवरी में 11 आधार अंक नीचे थी। प्रचलन में रहने वाली मुद्रा दिसंबर और जनवरी के दौरान तेजी से बढ़ी। मुद्रा में विस्तार के कारण उत्पन्न चलनिधि आवश्यकता को रिज़र्व बैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन (ओएमए) के अंतर्गत खरीद के जरिए दिसंबर और जनवरी में प्रत्येक बार ₹500 बिलियन तक स्थायी चलनिधि उपलब्ध कराकर पूरा किया गया। तदनुसार, ओएमओ के माध्यम से उपलब्ध कराई गई कुल स्थायी चलनिधि वर्ष 2018-19 के दौरान अब तक कुल ₹2.36 ट्रिलियन तक पहुंच गई। एलएएफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई चलनिधि औसतन दैनिक निवल आधार पर दिसंबर में ₹996 बिलियन और जनवरी में ₹329 बिलियन रही। तथापि, फरवरी में औसत दैनिक चलनिधि स्थिति ₹279 बिलियन के औसत अवशोषण के साथ अधिशेष में बदल गई।

19. वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्यात वृद्धि नवंबर और दिसंबर 2018 में लगभग सपाट रही जिसका प्रमुख कारण उच्च आधार प्रभाव और कमजोर वैश्विक मांग रही। जबकि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में वृद्धि सकारात्मक रही, गैर-तेल निर्यात में कमी आई, ऐसा हीरे और जवाहारात, अभियांत्रिकी वस्तुओं, मांस और पोल्ट्री के कम पोत-लदान के कारण हुआ। नवंबर में आयात वृद्धि धीमी हुई तथा दिसंबर 2018 में यह नकारात्मक हो गई। जबकि आयात

मात्रा में वृद्धि के अनुरूप पेट्रोलियम (कच्चे तेल और उत्पाद) के आयात में वृद्धि हुई, गैर-तेल आयात जैसे मोती तथा बहुमूल्य रत्न (स्टोन), स्वर्ण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं तथा परिवहन उपकरणों में कमी दर्ज की गई। अप्रैल-दिसंबर 2018 के लिए व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार घाटा एक वर्ष पहले के इसके स्तर से थोड़ा सा ज्यादा रहा। निवल सेवा निर्यात जो तेल की कम कीमतों के साथ संयुक्त था, में अक्तूबर तथा नवंबर 2018 में बढ़ोतरी हुई, का तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटे पर उपयोग प्रभाव हो सकता है। वित्तपोषण पक्ष पर, अप्रैल-नवंबर 2018 के दौरान भारत में निवल एफडीआई प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर रहा। विदेशी संविभाग प्रवाह नवंबर और दिसंबर 2018 में सुधरने (रिबाउंड) के बाद, जनवरी 2019 में नकारात्मक हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 फरवरी 2019 को 400.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

संभावना

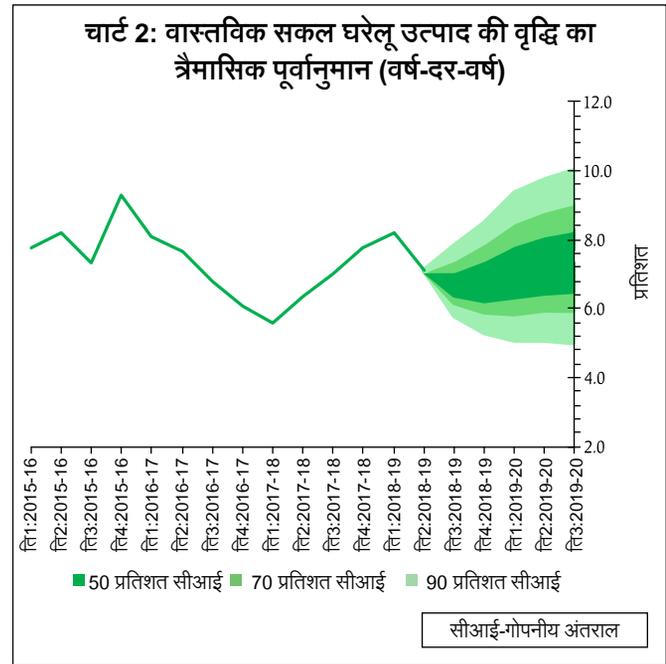
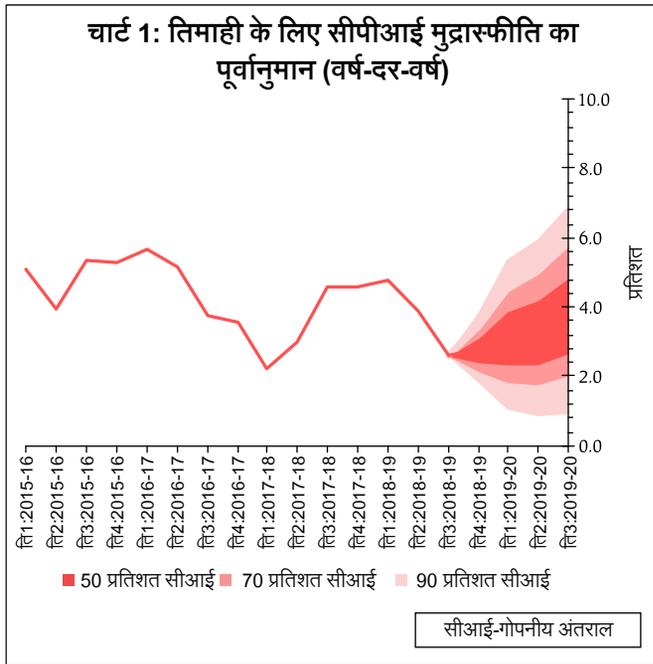
20. दिसंबर 2018 में पांचवें द्विमासिक मौद्रिक नीति संकल्प में, ऊपरी ओर की जोखिम के साथ 2018-19 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 की दूसरी छमाही में 2.7-3.2 प्रतिशत और 2019-20 की पहली छमाही में 3.8-4.2 प्रतिशत के दायरे में अनुमानित की गई। 2018-19 की तीसरी तिमाही में वास्तविक मुद्रास्फीति आउटकम अनुमान से थोड़ा कम 2.6 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के अनुमानों में गिरावट देखी गई जो मुख्य रूप से खाद्य उप-समूहों में दर्ज की गई नरम मुद्रास्फीति को दर्शाती है।

21. आगे कई कारक मुद्रास्फीति की राह को आकार देंगे। पहला, खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति ने कई वस्तुओं में निरंतर अपस्फीति और अनाज मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण गिरावट के साथ-साथ आश्चर्यचकित करना जारी रखा है। कई खाद्य समूह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसलिए, प्रतिकूल आधार प्रभावों के बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति के लिए अल्पकालिक दृष्टिकोण विशेष रूप से सौम्य दिखाई देता है। दूसरे, ईंधन समूह में मॉडरेशन प्रत्याशित से अधिक रहा। ग्रामीण उपभोग की वस्तुओं जैसे कि जलाऊ लकड़ी और चिप्स में मुद्रास्फीति, जो चिपचिपी और ऊंचे स्तर पर बनी हुई थी, हाल के महीनों में कम हो गई। बिजली की कीमतों में भी एक

अप्रत्याशित बदलाव दिखा, जो ईंधन समूह के लिए एक नरम दृष्टिकोण प्रदान करता है। तीसरा, खाद्य और ईंधन को छोड़कर महंगाई का बढ़ना, हाल ही में स्वास्थ्य और शिक्षा की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी एक बार की घटना हो सकती है। चौथा, कच्चे तेल की कीमत का दृष्टिकोण मोटे तौर पर दिसंबर की नीति के समान है। पाँचवें, रिजर्व बैंक के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उत्पादकों के इनपुट और आउटपुट मूल्य अपेक्षाओं के साथ-साथ परिवारों की मुद्रास्फीति की उम्मीदों में भी मामूली वृद्धि हुई है। अंत में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरए वृद्धि का प्रभाव अपेक्षित लाइनों के साथ पूरी तरह से अलग हो गया है। इन विकासों को ध्यान में रखते हुए और 2019 में एक सामान्य मानसून मानकर, केंद्रीय प्रक्षेप वक्र के आसपास मोटे तौर पर संतुलित जोखिमों के साथ क्यू 4: 2018-19 में सीपीआई मुद्रास्फीति का मार्ग नीचे की ओर 2.8 प्रतिशत, एच 1: 2019-20 में 3.2-3.4 प्रतिशत और क्यू 3: 2019-20 में 3.9 प्रतिशत संशोधित किया गया है।

22. विकासात्मक दृष्टिकोण की ओर मुड़ते हुए दिसंबर पॉलिसी में निचली ओर की जोखिम के साथ 2018-19 के लिए जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत (एच 2 में 7.2-7.3 प्रतिशत) और एच 1: 2019-20 के लिए 7.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। सीएसओ ने 2018-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। चालू वर्ष से परे, विकास का दृष्टिकोण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होने की संभावना है। पहले, वाणिज्यिक क्षेत्र में समग्र बैंक ऋण और समग्र वित्तीय प्रवाह का मजबूत होना जारी है, लेकिन अभी तक उनका आधार व्यापक नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि नरम कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद और शुद्ध निर्यात पर भारतीय रुपये के हाल ही में मूल्यहास के सुस्त प्रभाव के कारण, धीमी वैश्विक मांग प्रतिकूल प्रभाव बढ़ा सकती है। विशेष रूप से, व्यापार तनाव और संबंधित अनिश्चितताएं वैश्विक वृद्धि को नियंत्रित करती दिखाई देती हैं। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत - एच 1 में 7.2-7.4 प्रतिशत और क्यू 3 में 7.5 प्रतिशत की सीमा तक अनुमानित है।

23. मुद्रास्फीति के मौजूदा निम्न स्तर और सौम्य खाद्य मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को दर्शाते हुए निकट अवधि में हेडलाइन



मुद्रास्फीति नरम रहने का अनुमान है। निकट अवधि से परे, कुछ अनिश्चितताओं की सावधानीपूर्वक निगरानी आवश्यक है। सबसे पहले, हाल की अवधि में सब्जी की कीमतें अस्थिर रही हैं; सब्जी की कीमतों में उलटफेर खाद्य मुद्रास्फीति प्रक्षेप वक्र के लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं। दूसरे, तेल की कीमत का दृष्टिकोण धुंधला बना हुआ है। तीसरा, व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का एक और बड़ा कारण वैश्विक विकास की संभावनाओं, वैश्विक मांग में गिरावट और वैश्विक कमोडिटी की कीमतों को, विशेष रूप से तेल की कीमतों को नरम कर सकता है। चौथा, स्वास्थ्य और शिक्षा की कीमतों में असामान्य वृद्धि को बारीकी से देखने की जरूरत है। पांचवां, वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। छठे, मानसून का परिणाम सामान्य माना जाता है; वर्षा में कोई भी स्थानिक या अस्थायी परिवर्तन खाद्य मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को बदल सकता है। अंत में, 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट में कई प्रस्तावों के कारण प्रयोज्य आय बढ़कर कुल मांग को बढ़ावा मिलने की संभावना है, लेकिन कुछ उपायों का पूर्ण प्रभाव समय की अवधि में लागू हो जाने की संभावना है।

24. एमपीसी नोट करता है कि आउटपुट अंतर मामूली रूप से कम हो गया है क्योंकि वास्तविक आउटपुट संभावित से कम

है। निवेश गतिविधि ठीक हो रही है लेकिन मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च से समर्थित है। जरूरत निजी निवेश गतिविधि और निजी उपभोग को मजबूत करने की है।

25. इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने मौद्रिक नीति के रुख को नपी-तुली कसावट से तटस्थ में बदलने और नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने का निर्णय लिया है।

26. मौद्रिक नीति के रुख को बदलने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। नीति रेपो दर को कम करने के संबंध में, डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया, डॉ. पामी दुआ, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा और श्री शक्तिकांत दास ने निर्णय के पक्ष में मतदान किया। डॉ. चेतन घाटे और डॉ. विरल वी. आचार्य ने नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। एमपीसी स्थायी आधार पर 4 प्रतिशत की हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। एमपीसी की बैठक के मिनट 21 फरवरी 2019 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

27. एमपीसी की अगली बैठक 2 से 4 अप्रैल 2019 तक निर्धारित की गई है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने; वित्तीय बाजारों के विस्तार और सघनता; भुगतान और निपटान प्रणाली; और, वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

1. विनियमन और पर्यवेक्षण

1. रिजॉल्यूशन आवेदकों के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे में छूट

मौजूदा ईसीबी ढांचे के तहत, ईसीबी की आय जिसे विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपये (आईएनआर) में नामित किया जाता है, को घरेलू रूप से ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उधार या पुनर्भुगतान के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं है। दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत कॉरपोरेट ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत रिजॉल्यूशन आवेदक को मौजूदा उधारदाताओं को चुकाने के लिए विदेश में उधार लेना आकर्षक लग सकता है। उपरोक्त को देखते हुए, सीआईआरपी के अंतर्गत रिजॉल्यूशन आवेदकों के लिए ईसीबी ढांचे के अनुमोदित मार्ग के तहत एंड-युज प्रतिबंधों में छूट देने का प्रस्ताव है और उन्हें लक्ष्य कंपनी के रूप या ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए ईसीबी आय का उपयोग करने की अनुमति देना है। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों को छोड़कर ऐसे ईसीबी का लाभ मौजूदा ईसीबी ढांचे के अंतर्गत सभी पात्र ऋणदाताओं द्वारा उठाया जा सकता है। इस संबंध में दिशानिर्देश फरवरी 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

2. थोक जमा पर निर्देशों की समीक्षा

वर्तमान निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपनी आवश्यकताओं और आस्ति- देयताएं प्रबंधन (एएलएम) अनुमानों के अनुसार थोक जमा पर ब्याज की अंतर दर की पेशकश करने का अधिकार भी दिया गया है। इस संबंध में निर्देश, की समीक्षा पिछली बार जनवरी 2013 में की गई, जिसमें "थोक जमा" को ₹1 करोड़ और उससे अधिक के एकल रूप जमा के रूप में परिभाषित किया गया। जमा बढ़ाने में बैंकों की परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से,

यह प्रस्तावित है। ₹2 करोड़ और उससे अधिक के एकल रूप जमा के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित किया जाए; तथा इसके बाद बैंक पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली में अपने थोक जमा ब्याज दर कार्ड बनाए रखेंगे।

इस संबंध में दिशानिर्देश फरवरी 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

3. शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकछत्र (अंब्रेला) संगठन

पूंजीगत धन जुटाने के लिए संरचना, आकार, अवसर की कमी और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संचालन का सीमित क्षेत्र उनकी वित्तीय कमजोरियों को बढ़ाता है। यूसीबी क्षेत्र को वित्तीय रूप से लचीला बनाने और जमाकर्ताओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में एकछत्र संगठन (यूओ) का गठन करना है जैसा कि कई देशों में प्रचलित है। यूओ, अपने सदस्य यूसीबी को चलनिधि और पूंजी समर्थन प्रदान करने के अलावा, सदस्यों से साझा उपयोग के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचा स्थापित करने की भी अपेक्षा करेगा ताकि वे अपेक्षाकृत कम लागत पर संचार प्रौद्योगिकी सूचना के क्षेत्र में अपनी सेवाओं को व्यापक बना सकें। यूओ फंड प्रबंधन और अन्य परामर्श सेवाओं को भी प्रदान कर सकता है।

यूसीबी क्षेत्र के लिए यूओ के गठन का विचार पहली बार वर्ष 2006 में यूसीबी की पूंजी के संवर्द्धन पर रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री एन. एस. विश्वनाथन) द्वारा किया गया था। इसे 2009 में शहरी सहकारी बैंकों के एकछत्र संगठन पर कार्यदल और रिवाइवल फंड के गठन (अध्यक्ष: श्री वी एस दास) और वर्ष 2011 में नए शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री वाई एच मालेगाम) द्वारा अधिक विस्तार से जांचा गया था। वर्ष 2015 में यूसीबी (अध्यक्ष: श्री आर गांधी) पर उच्चाधिकार समिति द्वारा यूओ की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

रिजर्व बैंक को नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (एनएफसीयूसीबी) से यूओ स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है। रिजर्व बैंक द्वारा यूओ प्रस्ताव की बारीकियों पर निर्णय जल्द ही लिया जाएगा।

4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को रेटेड जोखिमों के लिए जोखिम भार

बासल III पूंजी विनियमावली पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत आस्ति फाइनेंस कंपनियों (एएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां (एनबीएफसी-आईएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड (एनबीएफसी-आईडीएफ) के अलावा रेटेड साथ ही अनरेटेड जमा स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) पर बैंकों के एक्सपोजर / दावों को समान रूप से 100% पर जोखिम भारित करना होगा। सही रेटिंगवाली एनबीएफसी के लिए ऋण के प्रवाह को सुगम बनाने की दृष्टि से, अब यह निर्णय लिया गया है कि कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी एनबीएफसी के लिए बैंकों का रेटेड एक्सपोजर प्रत्याशित रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग के अनुसार उसी तरीके से जोखिम-भारित किया जाएगा जैसा कि कॉरपोरेटों के मामले में किया जाता है। सीआईसी के लिए एक्सपोजर 100% पर जोखिम भारित बना रहेगा। इस संबंध में दिशानिर्देश फरवरी 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

5. एनबीएफसी श्रेणियों का संगतिकरण

विशिष्ट क्षेत्र / आस्ति वर्गों से संबंधित एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियां पिछले कुछ समय के साथ विकसित हुई हैं। प्रत्येक एनबीएफसी श्रेणी के लिए लगाए गए विनियम भी कुछ भिन्न हैं। वर्तमान में, ऐसी बारह श्रेणियां हैं। छोटे कारोबार और निम्न आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति (अध्यक्ष: डॉ. नचिकेत मोर) और आंतरिक समिति (अध्यक्ष: श्री जी.पद्मनाभन), जिन्होंने क्रमशः जनवरी 2014 और अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के संगतिकरण की सिफारिश की थी। रिज़र्व बैंक इस तरह के संगतिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और एनबीएफसी क्षेत्र के लिए वर्तमान इकाई-आधारित विनियमन की जगह गतिविधि-आधारित विनियमन की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, नवंबर 2014 में जमा स्वीकृति विनियमों का संगतिकरण किया गया था। इसके अलावा, ईसीबी मानदंडों के हाल के युक्तिकरण और उदारीकरण के साथ, एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू विभिन्न नियम संगतिकृत हैं।

अब क्रेडिट इंटरमीडिएट, अर्थात, आस्ति फाइनेंस कंपनियों (एएफसी), ऋण कंपनियों और निवेश कंपनियों में लगी एनबीएफसी की प्रमुख श्रेणियों को एक ही श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा श्रेणियों का प्रस्तावित विलय करने से कई श्रेणियों से उत्पन्न होने वाली जटिलताएं काफी हद तक कम हो जाएगी और यह एनबीएफसी को उनके परिचालन में अधिक से अधिक लचीलापन प्रदान करेगा। यह संख्या में 99% एनबीएफसी को कवर करेगा। इस संबंध में दिशानिर्देश फरवरी 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

II. वित्तीय बाजार

6. निवासियों और गैर-निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सुविधाएं (विनियमन फेमा-25)

गैर-निवासियों और निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम के हेजिंग के लिए मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा क्रमशः फरवरी 2018 और अगस्त 2018 में मौद्रिक नीति वक्तव्यों में विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर विवरण में घोषित की गई थी। उक्त समीक्षाएं की गईं।

समीक्षा के बाद, संशोधित दिशा-निर्देशों का एक डाफ्ट टिप्पणी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में डाला जा रहा है। मसौदा निर्देश अन्य बातों के साथ, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एकल एकीकृत सुविधा में निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सुविधाओं का विलय करने का, उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंद के किसी भी उपकरण का उपयोग करके लचीले ढंग से हेज करने के लिए वैध अंतर्निहित जोखिम की अनुमति देने का, विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए प्रत्याशित जोखिम को रोकने की क्षमता का परिचय देने का, और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव की पेशकश करने के लिए अधिकृत डीलरों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रस्ताव करते हैं। संशोधित दिशानिर्देशों पर डाफ्ट परिपत्र फरवरी 2019 के अंत तक जारी किया जाएगा।

7. ऑफशोर रुपी मार्केट पर कार्य बल

भारतीय रुपये में अपतटीय हित को देखते हुए, गैर-निवासियों को धीरे-धीरे घरेलू बाजार में अपनी हेजिंग आवश्यकताओं के लिए प्रोत्साहन देने के लिए हैं रिज़र्व बैंक के नीतिगत प्रयास जारी हैं। इसी समय, अपनी मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए डेरिवेटिव

बाजारों में निवासियों के एक्सेस में सुधार करने की आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक उद्घाटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और प्रतिभागियों और विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला से लाभ उठाने के लिए, ऑफशोर रुपी मार्केट पर कार्य बल स्थापित करने का प्रस्ताव है। कार्य बल ऑफशोर रुपी मार्केट से संबंधित मुद्दों की गहराई से जांच करेगा और उचित नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगा जो रुपये के बाहरी मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए भी कारगर है। फरवरी 2019 के अंत तक कार्य बल की रचना और विचारार्थ विषय के बारे में अगला विवरण अलग से जारी किया जाएगा।

8. ब्याज दर डेरिवेटिव निर्देशों को युक्तिसंगत बनाना

रिज़र्व बैंक ने, समय-समय पर, विभिन्न ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों जैसे कि ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए), ब्याज दर भविष्य (आईआरएफ), ब्याज दर विकल्प (आईआरओ) और मनी मार्केट फ्यूचर (एमएमएफ) से संबंधित विनियमनों को जारी किया था। डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देश 2007 में उपयोगकर्ताओं और बाजार निर्माताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए जारी किए गए थे। हालांकि, ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप (आईओएस) को छोड़कर, इन डेरिवेटिव बाजारों में गतिविधि काफी सूक्ष्म और सीमित रही है। अन्य कारणों से, इसने भारतीय वित्तीय क्षेत्र में ब्याज दर डेरिवेटिव के सीमित उपयोग में योगदान दिया है। इनमें से कुछ विनियमों की समीक्षा लगभग दो दशकों (1999 के आईआरएस / एफआरए दिशानिर्देश) से भी नहीं की गई है। इसलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए एक संपन्न वातावरण को बढ़ावा देने के अंतिम उद्देश्य के साथ स्थिरता और पहुंच को आसान बनाने के लिए ब्याज दर डेरिवेटिव नियमों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। मार्च 2019 के अंत तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

9. वित्तीय बेंचमार्क का विनियमन

इसे रिज़र्व बैंक द्वारा नियमित वित्तीय उत्पादों और बाजारों से संबंधित बेंचमार्क प्रक्रियाओं के अभिशासन में सुधार के लिए वित्तीय बेंचमार्क के लिए एक विनियामक ढांचा पेश करने के लिए 05 अक्टूबर 2018 की चौथी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में प्रस्तावित किया गया था। सार्वजनिक परामर्श के लिए डाफ्टर दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

10. कॉर्पोरेट ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश

अप्रैल 2018 में कॉर्पोरेट ऋण में किए गए एफपीआई निवेश की समीक्षा के एक हिस्से के रूप में, यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी एफपीआई के पास अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो के 20 प्रतिशत से अधिक एकल कॉर्पोरेट के लिए एक्सपोजर नहीं होगा (कॉर्पोरेट से संबंधित संस्थाओं के एक्सपोजर सहित)।

एफपीआई को अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करने के लिए मार्च 2019 तक अपने नए निवेश पर इस आवश्यकता से छूट दी गई थी। हालांकि यह प्रावधान एफपीआई को परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन आगे बाजार प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि एफपीआई को बाधित कर रही है। भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार तक एक्सेस के लिए निवेशकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रोत्साहित करने के लिए, अब इस प्रावधान को वापस लेने का प्रस्ताव है। इस आशय का एक परिपत्र फरवरी 2019 के मध्य तक जारी किया जाएगा।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

11. भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन

रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2009 में भुगतान गेटवे प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर जैसे बिचौलियों के नोडल खातों के रखरखाव के बारे में निर्देश जारी किए थे। "भुगतान और निपटान प्रणाली - विजन 2018" दस्तावेज़ में, रिज़र्व बैंक ने संकेत दिया था कि ऐसी संस्थाओं की बढ़ती भूमिका और महत्व को देखते हुए, इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाएगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर्स को विनियमित करने की आवश्यकता और व्यवहार्यता की जांच कर रहा है। हितधारकों के परामर्श के लिए इन संस्थाओं के भुगतान संबंधी गतिविधियों को कवर करने वाले व्यापक दिशानिर्देशों पर एक चर्चा पत्र पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत किया जाएगा।

IV. वित्तीय समावेशन

12. कृषि ऋण की समीक्षा के लिए कार्य समूह

पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण वृद्धि महत्वपूर्ण बनी रही है। इसके बावजूद, कृषि ऋण से संबंधित प्रश्न जैसे कि क्षेत्रीय असमानता, कवरेज की सीमा, आदि भी बने रहे हैं। पूंजी निर्माण के लिए दीर्घकालिक कृषि ऋण को अधिक गहरा करने का भी प्रश्न है। इन मुद्दों की जांच करने और व्यावहारिक समाधान और नीतिगत पहल करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा कृषि ऋण की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है।

13. संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण-सीमा का संवर्धन

वर्तमान में बैंकों को-1 लाख तक संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण प्रदान करना अनिवार्य है। 1 लाख की यह सीमा वर्ष 2010 में तय की गई थी। तब से समग्र मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को ₹1 लाख से ₹1.6 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज में वृद्धि होगी। इस आशय का परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

भाषण

भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद नीतिगत मुद्दों पर चिंतन
शक्तिकांत दास

सूक्ष्म ऋण और कैसे कोई लोक ऋण रजिस्ट्री इसे सुदृढ़ कर सकता है
इसके संबंध में कुछ विचार
विरल वी. आचार्य

राष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकारी एवं वैश्विक वित्तीय चक्र
हेलेन रे

भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद नीतिगत मुद्दों पर चिंतन*

शक्तिकांत दास

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के नवें संस्करण में भाग लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहां आना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूपों पर अपने विचार रखना वास्तव में खुशी की बात है। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों, अर्थात् गुजरात सरकार, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष तथा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

जैसा कि यहां सम्माननीय श्रोता जानते हैं, हाल के वर्षों में भारत विश्व की सर्वाधिक आकर्षक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। भारत ने हाल के वर्षों में न केवल अनेक वैश्विक आघातों को सफलतापूर्वक सहा है, बल्कि यह विश्व में सबसे तेज संवृद्धि वाली उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की सूची में शीर्ष स्थान पर है। आईएमएफ के डेटाबेस के अनुसार वैश्विक संवृद्धि में भारत का योगदान 2000 से 2008 के दौरान 7.6% से बढ़कर 2018 में 14.5% हो गया है। जहां तक मध्यावधि संभावना का संबंध है, बहुपक्षीय एजेंसियां इस बारे में और भी आशावादी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत की संवृद्धि गाथा को मजबूत घरेलू मूलभूत तत्वों का सहारा मिला है। उदाहरण के लिए (i) मुद्रास्फीति कम हुई है, (ii) केंद्र सरकार राजस्व संबंधी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और (iii) चालू खाता घाटा (सीएडी) दबावग्रस्त अवधि (अर्थात् 2013 के मध्य की टेपर टॉक अवधि) के शीर्ष स्तर से बहुत कम है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में घरेलू सुधारों की तेज गति को देखा है। इन सुधारों में अन्य बातों के साथ साथ मुद्रास्फीति के लचीले लक्ष्य वाली मौद्रिक नीति संरचना, दिवाला

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। दिनांक 18 जनवरी 2019 को इन्वेस्टर राउंड टेबल, 9वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में दिया गया व्याख्यान।

और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा एफडीआई व्यवस्था को उदार बनाकर विदेशी निवेश बढ़ाना और एक सुचारू कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना शामिल हैं।

अब मैं इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

मुद्रास्फीति

पहले मैं मुद्रास्फीति पर बात करना चाहूंगा। एक केंद्रीय बैंक का मूल अधिदेश अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता को बनाए रखना है। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को कम बनाए रखने से घरेलू और वैश्विक निवेशकों में ज्यादा भरोसा पैदा होता है। भारत में 2012-13 से काफी अवस्फीति हुई है जिसमें सीपीआई मुद्रास्फीति 2012-13 के 10% के वार्षिक औसत से घटकर 2017-18 में 3.6% और 2018-19 में अब तक (अप्रैल) 3.7% रह गई है। अद्यतन स्थिति के अनुसार दिसंबर 2018 में हेड लाइन मुद्रास्फीति कम होकर 2.2% रह गई है। रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को क्रमबद्ध रूप से कम करने - जनवरी 2015 तक 8%, जनवरी 2016 तक 6% और 2017 की चौथी तिमाही तक 5% पर लाने की प्रतिबद्धता, जिसे मुद्रास्फीति का अनुसरण पथ कहा गया है, के कारण यह अवस्फीति हुई है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम में वैधानिक संशोधन, जिसमें संवृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कीमत स्थिरता को मौद्रिक नीति के मूल लक्ष्य के रूप में अधिदेशित किया गया है, के द्वारा लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) को औपचारिक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा ± 2 प्रतिशत की छूट के दायरे के साथ 4 प्रतिशत के संख्यात्मक मुद्रास्फीति लक्ष्य के निर्धारण के अनुसार कीमत को परिभाषित किया गया है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के औपचारिक रूप से गठन के साथ ही मौद्रिक नीति का निर्धारण समिति आधारित दृष्टिकोण में बदल गया। इससे निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ गई है।

भारत में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य को अपनाने के बाद से मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्य की सीमाओं के भीतर बनी हुई है। यहां मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारे मुद्रास्फीति के परिणामों में कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट भी लाभदायक रही है।

वित्तीय क्षेत्र

अब मैं हाल के वर्षों में घरेलू वित्तीय क्षेत्र की कुछ प्रमुख नीतिगत गतिविधियों पर चर्चा करूंगा।

बैंकिंग क्षेत्र

हम सब जानते हैं कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। तथापि, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां आईं। बैंकों की अतिसंवेदनशीलता कम करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए हाल ही में किए गए नीतिगत उपायों के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली कायापलट के कगार पर है। इन संस्थाओं की आघात-सहनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से विनियामक और लेखांकन संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा हाल की अवधि में की जा रही पहलों का उद्देश्य दबावपूर्ण आस्तियों का बेहतर और समय पर निर्धारण, समुचित प्रावधानीकरण और कुशल समाधान प्रक्रिया बनाना है। अद्यतन पर्यवेक्षी आंकड़े बताते हैं कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार के आरंभिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत के अधिकतम पर पहुंचने के बाद सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात सुधर कर सितंबर 2018 में 10.8 प्रतिशत हुआ। रिजर्व बैंक के वर्तमान आकलन के अनुसार इस अनुपात में और सुधार होगा और मार्च 2019 तक यह 10.3 प्रतिशत हो जाएगा।¹

नया समाधान ढांचा बदलाव लाएगा, जिसकी धुरी दिवालिया और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) है और आरबीआई का विनियामक ढांचा सुकारक है। यह एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करता है, जिसमें आरंभिक दबाव की शीघ्र पहचान की सहायता से संकटग्रस्त आस्ति का अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सकेगा। आईबीसी फ्रेमवर्क में देनदारों का पक्ष शक्तिशाली हो जाने से तेज और निष्पक्ष समाधान प्रक्रिया की सुविधा होगी और इससे ऋण चुकौती संस्कृति में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। यह ढांचा एक कॉर्पोरेट कर्जदार को बाजार-चालित, समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराता है, और इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं को उनके

तुलनपत्र लाभ की स्थिति में लाने में सहायता करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा ऋण-संस्कृति में दर्शनीय बदलाव ला रहा है।

आईबीसी ढांचे में अब तक की प्रगति उत्साहजनक रही है और इसके अंतर्गत पहले की प्रणालियों की तुलना में बेहतर वसूली हुई है। दिनांक 03 जनवरी 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 66 मामलों में समाधान प्रक्रियाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनमें समाधान मूल्य के रूप में ऋणदाताओं की लगभग ₹800 बिलियन राशि शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सुदृढ़ता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि बैंकों के लाभप्रदता अनुपात और पूंजी स्थितियों में सुधार हुआ है। सितंबर 2018 के अंत में अन्य सुदृढ़ता संकेतक, जैसे टियर I लीवरेज अनुपात 6.7 प्रतिशत तथा चलनिधि कवरेज अनुपात 134.8 प्रतिशत रहा, जो न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षाओं से काफी ऊपर था। प्रावधान कवरेज अनुपात भी मार्च 2018 के अंत में 48.3 से बढ़ कर सितंबर 2018 के अंत में 52.4 प्रतिशत हो गया। बैंक ऋण हाल के वर्षों के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति से उबर रहे हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र को संसाधनों के प्रवाह में बैंकों की मध्यस्थता फिर से बढ़ रही है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के बढ़ते हुए आकार और जटिलताओं के कारण बैंकों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणालियों को मजबूत बनाना आवश्यक हो गया है। हाल ही में हुई वित्तीय धोखाधड़ियों ने बैंकों में सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों के महत्व को और अधिक रेखांकित किया है। सरकार, बैंक बोर्ड ब्यूरो और रिजर्व बैंक फिलहाल कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ संरचना का विकास करने में लगे हुए हैं, और इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रूपरेखा को पुनर्परिभाषित किया जा सकेगा।

उपभोक्ता संरक्षण के मामले में शिकायत निवारण में सुधार, डिजिटल भुगतानों के लिए अभिनव उत्पादों की शुरुआत तथा बैंकिंग में साइबर सुरक्षा में सुधार के उपायों के कारण आशा है कि वित्तीय समावेशन में विस्तार होगा तथा वित्तीय सेवाएं कुशलता से और कम लागत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। रिजर्व बैंक इस तथ्य से वाकिफ है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली मजबूत होने से

¹ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2018.

अनौपचारिक क्षेत्र को संस्थागत वित्त तक अधिक पहुंच मिलेगी, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। हमने भुगतानों के डिजिटलाइजेशन में वृद्धि करने और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए हाल ही में श्री नंदन निलेकनी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतानों को मजबूत करने पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

आरबीआई के विनियामक दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है, और रहेगा कि बैंकिंग प्रणाली इस अस्थायी कठिन दौर में मजबूत बनी रहती है और हमारी वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक मध्यस्थ की भूमिका निभाना जारी रखती है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की बैंकों के पूरक और प्रतिस्पर्धी के रूप में विशिष्ट स्थिति को देखते हुए, यह ऐसा अन्य क्षेत्र है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के संयुक्त तुलन-पत्र के लगभग 15 प्रतिशत आकार वाला यह क्षेत्र हाल के वर्षों में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जो वाणिज्यिक क्षेत्र को निधि का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराता है। फिर भी, हाल ही में इस क्षेत्र ने बहुत चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया है।

एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी की ऋण चुकोती में हुई चूक के कारण इस क्षेत्र की अतिसंवेदनशीलता और सामान्यतः पर्यवेक्षी निगरानी, और विशेषतः आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एनबीएफसी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक चाहता है कि एनबीएफसी के एएलएम ढांचे को सुदृढ़ किया जाए तथा इसे एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों में सुसंगत बनाया जाए। हाल के संकट के मद्देनजर एनबीएफसी क्षेत्र की निधीयन तक अतिरिक्त पहुंच की अनुमति देने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी की ऋण-बहियों के प्रतिभूतीकरण के मानदंडों में छूट दी है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए

गए बांडों पर आंशिक ऋण-वृद्धि उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। इस उपाय के कारण बांडों की क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाएगी और कंपनियों को बेहतर शर्तों पर बाजार से निधियां उपलब्ध हो सकेंगी।

बाह्य क्षेत्र

कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने तथा वैश्विक मांग स्थितियों की अनिश्चितता के कारण व्यापार की शर्तों में हानि होने के बावजूद हाल की अवधि में भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत बना रहा। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2013-14 (अर्थात् टेपर टॉक के बाद की अवधि) से ही जीडीपी के 2 प्रतिशत से कम बना हुआ था, यद्यपि वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में यह बढ़ कर 2.7 प्रतिशत हो गया, जो कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों को दर्शाता है। हाल के वर्षों में चालू खाता में मामूली घाटे को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के मजबूत प्रवाह के द्वारा समायोजित किया गया। घरेलू पूंजी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्वाह के बावजूद मजबूत एफडीआई अंतर्वाहों और विदेशी मुद्रा रिजर्व बफर के निर्माण के कारण भारत को अपनी बाह्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिली।

कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अपनी मौद्रिक नीति को सामान्य करने के पथ पर हैं, इसलिए वैश्विक पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन का कार्य भारत सहित ईएमई से दूर हो रहा है। एक अन्य कारक, जो भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए हानिकारक है, वह है ब्रेकिजट में हुई हाल की गतिविधियां। इसके परिणामस्वरूप भारत को नीतिगत चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि यूके और ईयू के साथ भारत के मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंध हैं। हम आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर सावधानी से विचार करेंगे और समुचित नीतिगत प्रतिक्रिया देंगे।

जहां तक बाह्य क्षेत्र संबंधी नीतिगत परिवेश का संबंध है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्रीय मानदंडों को क्रमिक रूप से सरल किया गया है, और अब कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ कर सभी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। हाल के वर्षों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त करके, विभिन्न प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बना कर, केंद्र सरकार से अनापत्ति प्राप्त

करने हेतु एकल विंडो के रूप में ई-बिज़ पोर्टल की शुरुआत करके तथा शासन को अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एफडीआई नीति के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमने दो दिन पहले ही कारोबार में आसानी के लिए भारतीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारों को शासित करने वाले विनियमों को भी काफी तर्कसंगत और उदार बनाया है। आने वाले वर्षों में इन सभी सुधारों और एक स्थिर घरेलू समष्टि आर्थिक परिवेश का पूर्ण प्रभाव दिखेगा और परिणाम प्राप्त होंगे। वास्तव में, 2017-18 में भारत में एफडीआई के अंतर्वाह यूएस\$ 61 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर थे।

इसके अतिरिक्त, जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2013 में 22.4 प्रतिशत से घट कर सितंबर 2018 के अंत में 20.8 प्रतिशत रह गया है। अन्य बाह्य संकेतक, जैसे आयात कवर और अल्पकालिक ऋण की तुलना में आरक्षित निधि अनुपात में भी 2013 के मध्य की टेपर टॉक अवधि, जब भारतीय रुपये पर अत्यंत दबाव था, की तुलना में सुधार आया है (सारणी)।

चुनौतियां और संभावनाएं

यह माना जाता है कि भारत मध्यम से दीर्घावधि में विश्व की सबसे तेज वृद्धि वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। कतिपय वैश्विक एजेंसियों के वृद्धि अनुमानों ने भारत को जी-20 अर्थव्यवस्थाओं के बीच शीर्ष रैंक दिया है। आईएमएफ और विश्व बैंक ने मध्यावधि में लगभग 7.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह संभावना है कि निवेश और निजी उपभोग द्वारा प्रेरित यह वृद्धि अब अधिक संधारणीय होगी। राष्ट्रीय लेखा

सारणी: बाह्य क्षेत्र संकेतक

(प्रतिशत, जब तक कि अन्यथा न दर्शाया जाए)

संकेतक	मार्च 2013 के अंत में	मार्च 2017 के अंत में	मार्च 2018 के अंत में	सितं. 2018 के अंत में
चालू खाता घाटा/जीडीपी अनुपात*	4.8	0.6	1.9	2.7**
बाह्य ऋण का जीडीपी से अनुपात	22.4	20.0	20.5	20.8
आरक्षित निधियों का कुल ऋण से अनुपात	71.3	78.5	80.2	78.5
आरक्षित निधियों का अल्पकालिक ऋण से अनुपात	33.1	23.8	24.1	26.1
आयातों का रिज़र्व कवर (महीनों की संख्या में)	7.0	11.3	10.9	9.5

*वित्त वर्ष के दौरान औसत; **: वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के लिए औसत

के अद्यतन अनुमान बताते हैं कि निवेश गतिविधियां 2017-18 के 7.6 प्रतिशत की तुलना में बढ़ कर 2018-19 के दौरान 12.2 प्रतिशत हो गई हैं। हाल के संरचनागत सुधारों के लाभ प्राप्त होने पर निवेश गतिविधि के और मजबूत होने की आशा है।

आगे बढ़ते हुए, सबसे ज्यादा प्राथमिकता घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने की होगी, विशेषतः ऐसे वैश्विक वातावरण में, जो अत्यधिक अनिश्चितता से घिरा है। वैश्विक वृद्धि, व्यापार और निवेश में गिरावट का जोखिम न केवल बढ़ा है, बल्कि उभरते हुए बाजारों पर उसका प्लवन प्रभाव भी बहुत गंभीर हो सकता है। अतएव, हमें आगे आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय बाजार में अचानक उथल-पुथल होने और घरेलू अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों द्वारा उसका सामना किए जाने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे वातावरण में, घरेलू समष्टि आर्थिक नीति संरचना की सहायता के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय पर्यवेक्षण और विनियमन होना आवश्यक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में जिन प्रमुख नीतिगत चुनौतियों का सामना कर रही है, अब मैं उन पर चर्चा करूंगा।

(ए) मुद्रास्फीति

- हाल के वर्षों में हेडलाइन मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, इसके प्रमुख घटकों – खाद्य, ईंधन में मुद्रास्फीति और खाद्य और ईंधन को छोड़ कर मुद्रास्फीति – ने इस वर्ष काफी भिन्नता दर्शाई है। खाद्य स्फीति अक्तूबर 2018 से ऋणात्मक हो गई है, और ईंधन-स्फीति में अत्यधिक उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जबकि खाद्य और ईंधन को छोड़ कर मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के आसपास स्थिर बनी हुई है। विभिन्न समूहों के बीच ऐसी अधिक भिन्नता के कारण मुद्रास्फीति के आकलन में समस्या होती है। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य वाली संरचना के अंतर्गत मुद्रास्फीति के उद्देश्यों और संवृद्धि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक नए डेटा का सावधानी से विश्लेषण करना आवश्यक है।

(बी) वित्तीय क्षेत्र

- नए समाधान ढांचे के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंकों की आस्ति गुणवत्ता तथा दबावपूर्ण आस्तियों के समाधान पर लगातार निगरानी रखना आवश्यक है। आस्ति गुणवत्ता में और गिरावट की रोकथाम सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
- यद्यपि प्रौद्योगिकी बैंकिंग क्षेत्र में संवृद्धि और नवोन्मेष के अवसर उपलब्ध कराती है, किंतु इसमें नई चुनौतियां और जोखिम भी जुड़े होते हैं। साइबर जोखिम एक प्रमुख चुनौती है। व्यापक साइबर जोखिम और सुदृढ़ता नीतियां निर्माण करना और उनका सावधानी से क्रियान्वयन करना आवश्यक है।
- एक अन्य क्षेत्र, जहां नीतिगत कार्रवाई करना अपेक्षित है, वह है बैंकों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना।

(सी) बाह्य क्षेत्र

- हालांकि सकारात्मक नीति निर्धारण और समष्टि आर्थिक स्थिरता बने रहने से भारत की बाह्य अतिसंवेदनशीलता को रोकने में सहायता मिली है, फिर भी कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता को देखते हुए बाह्य क्षेत्र की गहन निगरानी करना आवश्यक है।

ये ऐसे दो वैश्विक आघात हैं, जिनका हमारे सीएडी और वित्तीय प्रवाहों पर प्रभाव पड़ेगा।

- भारतीय कंपनियों के सामने आ सकने वाली एक अन्य चुनौती ब्रेकिजट की गतिविधियों से संबंधित है। भारतीय कंपनियों और नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे सभी अवसरों और चुनौतियों पर गौर करें और तदनुसार उचित प्रतिसाद देने के लिए पुनः रणनीति तैयार करें।

अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि आरबीआई में हम संवृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिदेशित कीमत स्थिरता बनाए रखने हेतु मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में; तथा बैंकिंग क्षेत्र और भुगतान प्रणालियों के विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वित्तीय स्थिरता बनाए रखने तथा संधारणीय और सुदृढ़ संवृद्धि के लिए योग्य स्थितियां बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

अक्तूबर 2018 में, जब मुझे कोई अंदाजा भी नहीं था कि मैं दिसंबर 2018 में आरबीआई में होऊंगा, मैंने यह ट्वीट किया था कि “मौजूदा स्थितियों में सभी देशों में केंद्रीय बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके सामने स्थिति को आजमाने और समझने, और अपनी बहुविध जिम्मेदारियों को निभाते हुए निर्णायक कदम उठाने की चुनौती है।” भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार काम करूं।

धन्यवाद।

सूक्ष्म ऋण और कैसे कोई लोक ऋण रजिस्ट्री इसे सुदृढ़ कर सकता है इसके संबंध में कुछ विचार*

विरल वी. आचार्य

कभी-कभी जब मैं नई चीजें लिखने बैठता हूँ तो वही पुराने ख्यालात मेरे दिमाग में आते हैं ठीक उसी तरह जैसे कोई पसंदीदा गाना मन-मस्तिष्क में इस तरह गहरे पैठ कर जाता है कि जब कोई किसी विषय पर सोच रहा हो तो वह बिना किसी वजह के अनायास ही गुनगुनाने लगता है। मेरे मामले में, मेरी आँखों के सामने कुछ अनोखे चित्र उभरते हैं। मैंने कोशिश की है कि इन चित्रों का वर्णन किस प्रकार किया जाए और उनके कोलाज मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। वे यह भी बताते हैं कि मैं कैसे अर्थशास्त्र और वित्त के बारे में और सामान्य तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ - जैसा कि मीडिया कई बार कुछ छोटे-मोटे तरीके से और कभी-कभी बड़े तौर-तरीके से हमारे आसपास के घर-परिवारों की दैनिक स्थितियों को समझने और इन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। बहरहाल, 'इकोनॉमिक्स' शब्द की व्युत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द 'ओइकोनोमिया' से हुई है जिसका अर्थ 'घर-परिवार का प्रबंधन' है। गहन शोध के आधार पर, कई लोग [मेस्सचुएट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के विख्यात प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डफलो] का स्पष्ट मानना है कि गरीब आदमी ही प्रायः सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था को अमल में लाता है क्योंकि घर-परिवार का कुप्रबंधन उनके लिए काफी महंगा पड़ सकता है।

* डॉ. विरल वी. आचार्य, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का आईआईटी बॉम्बे टेक फेस्ट मुंबई में 15 दिसंबर 2018 को दिया गया भाषण।

मैं ये टिप्पणी अपने प्रिय स्कूल शिक्षक, मुंबई के फैलोशिप स्कूल के शैलेश शाह सर को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने 5 जनवरी, 2019 की सुबह अपनी अंतिम सांस ली; उन्होंने मुझे भारतीय भाषाएँ, सामाजिक विज्ञान और रचनात्मक लेखन की कला सिखाई; उन्होंने वास्तव में अपने सभी छात्रों के भीतर महत्वाकांक्षा जागृत करके हमें कल्पना से लवरेज कर दिया।

इन टिप्पणियों के कुछ हिस्सों को पहली बार 2017 में एक पुस्तक विमोचन के लिए तैयार किया गया था, इसके बाद कई छात्र समारोहों और कुछ दीक्षांत समारोह में दिया गया भाषण है। यह अंतिम संस्करण इन वार्ताओं में मेरी टिप्पणियों के संचय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका समापन 15 दिसंबर, 2018 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (आईआईटीबी) टेक फेस्ट में हुआ था। मैं अनुजित मित्रा, जोस कडूर और विनीत श्रीवास्तव के बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभारी हूँ।

इसलिए मैं अपनी आँखों के समक्ष उभरते चित्रों का एक-एक कर वर्णन कर रहा हूँ।

पहला चित्र: कई बार शाम में या रात जब मैं अपने भाई के साथ मुंबई में अपने छत पर चहलकदमी कर रहा होता हूँ तो एक तरफ पवन हंस हेलीपैड, नहरू नगर के बेतरतीब तरीके से फैली हुई झुगियाँ, स्वामी विवेकानंद रोड (एस वी रोड) की ओर से आने वाला शोरगुल, और जुहू तट की मंद-मंद हवा व लहरें हमारा अभिवादन करती हैं। मैं मुंबई में गिरगाँव की भीड़भाड़ वाली गली में पला-बढ़ा हूँ। हमारे बचपन का पसंदीदा मनोरंजन अपनी पहली मंजिल की खिड़की से यह देखना था कि कैसे लोग गलियों में अपनी जिंदगी तलाशते हैं। उसी अनुकूल, जब मैं छत पर जाता हूँ तो मेरी आँखें निरपवाद रूप से नेहरू नगर की झुगियों पर जाकर ठहर जाती है। संकीर्ण गलियों में दूर, घनी आबादी के बीच हलचल और जोश से भरपूर झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले हैं जो, लघु बिंब की भांति प्रतीत होते हैं जिनके चारों ओर काफी चहलपहल और सक्रियता है। एक आदमी अपने नीले छत पर डिश एंटीना लगा रहा है; एक वृद्ध जोड़ा मामूली झोंपड़ी के बाहर शायद स्वादिष्ट देशी चाट का आनंद ले रहा है; एक औरत बगल में रखे कपड़े को पटक-पटक कर धो रही है; और लगभग हमेशा बच्चे उल्लासपूर्ण धमाचौकड़ी मचाए रहते हैं, जिनमें से अधिकतर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और मौसमी पतंगबाजी कर रहे होते हैं।

कई बार शाम में, एक विमान पूर्व में स्थित घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरता है और पश्चिम की ओर चला जाता है; और पवन हंस हेलीपैड के ऊपर चॉपर मंडराता है और तेज गड़गड़ाहट के साथ लैंड करता है। आधुनिक परिवहन के ये परिष्कृत साधन जब अपनी कोलाहलपूर्ण उपस्थिति का एहसास कराते हैं तो ऐसे में आप बच्चों को एक साथ झुंड में देख सकते हैं। उनमें से एक आकाश की ओर इशारा कर रहा होता है, वहीं अन्य जोश में आकार उसके चारों ओर घेर कर आश्चर्य से नजारा देखने लगते हैं। बेशक बाद में बच्चे निर्लिप्त भाव से गली क्रिकेट खेलने लौट जाते हैं या पतंग के पीछे भागने लगते हैं।

कोई यह आशा कर ही नहीं सकता है कि ये बच्चे - आश्चर्य के उस थोड़े क्षण में - महत्वाकांक्षी हो गए हैं; कि उनकी आँखें अब आसमान पर ही टिकी हुई हैं; यह कि इसके लिए उनके पास अवसर होगा और उन्हें अपनी संकीर्ण गली से दो कदम पर स्थित पवन हंस हेलीपैड और ऊपर उड़ने वाले विशाल

यांत्रिक पक्षियों के बीच की खाई को पाटने के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त होगा।

क्या ये बच्चे उड़ान भर पाएंगे?

उनकी यात्रा कैसी होगी?

वे कहाँ उतरेंगे?

मैं कुछ सेकंड के लिए इस पर विचार करता हूँ, लेकिन फिर मेरा ध्यान एस वी रोड पर वाहनों के लगातार बज रहे हॉर्न पर चला जाता है।

दूसरा चित्र : लगभग दस साल पहले तक मैं एक डॉक्टरेट छात्र के रूप में अपना अच्छा-खासा समय बीतता था, और बाद में पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा केंद्रित एक भारतीय गैर सरकारी संगठन के साथ काम करते हुए एक प्रोफेसर के रूप में। भारत के लिए यह कार्यकलाप मेरा जीवन आधार बन गया था। न्यूयॉर्क या लंदन से अपनी छुट्टियों में जब वापस घर आता था तो मैं शहरी इलाकों में उनके कुछ पालनाघरों का दौरा करने के लिए कुछ दिन निकालता था, और अगर यात्रा कार्यक्रम में समय रहता था तो मैं गांवों में त्वरित पठन कार्यक्रमों के आयोजन केन्द्रों पर भी जाता था। इन यात्राओं ने हितधारकों के साथ मेरी बातचीत को अधिक विश्वसनीय, आकर्षक और विशद बना दिया। लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान देने वाला थे।

पहली बार किसी बच्चे को वर्णमाला ढूँढने से ज्यादा प्रेरणादायी यदि कोई चीज है तो वह है पहली किताब को पढ़ना, असीम उत्साह और बावलापन के साथ पन्नों को बार-बार पलटना, या अपने पत्थरों के संग्रह को गिनना और जोड़ना, उसके बाद सटीक अंदाजा लगा लेना, जैसा कि महज खजाने पर एक नजर डाल कर बिना गिनती किए सटीक गणना कर लेना! यह बच्चे के चेहरे पर चमक हो सकती है, या कि “वाह!” अथवा उल्लास का क्षण हो सकता है क्योंकि चाहे यह कुछ भी हो बच्चा जब पढ़ना, गणना करना, सीखना शुरू करता है तो यह देखने वाले पर जादू कर देता है।

कोई कुछ और करने के जब्बे के साथ इन दौरों से लौटता है; किसी को महसूस होता है कि वह भारत के जीवन स्रोत को और पोषित करने का काम रहा है; किसी को लगता है कि इन यात्राओं, उड़ान और आरोहण के लिए आनंदपूर्ण शिक्षा आवश्यक पहलू है जिसे बच्चे यथासमय उत्तरदायित्व लेंगे।

तीसरा चित्र : सुबह-सुबह मैं आमतौर पर कार से आरबीआई कार्यालय या बॉम्बे जिमखाना के लिए रास्ते में रहता हूँ। मुझे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे को जोड़ने वाले मिलन मेट्रो सबवे या अब फ्लाईओवर की ओर मुड़ने से पहले एस वी रोड पर रहना होता है। मोड़ से ठीक पहले, बाएँ फुटपाथ पर, हनुमान मंदिर और सांताक्रूज बस डिपो पहुंचने से पहले, वहाँ हमेशा - एक माँ रहती है जो हर समय मेहनत कर रही होती है। यह स्पष्ट है कि वह बेघर है; उसके कम से कम दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र लगभग एक ही है। सुबह के समय के अनुसार, उसे अपना काम बंद कर देना पड़ता है। कई दिन वह अपने चेहरे पर कुछ सख्ती के साथ बच्चों को जगा रही है; वहीं किसी दूसरे दिन जलापूर्ति वाले नल के पानी से वह उन्हें स्नान करा रही है; कई बार वह उन्हें स्कूल ड्रेस पहना रही है; और फिर वह पड़ोस के स्कूल की ओर अक्सर पीठ पर बैग रखे उन बच्चों के साथ भाग रही है। दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका दिमाग एक ही जगह यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित है कि उसके बच्चों को उड़ने और ऊंची उड़ान भरने का मौका मिले। एक माँ के रूप में उसकी भूमिका निश्चित रूप से महान लगती है, ठीक उसी तरह जैसा कि महाभारत में युधिष्ठिर ने इस यक्ष प्रश्न का उत्तर दिया था कि पृथ्वी से भारी क्या है।

कैसे माँ यह सारा काम कर लेती है?

क्या वह किताबों और रसद का खर्चा उठा सकती है?

क्या बच्चों के वापस आने पर वह घर लौट आती है?

दिन भर वह क्या काम करती रहती है?

क्या वह सूक्ष्म उद्यमी हो सकती है?

हालांकि, मन इतना चंचल है कि ज्योंही कार ट्रैफिक सिगनल से बाएँ मुड़ती है और फ्लाईओवर की ओर बढ़ती है तो ये सारे प्रश्न पृष्ठभूमि में छूटते चले जाते हैं और रोजमर्रे के काम में लग जाते हैं।

चौथा चित्र : शनिवार सुबह-सुबह, चटकीली धूप निकल चुकी थी, एक बैंकर अपना थैला कंधे पर टाँगे हुए कच्चे-पक्के घरों के सामने वाली गली से गुजरता है। आस-पास का क्षेत्र अर्द्ध-शहरी है। पलक झपकते ही 20 से 50 वर्ष और कुछ 50 वर्ष से भी ज्यादा उम्र की महिलाएं, जो अधिकतर साड़ी में हैं, उसे घेर लेती हैं। उन सभी ने बैंकर से कुछ न कुछ रकम उधार

लिया हुआ है। वे एक-एक करके अपनी अदायगी करती हैं; प्रत्येक लेनदेन को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है; प्वाइंट-ऑफ-सेल या पीओएस-स्टाइल मशीन से उनके बैंक कार्ड को डिजिटल रूप से स्वाइप भी किया जाता है। कुछ महिलाएं फिर से उधार ले रही हैं; कुछ अपने खातों से पैसा निकाल रही हैं। महीने भर के लिए नियुक्त महिलाओं के इस समूह का रजिस्ट्रार खाते में की गयी प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद अभिलेख को बंद कर देता है।

बैंकिंग पूरी हुई। वृद्धि लगभग शुरू होने वाली है।

मैं उन महिलाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ कि वे उन पैसों का क्या कर रही हैं। निरपवाद रूप से वे सभी उद्यमी हैं। एक ने साड़ी की खरीद बिक्री का कारोबार शुरू किया है, उसे शहर से खरीद कर मुनाफे पर पड़ोस में बेच रही है; उसने कई वर्षों में अपने उद्यम को खड़ा किया है और उसे इस समूह में सबसे लंबे समय तक परिपक्वता (एक वर्ष) वाला सबसे बड़ा ऋण (एक लाख रुपये) मिला है; उसके दोस्त ने ऋण से एक सिलाई मशीन ली है और साड़ियों के मैच की ब्लाउज सिलाई कर रही है; एक दूसरे ने ब्यूटी पार्लर खोला है; वहीं एक अन्य ने अपने पति के स्टेशनरी स्टोर में सॉफ्ट-ड्रिंक का स्टॉल शुरू किया है क्योंकि वहाँ अतिरिक्त, अप्रयुक्त स्थान था, विशेष रूप से दोपहर के दौरान इसका उपयोग किया जाता है जब स्टेशनरी के लिए ग्राहक काफी कम रहते हैं लेकिन गर्मी असहनीय होती है। ऐसा लग रहा था कि उनके प्रभाव क्षेत्र में तत्काल सेवाएं प्रदान करने में कोई कमी नहीं है।

मैं यह जानने के लिए विशेष रूप से उत्सुक था कि इन महिलाओं को किस चीज ने पहली बार में उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया। मुझे जो उत्तर मिला वह पूरी तरह से अपेक्षित नहीं था: दस में से नौ मामलों में, महिलाएं इसलिए उद्यमी बन गई थीं ताकि वे अपने बच्चों को 'टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल' में भेज सकें, या निजी कोचिंग हेतु अतिरिक्त पैसे कमा पाए ताकि बच्चा राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके, या बच्चे को कुछ कंप्यूटिंग और प्रोग्रामिंग सीखा सके क्योंकि यहीं पर भविष्य की नौकरियां हैं!

चित्रों का कोलाज

जब ये चित्र मेरी आँखों के सामने उभरे तो मुझे एहसास हुआ कि पूरी तरह से पूरक होने के बजाय, ये सभी चित्र आपस

में जुड़े हुए थे, कि वित्त - मेरे दिन के काम, और इन चित्रों के बीच एक संबंध था जिसे मेरा मन अवचेतन रूप से सुबह, शाम और छुट्टियों में इकट्ठा कर रहा था। वित्तीय समावेशन से लेकर बच्चों की शिक्षा - महिला उद्यमियों के लिए सूक्ष्म वित्त से लेकर बच्चों को स्कूलों में भेजने तक में एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित हुई है, बदले में बच्चों को पढ़ते और गिनती करते समय, और अनंत आकाश और उससे भी आगे की अपनी उड़ान भरने में लगता है कि "अहा!" मैंने यह कर दिया !!

वित्त तक पहुंच किसी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। इसका विवेकपूर्ण निर्धारण अवसर और वृद्धि का द्वार खोलने के लिए जाना जाता है। यह वास्तव में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे युवाओं के कौशल को सपोर्ट करके, और दिमाग में जोश एवं कल्पना का संचार करके वृद्धि के लिए सबसे बुनियादी सुधार में सहायता कर सकता है ताकि वे खुद को, अपने परिवार को, बाकी हम सबको आगे बढ़ा सकें। कई परिवारों द्वारा शिक्षा को ऐसा जरिया माना जाता है जो उन्हें आर्थिक तनाव से बाहर निकाल देगा। मामूली अपवादों को दरकिनार कर दें तो वास्तव में शिक्षा इनसे उबरने का एक जरिया है।

अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए एक उद्यम करने वाली माँ के पास अपना कर्ज चुकाने की सभी इच्छाएँ होती हैं। जैसे-जैसे बच्चा बढ़ेगा, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। उसे फिर से उधार लेने में सक्षम होने के लिए एक साफ-सुथड़े क्रेडिट रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी ताकि उसकी अब बड़ी चलनिधि आवश्यकताओं को वित्तपोषित किया जा सके। इस तरह, उसके और वित्त प्रदाता के बीच पूर्ण प्रोत्साहन अनुकूलता है। चुकता करने की उसकी इच्छा के अलावा, समय के साथ शिक्षा का लाभ उठाने की आवश्यकता से प्रेरित, उसके उद्यम को कुशलता से चलाना उसके भुगतान करने की क्षमता को मजबूत करेगा। किसी भी दर पर, वित्तदाता एक छोटे ऋण के साथ शुरुआत कर सकता है, पुनर्भुगतान की क्षमता का आकलन करने के लिए एक छोटी अवधि का उपयोग कर सकता है, और उसके लिए बैंक खाते को खोल सकता है जो अन्य भुगतान प्रवाह को ट्रैक करने और क्रेडिट मूल्यांकन में सुधार करने में मदद कर सकता है। एक उधारकर्ता के रूप में महिला उद्यमी की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ सकती है क्योंकि वह पुनर्भुगतान करती रहती है और उसे लंबी अवधि के दौरान अधिक ऋण जुटाने में सक्षम बनाती रहती है।

किसी समूह के रूप में उधारी पुनर्भुगतान करने के लिए गहन प्रोत्साहन पर बल देता है; जब दूसरों द्वारा पुनर्भुगतान किया जा रहा है तो ऐसे में किसी एक उधारकर्ता द्वारा किया गया चूक बड़ा हो सकता है। इसके विपरीत, कुछ लोगों द्वारा चूक को प्रोत्साहित करने से अन्यथा समृद्ध ऋण संस्कृति बिगड़ सकती है।

इसके बदले में, वित्तदाता उधार लेने वाले फंडों की अपनी लागत पर एक स्वस्थ प्रसार कर सकता है, यहां तक कि शुरुआती चूक से कुछ नुकसानों का भी हिसाब लगा सकता है, जिसकी प्राप्ति पर उद्यमी को भविष्य के ऋण से सीमित किया जा सकता है या केवल सख्त ऋण शर्तों और कार्यकाल की पेशकश की जा सकती है।

इस तरह, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता समाज को लाभान्वित करती है।¹

अब मैं इन चित्रों से आरबीआई में अपने काम की ओर चलता हूँ और हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं कि सूक्ष्म ऋण अधिक उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो सके; सूक्ष्म वित्त को एक मजबूत आधार प्रदान किया गया; सूक्ष्म उद्यम को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया; और अप्रत्यक्ष रूप से, इस प्रक्रिया में, हमारे बच्चों को स्कूली शिक्षा और हुनरमंद बनाने के लिए अधिक अवसर प्रदान किए गए।

लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) – ऋण को लोकतांत्रिक और औपचारिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम²

भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में, यह हमेशा महसूस किया जाता है कि छोटे उद्यमी, जो ज्यादातर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के तहत काम करते हैं, उन्हें पर्याप्त ऋण नहीं मिलता है क्योंकि वे अपने उधारदाताओं के लिए सूचनात्मक रूप से अपारदर्शी हैं जो अधिक पारदर्शी बड़े व्यवसायों को ऋण प्रदान करना पसंद करते हैं। रिजर्व बैंक के मूल सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के मार्च 2018 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि बकाया ऋण का लगभग आधा हिस्सा सौ मिलियन रुपये से ऊपर के टिकट आकार के लिए है और तीस प्रतिशत एक बिलियन रुपये से ऊपर है। सूक्ष्म, लघु

¹ छात्र सभा और दीक्षांत समारोह में से कुछ में, मैंने 22 दिसंबर 2017 को युवराज गलाडा से प्राप्त "द इनविटेशन" नामक कविता का पाठ करके यहाँ टिप्पणी को समाप्त किया। यह कविता 1999 में ओरियाह माउंटन ड्रीमर द्वारा लिखी गई थी, जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया।

² इस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए, अगस्त 2018 में दिए गए मेरे भाषण "पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन): जाइंट स्ट्राइड्स टू डेमोक्रेटाइज एंड फॉर्मलाइज क्रेडिट इन इंडिया" देखें।

और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए ऋण व्यापन विशेष रूप से कम है जहां टिकट का आकार आमतौर पर एक से दस मिलियन रुपये के बीच माना जाता है। भले ही एससीबी वाले 95 प्रतिशत से अधिक खातों में ऋण सीमा एक मिलियन से कम हो, लेकिन इन खातों पर बकाया राशि कुल बकाया का सिर्फ 23 प्रतिशत ही है।

क्या हमारे लिए भविष्य में अपने ऋण पारिस्थिकी को नए सिरे से तैयार करने और उस पर पुनर्विचार करने का एक बड़ा अवसर है, ताकि सूक्ष्म ऋण के आर्थिक मूल्य को तलाश करने में कामयाब हो सके ठीक उसी प्रकार जैसा कि मैंने अपने चित्रों के कोलाज में एक खांका खिंचा है?

रिजर्व बैंक में, हम दृढ़ता से ऐसा मानते हैं। हमने लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) पर काम शुरू किया है। हम इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि हम सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट तक पहुंच को प्रभावित करने वाली सूचना की समस्या को किस तरह से हल कर सकते हैं।

अब मैं सूचना की समस्या के बारे में विस्तारपूर्वक बताता हूँ और और कैसे पीसीआर इसको सुलझाने में मदद कर सकता है।

ऋण देते समय ऋणदाता के समक्ष प्रमुख कठिनाई उधारकर्ता की सूचना विषमता की होती है। सीधे शब्दों में कहें तो उधारकर्ता के पास ऋणदाता की तुलना में अपनी आर्थिक स्थिति और जोखिमों के बारे में अधिक जानकारी होती है। ऋण सूचना प्रणाली का उद्देश्य पिछले ऋणदाताओं और उधारकर्ता की वर्तमान ऋणग्रस्तता के साथ ऋण इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऋणदाता को सक्षम करके इस विषमता को कम करना है। वे ऋण आवंटन की दक्षता में सुधार करते हैं, क्योंकि ऋणदाता ऋण सूचना प्रणालियों का उपयोग उचित रूप से भेद करने और समुचित रूप से मूल्य निर्धारण (ब्याज दर) करने के साथ-साथ ऋण की शर्तों (परिपक्वता, संपार्श्विकता, अनुबंध आदि) को बदलने के लिए कर सकते हैं।

ऋण सूचना प्रणाली के बिना क्या होगा?

जहां उधारकर्ता के ऋण का विवरण तैयार होता है, वहीं उधारदाता अपने लाभदायक ग्राहकों की जानकारी की रक्षा करना चाहते हैं और अन्य उधारदाताओं के साथ इसे सीधे साझा करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। इस तरह, उधारकर्ता अपने शुरुआती ऋणदाताओं तक ही सीमित हो सकते हैं, ऋण की शर्तों के चंगुल में फंस सकते हैं, और इससे भी बदतर, यदि मौजूदा

ऋणदाता को खुद की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो नए उधारदाताओं को अपनी ऋण गुणवत्ता बताने में असमर्थ हो जाते हैं (जैसे कि हानियों की पहचान की वजह से पूंजी क्षरण होना जो कि पिछले एक दशक में भारत में बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ता के ऋण के अनर्जक में तबदील होने के प्रभाव की वजह से उच्च खुदरा और बैंकों से एमएसएमई की उधारी लागत के रूप में देखने को मिला था)।

यहीं पर थर्ड-पार्टी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों की बात आती है, जो कि उधारदाताओं से डेटा लेकर उसे इकट्ठा करेंगे और निर्धारित पॉलिसी के अनुसार अन्य उधारदाताओं के साथ इस जानकारी को साझा करेंगे। वैश्विक स्तर पर प्राइवेट क्रेडिट ब्यूरो (पीसीबी) और पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्रज (पीसीआर) दोनों इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। पीसीबी को ऋण संबंधी डेटा प्राप्त करने के लिए विधायी रूप से अधिकृत किया जा सकता है; हालाँकि, लाभकारी उद्यम होने के कारण वे मुख्य रूप से उन डेटा सेगमेंट की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो एक कारोबारी मॉडल का निर्माण करने के लिए सबसे अधिक लाभदायक हो (जैसे, एकत्रित आंकड़ों के आधार पर क्रेडिट स्कोर का प्रावधान)। वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पाया गया है कि पीसीबी की तुलना में कोई पीसीआर, एक गैर-लाभकारी उद्यम होने के नाते बेहतर डेटा कवरेज सुनिश्चित करने में सक्षम है। बदले में, पीसीबी को जब पीसीआर के व्यापक डेटा तक पहुंच प्रदान किया जाए तो यह पीसीआर को पूरक बनाकर डेटा विश्लेषण और नवाचारों के माध्यम से बेहतर और अधिक मूल्यवर्धन कर सकता है।

जहां कोई भी आसानी से इसे उपयोगी समझ सकता है, वहीं क्रेडिट सूचना प्रणालियों के लिए पूरी क्रेडिट जानकारी इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है, संभवतः यहां तक कि आस्ति और नगद-प्रवाह विवरण के बारे में भी, जिसे कभी-कभी '360-डिग्री व्यू' के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, नवीनतम जानकारी अधिक महत्वपूर्ण है, जो सन्निकट-वास्तविक-समय डेटा की मांग को बढ़ा देती है। श्री वाई.एम. देवस्थली की अध्यक्षता में भारत के लिए लोक ऋण रजिस्ट्री से संबंधित उच्च-स्तरीय कार्य बल (एचटीएफ) की रिपोर्ट में लोक ऋण रजिस्ट्री के इसी प्रकार के होने की परिकल्पना की गयी है। एचटीएफ ने भारत में वर्तमान क्रेडिट सूचना प्रणाली में डेटा अंतराल की जांच की और उपयुक्त अधिनियम द्वारा समर्थित एक पीसीआर की स्थापना किए जाने की सिफारिश की ताकि ऋण बाजार की सूचना दक्षता में सुधार हो सके और भारत में ऋण संस्कृति को मजबूत किया जा सके।

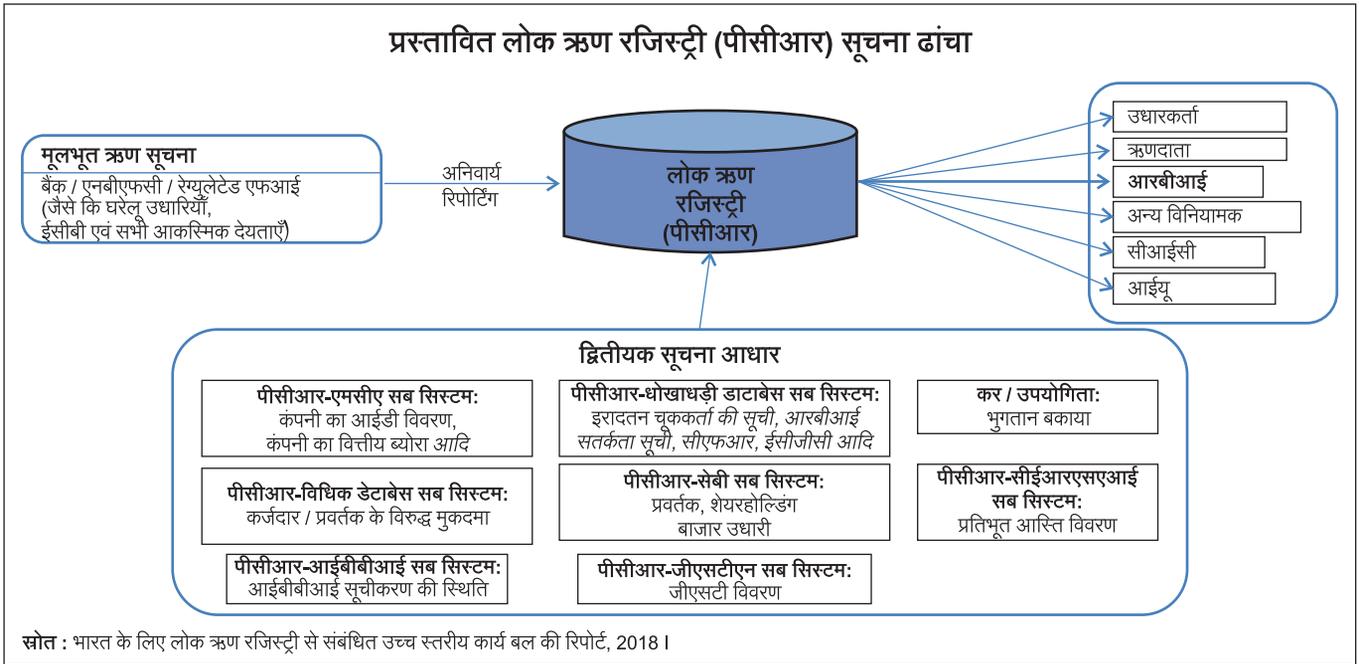
भारत के लिए लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) कैसे काम करेगी?

पीसीआर की परिकल्पना मूलभूत ऋण सूचना के डेटाबेस के रूप में की गई है – यह एक तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा, जिस पर क्रेडिट डेटा के उपयोगकर्ता आगे का विश्लेषण कर सकते हैं। यह सभी विनियमित संस्थाओं (यानी, वित्तदाताओं) को चरणवार कवर करने का प्रयास करेगा और इस तरह से उधारकर्ताओं के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्राप्त कर सकता है। यह कॉर्पोरेट फाइलिंग, कर प्रणाली (वस्तु एवं सेवा नेटवर्क या जीएसटीएन सहित), और उपयोगिता भुगतान सहित बैंकिंग प्रणाली से इतर संबंधित अनुषंगी सूचना प्रणाली के साथ जुड़ने की सुविधा प्रदान करेगा। पीसीआर को सरकार के परामर्श से लाए जाने वाले एक व्यापक लोक ऋण रजिस्ट्री अधिनियम द्वारा समर्थित और शासित होना पड़ेगा। इसे निर्धारित गोपनीयता फ्रेमवर्क के आधार पर नवीनतम गोपनीयता दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

प्रस्तावित लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) की सूचना संरचना

अब मैं पीसीआर पर कुछ प्रकाश डालूंगा कि यह कैसे काम करेगा और कैसे ऋण संस्कृति को मजबूत करने में मदद करेगा।

- (1) पहला, पीसीआर उधारदाता संस्थाओं की बढ़ती कवरेज के साथ उधारकर्ता की जानकारी को और अधिक संपूर्ण बनाएगा। विशेष रूप से, इसकी पहुँच अंततः सबसे छोटी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तक भी होगी। यह उन संस्थाओं को भी कवर करेगा, जिन्हें आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। यह चरणवार किया जाना चाहिए और इसे पूरा करने में तीन से पांच साल लग सकते हैं, संभवतः जल्दी भी हो सकता है।
- (2) दूसरा, पीसीआर बड़े पैमाने पर उधारदाताओं के संबंध में रिपोर्टिंग को सरल बना देगा और इसके बोझ को कम करेगा। नियामकों और पर्यवेक्षकों सहित अन्य संस्थाएं इसे मूलभूत ऋण जानकारी के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होंगी और इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार केवल वृद्धिशील पक्ष के साथ पूरक जोड़ सकेंगी। आरबीआई द्वारा वर्तमान में एकत्र किए गए कई सांख्यिकीय विवरणों को भी तदनुसार ठीक से तर्कसंगत बनाया जा सकता है और इसकी छंटनी की जा सकती है जिससे डेटा संग्रह, अनुसरण और शोधन में दोहराए गए प्रयासों के बजाय विश्लेषण के लिए वित्तीय पारिस्थिकी-तंत्र में संसाधनों को मुक्त किया जा सकता है।



अन्य संस्थाओं के मामले में भी ऐसा ही होगा जो वर्तमान में बैंकों से इस तरह के डेटा एकत्र करते हैं।

- (3) तीसरा, पीसीआर में ऋण संबंधी आंकड़े वर्तमान की तुलना में अधिक बारंबारता पर डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे। इसलिए, इससे ऋण संबंधी निर्णय लेने में तेजी और दक्षता आएगी।
- (4) चौथा, जैसा कि यहां चार्ट से पता चलता है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए21) के कॉर्पोरेट डेटा और टैक्स फाइलिंग या चालान डेटा (जीएसटीएन) जैसे अन्य सूचना प्रणालियों को लिंक करने से यह उपयोगकर्ताओं को उधारकर्ताओं की आस्तियों एवं बढ़ते नगदी प्रवाह से संबंधित अन्य आंकड़े हासिल करने में मदद करेगा, जो कुशल ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं।
- (5) अंत में, वर्तमान में जो भी संभव है उससे बेहतर तरीके से पीसीआर संरचना के भीतर गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करना और समुचित उपयोग के लिए उचित सहमति-आधारित फ्रेमवर्क के साथ डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करना संभव होगा। इन चिंताओं को इस उद्देश्य को संतुलित करना होगा कि पीसीआर ऋण के लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक कदम मात्र है, जिसके ऋण संबंधी आंकड़ों का उपयोग न केवल विनियामकीय / पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि ऋण बाजार को कुशलतापूर्वक विस्तार करने के लिए भी किया जाता है। विशेष रूप से,

- ए. जहां किसी व्यक्ति के पास पीसीआर में संग्रहीत उसके डेटा तक उसकी पहुंच होगी, वहीं उसे ऋण प्राप्त करने के लिए इसे अन्य उधारदाताओं के साथ साझा करने का अधिकार भी होना चाहिए।
- बी. इसी तरह, उधारदाताओं को ऐसे खातों की निगरानी के लिए अपने खुद के ग्राहकों के संपूर्ण डेटा तक पहुंच दिए जाने की जरूरत होगी।
- सी. नियामकों / पर्यवेक्षकों को अपने काम के लिए डेटा तक पूर्ण पहुंच अपेक्षित होगा ताकि वे समग्र दृष्टिकोण का लाभ उठाकर प्रणालीगत जोखिम चिंताओं को दूर कर सकें।

अपेक्षित पहुंच और नियंत्रण नीतियों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स ने अलग से एक लोक ऋण रजिस्ट्री अधिनियम (पीसीआर अधिनियम) लाए जाने की सिफारिश की है। पीसीआर अधिनियम को जहां एक तरफ डेटा की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी, वहीं दूसरी तरफ ऋण संबंधी आंकड़ों के साझा करने के संबंध में मौजूदा प्रतिबंधों को भी ध्यान में रखना होगा जो ऋण के प्रभावशाली आवंटन और विनियामक पर्यवेक्षण से रोकते हैं। पीसीआर अधिनियम को व्यापक भी बनाना होगा ताकि उन उधारदाताओं से भी डेटा लिया जा सके जो सीधे आरबीआई के विनियमों के तहत नहीं आते हैं। इसके लिए, आने वाले महीनों में आरबीआई की सरकार

और अन्य नियामकों के साथ बातचीत करने की योजना है। इस बीच, आरबीआई ने एक कार्यान्वयन कार्यबल का गठन किया है जो विनियमित संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों के साथ पीसीआर को शुरू करने के लिए सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीकठाक कर रहा है, जिसे दोनों के अंतर्गत अथवा मामूली सुधार के साथ मौजूदा विधायी फ्रेमवर्क के तहत कवर किया जा सकता है।

लोक ऋण रजिस्ट्री सूक्ष्म ऋण का “छोटे-छोटे पैकेज (सूची)” बनाने में मदद कर सकता है

व्यक्तियों और छोटे क्रेडिट हेतु ऋण मॉडल तैयार करने के लिए वित्तदाताओं और उसके लिए मॉडल बनाने वाले को सूक्ष्म उधारकर्ताओं के न केवल बकाया ऋण, बल्कि संभवतः उनके पूरे पुनर्भुगतान का इतिहास और उनके नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव जानने की भी आवश्यकता होती है ताकि उपयुक्त रूप से ऋण की शर्तों को पूरा किया जा सके। इस तरह की जानकारी के अभाव में कई उधारकर्ताओं को वित्तदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर सूचना विषमता के कारण आसानी से बाजार से 'बाहर' होना पड़ सकता है।

पीसीआर द्वारा ऋण शुरू होने से लेकर उसके बंद होने तक यानी ऋण संबंधी प्रत्येक लेनदेन (प्रारंभिक शर्तें, चूक, पुनर्गठन, आदि) पर नज़र रखने से और विभिन्न डिजिटल प्रणालियों से जुड़े होने से (जैसा कि ऊपर चार्ट में दर्शाया गया है) यह पहचान करना और कारोबारों, यहाँ तक कि सूक्ष्म उद्यमों एवं सूक्ष्म उद्यमियों को अच्छी तरह से जान पाना संभव होगा। दूसरे शब्दों में, पीसीआर वह लुप्त कड़ी उपलब्ध करा सकती है, जो उधारकर्ता या भावी उधारकर्ता की पूरी जानकारी अर्थात् '360-डिग्री व्यू' देती है। यह उधारदाताओं को नकदी प्रवाह की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए उधारकर्ता के ऋण जोखिम का आकलन करने, प्रासंगिक प्रश्न पूछने (जैसे, क्या कोई अन्य अंतर्निहित मुद्दे हैं जो सूक्ष्म उद्यम से अच्छे-खासे नकदी प्रवाह के बावजूद ऋण का भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं?), और समुचित सावधानी से कोई समझौता किए बिना ऋण शर्तों का निर्धारण करने की अनुमति देगा।

इन सबके आधार पर, लगभग स्वचालित ऋण मंजूरी और संवितरण तंत्र तैयार किए जा सकते हैं, जैसा कि फिन-टेक कंपनियों द्वारा भी इसकी कोशिश की जा रही है।

वास्तव में, ऋण उत्पाद में अल्प परिपक्वता और शून्य या कम संपार्श्विक अपेक्षा वाले छोटे राशि के ऋण को मंजूरी देने की संभावना से बदलाव लाया जा सकता है। उधारकर्ता और उद्यमी इस तरह के प्रारंभिक सूचना-निर्माण ऋणों को चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा और ऋण गुणवत्ता का निर्माण कर सकते हैं। धीरे-धीरे,

वे लंबी अवधि की परिपक्वता पर और अधिक उधार ले सकते हैं जिससे वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए संभवतः पूंजी निवेश कर सकते हैं। एक बार जब उनका आकार बढ़ जाता है और वे जीएसटीएन के साथ पंजीकृत हो जाते हैं, तो कर चालान पीसीआर के साथ नकदी-प्रवाह के सत्यापन के रूप में कार्य कर सकते हैं। समय के साथ तैयार हुई सुदृढ़ ऋण विवरण उधारदाताओं के विश्वास को बढ़ाते हुए मजबूत संपार्श्विक के रूप में काम कर सकता है। ऋण का इस तरह के 'छोटे-छोटे पैकेट तैयार होने' से उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक ऋण तेजी से पहुँच सकता है जो औपचारिक ऋण बाजार में अब तक शामिल नहीं हैं।

यह महत्वपूर्ण होगा कि उधारकर्ताओं को ऋण नहीं चुकाने के लिए इसे आसान बनाकर उनकी स्वाभाविक रूप से मजबूत ऋण संस्कृति को कमजोर न करें, जैसा कि मैंने सूक्ष्म उद्यमियों के भुगतान करने की सक्षमता और इच्छा का जिक्र करते हुए इस पर जोर दिया है। यह इस बात के मूलतत्त्व से समझौता करने जैसा होगा कि कैसे सूक्ष्म उद्यमी एक प्रतिष्ठित ऋण विवरण का निर्माण करने के लिए दूसरों से विभेद करते हैं और समय के साथ आकार और आर्थिक मूल्य सृजन में वृद्धि करते हैं।

अब मैं निष्कर्ष पर आता हूँ।

शुरुआत में मैंने जिन चित्रों और मेरे दिमाग में बने उनके कोलाज की चर्चा की थी उनमें और रिजर्व बैंक में मेरे काम के बीच एक गहरा रिश्ता है। अंततः, जहाँ केंद्रीय बैंक हमेशा आम आदमी के नजर में नहीं होते हैं, वहीं उनकी नीतियों में उसे सार्थक तरीके से असर डालने की क्षमता होती है। अंत में अर्थव्यवस्था को जिस चीज को हासिल करने में मदद करनी चाहिए वह है – घर-परिवार का बेहतर प्रबंधन जैसा कि इसके शब्द व्युत्पत्ति से स्पष्ट होता है। यह मानना शायद हमारे भविष्य का एक अति महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण होगा कि पीसीआर जैसे वित्तीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में मूलभूत परिवर्तन से सूक्ष्म ऋण तक पहुंच में सुधार के साथ-साथ हमारे बच्चों और युवाओं के लिए स्कूली शिक्षा और कौशल संबंधी परिणामों में सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। पिछले साल मेरे बेटे के स्कूल में उसके पोस्टर ने मुझे माइकल एंजेलो के एक ऐसे सर्वोत्तम कृति से रु-ब-रु कराया जो इस बात को रेखांकित करता है कि हमें इस तरह की दृष्टि क्यों रखनी चाहिए और इसे वास्तविकता में बदलने के प्रयास करते रहना चाहिए। उसमें कहा गया है,

“हम में से अधिकांश के लिए सबसे बड़ा खतरा अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा रखने और उसे पूरी तरह हासिल न कर पाने में नहीं है; बल्कि अपने लक्ष्य को बहुत छोटा रखकर उसे हासिल कर लेने में है।”

राष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकारी एवं वैश्विक वित्तीय चक्र*

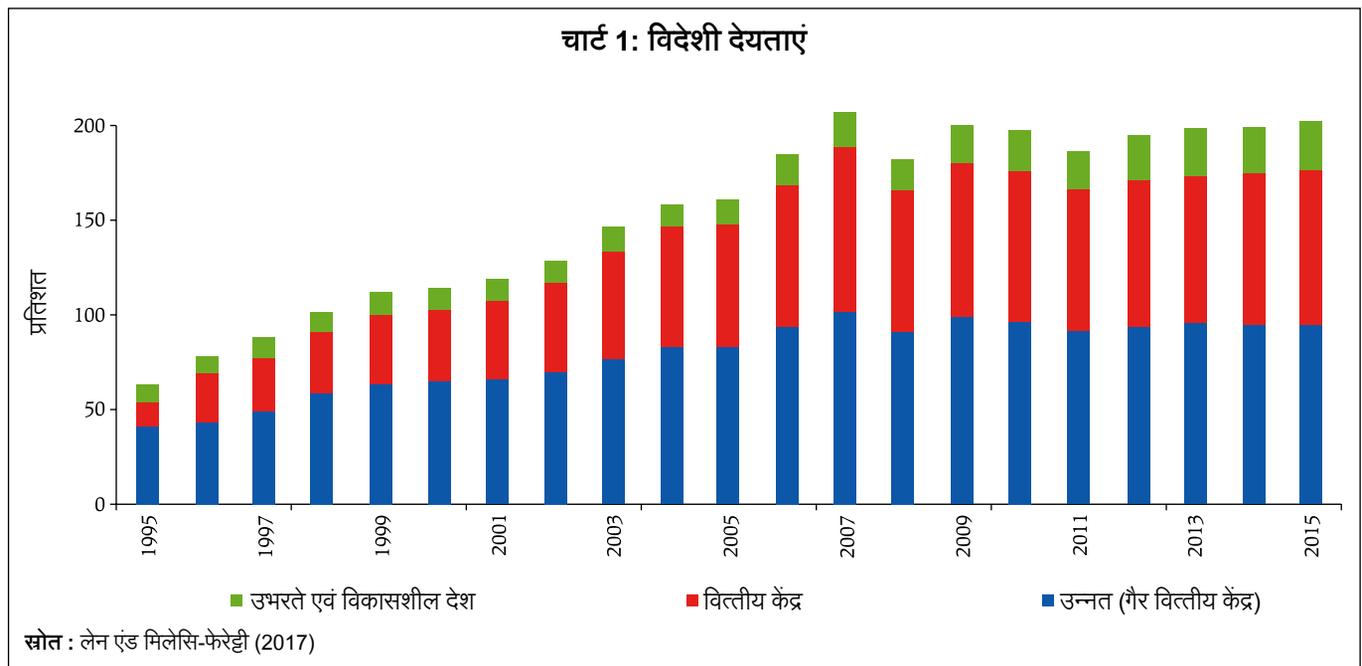
हेलेन रे

सोलहवें एल. के. झा स्मृति व्याख्यान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में आमंत्रित किया जाना गौरव की बात है। लक्ष्मीकांत झा का भारतीय सिविल सेवा के अग्रणी, प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और केंद्रीय बैंक का गवर्नर होना उनकी बहुत सी अन्य उपलब्धियों में से कुछ हैं। वह ब्रेंट आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, जिसे वैश्विक विकास के लिए उत्तर-दक्षिण वार्ताओं में सुधार लाने के संबंध में अनुशांसा का कार्य सौंपा गया था। वक्त के इस पड़ाव में, हमारे ग्रह को सहायता के लिए निश्चितरूप से इस तरह के अधिक कदम उठाने तथा एल. के. झा की पूर्ण प्रतिभा की जरूरत होगी। बहुत से वैश्विक मुद्दे हमारे समक्ष हैं, जिन पर करवाई करना आज बहुत आवश्यक है : वायु और जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय प्रभावों का फैलाव इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे हैं।

मैं, इस व्याख्यान में इनमें से विषय से संबंधित मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगी। मैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के बदल रहे परिदृश्य और अपने देशों में स्वतंत्र मौद्रिक एवं वित्तीय परिस्थितियों के निर्धारण में राष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकारियों की योग्यता के इससे संबंध के बारे में चर्चा करूंगी। मैं, सर्वप्रथम वर्तमान वित्तीय वैश्वीकरण और उनके प्रभावों की विशेषताओं की चर्चा करूंगी, उसके बाद मैं वैश्विक वित्तीय चक्र से संबंधित कुछ साक्ष्यों की समीक्षा करूंगी। तदोपरांत, विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता से संबंधित नीतिगत विकल्पों की थोड़ी चर्चा करूंगी

2. हाल के काल में वित्तीय वैश्वीकरण

1990 के दशक से वित्तीय वैश्वीकरण में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट ने इस बढ़ोतरी को रोक दिया है। सभी विदेशी वित्तीय देयताओं (या विदेशी वित्तीय आस्तियों) का योग वस्तुतः होने वाले वित्तीय समेकन के सहज और व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली माप है, जिसका पैमाना वार्षिक वैश्विक जीडीपी होता है। जैसा कि लैन एवं मिलेसि-फेरेट्टी (2017) की रिपोर्ट में दर्शाया गया है, 1990 के दशक से 2007 तक वित्तीय समेकन में असाधारण ढंग से बढ़ोतरी हुई है : जो विदेशी देयताएं 1995 में वैश्विक जीडीपी के लगभग 70 प्रतिशत हुआ करती थीं, वह 2007 में बढ़कर वैश्विक जीडीपी के लगभग 210 प्रतिशत हो गईं



* 14 दिसंबर, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई में सोलहवें एल.के. झा स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत प्रोफेसर हेलेन रे, लंदन बिजनेस स्कूल का भाषण।

(चार्ट 1 देखें)। इन देयताओं (या आस्तियों) के सबसे बड़े हिस्से का संबंध उन्नत अर्थव्यवस्थाओं या वित्तीय केंद्रों से है। इसके विपरीत, विदेशी वित्तीय आस्तियों में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विदेशी वित्तीय आस्तियों में योगदान सिर्फ 10 प्रतिशत रहा, जो 2007 में वैश्विक जीडीपी का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा निर्मित करती थीं। उनके आर्थिक परिमाण में 2015 की तरह उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जब वैश्विक जीडीपी में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत हुआ करती थी। हालांकि, बाहरी आस्तियों के उनके हिस्से में सिर्फ 13 प्रतिशत का ही विस्तार हुआ।

व्युत्पन्नियों और आस्ति-समर्थित रहन प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार किए जाने के साथ विभिन्न देशों के बीच आस्तियों के विनिमय के विकल्प विस्तृत हुए हैं। आस्ति प्रबंधकों की हिस्सेदारी में भी हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर बैंकों से होने वाले संबंधित प्रवाह में कमी आई है। विदेशी आस्तियों की इस विशाल मात्रा के मद्देनजर, अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह के कल्याणकारी लाभ अथवा हानि पहुंचाने की संभावना में 1990 के दशक से काफी वृद्धि हुई है।

वित्तीय वैश्वीकरण के छुपे हुए पहलू

सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय नवोन्मेषों ने विदेशों में निधि पहुंचाना आसान बना दिया है, इसलिए बहुत से वित्तीय केंद्रों द्वारा प्रबंधित वैश्विक संपत्ति में वृद्धि हो रही है। आंकड़ों से विदेशी आस्ति धारिता में वित्तीय केंद्रों के बहुत अधिक प्रतिनिधित्व (आर्थिक आकार की तुलना में) का पता चलता है। 2007 की स्थिति में, वैश्विक जीडीपी में वित्तीय केंद्रों¹ की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत थी, किंतु वैश्विक वित्तीय आस्तियों में इनकी हिस्सेदारी 43 प्रतिशत से अधिक रही। वर्ष 2015 में, वैश्विक जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी घटकर 8 प्रतिशत रह गई, किंतु बाहरी आस्तियों में उनकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 43 प्रतिशत बनी रही। विदेशी केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बहुत सी सवाएं वैधानिक हैं, किंतु कुछ केंद्र टैक्स “ऑप्टिमाइजेशन” सेवा प्रदान करते हैं। यह माने जाने के भी कारण मौजूद हैं कि इनके कारण कर अपवंचन और हवाला आसान हो जाता है। जुकमैन में सारांश रूप में दिए गए हाल के कार्य से पता चलता है कि विदेशी केंद्रों में धारित संपत्ति बहुत अधिक केंद्रित (एक ही स्थान पर) है। उदाहरण के लिए,

¹ लेन एवं मिलेसि – फेरेट्टी (2017) से : वित्तीय केंद्र – बहरीन, बेल्जियम, साइप्रस, हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर), आयरलैंड, लक्जेंबर्ग, मकाओ चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर), माल्टा, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, बहामास, बार्बाडोस, बर्मुडा, ब्रिटिश विर्जिन आईलैंड्स, कैमैन आईलैंड्स, कुराकाओ, जिब्राल्टर, गुएर्नसे, आइजलैंड ऑफ मैन, जेर्सी, मारिशस, नीदरलैंड्स द्वीप समूह (एंटिलेज), पनामा, सैन मैरिनो, टर्कस एंड कैकोज।

स्कैंडिनेविया में संपत्ति वितरण के शीर्ष 0.01 प्रतिशत हिस्से में विदेशी वित्तीय केंद्रों में छुपी हुई संपत्ति के लगभग 50 प्रतिशत हिस्से का विद्यमान होना प्रतीत होता है। यदि केंद्रीय बैंकिंग समुदाय द्वारा विनियमों को नवीनतम प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के अनुरूप सावधानीपूर्वक तैयार नहीं किए जाते और पूंजी प्रवाहों के इन नए प्रकारों की निगरानी नहीं की जाती, तो भुगतान के अधिक विकेंद्रीकृत माध्यमों (क्रिप्टोकॉरेंसी, डिजिटल मुद्रा) के उद्भव के कारण इस प्रवृत्ति में अधिक तीव्रता आ सकती है।

वित्तीय वैश्वीकरण के लाभ

अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की सोच में वित्तीय वैश्वीकरण के जिन लाभों का सर्वाधिक सर्वाधिक उल्लेख समानरूप से किया जाता है, वे हैं – जोखिम का विविधीकरण एवं पूंजी का बेहतर आबंटन (अंतरण में बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी प्रवाह ऐसे स्थानों पर होना चाहिए, जहां पूंजी का सीमांत उत्पाद सर्वाधिक हो)। इसके विपरीत, यह हो सकता है कि चूंकि वे नीति जगत में वे बहुत प्रभावशील रहे हैं, इसलिए हाल के समय तक उन लाभों का मूल्यांकन स्टॉकैस्टिक निओक्लासिकल ग्रोथ मॉडल, जो उनको सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है, के अंतर्गत मात्रात्मक रूप में नहीं की गई हो। हाल ही के एक पेपर में, मैंने अपने सह-लेखक (कोयूर्डेसिअर एवं अन्य (2008) देखें) के साथ यह दर्शाया है कि जोखिम को बेहतर ढंग से साझा करने एवं पूंजी के बेहतर आबंटन के कारण वित्तीय एकीकरण के कल्याण संबंधी लाभ बहुत कम रहे हैं। पूंजी की कमी और जोखिमपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी ऐसा पाया गया।

इन परिणामों के अनुभव सारांश रूप में इस प्रकार से कहा जा सकता है। अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित विकसित देश उपभोग की कम होती घटबढ़ से थोड़े लाभ की स्थिति में हैं। वित्तीय एकीकरण के बाद पूंजी के विश्व भर में अधिक दक्षतापूर्वक आबंटन के कारण भी वे थोड़े लाभपूर्ण स्थिति में हैं। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश अधिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे होते हैं और जब वे जोखिम साझा कर रहे होते हैं तो उनमें अधिक लाभ की क्षमता हो सकती है। हालांकि, विभिन्न देशों में जोखिम वितरण को प्रभावित करने के माध्यम से वित्तीय एकीकरण राज्य पूंजी के स्थिर भंडार के मूल्य में परिवर्तन का कारण भी बनता है। जब तक अधिक जोखिमपूर्ण देशों में भी पूंजी की कमी न हो, वे उन्हें पूंजी के बहिर्वाह का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एहतियाती बचतों का आबंटन अधिक सुरक्षित (विकसित) देशों में किया जाता है। जब अधिक जोखिमपूर्ण देशों में भी पूंजी की काफी कमी हो (जैसा कि आंकड़ों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों

को दर्शाया गया है), तो अपेक्षाकृत तीव्र अभिसरण से निर्धारित होने वाले मानक दक्षता लाभों में एहतियातन की गई बचत के पुनः आबंटन के कारण बहुत कमी हो जाती है।

इससे यह निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है कि वित्तीय एकीकरण के लाभ समग्ररूप से बहुत कम हैं, किंतु यह अवश्य ही अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के समक्ष यह चुनौती प्रस्तुत करता है कि वे जोखिम के विविधीकरण और पूंजी के अभीष्टतम अंतरराष्ट्रीय आबंटन की पुरातन तर्कसंगतता से परे देखें। ऐसी प्रणालियां हो सकती हैं, जिनके माध्यम से वित्तीय प्रवाह कुल प्रभाजी उत्पादकता में सुधार लाते हैं, उदाहरण के लिए – प्राप्तकर्ता देशों में आने वाले सुधार। निश्चित रूप से महत्व की बात होगी कि इन प्रणालियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जाए एवं उनके आमतौर पर होने की जानकारी का पता लगाया जाए, और विशिष्ट रूप से यह जानकारी होना कि क्या उनका पूंजी प्रवाहों की सभी श्रेणियों से संबंध होता है।

2. वैश्विक वित्तीय चक्र

मैंने 2013 के जैक्शन होल सिंपोजियम के लिए लिखे गए एक पर्चे (पेपर) में वैश्विक वित्तीय चक्र सकल पूंजी प्रवाह, ऋण वृद्धि, जोखिमपूर्ण आस्ति मूल्यों तथा सभी देशों के बीच लिक्विडिटी का सहगामी होने को स्पष्ट किया है।

पूंजी प्रवाह

चार्ट 2ए में पूंजी प्रवाहों (देशों की देयताएं) के सहसंबंध के आव्यूह (मैट्रिक्स) को आस्ति श्रेणी-वार दर्शाता है, जिसमें आस्ति

श्रेणी को 1990 की पहली तिमाही से 2017 की चौथी तिमाही के दौरान भुगतान संतुलन (एफडीआई, पोर्टफोलियो (कर्ज एवं इक्विटी) तथा ऋण²) की पारंपरिक श्रेणियों को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों (उत्तरी अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया, उभरता एशिया, अफ्रीका) में विभक्त किया गया है। हीटमैप के रंग सभी क्षेत्रों एवं प्रवाहों के प्रकारों (सहसंबंध धनात्मक होने पर हरा, अन्यथा लाल) के सहसंबंध संकेतों के अनुरूप हैं। हीटमैप में हरे रंग की स्पष्ट अधिकता से साबित होता है कि सभी क्षेत्रों के अंतर्गत पूंजी प्रवाह के अधिकांश प्रकारों का एक दूसरे से धनात्मक सहसंबंध है। पूरी दुनिया में देयताओं के प्रवाह में बहुत अधिक समानता देखी गई है। यह बात चार्ट 2बी में दर्शाए गए पूंजी के बहिर्वाह (आस्तियों) से सहसंबंध के आव्यूह (मैट्रिक्स) के बारे में भी सत्य है। दूसरी तरफ, निवल प्रवाहों के सहसंबंधों के हीटमैप में कोई व्यवस्थित पैटर्न दिखाई नहीं देता है। सकल प्रवाहों के सहगामी परिवर्तनों का क्या कारण है, और क्या वे वैश्विक ऋण संवृद्धि तथा आस्ति मूल्य घट-बढ़ से संबद्ध हैं ?

वैश्विक कारक

लंबे समय से यह बात नोट की जाती रही है कि वैश्विक कारक अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह का प्रमुख निर्धारक है। जैसा कि कैल्वो एवं अन्य (1996) ने पाया कि “विदेशी निवेश को प्रभावित करने वाले वैश्विक कारकों में महत्वपूर्ण चक्रीयता का गुण पाया जाता है, जिसने बारंबार पूंजी प्रवाहों में उछाल और मंदी को

चार्ट 2ए: देयताओं के सभी प्रवाहों के बीच सहसंबंध (1990 ति1 – 2017 ति4)

देयताएं	पोर्टफोलियो उ.अमे.	पोर्टफोलियो एशिया	पोर्टफोलियो यू.सं.	पोर्टफोलियो अफ्रीका	पोर्टफोलियो लातिन अमे.	पोर्टफोलियो ईएम.एएस.	एफडीआई उ.अमे.	एफडीआई एशिया	एफडीआई यू.सं.	एफडीआई अफ्रीका	एफडीआई लातिन अमे.	एफडीआई ईएम.एएस.	ऋण उ.अमे.	ऋण एशिया	ऋण यू.सं.	ऋण अफ्रीका	ऋण लातिन अमे.	ऋण ईएम.एएस.
पोर्टफोलियो उ.अमे.	1.0																	
पोर्टफोलियो एशिया	0.6	1.0																
पोर्टफोलियो यू.सं.	0.7	0.5	1.0															
पोर्टफोलियो अफ्रीका	0.6	0.6	0.4	1.0														
पोर्टफोलियो लातिन अमे.	0.5	0.5	0.3	0.6	1.0													
पोर्टफोलियो ईएम.एएस.	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	1.0												
एफडीआई उ.अमे.	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	1.0											
एफडीआई एशिया	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	1.0										
एफडीआई यू.सं.	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.6	0.7	1.0									
एफडीआई अफ्रीका	0.4	0.5	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	1.0								
एफडीआई लातिन अमे.	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.8	1.0							
एफडीआई ईएम.एएस.	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	1.0	0.7	0.9	0.9	1.0						
ऋण उ.अमे.	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	1.0					
ऋण एशिया	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	1.0				
ऋण यू.सं.	0.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.6	0.4	1.0			
ऋण अफ्रीका	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6	0.7	0.7	0.4	0.0	0.4	1.0		
ऋण लातिन अमे.	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1	0.4	0.1	0.2	1.0	
ऋण ईएम.एएस.	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.1	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.7	0.2	0.2	0.3	1.0

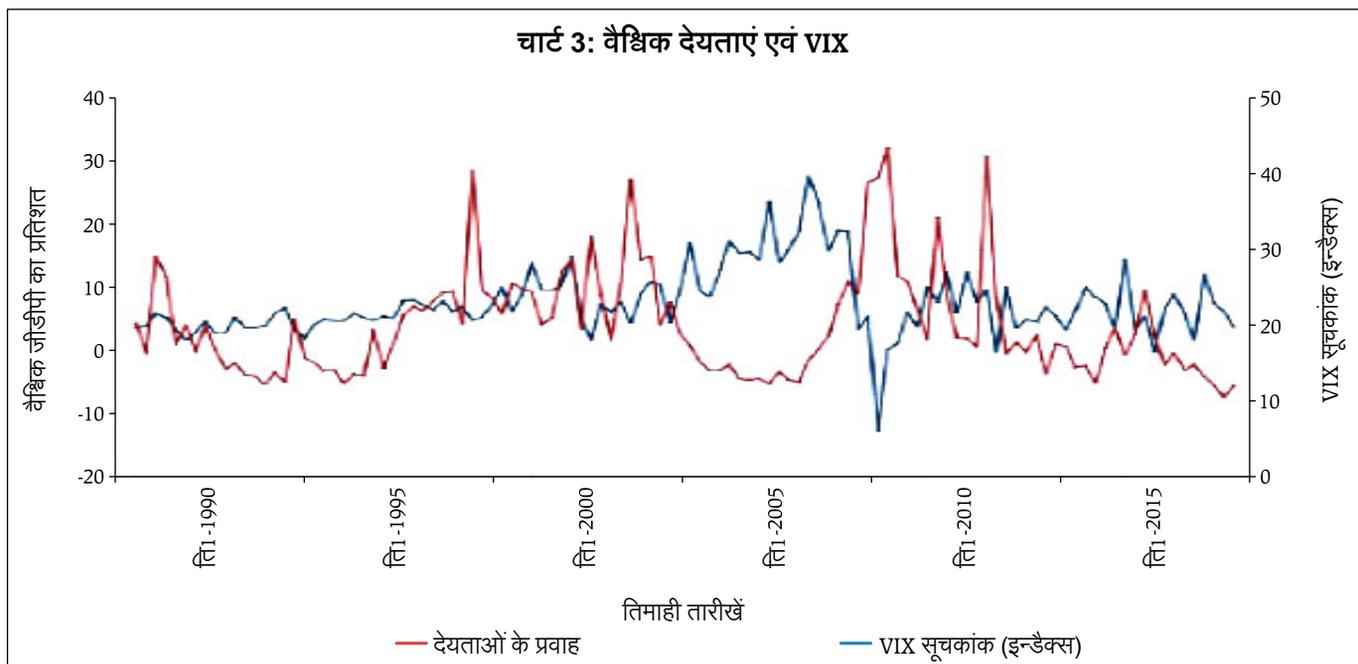
² तकनीकी रूप से मैं “अन्य निवेश” का प्रयोग करती हूँ, जिसके अंतर्गत बैंक ऋण और व्यापार ऋण आते हैं। तिमाही आधार पर आंकड़े 1990 की पहली तिमाही से 2017 की चौथी तिमाही तक के हैं और इन्हें आईएमएफ बीओपीएस से लिया गया है।

चार्ट 2बी: आस्तियों के सभी प्रवाहों के बीच सहसंबंध (1990 ति1 – 2017 ति4)

देयताएं	पोर्टफोलियो उ.अमे.	पोर्टफोलियो एशिया	पोर्टफोलियो यू.सं.	पोर्टफोलियो अफ्रीका	पोर्टफोलियो लातिन अमे.	पोर्टफोलियो ईएम.एएस.	एफडीआई उ.अमे.	एफडीआई एशिया	एफडीआई यू.सं.	एफडीआई अफ्रीका	एफडीआई लातिन अमे.	एफडीआई ईएम.एएस.	ऋण उ.अमे.	ऋण एशिया	ऋण यू.सं.	ऋण अफ्रीका	ऋण लातिन अमे.	ऋण ईएम.एएस.
पोर्टफोलियो उ.अमे.	1.0																	
पोर्टफोलियो एशिया	0.4	1.0																
पोर्टफोलियो यू.सं.	0.7	0.4	1.0															
पोर्टफोलियो अफ्रीका	0.2	0.4	0.2	1.0														
पोर्टफोलियो लातिन अमे.	0.5	0.3	0.6	0.3	1.0													
पोर्टफोलियो ईएम.एएस.	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	1.0												
एफडीआई उ.अमे.	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	1.0											
एफडीआई एशिया	0.4	0.7	0.3	0.5	0.3	0.6	0.8	1.0										
एफडीआई यू.सं.	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.7	0.7	1.0									
एफडीआई अफ्रीका	0.3	0.3	0.0	0.3	0.1	0.3	0.5	0.6	0.4	1.0								
एफडीआई लातिन अमे.	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	0.7	0.6	1.0							
एफडीआई ईएम.एएस.	0.3	0.7	0.2	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	0.6	0.6	0.7	1.0						
ऋण उ.अमे.	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	1.0					
ऋण एशिया	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.1	1.0				
ऋण यू.सं.	0.3	0.2	0.5	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.6	0.4	1.0			
ऋण अफ्रीका	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1	1.0		
ऋण लातिन अमे.	0.3	0.4	0.1	0.4	0.1	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.2	0.2	1.0	
ऋण ईएम.एएस.	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	-0.2	0.7	0.1	0.4	0.4	1.0

जन्म दिया है। अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक ब्याज दर एवं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में चक्रियता की पहचान पूंजी प्रवाहों के बारे में महत्वपूर्ण “पुश/बढ़ावा देने वाले” कारकों के रूप में की है। बहुत से अध्ययनों में यह पाया गया है कि VIX³ में घटबढ़ का पूंजी प्रवाहों से मजबूत संबंध होता है। व्यापक रूप से VIX को “भय की माप”, जोखिम विमुखता एवं अनिश्चितता के संबंध में बाजार बाजार

के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए VIX के कम रहने की स्थिति में मुद्रा व्यापार (कैरी ट्रेड) में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है और VIX के अधिक रहने पर इसमें गिरावट होती है। चार्ट 3 में सकल अंतर्वाह को VIX के साथ में, 1990 की पहली तिमाही से 2017 की चौथी तिमाही की अवधि के लिए, वैश्विक जीडीपी के अनुपात के रूप में दर्शाया गया है। 2002-2007 की



³ VIX शिकागो बोर्ड ऑफ़ ऑप्शन्स एक्सचेंज मार्केट वॉलेटिलिटी इन्डैक्स है। यह एस एंड पी 500 इन्डैक्स ऑप्शन्स की अंतर्निहित वॉलेटिलिटी की माप है। फोर्ब्स एंड वार्नॉक (2012) तथा ब्रूनो एंड शिन (2015ए) VIX में गिरावट के साथ पूंजी प्रवाह में तेजी को निरूपित करते हैं।

अवधि के दौरान VIX में दीर्घावधिक कमी विशेषरूप से चौंकाने वाली है, क्योंकि इस अवधि के दौरान पूंजी अंतर्वाह में बहुत तेजी थी। ऋण प्रवाहों में अधिक घट-बढ़ रही है और सभी प्रवाहों में इसमें अनुचक्रीयता अधिक देखी गई है। इसमें संकट के समय तक विशेषरूप से नाटकीय तेजी और संकट के दौरान उसी भांति नाटकीय गिरावट आई। ऋण संवृद्धि और लिवरेज का VIX से ऋणात्मक संबंध रहा है।

आस्ति मूल्य

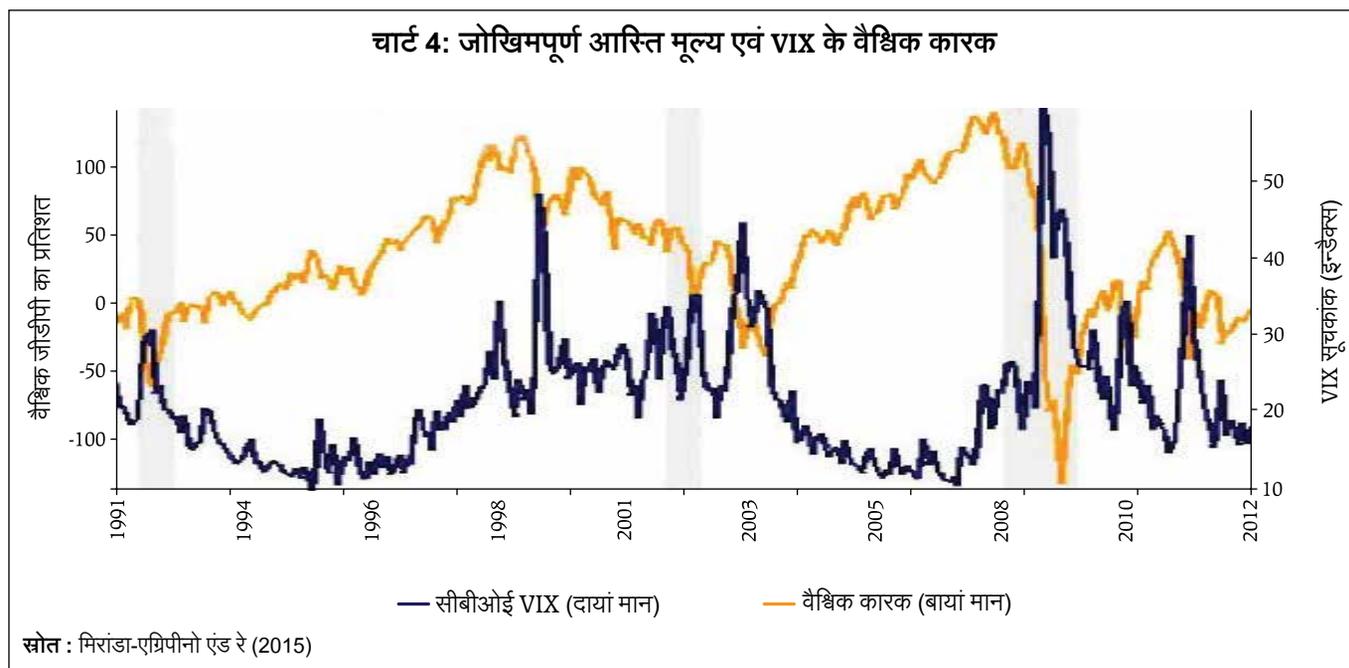
इसी तरह से, दुनिया भर में जोखिमपूर्ण आस्ति मूल्यों में VIX के सापेक्ष ऋणात्मक सहगामी परिवर्तन होता है। बड़े हिस्से के रूप में वे क्षेत्र-विशेष, देश-विशेष या कंपनी-विशेष के कारकों को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि वे किसी एक वैश्विक कारक को दर्शाते हैं। जैसा कि मिरांडा-एग्रिप्पिनो एवं रे (2015) ने पाँच महाद्वीपों में फैले हुए विभिन्न बड़े क्षेत्रों के 858 जोखिमपूर्ण आस्ति मूल्यों (अर्थात्, स्टॉक मूल्य, कॉर्पोरेट बॉण्ड मूल्य) का प्रयोग करते हुए दर्शाया कि जोखिमपूर्ण आस्तियों के प्रतिफल (25 प्रतिशत) में परिवर्तन के महत्वपूर्ण हिस्से की व्याख्या एकल वैश्विक कारक⁴ से होती है। जैसा कि चार्ट 4 से स्पष्ट होता है, 1990 के दशक के प्रारंभ से लेकर 1998 के मध्य तक, जब दीर्घावधिक पूंजी प्रबंधन (एलटीसीएम) दिवालियापन के बाद रूसी संकट प्रारंभ हुआ और अंततोगत्वा डॉटकॉम बबल फूटा, इस कारक में वृद्धि हुई। वर्ष 2003 के प्रारंभ से 2007 की तीसरी तिमाही की शुरुआत तक,

जब अचानक लुढ़क गया, सूचकांक में तीव्र वृद्धि हुई। यह घटना सबप्राइम बाजार ढहने के थोड़े बाद की है और यह वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई कमजोरियों के पहले संकेत प्राप्त होने के समय हुआ। वैश्विक कारक का VIX के साथ ऋणात्मक सहसंबंध की तीव्रता चौंकाने वाली है।

आर्थिक कार्यप्रणाली

ऋण की बेहतर आपूर्ति, आस्ति मूल्य वृद्धि, एवं स्प्रेडों के घटने के बीच सकारात्मक फीडबैक लूप का विद्यमान होना उन तथ्यों के अनुरूप एक-कार्यप्रणाली है। जोखिम प्रीमियम के अपेक्षाकृत कम होने से बैंक और गैर-बैंक ऋण देने में तेजी आती है। पूंजी मूल्यों के बढ़ने से मापित जोखिम कम होता है और सभी तुलन-पत्र में मजबूती आती है। जोखिम-पर-मूल्य की बाधाओं, जिनका बैंकिंग क्षेत्र के साथ ही साथ आस्ति प्रबंधन उद्योग में भी व्यापकरूप से इस्तेमाल किया जाता है, को शिथिल करने से ऋण देने और अन्य गतिविधियों के लिए अतिरिक्त गुंजाइश बनती है। इसके कारण ऋण और संविभाग प्रवाहों और वित्तीय भंगुरता की निर्मिती के उनके महत्व की अनुचक्रीयता में योगदान मिलता है। हाल के कुछ शोध कार्य (कोइंब्रा एवं रे (2018)), मेरे सह-लेखक और मैंने दर्शाया कि निधीयन की लागत कम होने के समय के दौरान सर्वाधिक जोखिम लेने की क्षमता वाले ऐजेंटों, अर्थात् कम-जोखिम पर-मूल्य की बाधाएं अपेक्षाकृत कम होने के कारण, में उनके तुलन-पत्रों में तीव्र वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है और

चार्ट 4: जोखिमपूर्ण आस्ति मूल्य एवं VIX के वैश्विक कारक



⁴ जोर्ड, सुलारिक, टेलर एवं वार्ड (2018) भी देखें।

कभी-कभी वे अधिक रुढ़िवादी प्रतिभागियों को बाजार से खदेड़ देते हैं। इसके कारण जोखिम का तीव्र गति से वृद्धिशील कुछ तुलन-पत्रों में संकेंद्रण होता है। हमने आंकड़ों में पाया कि निधीयन की अपेक्षाकृत कम लागत वाली उछाल की अवधि में बैंकों के लिवरेज के वितरण का वैषम्य बढ़ता है। जोखिम लेने वाले वित्तीय मध्यस्थों की फैंट राइट-टेल दिखाई देती है जो बहुत से समष्टि आर्थिक जोखिमों को संकेंद्रित करती है। उदाहरण के लिए, 1990 के दशक की शुरुआत के स्वीडन में आए वित्तीय संकट के बारे में इंग्लुंड (2016) यह व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से 1985 और 1990 के बीच वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण प्रदान करने की दर अचानक बढ़कर 16 प्रतिशत हो गई, जिसका आंशिक कारण विनियमन में ढील देना रहा। बाजार की हिस्सेदारियों में तेजी से परिवर्तन हुए : 1985 एवं 1988 के बीच स्पायरबैंकेन स्वीरिज एवं गोटा के उधार देने संबंधी हिस्सेदारी में सभी बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने में क्रमशः 20.8 से 22.1 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अधिक पारंपरिक प्रतिभागी इसमें पीछे रह गए। इन दो बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि 'इक्विटी की तुलना में प्रतिफलों को अधिकतम बनाए जाने के आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप विधिवत लेखा धारित किए या जोखिम लिए बगैर इसमें विस्तार हुआ'। जमानती रिहाई (बेलआउट) के रूप में परिणत होने वाले ऋण विस्तार की दर और उसके पश्चात संकट के समय ऋण की होने वाली हानियों के बीच महत्वपूर्ण सहसंबंध देखा गया।

चूंकि ऋण चक्र और पूंजी प्रवाह वैश्विक कारकों का अनुशरण करते हैं, इसलिए वे कुछ अर्थव्यवस्थाओं की चक्रीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। कुछ देशों के संबंध में, वैश्विक चक्र के कारण उछाल की अवधि में ऋण की अत्यधिक वृद्धि तथा बुरे समय में व्यय में अत्यधिक कमी भी हो सकती है। ऋण में अत्यधिक वृद्धि होना संकट⁵ के आगमन की सूचना देने वाला सबसे अच्छा लक्षण माने जाने के कारण वैश्विक वित्तीय चक्रों को पूंजी प्रवाहों में तीव्र वृद्धि और गिरावट, आस्ति मूल्यों में उछाल एवं कमी तथा संकट से जोड़कर देखा जा सकता है। इससे मजबूत वैश्विक वित्तीय चक्रों वाले संसार की तस्वीर उभरकर सामने आती है। यह छिपे हुए हितों की समता से बहुत अधिक परिवर्तन वाले संसार को भी दर्शाता है। केंद्रीय देश (अमेरिका) की मौद्रिक परिस्थितियों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के बहुत से हिस्सों में पूंजी प्रवाहों तथा वित्तीय क्षेत्र के लिवरेज के बीच अंतःसंबंध रहे हैं।

⁵ इचेंग्रीन एंड पोर्ट्स (1987), गोरिंचाज एंड ऑब्सट्फिल्ड (2012), सुलारिक एंड टेलर (2012)।

3. राष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकारी की बाध्यता

हम अंतरराष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र एवं वित्त में अक्सर "त्रिविधापाश/ट्राइलेमा" ढांचे के अंतर्गत सोचते हैं : वित्तीय रूप से एकीकृत संसार में नियत विनिमय दरों के कारण केंद्रीय देश की मौद्रिक नीति का असर सीमा पर स्थित देशों पर पड़ता है। उप सिद्धांत यह है कि सिर्फ परिवर्तनशील विनिमय दरें ही मौद्रिक नीतिगत स्वतंत्रता को सुकर बना सकती हैं (उदाहरण के लिए ऑब्सट्फिल्ड एवं टेलर (2004) का अवलोकन करें)। किंतु, वैश्विक वित्तीय चक्र ने नियत विनिमय दर के त्रिविधापाश को दुविधा में परिवर्तित कर दिया है। इस त्रिविधापाश से हम यह मानते हुए दिग्भ्रमित होते हैं कि किसी देश की समष्टि आर्थिक परिस्थितियों का निर्धारण करने वाली घरेलू मौद्रिक और वित्तीय परिस्थितियों को सारांश रूप में इस एकल चर – अल्पावधिक ब्याज दर, से सुविधापूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ऐसा होता तो लचीली विनिमय दर के माध्यम से हासिल अतिरिक्त स्वतंत्रता घरेलू समष्टि अर्थव्यवस्था पर विदेशी वित्तीय परिस्थितियों के किसी भी तरह के प्रभाव को निरस्त करने के लिए सचमुच पर्याप्त होती। तथापि, वैश्वीकृत वित्त वाले संसार में, जहां स्प्रेड, रिस्क प्रीमिया, निधियों की लागत जैसी वित्तीय परिस्थितियां अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के केंद्र वाले देश से ग्रहण की जाती हैं; मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता बाधित होती है, जिसमें परिवर्तनशील विनिमय दर वाले देश भी शामिल हैं। बढ़ रहे अनुभवजन्य प्रमाणों⁶ से पता चलता है कि एफओएमसी मीटिंग विंडोज के आसपास अमेरिकी मौद्रिक नीतिगत आघात का संचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ और परिवर्तनशील दरों वाले क्षेत्राधिकारों सहित दुनिया भर में इनका असर लिवरेज, आस्ति मूल्यों एवं स्प्रेड, पूंजी प्रवाहों तथा ऋण की उत्पत्ति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, मॉर्टगेज स्प्रेडों का अमेरिकी नीतिगत आघातों का प्रभाव अमेरिका और कनाडा पर एक समान पड़ा।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परिवर्तनशील विनिमय दरों का कोई उद्देश्य नहीं होता। उनका उद्देश्य अवश्य होता है और वे बड़े समष्टि आर्थिक आघातों के बाद देशों के बाहरी समायोजन में मदद करती हैं, जैसा कि ऑब्सट्फिल्ड एवं टेलर (2017) ने जोर देकर कहा है। किंतु इसका तात्पर्य यह है कि परिवर्तनशील विनिमय दर अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक वित्तीय चक्र को नहीं रोक सकती हैं, ऐसा विशेषरूप से चक्र की उछाल अवस्था के दौरान नहीं हो सकता है। ह्यून शिन और उनके सह-लेखकों (ब्रूनो एवं शिन (2015), हॉफमैन एवं अन्य (2016)) तथा पोर्ट्स एवं वीन्स

⁶ अन्य के साथ-साथ मिरांडा-एग्नीपीनो एंड रे (2015), गेर्को एंड रे (2017)।

(1997) द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार उछाल की अवधि के दौरान विनिमय दर में होने वाली मूल्य वृद्धि से पूंजी प्रवाहों को मजबूत प्राप्त हो सकती है और अधिक ऋण दिए जाने को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अलावा, जैसा कि (कारुआना (2012)) ने बताया है, वैश्विक आरिष्ठ बाजारों में दबाव की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक प्रतिफल देने वाली मुद्राओं का मूल्यहास तीव्र गति से होने की प्रवृत्ति होती है, और बहुत सी उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं ने इसे अस्थिरताकारक पाया है।

4. मुक्ति की राहें

अपनी अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिरोधी बनाने और वैश्विक वित्तीय चक्र का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारियों के पास निम्नलिखित नीतिगत विकल्प हैं :

- लक्षित पूंजीगत नियंत्रण लागू करना।
- बैंकों और गैर-बैंकों से संबंधित राष्ट्रीय समष्टिगत विवेकसम्मत नीतियों का प्रयोग करते हुए चक्र के चढ़ाव के दौरान ऋण वृद्धि और लिवरेज को नियंत्रित करना।
- ऋण उत्पन्न करने वाले, बैंकों और गैर-बैंकों सभी वित्तीय मध्यस्थों पर अधिक कठोर विनियमन लागू करते हुए संचरण माध्यमों पर संरचनात्मक कार्रवाई करना।
- अनुचक्रीय राजकोषीय प्रोत्साहनों में कमी करना।

यदि ऋण वृद्धि अत्यधिक होना चिंता का मुख्य विषय है (विनिमय दर वृद्धि के विपरीत) तो पूंजीगत नियंत्रणों को समष्टिगत विवेकसम्मत उपायों के आंशिक विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। इनमें बाद वाले में अधिक नियोजित होने की प्रवृत्ति होती है। किंतु सीमा-पार से बहुत अधिक प्रत्यक्ष ऋण दिया जा रहा हो और बैंकिंग प्रणाली के लिए गतिरोध पैदा किए जा सकें तो पूंजीगत नियंत्रण उचित हो सकते हैं (ऑस्ट्रे एवं अन्य (2011) को देखें)। पूंजीगत नियंत्रण लागू किए बगैर समष्टिगत विवेकसम्मत नीतियां घरेलू मौद्रिक नीति और पूंजी के अंतर्वाह के बीच संबंध को कमजोर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, उछाल के समय में ऋण की अत्यधिक वृद्धि को केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित करने से बैंकों द्वारा बाहर से उधार लेने का प्रोत्साहन कम हो सकता है।

विभिन्न देशों में समष्टिगत विवेकसम्मत निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों के पास अब बहुत से उपाय उपलब्ध होते हैं (प्रतिचक्रीय बफर, बैंकों के लिए क्षेत्रगत जोखिम भार इत्यादि,

आय की तुलना में कर्ज अनुपात, उधारकर्ताओं के लिए कीमत की तुलना में ऋण अनुपात इत्यादि)। किंतु अधिकांश वर्तमान उपायों की हिफाजत को सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र पर ही लागू किया जा सकता है। चूंकि हाल ही में होने वाली बहुत अधिक ऋण उत्पत्ति बैंकों के बाहर हुई है – उदाहरण के लिए, भारत में दिए गए कुल ऋण में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का हिस्सा मार्च 2009 के 9.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में 17 प्रतिशत से अधिक हो गया है। समष्टिगत विवेकसम्मत निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों तथा केंद्रीय बैंकों के पास गैर-बैंक क्षेत्र में भी ऋण वृद्धि को नियंत्रित करने की शक्तियां होना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

समष्टिगत विवेकसम्मत हस्तक्षेप

उपायों से परे, हस्तक्षेप के समय का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक मुद्दों में से एक है। पूर्व वर्णित सकारात्मक फीडबैक लूप से हटने के लिए परिपथ भंजकों को कब सक्रिय किया जाए? यह महत्वपूर्ण है कि बहुत देर तक इंतजार नहीं किए जाए; उदाहरण के लिए हस्तक्षेप के लिए आरिष्ठ मूल्यों या स्थावर संपदा में बबल विद्यमान होने की अर्द्ध-निश्चयता का इंतजार न किया जाए।

एक विकल्प यह है कि पूर्व-चेतावनी संसूचकों, जो विशिष्ट सीमाओं के पार होते ही कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं (या किसी प्राधिकारी के कार्रवाई नहीं करने पर दस्तावेजीकृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं), पर आधारित आंशिकरूप से स्वचालित नियम तैयार करना है। इस प्रणाली में रुचि दर्शाने वाले पक्षों, बैंकों या वित्त मंत्रालयों⁷ के एक साथ आने की अधिक मजबूत व्यवस्था होने का लाभ होता है। यह व्यवस्था अच्छे दिन आने और बढ़ते हुए जोखिम को भुलाकर सभी के द्वारा बढ़ते हुए आरिष्ठ प्रतिलाभों के लाभांशों के खुशी-खुशी साझा करने के सामय कार्यशील नहीं रहने के सुपरिचित पूर्वाग्रह पर भी विजय पा लेती है। मशीनी ज्ञान की हालिया तकनीकों से अधिक मजबूत पूर्व-चेतावनी संसूचक तैयार करने में मदद मिल सकती है (फौलिआर्ड, हॉवेल एवं रे का अवलोकन करें (2018))।

समष्टिगत विवेकसम्मत प्राधिकारियों के निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने वाले उपायों में, वित्तीय क्षेत्र (बैंक एवं गैर-

⁷ वित्तीय संकटों के जोखिम के संबंध में सरकारी अदूरदर्शिता के प्रभाव के सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए आचार्य एवं राजन (2013) देखें।

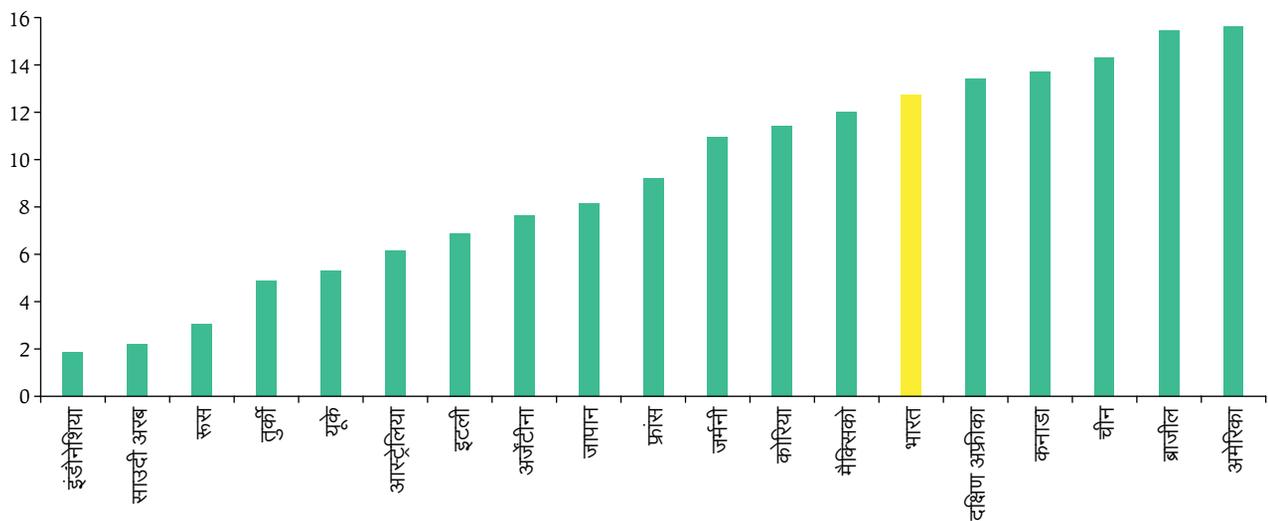
बैंक) के तुलन-पत्रों के दबाव परीक्षण की क्षमता, जो लक्षित हो या व्यापक हो, को प्रमुखता होनी चाहिए। यह इस बात का निर्णय लिए जाने के अनुरूप है कि क्या आस्ति मूल्यों में बढ़े किंतु वास्तविक परिवर्तन वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। आमतौर पर दबाव परीक्षण एक कठिन कार्य होता है और भारत जैसे देश में, जहां पर कुल आस्तियों में छाया बैंकों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी (वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अनुसार 2016 के अंत में लगभग 13 प्रतिशत – चार्ट 5 देखें) होती है और वे परिपक्वता रूपांतरण में भाग लेते हैं, जो अफरातफरी में बिक्री के रूप में परिणत हो सकती है; दूसरे दौर के प्रभावों का अनुमान लगाना विशेषरूप से महत्वपूर्ण होता है। दबाव परीक्षणों के लिए संचार नीति (और/ अथवा यथास्थिति पूर्ण गोपनीयता) के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा, दबाव परीक्षण करने विश्वसनीयता की गारंटी देने के लिए राजकोषीय सहारे की कार्यनीतियों की जरूरत है। इनमें से कोई भी तरीका आसान नहीं है। किंतु नियमित रूप से और अक्सर दबाव परीक्षण करना, यह प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होने पर भी, निगरानी का जरूरी उपाय है। इससे पर्यवेक्षकों की जानकारी में बेहतरी आती है और यह भी सुनिश्चित होता है कि उन्हें बाजार की हाल की गतिविधियों की अद्यतन जानकारी हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके कारण संस्थानों की आंतरिक जोखिम निगरानी को संरचनात्मक चुनौती भी मिल सकती है। यह संगठनों में कॉर्पोरेट अभिशासन की विफलताओं को उजागर कर सकता है, जहां पर प्रोत्साहनों को जोखिम को नियंत्रित करने के अनुरूप नहीं रखा गया हो या जहां

पर सूचना उपलब्ध नहीं हो या पर्याप्तरूप से केंद्रीकृत न हो। यह जोखिम लेने संबंधी गतिविधियों के “दृष्टि बाधित” क्षेत्र को भी प्रकट कर सकता है।

वित्तीय मध्यस्थों की कार्यकुशलता वैश्विक वित्तीय चक्र से घरेलू अर्थव्यवस्था में संचरण प्रणाली के मूल में होती है, जहां पर वित्तीयन की परिस्थितियां अनुकूल होने पर बैंक या छाया बैंक बहुत उच्च स्तर पर लिवरेज करने में सहायक होते हैं। ऋण वित्तीयन की लागत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वित्तीय मध्यस्थों की अत्यधिक अनुचक्रीय होने की क्षमता को सीमित करने के लिए वित्तीय विनियमों के अतिरिक्त या इनके स्थान पर ऋण संवृद्धि के चक्रीय गुणों की निगरानी करना संभव हो सकता है। ऐसा करने के नीतिगत उपाय लिवरेज अनुपात या अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता हैं।

महत्वपूर्ण बात है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूंजी प्रवाहों और ऋण संवृद्धि के संपर्क में आने वाली बहुत से महत्वपूर्ण घरेलू विकृतियां हैं। व्यवहार में, राजनैतिक कारणों से, हम निवेश की तुलना में छूट (रियायतों) को वरियता देते हैं और बहुत से देशों में कर्ज को वरियता दी जाती है। भू-संपदा के मूल्यों और निवेश में प्रारंभिक गतिविधि के रूप में छूट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन विकृतियों को दूर करना निस्संदेह प्रथम कार्य होना चाहिए। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि किसी देश द्वारा अत्यधिक उधार लेने का अक्सर यह अर्थ होता है कि कोई अन्य देश अत्यधिक ऋण प्रदान कर रहा है : समष्टिगत विवेकपूर्ण नीतियां ऋण प्रदान

चार्ट 5: कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में छाया बैंक (2016 के अंत में)



स्रोत : वित्तीय स्थिरता बोर्ड

करने वाले देशों पर भी उतनी ही लागू होती हैं जितनी वे उधार लेने वाले देशों पर लागू होती हैं।

अंततः, इस तरह के किसी भी कार्य के लिए समष्टिगत विवेकपूर्ण प्राधिकारियों को स्वतंत्र होना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता के बदले समष्टिगत विवेकपूर्ण प्राधिकारियों को चुनी गई संस्थाओं के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। वित्तीय स्थिरता के संबंध में उनका अधिदेश यथासंभव पारदर्शी होना चाहिए और यह संसद तथा आम जनता को अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए। इसके अंतर्गत वित्तीय संकट आने पर पड़ने वाली बहुत बड़ी लागत के बारे में नागरिकों को सूचना देना भी शामिल है। दुर्भाग्यवश, दुनियाभर में इस तरह की बड़ी लागतों के स्पष्ट उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं : आर्थिक लागत, सामाजिक और राजनैतिक लागत एवं हमारे देश की सामाजिक संरचना तक को सीधा खतरा इसके अंतर्गत आता है। वित्तीय संकट को टालना एक कठिन कार्य है, जिसके लिए किसी मामले को बेहतर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना दुर्लभ होता है। इस संबंध में कोई नाटकीय घटना नहीं होती है। फिर भी, इसे नीतिगत प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संदर्भ :

आचार्य, विरल वी. और रघुराम जी. राजन (2013)। सॉवरिन डेब्ट, गवर्नमेंट मायोपिआ एंड द फाइनेंसियल सेक्टर, *रिव्यू ऑफ फाइनेंसियल स्टडीज*, 26 (6), 1526-1560.

ब्रूनो, वेलेंटीना और ह्यून सांग शिन (2015)। "कैपिटल फ्लोज एंड द रिस्क टेकिंग चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिशी", *मौद्रिक अर्थशास्त्र संबंधी जर्नल*, 71, 119-132.

कैल्वो, गुडलेर्मो ए., लियोनार्डो लीडरमैन, और कारमेन रेनहार्ट (1996)। "कैपिटल फ्लोज टू डेवलपिंग कंट्रीज इन 1990ज : काजेज एंड इफेक्ट्स" *जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स*, 10, स्प्रिंग 1996, 123-139.

कारुआना, जे. (2012)। पॉलिशी मेकिंग इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, *जैक्सन होल इकोनॉमिक सीपोजियम*।

कोएरडैसिएर निकोलस, हेलेन रे और पाब्लो विनेंट (2015)। "फाइनेंसियल इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ इन अ रिस्की वर्ल्ड", *एनबीईआर डब्ल्यूपी*, 21817.

कोयम्बरा, नूनो। और हेलेन रे (2017)। "फाइनेंसियल साइकल्स विद हिटरोजीनस इंटरमीडिअरीज", *एनबीईआर डब्ल्यूपी* 23245.

इचेंग्रीन बैरी और रिचर्ड पोर्ट्स (1987)। रिचर्ड पोर्ट्स और अलेक्जेंडर स्वोबोडा ईडीएस में 'द फाइनेंसियल क्राइसिस' का एनाटॉमी, एडा, थ्रेट्स टू इंटरनेशनल फाइनेंसियल स्टेबिलिटी, *कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस*।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड: *ग्लोबल शैंडो बैंकिंग मॉनिटरिंग रिपोर्ट* 2017.

फोर्ब्स, क्रिस्टिन जे और फ्रांसिस ई. वार्नाक (2012)। "कैपिटल फ्लो वेक्स: सर्जिस, स्टॉप्स, फ्लाइट एंड रिटेनमेंट" *जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स* 88 (2): 235-251.

फौलियार्ड, हॉवेल और रे (2018)। "आन्सरिंग द क्वीन : ऑनलाइन मशीन लर्निंग एंड फाइनेंसियल क्राइसिस", *माइमिओ लंदन बिजनेस स्कूल*।

गेरको और रे (2017)। "मॉनेटरी पॉलिशी इन द कैपिटल्स ऑफ कैपिटल" *यूरोपीय आर्थिक संघ की जर्नल* 15 (4), 721-745.

गोरिच, पियरे-ओलिवियर और मौरिस ओब्सटफेल्ड (2012)। "स्टोरीज ऑफ द ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट" *अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: मैक्रोइकोनॉमिक्स*, 4 (1), 226-65.

हॉफमैन, बी., लिहॉक शिम, और एच.एस. शिन (2016)। सॉवरिन यिल्ड्स एंड द रिस्क टेकिंग चैनल ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। *बीआईएस डब्ल्यूपी* 538.

ऑस्कर जोर्डा, मोरिज स्कुलर, एलन एम. टेलर, फेलिक्स वार्ड (2018)। "ग्लोबल फाइनेंसियल साइकल एंड रिस्क प्रीमियम्स, *एनबीईआर डब्ल्यूपी* 24677.

लैन, फिलिप और जियान मारिया मीलेसी-फेरेटी (2017); 'इंटरनेशनल फाइनेंसियल इंटीग्रेशन इन द आफ्टरमॉथ ऑफ द फाइनेंसियल क्राइसिस'; *आईएमएफ वर्किंग पेपर*, 17/115।

मिरांडा-एग्रिपीनो, सिल्विया, रे हेलेन (2015)। यूएस मॉनेटरी पॉलिशी एंड द ग्लोबल फाइनेंसियल साइकिल, *एनबीईआर, डब्ल्यूपी* 21722.

ओब्सटफेल्ड, एम. और ए. टेलर (2017)। "इंटरनेशनल मॉनेटरी रिलेशन्स : टेकिंग फाइनेंस सीरियसली"। *जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स*।

ऑब्सटफेल्ड, मौरिस और एलन टेलर (2004)। "ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स : इंटीग्रेशन, क्राइसिस एंड ग्रोथ", *कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस*।

ओस्टरी, जोनाथन डी., आतिश आर. घोष, कार्ल हेबरमीयर, ल्यूक लेवेन, मार्कोस शैमोन, महवाश एस. कुरैशी, और अन्नामारिया

कोकेन्ये। "मैनेजिंग कैपिटल इन्फ्लो: व्हाट टूल टू यूज ?" आईएमएफ स्टाफ डिस्कशन नोट एसडीएन/ 11/06, अप्रैल 2011. पोर्ट्स, आर. एवं डी. वाइन्स (1997)। कोपिंग विद कैपिटल इनफ्लोज़, कॉमनवैल्थ सेक्रेटेरिएट इकोनॉमिक पेपर (30)। रे, एच. (2013)। द ग्लोबल फाइनेंसियल साइकिल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन्डिपेंडेंस। प्रोसीडिंग्स ऑफ द जैक्सन होल सिंपोजिअम।

भारतीय रिजर्व बैंक (2018)। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। स्कुलर, मोरिट्ज़ एवं एलन एम. टेलर (2012)। "क्रेडिट बूम गन्स बस्ट : मॉनेटरी पॉलिसी, लिवरेज साइकिल्स, एंड फाइनेंसियल क्राइसिस 1870-2008"। अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू 102, 1029-61. जुकमान, गेब्रियल (2018)। "ग्लोबल वेल्थ इनइक्वैलिटी", यूसी बर्कले, माइमो।

लेख

भारत में बैंक क्रेडिट का क्षेत्रवार विनियोजन

चलनिधि प्रबंधन का स्वरूप: 2018-19 के दौरान आए बदलाव

भारत में बैंक क्रेडिट का क्षेत्रवार विनियोजन*

खुदरा क्षेत्र को दिए जा रहे अत्यधिक उधार, विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋणों के रूप में, के कारण बैंक क्रेडिट के क्षेत्रवार विनियोजन में गुणात्मक परिवर्तन आया है। उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों में लंबे समय तक मंदी का रुख बने रहने के बाद वर्ष 2018-19 में अभी तक धीरे-धीरे तेजी आती दिख रही है। आर्थिक गतिविधियों में आयी तेजी ने जहाँ क्रेडिट की माँग में वृद्धि की है, वहीं बैंकों में पहले की तुलना में बढ़ी हुई भारित औसत उधार दरों और अनर्जक ऋणों के काफी लंबे समय से बने रहने के कारण क्रेडिट की माँग घटी है।

भूमिका

भारत जैसी अर्थव्यवस्था में बैंक जहाँ एक ओर प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, वहीं इनके द्वारा दिया जा रहा ऋण मौद्रिक नीति के संचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। मौद्रिक नीति का संचरण एक ऐसा विषय है जिसमें बीसवीं शताब्दी के शुरुआती साहित्य (ब्रूनर और मेल्टज़र, 1963; बर्नानके और ब्लिंडर, 1988) से लेकर अब तक विद्वानों की रुचि बनी हुई है। बैंक क्रेडिट वाले बाजार उनमें मौजूद असंगति के लिए कुख्यात रहे हैं और वहाँ नुकसान में रहने वाले प्रतिभागियों को बाहर का रास्ता दिखाने की प्रवृत्ति होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में नीतिगत हस्तक्षेप की वकालत की जाती है ताकि बाजारों की असंगति को सुधारा जा सके, समावेशी संतुलन बनाए जा सकें और क्रेडिट के विनियोजन को परिचालित करने के लिए सटीक मूल्य-निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके (कनेल्स और नंदा, 2012)। भारत में, 1980 के दशक की अवधि में ऋण और नीति-प्रशासित उधार दरों के आबंटन में राज्य का प्रभुत्व हुआ करता था। 1990 के दशक के बाद से, उदारीकरण के साथ-साथ सांविधिक पूर्वापेक्षाओं में भी कमी आयी, ब्याज दरों को विनियमन से क्रमशः मुक्त करने की दिशा में प्रगामी प्रगति हुई और नये निजी बैंकों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ी। यद्यपि इन सब कदमों के बावजूद अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में बैंक-ऋण का पर्याप्त

और एकसमान वितरण अकादमिक और नीति निर्माताओं के बीच समान रूप से चिंता का विषय रहा है (यकूबू और अफोर्ड, 2014 और मर्किंडे, 2016)। इसे देखते हुए, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक ऋण के प्रवाह को मापने और इसकी निगरानी के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया है और इस कार्य में काफी संसाधन लगाए गए हैं।

सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय प्रवाह की जानकारी पर मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) डेटा संग्रह प्रणाली के माध्यम से वार्षिक आधार पर और हाल के वर्षों में, ति.1: 2014-15 से तिमाही आधार पर नज़र रखी जा रही है। मौद्रिक नीति के निर्माण के उद्देश्य से न्यूनतम समय अंतराल के साथ बार-बार निगरानी की आवश्यकता के मद्देनजर, चुनिंदा बैंकों - वर्तमान में 41 बैंक जिनकी हिस्सेदारी सकल बैंक ऋण में लगभग 90 प्रतिशत है - से क्रेडिट के क्षेत्रवार विनियोजन की जानकारी प्राप्त की जाती है। इन आंकड़ों में अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होते हैं और ये रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर हर महीने के आखिरी कार्य दिवस को लगभग एक माह के विलंब के साथ जारी किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक अपने विभिन्न प्रकाशनों और अपने डेटा वेयरहाउस के ज़रिए भी इन आंकड़ों को सार्वजनिक करता रहता है। ऐसा बहुपक्षीय एजेंसियों (संलग्न सारणी I) के डेटा प्रसार मानकों तथा सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक के प्रमुख प्रकाशनों में इन आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है और यहाँ से सभी क्षेत्रों में मौद्रिक नीति के संचरण का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, ये आंकड़े मौद्रिक नीति के कारण लगने वाले झटकों पर अलग-अलग क्षेत्रों की प्रतिक्रियाओं, वित्त-पोषण की स्थितियों, उधार-लागतों और जीडीपी की तुलना में क्रेडिट के अलग-अलग प्रतिशतों पर भी प्रकाश डालते हैं।

इस पृष्ठभूमि में देखने पर, अंतर्निहित क्षेत्र-वार गतिशीलता के साथ-साथ समग्र खाद्येतर क्रेडिट में जो उतार-चढ़ाव आया है, उसका विश्लेषण करना इस लेख का प्रमुख उद्देश्य है। आलेख के भाग II में कुछ सुव्यवस्थित साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए, भाग III में बैंक क्रेडिट प्रवाह को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गयी है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों पर अनुभव के आधार पर निकाले गए कुछ निष्कर्षों की चर्चा भाग IV में की गयी है। अंतिम भाग में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

* यह आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग की जेसिका एम. एंथनी, शिव शंकर और सत्यानंद साहू द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

II. खाद्येतर ऋण : कुछ सुव्यवस्थित तथ्य

भारत की बैंक-आधारित वित्तीय प्रणाली में, वाणिज्यिक क्षेत्र¹ को दिए गए कुल क्रेडिट में बैंक क्रेडिट का हिस्सा अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है (चार्ट 1 ए)। हालांकि पिछली कुछ अवधि से, क्रेडिट के अन्य स्रोतों के आ जाने से संरचनात्मक बदलाव के संकेत दिखने लगे हैं, हालांकि उनकी हिस्सेदारी अभी भी कम है (चार्ट 1 बी)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा अधिकाधिक क्रेडिट उद्योगों को दिया जा रहा है हालांकि इसमें पिछले कुछ वर्षों से गिरावट जारी है (चार्ट 2 ए)। कृषि के लिए ऋण का हिस्सा वर्षों से स्थिर बना हुआ है, जबकि सेवाओं और व्यक्तिगत ऋण ऐसे संविभाग हैं जिनमें काफी वृद्धि हुई है (सारणी II और III) हैं। भारत के संदर्भ में बैंक ऋण की अनुचक्रीयता स्वतः स्पष्ट है (चार्ट 2 बी), तथापि यहाँ बैंकों की कई श्रेणियों की उपस्थिति से इसके प्रभाव को समाप्त करने में मदद मिलती है।

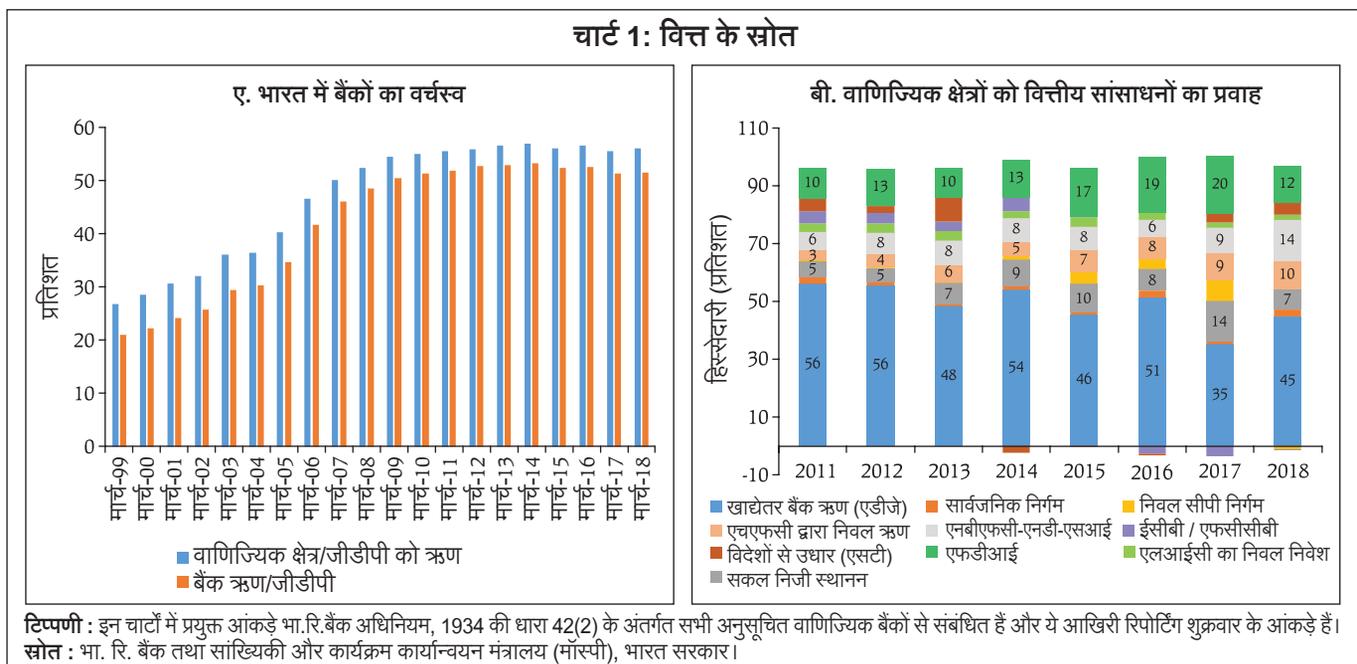
2009-13 की अवधि में बैंक ऋणों में उछाल आया, जिसमें गैर-खाद्य ऋण की वृद्धि औसतन 17 प्रतिशत रही। हालाँकि, आने वाले पाँच वर्षों में, यह धीमी होकर 10 प्रतिशत तक आ

गयी क्योंकि व्यापक स्तर पर हुई ऋण-हानि के चलते बैंकों के तुलन-पत्र पर अत्यधिक दबाव आ जाने से क्रेडिट चक्र नीचे की ओर घूम गया। वर्ष 2015 आते-आते क्रेडिट वृद्धि-दर तेजी से गिरकर एकल अंकों में आ गयी और यह मई 2017 तक जारी रही और इसके बाद ही इसमें धीरे-धीरे सुधार आना शुरू हुआ है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान औद्योगिक क्षेत्र को हुआ है, जहाँ अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का अंबार लग जाने की वजह से स्थिति अत्यधिक शोचनीय बनी हुई है।

म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) जैसे बैंकेतर क्रेडिट बिचौलियों के आ जाने से क्रेडिट के क्षेत्र में बैंकों की हिस्सेदारी को थोड़ा कम कर दिया है। इस विमध्यस्थीकरण का कुछ श्रेय तेज कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (सारणी 1) को भी दिया जा सकता है।

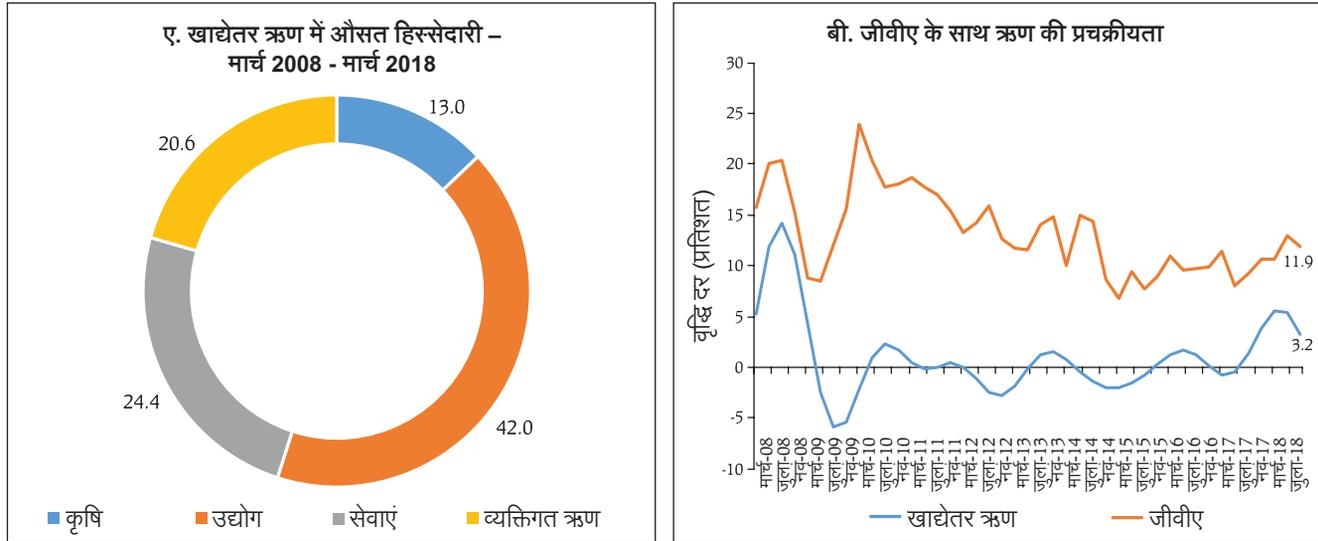
खुदरा क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में हुई तीव्र वृद्धि के साथ-साथ बैंक क्रेडिट में गुणात्मक बदलाव भी लक्षित किया गया है; तदनुसार, व्यक्तिगत ऋण संविभाग औसत औद्योगिक स्तर से काफी ऊपर पहुंच गया है। मार्च 2018 में वृद्धिशील ऋणों में व्यक्तिगत ऋण की

चार्ट 1: वित्त के स्रोत



¹ वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में शामिल हैं - रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया क्रेडिट जो वह वित्तीय संस्थानों के बॉन्ड / शेयरों में निवेश, उन्हें दिए गए ऋण और खरीदे गए तथा बड़ाकृत आंतरिक बिलों की धारिताओं के माध्यम से देता है, वाणिज्यिक क्षेत्र को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण और अग्रिमों के रूप में मिलने वाला क्रेडिट, प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ए) के तहत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में और एसएलआर से भिन्न प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश।

चार्ट 2: ऋण गतिकी



टिप्पणी: पैनेल बी में खाद्येतर ऋण के चक्रिय घटक का अनुमान हॉड्रिक-प्रेसकोट फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए लगाया गया है।
स्रोत: भा. रि. बैंक तथा लेखकों के अनुमान।

हिस्सेदारी 48.6 प्रतिशत थी जो कि मार्च 2013 के 20 प्रतिशत की तुलना में एक जबरदस्त उछाल थी(चार्ट 3 ए)। वर्ष-दर-वर्ष

उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी व्यक्तिगत ऋण और सेवाओं के बाद तीसरे स्थान पर बनी हुई है। वर्ष 2016-17 की अधिकांश अवधि

सारणी 1: वाणिज्यिक क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ बिलियन में)

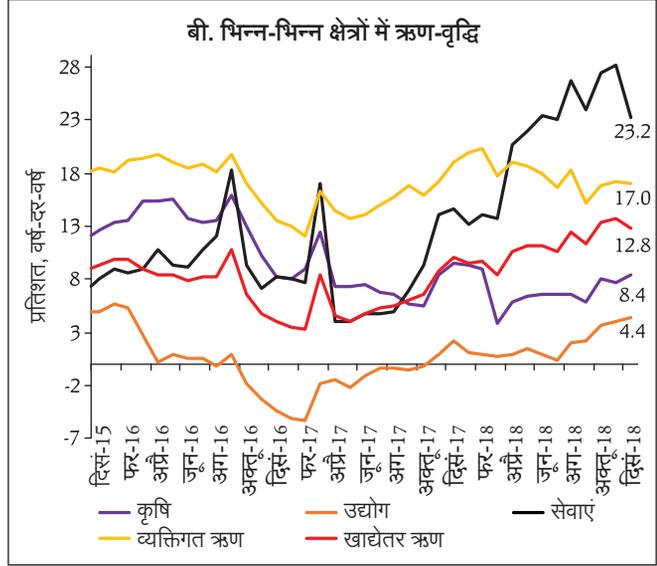
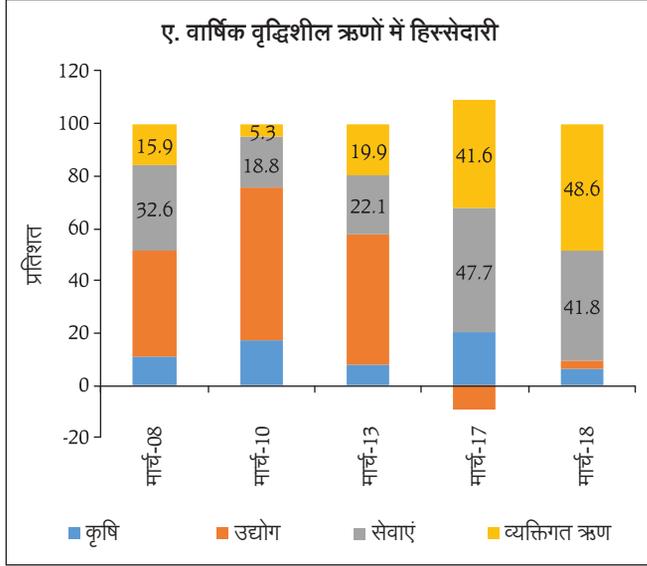
स्रोत	अप्रैल-मार्च			अप्रै 1 से जन 18	
	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18	2018-19
ए. समायोजित खाद्येतर ऋण (एनएफसी)	7,754	4,952	9161	3634	7071
i) खाद्येतर ऋण	7,024	3882	7959	2959	6773
जिसमें से : पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर ऋण	-18	133	27	-224	-153
ii) एससीबी द्वारा एसएलआर से इतर निवेश	731	1070	1202	675	298
बी. गैर-बैंक संस्थाओं से ऋण प्रवाह (बी1+बी2)	6,241	9,578	11,220	7,716	7,946
बी1. घरेलू स्रोत	3,782	6,820	7,836	5,762	5,677
1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निर्गम	378	155	438	174	84
2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सकल निजी स्थानन	1,135	2,004	1,462	1121	1123
3 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सीपी में किए गए अंशदान का निवल निर्गम	517	1,002	-254	570	2018
4 आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल ऋण	1,188	1,374	1,986	1,117	1141
5 भा.रि.बैंक द्वारा विनियमित 4 एआईएफआई – नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्विजम बैंक द्वारा कुल निभाव	472	469	951	545	1021
6 प्रणालीगत महत्व रखने वाली जमाराशि न स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (निवल बैंक क्रेडिट)	-277	1,539	2,875	1,959	128
7 कॉर्पोरेट कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र में एलआईसी का निवल निवेश	369	277	378	276	163
बी2. विदेशी स्रोत	2,459	2,758	3,385	1,954	2,269
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	13,995	14,530	20,381	11,350	15,017

टिप्पणी:(i) 2017-18 में एनबीएफसी-एनडीएसआई द्वारा दर्शाया गया उच्च क्रेडिट फ्लो सरकारी कंपनियों द्वारा की गयी अधिक रिपोर्टिंग के कारण था। 2015-16 में एनबीएफसी-एनडीएसआई द्वारा दर्शाया गया नकारात्मक निवल क्रेडिट फ्लो एनबीएफसी-एनडीएसआई के लिए बने वर्गीकरण मानदण्डों में हुए परिवर्तन के कारण था जिसके तहत एनबीएफसी-एनडीएसआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु आवश्यक आरिस्त आकार ₹100 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक कर दिया गया था। इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान दो बड़ी एनबीएफसी – बंधन तथा आईडीएफसी – के बैंक के रूप में परिवर्तित हो जाने से भी 2015-16 के दौरान एनबीएफसी द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को हुए ऋण प्रवाह में कमी आयी।

(ii) \$: नवंबर 2018 तक *: दिसंबर 2018 तक @ : जनवरी 2019 के मध्य तक

स्रोत: भा. रि. बैंक, सेबी, बीएसई, एनएसई, मचेंट बैंक, एलआईसी और एनएचबी।

चार्ट 3: प्रमुख क्षेत्रों में ऋण-वृद्धि



स्रोत : भार.रि.बैंक

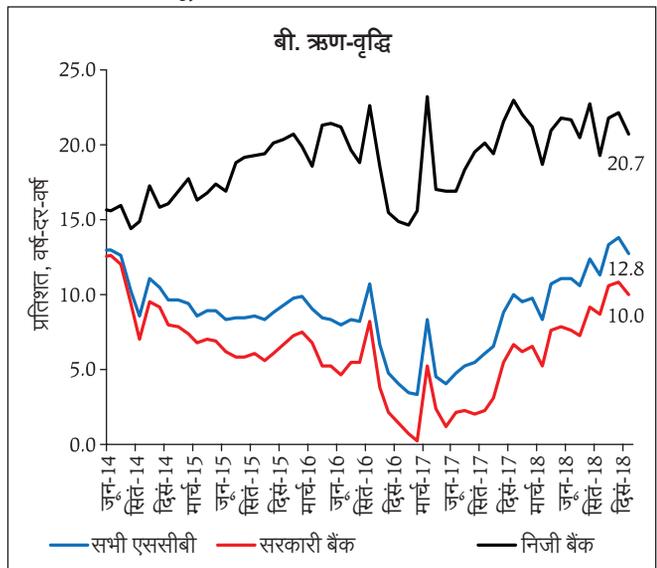
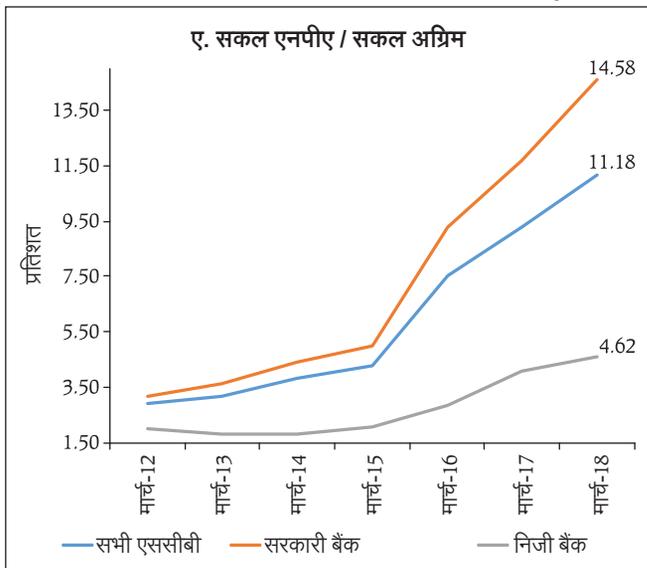
में उद्योग क्षेत्र को दिए गए क्रेडिट में संकुचन की स्थिति रही और नवंबर 2017 में जाकर यह धनात्मक हो पायी (चार्ट 3 बी और संलग्न सारणी II)।

मई 2017 के बाद से क्रेडिट में आयी तेजी मुख्यतया निजी क्षेत्र के बैंकों में देखी गयी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) एनपीए के भारी बोझ के तले दबे होने की वजह से लगातार पिछड़े रहे (चार्ट 4)।

III. प्रमुख क्षेत्रों को बैंक क्रेडिट

प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो, कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण जिनमें 2011-12 तक 20% से अधिक तेजी से वृद्धि हो रही थी, में हाल के वर्षों में मंदी आयी है और 2016-17 के दौरान हुई तीव्र गिरावट के बाद 2017-18 में उसमें थोड़ी वृद्धि दर्ज की गयी है। जहाँ कृषि क्षेत्र को ऋण में न्यूनाधिक उतार-चढ़ाव बना

चार्ट 4: ऋण-वृद्धि तथा एनपीए (बैंक - समूह वार)



स्रोत : भार.रि.बैंक

सारणी 2 : चुनिंदा क्षेत्रों में क्रेडिट विनियोजन

	बकाया (₹ बिलियन)					वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)			
	मार्च-08	मार्च-11	मार्च-14	मार्च-18	नव-18	2010-11	2013-14	2017-18	दिसं-18
खाद्येतर ऋण (1 से 4)	22,048	36,674	55,296	76,884	81,642	20.7	13.6	8.4	12.8
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	2,753	4,806	6,660	10,302	10,821	15.6	12.9	3.8	8.4
2. उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मँझोले और बड़े) जिनमें से	8,583	16,046	25,165	26,993	27,494	22.4	12.8	0.7	4.4
(i) इन्फ्रास्ट्रक्चर	2,053	5,214	8,364	8,909	9,719	37.2	14.6	-1.7	9.2
(ए) ऊर्जा	951	2,666	4,869	5,196	5,476	41.9	17.1	-1.1	5.3
(बी) दूरसंचार	383	933	882	846	906	57.2	0.5	-0.6	6.0
(सी) सड़कें	345	906	1,579	1,665	1,870	23.2	20.2	-7.5	9.8
(ii) मूल धातुएं और धातु उत्पाद	1,076	2,130	3,608	4,160	3,799	30.7	14.9	-1.2	-8.1
(iii) खाद्य-प्रसंस्करण	494	768	1,463	1,554	1,478	17.0	24.6	6.8	2.8
3. सेवाएं	5,493	8,942	13,375	20,505	22,330	23.0	16.1	13.8	23.2
(i) व्यापार	1,238	1,850	3,258	4,669	4,860	12.5	18.1	9.1	10.3
(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	789	1,903	2,938	4,964	5,709	67.7	12.9	26.9	55.1
4. व्यक्तिगत ऋण	5,218	6,879	10,097	19,085	20,997	17.5	12.5	17.8	17.0
(i) आवासन (प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों सहित)	2,603	3,499	5,386	9,746	10,966	16.3	17.9	13.3	17.1
(ii) वाहन ऋण	586	726	1,063	1,898	1,992	13.8	-4.3	11.3	8.8

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं और ये ऐसे चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जिनकी सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल खाद्येतर ऋण में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है।
स्रोत : आरबीआई।

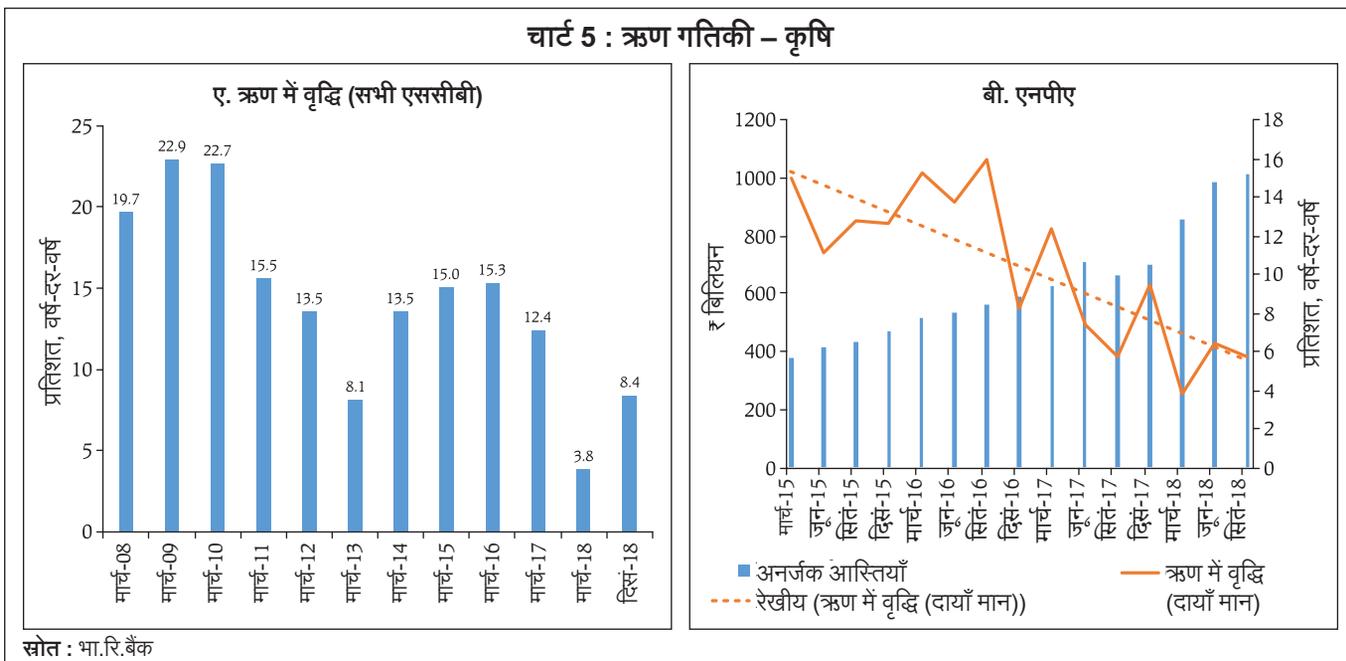
रहा, व्यक्तिगत ऋणों के रूप में ऋण का प्रवाह पिछले कुछ वर्षों के दौरान मोटे तौर पर स्थिर बना रहा है (सारणी 2)।

III.1 कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ

विकास में अस्थिरता के बावजूद, कुल गैर-खाद्य ऋण में कृषि (कृषि ऋण, कृषि अवसंरचना और सहायक गतिविधियों के लिए

उधार सहित) की हिस्सेदारी वर्षों से मोटे तौर पर 13 प्रतिशत के अपरिवर्तित स्तर पर बनी हुई है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार को दिया जा सकता है। लक्ष्यानुसूचित उधार दिए जाने के बावजूद, 2017-18 में कृषि को किया गया ऋण संवितरण मौजूदा रुझान (चार्ट 5 ए) से भिन्न रहा है, जो दक्षिणी क्षेत्र के कुछ राज्यों में सूखे को दर्शाता है, जबकि कृषि

चार्ट 5 : ऋण गतिकी – कृषि



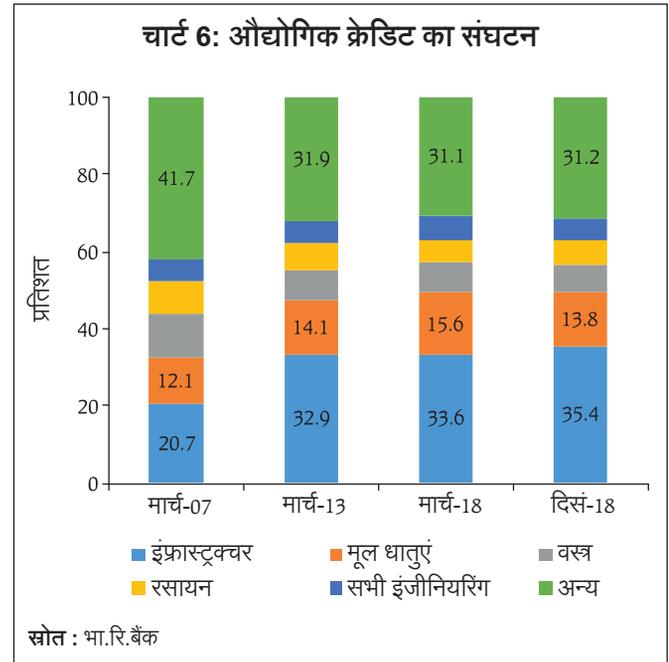
ऋणों की माफी के संबंध में सरकार द्वारा संभावित घोषणा के मद्देनजर बैंक आमतौर पर इस क्षेत्र को ऋण देने से परहेज करने लगे। नतीजतन, इस क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों का एक्सपोजर गिरता रहा है (चार्ट 5 बी)।

III.2. उद्योग

संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा के आधार पर, औद्योगिक क्षेत्र को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों यथा, सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा लिए जा रहे समग्र उधार में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बड़े उद्योगों का है, जबकि पिछले एक दशक में मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी में काफी कमी आई है। कुल क्रेडिट में सूक्ष्म और लघु उद्योगों ने अपनी हिस्सेदारी 10-15 प्रतिशत तक रखने में सफल रहे क्योंकि उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने का लाभ मिला। औद्योगिक क्षेत्र दिसंबर 2010 में अपने कारोबार के चरम पर पहुंचने के बाद मंदी / संकुचन के दौर से गुजर रहा था क्योंकि बड़े उद्योग साल-दर-साल निराशाजनक कारोबार कर रहे थे।

औद्योगिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की जानकारी प्राप्त करते समय बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) प्रणाली/राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) की तरह ही औद्योगिक क्षेत्र की 18 व्यापक उप-श्रेणियों को शामिल किया जाता है। इस उद्योग द्वारा लिए जाने वाले ऋण का लगभग एक तिहाई बुनियादी ढांचे के लिए होता है और उसके बाद मूल धातु और धातुओं से बने उत्पादन एवं वस्त्र उद्योग का स्थान आता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए लिए गए ऋण की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उद्योगों द्वारा लिए गए कुल ऋण में इसकी भागीदारी जो मार्च 2007 में कुल का पांचवां हिस्सा थी, मार्च 2018 में बढ़कर एक तिहाई हो गयी है। मूल धातुओं ने अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखी है जबकि वस्त्र-उद्योग की हिस्सेदारी में कमी आयी है (चार्ट 6)।

2016-17 की शुरुआत से ही उद्योग भीषण वित्तीय दबाव झेल रहा था, 2017-18 में ऋण की वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत तक गिर गई। रुकी हुई परियोजनाओं की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ी है। उद्योगों को दिए गए ऋणों की वृद्धि-दर में मामूली बढ़ोतरी के साथ-साथ क्षमता-उपयोग में सुधार के चलते इसमें बहाली आयी और 2018-19 में धीरे-धीरे मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं (चार्ट 7)।



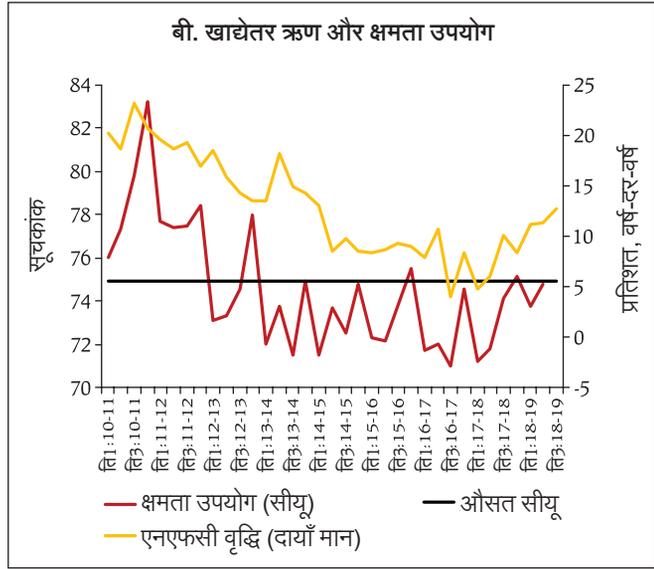
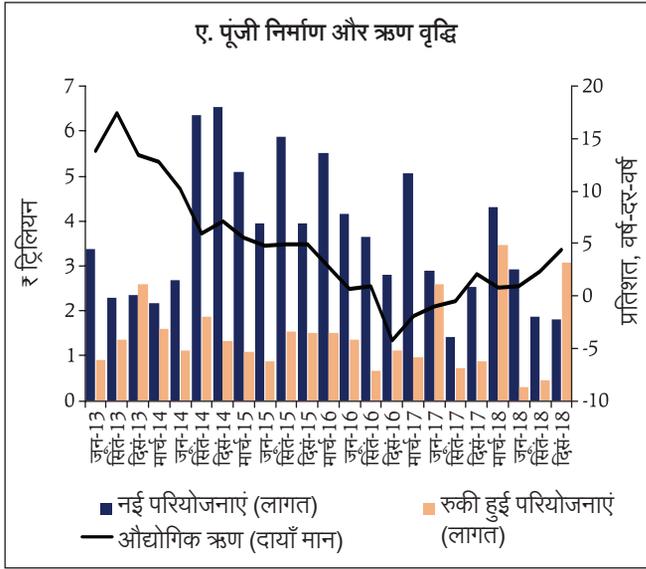
ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण, जो उद्योगों को दिए जाने वाले बैंक क्रेडिट का लगभग एक-तिहाई हिस्सा होता है, में वर्ष 2017-18 के दौरान 1.1 प्रतिशत की कमी आयी, जो अप्रैल 2016 से शुरू हुई मंदी का ही प्रतिफल था। यह गिरावट 2018-19 में जाकर कम होनी प्रारंभ हुई, हालांकि, ऋण उठाव जुलाई 2018 में जाकर धनात्मक स्तर पर पहुंचा। इस क्षेत्र के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण ऋणों को हुई हानि बताया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप सख्त विनियामकीय मानदण्ड आरोपित हो गए जिसका विपरीत प्रभाव लाभप्रदता पर पड़ा, विशेष रूप से दूरसंचार और ऊर्जा के क्षेत्रों में। भारत सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), चरण-7 सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर उधार को प्रोत्साहित करने की दिशा में नवीनतम पहल है। ऊर्जा क्षेत्र, जिसकी हिस्सेदारी बुनियादी ढांचे को दिए जा रहे ऋण की लगभग आधी होती है, में वर्ष 2017-18 के दौरान गिरावट / संकुचन देखा गया है हालांकि वर्ष 2018-19 में यह दबाव कुछ कम होता दिखा (चार्ट 8)।

बी. मूल धातुएं

उद्योगों को दिए जा रहे कुल क्रेडिट में मूल धातु संविभाग की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत होती है। वर्ष 2016 की शुरुआत से ही यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कुल क्रेडिट में हुई गिरावट के

चार्ट 7: उद्योगों को ऋण (वाहक)



स्रोत : भा.रि.बैंक और भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई)।

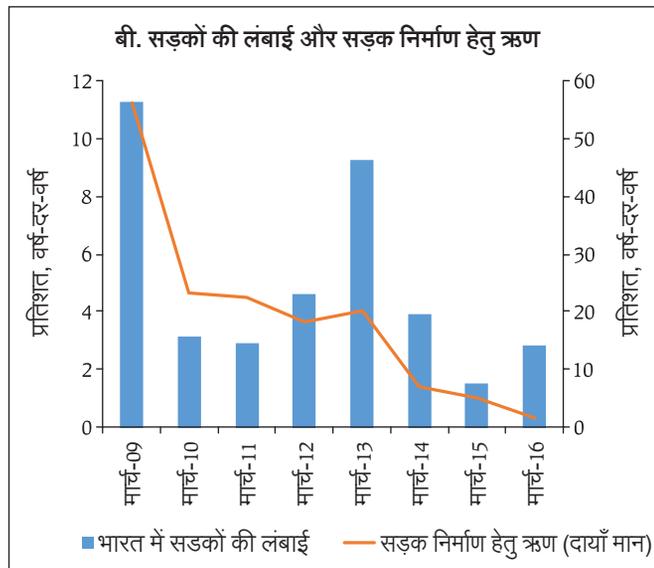
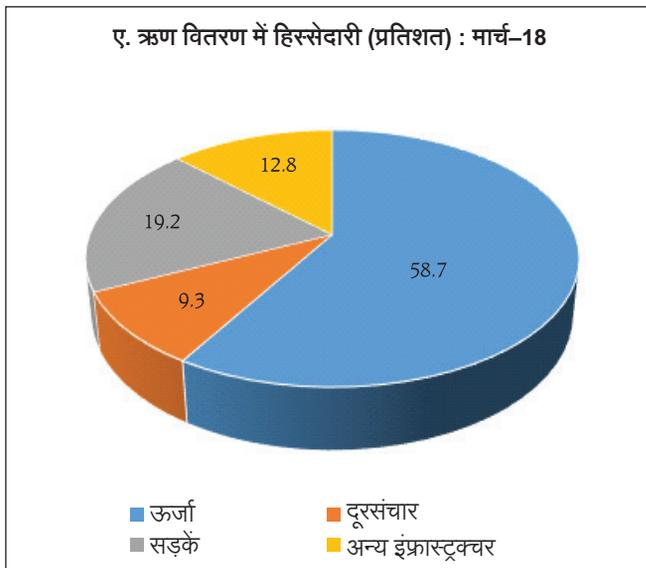
लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार क्षेत्र रहा है। इस संविभाग में, कुल क्रेडिट में लोहे और इस्पात की हिस्सेदारी लगभग तीन चौथाई है। वर्ष 2017-18 की अधिकांश अवधि के दौरान मूल धातुओं में संकुचन बना रहा, हालांकि वर्तमान चालू वित्त वर्ष में इस क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाने में सफलता हासिल की है। रूस, चीन और दक्षिण कोरिया से अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर आयात होने से भारत के लोह और इस्पात क्षेत्र को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में कोयले की उपलब्धता में कमी

से स्टील उत्पादन की इनपुट लागत में वृद्धि हुई। इसके बावजूद वर्ष 2018-19 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है।

सी. वस्त्र उद्योग

उद्योगों में कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत थी और यह मई 2014 तक इसी स्तर पर बनी रही। जीएसटी के लागू होने के बाद छोटी और विकेन्द्रीकृत कपड़ा इकाइयों के समक्ष जो परिचालनगत समस्याएं आयीं, उनका सामना इसने भी किया

चार्ट 8: इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके उपक्षेत्रों की ऋण गतिकी



स्रोत : भा.रि.बैंक और सीएमआईई।

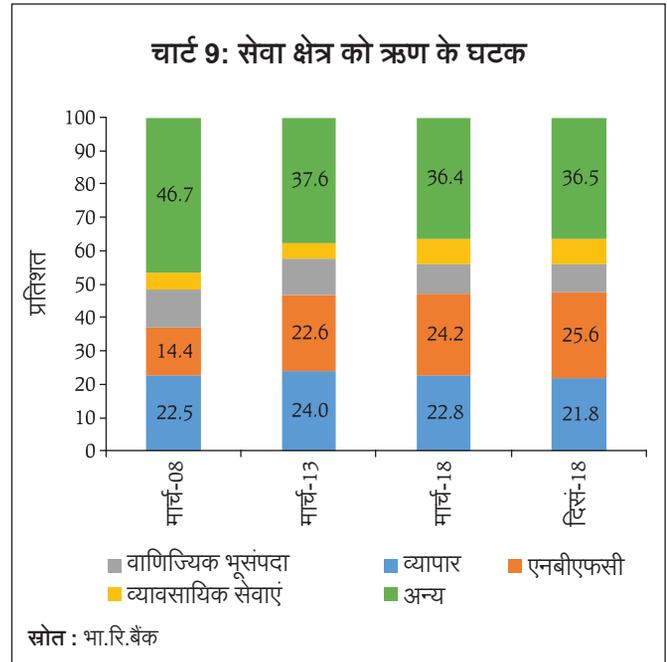
है, यथा- अनेक प्रोत्साहनों को हटा लिए जाने के कारण सूत के निर्यात में आयी गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में बढ़त की स्थिति खो देना। कपड़ा संविभाग को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी सूती कपड़े की है, इसके बाद मानव निर्मित फाइबर और फिर जूट से बने वस्त्रों का स्थान आता है। पिछले एक दशक में सूती कपड़ों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि मानव निर्मित रेशों की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है। पिछले कई वर्षों से सस्ती दरों पर हो रहे आयात के चलते भारत के वस्त्र उद्योग को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण 2016-17 में ऋण संकुचन की स्थिति आ गयी जबकि 2007-08 में इसमें 23.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी (अनुलग्नक तालिका IV)।

अधिकांश औद्योगिक उप-घटक परस्पर जुड़ते हुए उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए, सीमेंट और सीमेंट से बने उत्पादों के क्षेत्र काफी हद तक निर्माण, अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जनवरी 2015 से मार्च 2018 तक के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, निर्माण (0.27) और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों (0.45) के साथ सीमेंट और सीमेंट उत्पाद क्षेत्र द्वारा की गयी ऋण-उगाही के बीच एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण सह-संबंध देखा गया। हाल के वर्षों में ऋण की मांग में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं जिनका कारण सस्ते और ग्रामीण आवासों, सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में की गयी पहलों को माना जा सकता है।

III.3. सेवा-क्षेत्र

भारत के सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में लगभग 55 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाले सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी एससीबी द्वारा संवितरित कुल गैर-खाद्य ऋण की लगभग एक चौथाई है - मार्च 2018 तक 27 प्रतिशत। हाल के वर्षों में क्रेडिट वृद्धि दोहरे अंकों में रही है, हालांकि 2016-17 में विमुद्रीकरण की वजह से इसे झटका लगा है, परंतु इसके बाद 2017-18 की दूसरी छमाही में यह थोड़ा बहाल होकर 13.1 प्रतिशत तक पहुंची।

सेवा-क्षेत्र के भीतर देखें तो, व्यापार और एनबीएफसी क्षेत्र की हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र को दिए गए कुल क्रेडिट में क्रमशः लगभग 22 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है, जबकि वाणिज्यिक अचल संपत्ति तीसरे स्थान पर रही और इसके बाद पेशेवर सेवाओं का नंबर आता है (चार्ट 9)। अन्य घटकों में परिवहन ऑपरेटर, कंप्यूटर



सॉफ्टवेयर, पर्यटन होटल और रेस्तरां, शिपिंग और अन्य शामिल हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, व्यापार में कुछ नरमी देखी गयी; हालांकि, एनबीएफसी क्षेत्र के अच्छे कामकाज के कारण क्रेडिट की मांग को बनाए रखने में कामयाबी मिली।

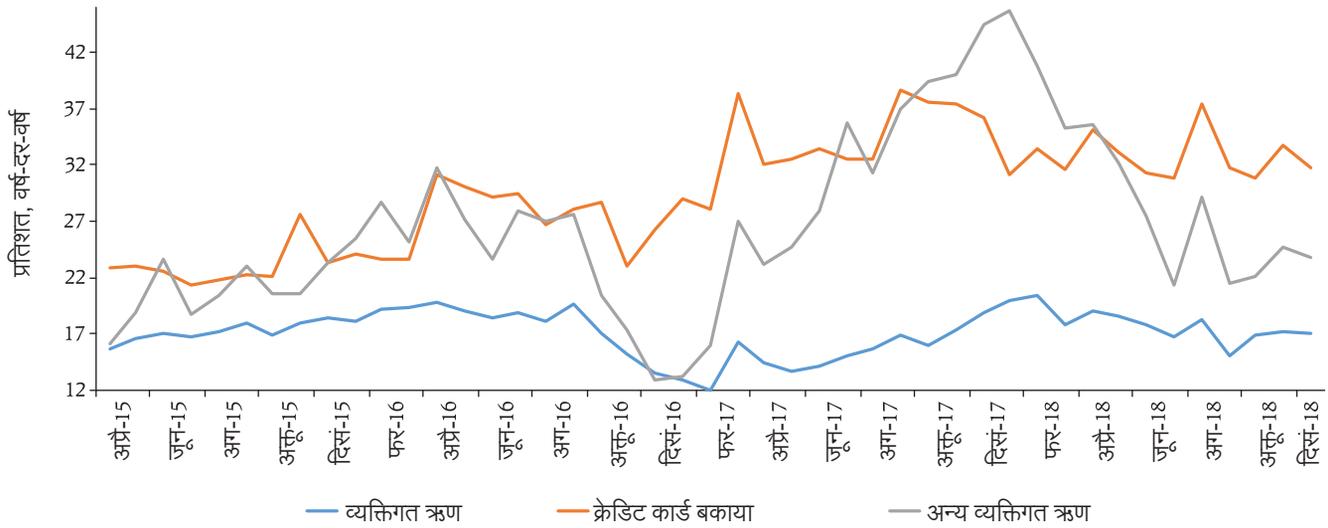
ए. व्यापार

2017-18 के दौरान व्यापार में मामूली ऋण वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष में 14.0 प्रतिशत की तुलना में 9.1 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र को दिए गए ऋण में पिछले कुछ वर्षों में कमी आती रही है जो नवंबर 2016 में 3.4 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गयी। व्यापार को खुदरा व्यापार और थोक व्यापार में विभाजित किया जाता है जिसमें पहले वाले का वर्चस्व बना रहा और 2007 से लेकर इसमें आंशिक रूप से वृद्धि देखी गयी है। सामान्यतया खुदरा क्षेत्र को दिए गए ऋणों में वृद्धि की दर ने थोक व्यापार क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया और जैसे-जैसे ई-कॉमर्स का प्रचलन बढ़ता जाएगा, ऐसी आशा है कि यह संविभाग डिजिटलीकरण की बढ़ती गति के सहयोग से और अधिक तेजी पकड़ेगा।

ख. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

सेवा क्षेत्र में एनबीएफसी की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी और यह मार्च 2007 के 11 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2018 में सेवा क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण की एक चौथाई हो गयी। हालांकि, पिछले दशक के दौरान एससीबी द्वारा इस क्षेत्र को दिए गए ऋण में कमी आयी और 2017-18 में तो यह 2007-08 की तुलना में लगभग

चार्ट 10: खुदरा ऋणों को पीछे छोड़ते अप्रतिभूत ऋण



स्रोत : भा.रि.बैंक

आधी रह गयी। विमुद्रीकरण के पश्चात भी ऋण वृद्धि में काफी गिरावट देखी गयी हालांकि जीएसटी से संबंधित अनिश्चितताओं के बावजूद इस क्षेत्र में 2018-19 में तेजी देखी गई है।

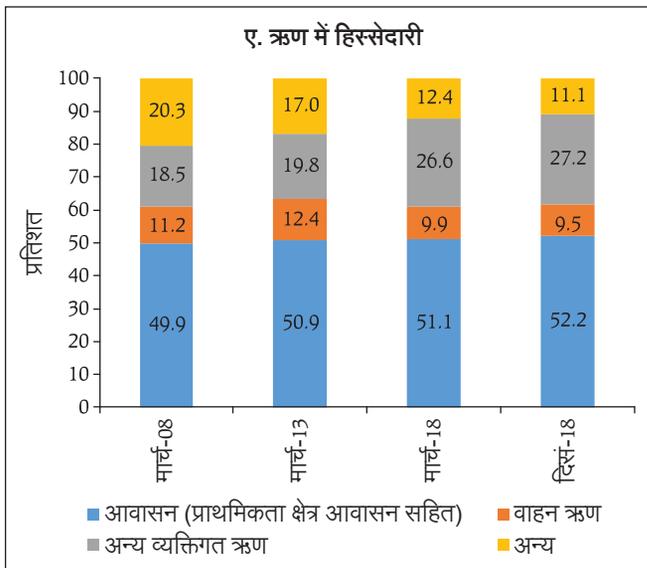
III.4. व्यक्तिगत ऋण

व्यक्तिगत ऋण संविभाग में, क्रेडिट में वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से काफी अधिक दर से होती रही है जो प्रमुख रूप से आवासन क्षेत्र से प्रेरित रही है जबकि वाहनों के क्षेत्र में हाल की अवधि में

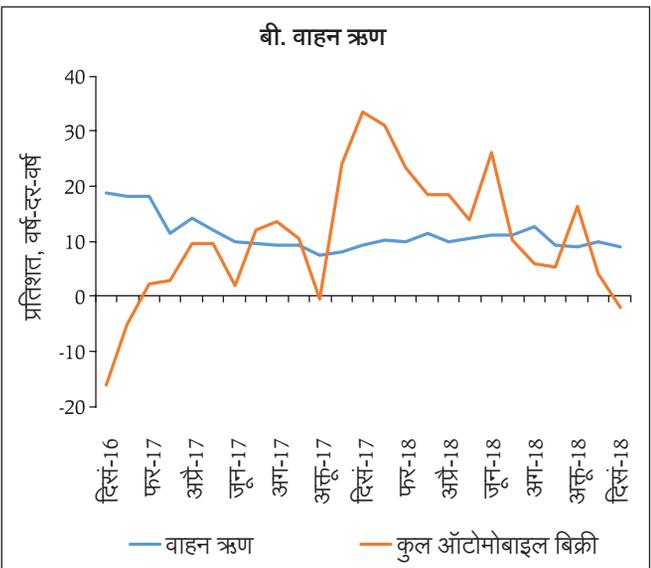
थोड़ी मंदी आयी है। इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में वृद्धिशील ऋण में अपनी हिस्सेदारी बनायी रखी है। अप्रतिभूत ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई है जिससे अन्य प्रकार के व्यक्तिगत ऋणों में और क्रेडिट कार्ड बकाया में उच्च वृद्धि परिलक्षित होती है (चार्ट 10)।

व्यक्तिगत ऋण संविभाग का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आवास और वाहन ऋणों का होता है जिसमें से पहला वाला क्रेडिट वृद्धि का प्रमुख वाहक होता है (चार्ट 11 ए)। क्रेडिट कार्ड बकाया

चार्ट 11: ऋण गतिकी - व्यक्तिगत ऋण और इसके उपक्षेत्र



स्रोत : भा.रि.बैंक



की हिस्सेदारी समग्र क्रेडिट में बहुत अधिक नहीं होती, तथापि इसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शिक्षा-ऋणों में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि देखी गई, जबकि 2017-18 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं हेतु ऋणों की वृद्धि-दर में भी कमी आयी।

ए. आवास ऋण

व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र द्वारा दिए जा रहे कुल ऋण में लगभग आधी हिस्सेदारी आवासीय ऋणों की होती है। यह क्षेत्र व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि का मुख्य वाहक बना हुआ है, हालांकि निर्माण, इस्पात और सीमेंट जैसे अन्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में हाल के महीनों आयी गिरावट का असर इस क्षेत्र पर भी पड़ा है। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान आवास ऋणों की मांग भी बढ़ने की प्रवृत्ति होती है जो कि वास्तविक बचत में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने का एक तरीका होता है। इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र की श्रेणी में भी आता है।

बी. वाहन ऋण

भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग का स्थान दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उद्योगों में है, जिसमें यात्री वाहन, तिपहिया वाहन और दोपहिया वाहन शामिल हैं, और इसमें बाद वाले की हिस्सेदारी तो विश्व में सर्वाधिक है। बढ़ता मध्यम वर्ग, देश की युवा आबादी और विकसित होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने भी दोपहिया वाहनों के उत्पादन को गति प्रदान की है। कुछ शुरुआती अड़चनों के बावजूद, 2017-18 में वाहन-ऋणों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हाल की अवधि में वाहन ऋण में वृद्धि थोड़ी कम हुई है जिससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बिक्री के संकेत मिलते हैं (चार्ट 11 बी)। अप्रैल 2017 से भारत IV² मानदंडों को अनिवार्य रूप से लागू करने और 2018 में नए बीमा मानदंडों को लागू किए जाने के बाद वाहन निर्माताओं ने बिक्री के लिए शेष वाहनों को बेचने के लिए कई उपाय किए जैसे छूट देकर और ऐसे वाहनों को उन बाजारों में भेजकर जहाँ पुराने मानक अभी भी लागू थे। जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होना ऑटोमोबाइल उद्योग के समक्ष एक और बाधा बनी जिसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल को

² भारत मानदण्ड उत्सर्जन नियंत्रण मानक हैं जो यूरोपीय विनियमन पर आधारित हैं। उनके अंतर्गत वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन का उपयोग करने वाले सभी उपकरणों द्वारा वायु प्रदूषक तत्व मुक्त करने की सीमाएं निर्धारित की गयी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा भारत के 13 शहरों में बीएस IV मानदंड अप्रैल 2010 से लागू कर दिए गए थे।

उपकर के परिवर्तनशील स्तरों सहित 28.0 प्रतिशत के उच्चतम स्लैब में रखा गया, हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद प्रभावी दरें अपेक्षाकृत कम हुईं जिसके फलस्वरूप कुछ मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) ने इससे हुए लाभ का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक भी पहुंचाया।

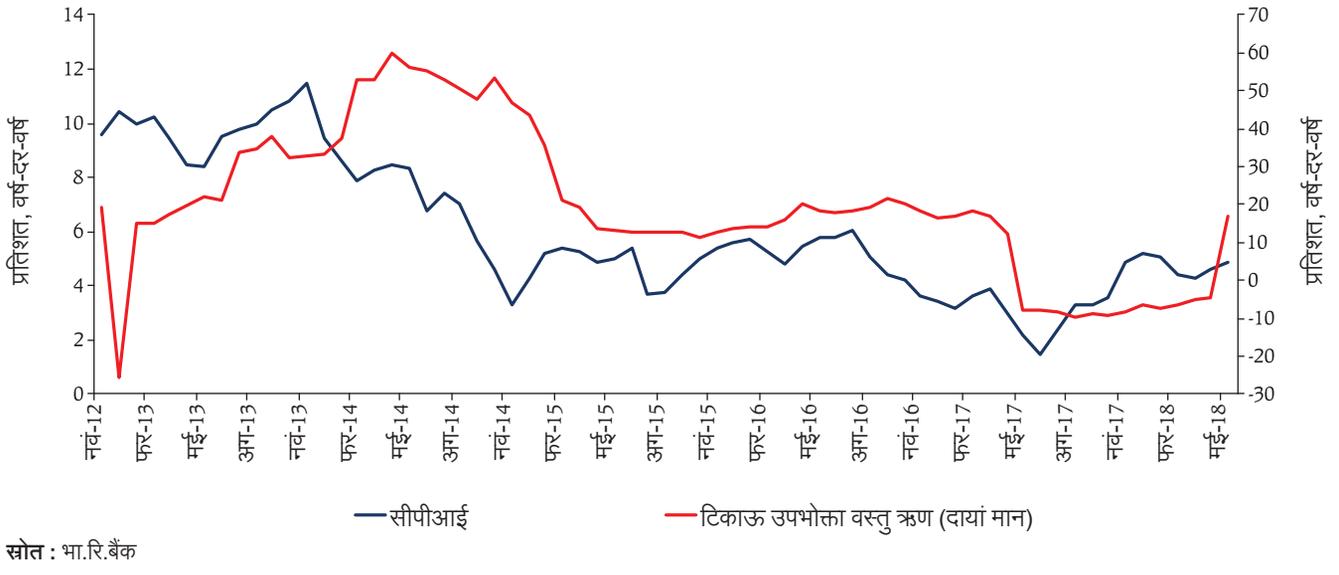
सी. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं

भारत में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के दोनों संविभागों- शहरी और ग्रामीण - में मध्यम वर्ग की बढ़ती आय के कारण मजबूती आने की क्षमता है। व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र को ऋण के कुल प्रवाह में इस क्षेत्र की भागीदारी मात्र 1.0 प्रतिशत है और 2017-18 के दौरान इसमें कमी आयी थी। 2014 में उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई में कमी आने के परिणामस्वरूप टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में 50% की वृद्धि दर्ज की गयी थी (चार्ट 12)। फिर भी, 2017-18 के दौरान इस क्षेत्र को दिए गए क्रेडिट में कमी आयी जिसका कारण जीएसटी लागू होने से उत्पन्न अनिश्चितता और एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे कुछ उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को माना जा सकता है।

IV. कुछ अनुभवजन्य निष्कर्ष

क्या क्रेडिट ग्रोथ और समष्टि वित्तीय चरों के बीच दीर्घकालिक संबंध है? अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह का आकलन एक स्वप्रतिगामी वितरित पश्चता (एआरडीएल) मॉडल द्वारा किया गया है क्योंकि चर एकीकरण के एक ही क्रम में नहीं हैं, अर्थात्, या तो आई (0) या आई (1)। इन मॉडलों का अनुमान न्यूनतम आकाइके सूचना मानदंड द्वारा निर्धारित पश्चता विस्तार के आधार पर किया गया था। इस प्रकार आकलित मॉडल त्रुटियों और मानदण्ड स्थिरता परीक्षणों के बीच किसी भी क्रमबद्ध सहसंबंध के लिए पश्चता परास गुणक परीक्षण की पुष्टि करते हैं। दीर्घकालिक मापदंड सह-एकीकृत संबंध से प्राप्त किया गया था। संरचनात्मक सुधार हेतु किए गए उपायों का प्रतिनिधित्व करने वाले छद्म चर, अर्थात् विमुद्रीकरण और जीएसटी और मौद्रिक नीति अनिश्चितता सूचकांक को बहिर्जात चर के रूप में शामिल किया गया था। खाद्येतर क्षेत्र को ऋण की वृद्धि दर जीविए में वृद्धि दर, ब्याज दर प्रसार (आईआरएसपीडी) के समनुरूप चलती थी - जो कि भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) और सावधि जमा दर - के अंतर से मापी जाती थी-, एससीबी की

चार्ट 12: मुद्रास्फीति और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं



जमा वृद्धि (डीईपीओएसआईटी) और कारोबार प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई)। ब्याज दर के प्रसार और खाद्येतर ऋण विस्तार के बीच सकारात्मक संबंध उच्च लाभ मार्जिन हो सकता है जिसके कारण बैंक अधिक से अधिक ऋण देने हेतु प्रेरित हुए। सकल एनपीए और कुल अग्रिमों का अनुपात (एनपीए) खाद्येतर ऋण की वृद्धि दर में प्रतिकूल संबंध था (संलग्न सारणी V)।

कृषि ऋण विकास दर (एजीआर_जीवीए) एवं कृषि में जीवीए की वृद्धि तथा एससीबी में जमा वृद्धि के बीच संबंध सकारात्मक हो गया जबकि इसके तथा उद्योग जगत में जीवीए (आईएनडी_जीवीए) में हुई वृद्धि और डब्लूएलएलआर के बीच संबंध नकारात्मक बना हुआ है (संलग्न सारणी VI)। कृषि क्षेत्र को ऋण और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बीच प्रतिकूल संबंध संभवतः प्रतिस्थापन प्रभावों के कारण है।

औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए क्रेडिट का अनुमान नियंत्रक चरों, यथा- उद्योग जगत में जीवीए (आईएनडी_जीवीए) में हुई वृद्धि, ब्याज दर, क्षमता उपयोग (सीयू) और सकल एनपीए अनुपात - ज़रिए लगाया गया था। अनुभवजन्य निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि क्षमता उपयोग और उद्योग जीवीए उद्योग जगत की ओर ऋण के प्रवाह के महत्वपूर्ण वाहक रहे हैं, जबकि उधार-दर और एनपीए अनुपात ने उद्योग जगत को ऋण के प्रवाह में बाधा पहुंचायी है (संलग्न सारणी VII)।

परिवहन ऑपरेटरों, पर्यटन, होटल और रेस्तरां और व्यापार (टीटीटीएच) जैसे उप-क्षेत्रों को ऋण तथा व्यापार, होटल, परिवहन और संचार (टीएचटीसी_जीवीए) की जीवीए वृद्धि, रेलवे माल दुलाई में वृद्धि (आरएआईएलएफ) तथा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री (सीवीसेल) में संबंध सकारात्मक रहा जबकि उधार-दरों के कारण क्रेडिट की मांग कमजोर होने की संभावना है। विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) में वृद्धि के कारण आने वाली विदेशी मुद्रा के चलते मिलने वाले राजस्व के कारण ऋण की मांग कम हो सकती है (संलग्न सारणी VIII)।

व्यावसायिक सेवा क्षेत्र, वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवासन (प्राथमिकता क्षेत्र आवास सहित) और एनबीएफसी द्वारा अचल संपत्ति अर्जन हेतु दिए जा रहे ऋण जैसे उप-क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों और जमाराशियों में वृद्धि, ऋण-जमा अनुपात एवं बीईआई के बीच सकारात्मक संबंध रहा जबकि डब्लूएलएलआर के साथ इनका संबंध नकारात्मक रहा (अनुबंध सारणी IX)।

संक्षेप में, अनुभवजन्य निष्कर्षों से पता चलता है कि ऋण-वृद्धि और समष्टि वित्तीय चरों के बीच दीर्घकालिक संबंध होता है। जहाँ एक ओर आर्थिक गतिविधियां, एससीबी में जमा-वृद्धि और कारोबारी अपेक्षाएं ऋण वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दरें और लंबे समय तक बनी रहने वाली अनर्जक आस्तियों से क्रेडिट की मांग कम हो जाती है।

V. निष्कर्ष

बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन पर आधारित आंकड़ों के विश्लेषण से अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह के संबंध में उपयोगी जानकारी मिलती है। वर्तमान में खुदरा ऋणों में वृद्धि की गति धीमी मालूम पड़ती है क्योंकि अधिकांश क्रेडिट प्रतिभूत है जबकि उद्योग जगत को ऋण-वृद्धि में बहाली आयी है और अब इसमें तेजी दिखने लगी है। जहाँ एनपीए के कारण कई प्रमुख क्षेत्रों को ऋण प्रवाह में कमी आयी है, वहीं क्षेत्र विशेष से जुड़े मुद्दों ने भी ऋण-प्रवाह की दिशा को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, अनुभवजन्य विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि उद्योगों को ऋण प्रवाह में वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कमी आयी है।

ऋण वृद्धि कई चक्रों में हुई है। हाल ही में आयी बहाली, जो 2017-18 की दूसरी छमाही के दौरान प्रारंभ हुई थी, 2018-19 में भी जारी है, और इसमें कई कारकों का योगदान है - अचल संपत्ति के सृजन में उछाल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर कम होता दबाव। उद्योगों के विभिन्न आकारों की दृष्टि से देखें तो, मध्यम और बड़े संविभागों में ऋण वृद्धि हाल के महीनों में धनात्मक स्तर पर रही लेकिन उनमें कोई उत्साह नहीं दिखा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण का प्रवाह अभी भी नगण्य बना हुआ है और इनमें भी ऋण वृद्धि संकुचन के दौर से गुजर रही है। कई नीतिगत प्रयास जैसे, बैंकों द्वारा ऋण संसाधन में तेजी लाकर, संपार्श्विक और ऋण गारंटियों से जुड़ी समुचित प्रणाली लागू करके सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को ऋण का प्रवाह बढ़ाया जा सकता है। कई मोर्चों पर नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है, यथा- कारोबारी सुगमता को और अधिक बढ़ाना, बैंकिंग क्षेत्र की एनपीए समस्या

का समाधान करके दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाना, रुकी हुई परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करना ताकि व्यापक आधार पर वसूली की जा सके।

संदर्भ

Bernanke, B. S. and Blinder, A. (1988), "Credit, Money and Aggregate Demand". *American Economic Review*. Vol.75, No.1, 435-439.

Brunner, K., and Meltzer, A. H. (1963), "The Place of Financial Intermediaries in the Transmission of Monetary Policy". *American Economic Review*, Vol. 53, No.2, 372-382.

Canales, R. and Nanda, R. (2012), "A Darker Side to Decentralized Banks: Market Power and Credit Rationing in SME Lending". *Journal of Financial Economics*, Vol. 105, 353-366.

Makinde, H.O. (2016), "Implications of Commercial Bank Loans on Economic Growth in Nigeria (1986-2014)". *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, Vol.7, No.3:124-136.

Yakubu, Z. and Affoi, A.Y. (2014), "An Analysis of Commercial Banks' Credit on Economic Growth in Nigeria". *Current Research Journal of Economic Theory*, Vol. 6, No.2, 11-15.

अनुबंध सारणी 1: बैंक ऋण के क्षेत्रवार नियोजन पर जारी आंकड़ें –देशवार प्रथाएँ

देश	क्षेत्र	आवधिकता
बांग्लादेश	कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, निर्यात और लघु और कुटीर उद्योग, वाणिज्यिक क्षेत्र	मासिक
भूटान	कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, विनिर्माण/उद्योग, वाणिज्य और व्यापार	मासिक
ब्राजील	उद्योग, ग्रामीण ऋण, वाणिज्यिक निजी क्षेत्र, हाउसहोल्ड, आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा आवास और ऋण	मासिक
भारत	कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, उद्योग, सेवाएँ, वैयक्तिक ऋण	मासिक
इंडोनेशिया	कृषि, खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन और सेवा क्षेत्र, बंधक	मासिक
मालदीव	कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, पर्यटन, व्यापार और संचार	मासिक
मैक्सिको	कृषि(पशुधन सहित), वाणिज्य, निर्माण, संचार और परिवहन, उद्योग(विनिर्माण), सेवाएँ	तिमाही
नेपाल	कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, विनिर्माण, बिजली, गैस और पानी, वित्त, बीमा और स्थावर संपदा	मासिक
पाकिस्तान	कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, एसएमई, वैयक्तिक ऋण, आवास, कॉर्पोरेट्स, ग्राहक, वाणिज्य और व्यापार	तिमाही
दक्षिण अफ्रीका	कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, खनन, विनिर्माण, ऊर्जा, निर्माण	तिमाही
स्विट्जरलैंड	कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन, सूचना और संचार, स्थावर संपदा, पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी क्रियाकलाप, प्रशासनिक और सहायक सेवाएँ	मासिक
थाईलैंड	गैर वित्तीय कारोबार, वित्तीय कारोबार, हाउसहोल्ड्स, वैयक्तिक उपभोग के लिए आवास ऋण(बंधक)	मासिक
ज़ाम्बिया	कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, खनन, विनिर्माण, ऊर्जा, निर्माण	तिमाही

स्रोत : केंद्रीय बैंक का वेबसाइट/ सांख्यिकी प्राधिकारी

अनुबंध सारणी II: विभिन्न क्षेत्रों में ऋण संवृद्धि

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

क्षेत्र	जून-17	सितं-17	दिसं-17	मार्च-18	अप्रै-18	मई-18	जून-18	सितं-18	अक्तू-18	नवं-18	दिसं-18
गैर खाद्य ऋण	4.8	6.1	10.0	8.4	10.7	11.1	11.1	11.3	13.4	13.8	12.8
कृषि गतिविधियां	7.5	5.8	9.5	3.8	5.9	6.4	6.5	5.8	8.0	7.7	8.4
उद्योग (सूक्ष्म, मझौले, और बड़े)	-1.1	-0.4	2.1	0.7	1.0	1.4	0.9	2.3	3.7	4.0	4.4
सूक्ष्म	0.5	1.7	7.2	0.9	0.3	0.2	0.7	-1.4	1.6	1.1	-0.9
मझौले	-8.1	-8.0	-9.7	-1.1	3.6	4.1	2.7	3.3	10.9	11.0	9.2
बड़े	-1.0	-0.4	1.9	0.8	1.0	1.5	0.8	2.9	3.8	4.2	5.1
सेवाएँ	4.7	7.0	14.7	13.8	20.7	21.9	23.3	24	27.4	28.1	23.2
परिवहन परिचालक	4.4	7.3	12.8	9.8	11.6	11.3	11.0	12.5	14.5	12.8	13.1
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-11.9	-0.9	-0.3	4.1	2.5	5.9	8.5	6.0	12.0	13.0	6.7
पर्यटन, होटल और रेस्तरां	-4.0	-3.9	-1.9	-2.7	3.1	3.3	1.4	1.0	5.5	4.5	5.6
नौवहन	-24.6	-23.2	-31.6	-24.7	-13.7	-11.7	-11.5	-12.1	-7.5	-15.4	-14.4
पेशेवर सेवाएँ	12.6	8.2	19.1	12.9	14.1	19.3	20.2	24.0	25.5	24.5	20.7
व्यापार	5.3	7.3	16.4	9.1	13.6	15.5	15.2	10.8	12.5	10.8	10.3
थोक व्यापार (खाद्य की सरकारी खरीद को छोड़कर)	4.5	3.6	13.3	6.2	11.7	16.3	14.6	11.8	13.0	10.8	10.6
खुदरा व्यापार	6.0	10.3	19.0	11.5	15.2	14.8	15.7	10.0	12.2	10.7	10.1
वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-3.3	2.9	2.6	0.1	1.6	3.3	5.2	-0.8	2.1	3.2	4.1
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	-1.2	4.4	14.3	26.9	29.5	30.0	35.4	41.5	55.6	57.2	55.1
अन्य सेवाएँ	14.0	12.5	21.3	15.9	36.7	36.6	36.5	37.9	35.6	39.2	23.7
व्यक्तिगत ऋण	14.1	16.8	18.9	17.8	19.1	18.6	17.9	15.1	16.8	17.2	17.0
आवास	11.4	12.8	14.2	13.3	14.9	15.5	15.8	15.6	17.6	16.8	17.1
मीयादी जमाराशि पर अग्रिम	-2.5	-1.6	-7.1	9.6	22.0	10.5	13.7	12.8	30.5	26.9	24.5
शेयर बॉन्डों आदि पर अग्रिम	-7.0	-3.6	21.8	17.0	4.9	7.5	8.3	10.6	11.3	9.4	6.9
क्रेडिट कार्ड बकाया	33.4	38.7	36.2	31.6	35.2	33.1	31.3	31.7	30.9	33.8	31.7
शिक्षा	1.8	1.1	-1.3	-0.5	-1.4	-0.8	-1.3	-4.0	-3.4	-3.5	-1.8
वाहन ऋण	9.7	9.2	9.3	11.3	9.9	10.4	11.1	9.4	9.1	9.9	8.8
अन्य व्यक्तिगत ऋण	28.0	37.0	44.5	35.3	35.5	32.2	27.5	21.6	22.1	24.7	23.8

टिप्पणी : 1. डाटा अनंतिम है और चुनिंदा बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत शामिल है।

2. टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस पर और <https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publication> पर भी उपलब्ध है।

स्रोत : भारिबैंक और लेखक द्वारा गणना।

अनुबंध सारणी III: हीट मैप - ऋण की संवृद्धि

क्षेत्र	नवंबर 17/ नवंबर 16	दिसंबर 17/ दिसंबर 16	जन 18/ जन 17	फर 18/ फर 17	मार्च 18/ मार्च 17	अप्रै 18/ अप्रै 17	मई 18/ मई 17	जून 18/ जून 17	जुला 18/ जुला 17	अग 18/ अग 17	सितंबर 18/ सितंबर 17	अक्तू 18/ अक्तू 17	नवंबर 18/ नवंबर 17	दिसंबर 18/ दिसंबर 17
गैर खाद्य ऋण	8.8	10.0	9.5	9.8	8.4	10.7	11.1	11.1	10.6	12.4	11.3	13.4	13.8	12.8
कृषि गतिविधियाँ	8.4	9.5	9.4	9.0	3.8	5.9	6.4	6.5	6.6	6.6	5.8	8.0	7.7	8.4
उद्योग (सूक्ष्म, मझौले, और बड़े)	1.0	2.1	1.1	1.0	0.7	1.0	1.4	0.9	0.3	1.9	2.3	3.7	4.0	4.4
इंफ्रास्ट्रक्चर	-2.3	-0.7	-2.9	-1.9	-1.7	-1.3	-0.7	0.0	2.2	4.3	4.7	8.0	8.9	9.2
मूल धातु और धातु - उत्पाद	1.0	0.1	0.0	-1.0	-1.2	-0.9	-3.6	-5.5	-8.3	-7.8	-7.9	-8.8	-8.2	-8.1
कपड़ा	4.6	7.6	9.5	7.9	6.9	5.1	5.6	5.5	4.2	2.5	1.3	1.7	1.8	-0.4
रसायन और रासायनिक उत्पाद	3.2	10.6	13.8	5.7	-5.5	-1.8	4.2	2.3	4.9	7.7	11.7	11.0	9.3	11.0
सेवाएँ	14.0	14.7	13.2	14.2	13.8	20.7	21.9	23.3	23.0	26.7	24.0	27.4	28.1	23.2
व्यापार	16.1	16.4	15.9	13.8	9.1	13.6	15.5	15.2	14.0	16.0	10.8	12.5	10.8	10.3
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	13.8	14.3	16.1	22.1	26.9	29.5	30.0	35.4	40.3	43.9	41.5	55.6	57.2	55.1
व्यक्तिगत ऋण	17.3	18.9	20.0	20.4	17.8	19.1	18.6	17.9	16.7	18.2	15.1	16.8	17.2	17
आवास (प्राथमिक क्षेत्र के आवास सहित)	13.1	14.2	15.2	16.5	13.3	14.9	15.5	15.8	16.5	17.0	15.6	17.6	16.8	17.1
वाहन ऋण	8.0	9.3	10.1	9.9	11.3	9.9	10.4	11.1	11.2	12.7	9.4	9.1	9.9	8.8

निम्नतर ऋण वृद्धि



उच्चतर ऋण वृद्धि



टिप्पणी : रंगीन वर्ण

स्रोत : भारिबैंक और लेखक द्वारा गणना।

सारणी IV: विभिन्न क्षेत्रों में ऋण की संवृद्धि

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

उद्योग	जून 17/ जून 16	सितं 17/ सितं 16	दिसं 17/ दिसं 16	मार्च 18/ मार्च 17	अप्रै 18/ अप्रै 17	मई 18/ मई 17	जून 18/ जून 17	जुला 18/ जुला 17	अग 18/ अग 17	सितं 18/ सितं 17	अक्तू 18/ अक्तू 17	नवं 18/ नवं 17	दिसं 18/ दिसं 17
खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	-3.5	-3.8	-2.3	19.7	6.4	22.5	22.2	24.6	30.1	29.8	32.3	31.8	24.9
खाद्य प्रसंस्करण	-0.7	0.6	11.6	6.8	5.6	5.2	3.3	1.4	1.8	2.2	4.2	1.3	2.8
चीनी	-20.1	-11.5	-5.4	-11.5	-13.3	-13.6	-7.0	-4.4	-7.0	-10.5	-7.5	-9.8	-7.8
खाद्य तेल और वनस्पति	-5.5	6.2	16.4	15.0	13.9	15.7	15.5	16.9	12.5	16.5	14.6	9.9	10.2
चाय	18.1	5.1	32.2	25.7	39.3	36.0	23.6	19.1	24.3	23.7	28.4	15.6	10.7
अन्य	8.1	3.7	15.7	10.9	9.4	8.4	3.3	-0.7	1.3	2.3	4.4	2.0	3.8
पेय पदार्थ और तंबाकू	-0.1	-4.5	-0.8	-9.7	-12.5	-7.7	-15.7	-22.1	-22.9	-16.4	-12.7	-15.9	-16.3
वस्त्र	-3.2	0.4	7.6	6.9	5.1	5.6	5.5	4.2	2.5	1.3	1.7	1.8	-0.4
सूती वस्त्र	-0.6	4.8	11.7	9.7	6.7	5.9	3.8	4.0	1.4	0.1	1.3	2.0	-0.2
जूट वस्त्र	14.1	23.1	22.4	-4.6	-0.3	1.8	-3.2	-25.2	-29.1	-24.7	-18.6	-12.5	-14.8
मानव-निर्मित वस्त्र	8.2	12.7	20.5	19.3	18.5	11.1	10.7	8.7	7.3	6.7	3.7	3.9	2.5
अन्य वस्त्र	-9.7	-8.3	-1.1	0.5	-0.4	3.7	6.5	4.3	3.7	2.3	2.4	1.3	-1.1
चमड़ा और चमड़ा - उत्पाद	0.6	3.3	8.4	5.7	8.3	6.3	4.8	5.1	5.4	2.6	4.4	3.7	-1.6
काष्ठ और काष्ठ - उत्पाद	-2.2	2.0	6.5	3.3	7.3	9.8	9.6	10.1	9.5	6.4	7.9	8.3	8.4
कागज़ और कागज़-उत्पाद	-6.5	-11.4	-8.8	-6.1	-7.1	-6.6	-4.5	-5.0	-3.8	-5.4	-2.1	-1.6	-3.2
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक ईंधन	0.3	-5.5	-4.0	9.4	16.0	19.7	21.8	5.9	10.8	18.5	9.5	15.1	20.7
रसायन और रासायनिक उत्पाद	-1.4	2.2	10.6	-5.5	-1.8	4.2	2.3	4.9	7.7	11.7	11.0	9.3	11.0
उर्वरक	8.6	-1.4	0.6	-8.6	16.9	16.8	-0.3	4.2	21.3	34.1	3.7	11.9	11.7
औषधि और दवाइयाँ	-18.2	-4.2	0.5	4.4	7.6	12.2	16.0	10.4	13.0	8.4	12.9	13.6	7.6
पेट्रो केमिकल्स	29.5	15.1	36.6	-23.7	-27.4	-18.9	-20.0	-15.6	-15.8	-8.8	-1.5	-8.3	4.5
अन्य	-10.5	0.5	7.6	8.1	8.5	14.1	13.5	21.2	18.4	23.6	25.9	20.8	20.9
रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	6.3	7.6	12.4	8.2	10.6	10.6	6.9	7.6	11.0	8.8	8.8	7.7	9.5
काँच और काँच के बर्तन	-9.6	-10.0	3.2	6.5	9.2	15.0	18.0	28.6	25.9	30.3	30.6	23.7	23.3
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	-7.7	3.3	-0.2	-3.1	-2.3	5.7	2.7	-4.8	-5.5	-10.4	-4.2	4.5	3.7
मूल धातु और धातु उत्पाद	-1.0	0.1	0.1	-1.2	-0.9	-3.6	-5.5	-8.3	-7.8	-7.9	-8.8	-8.2	-8.1
लोहा और इस्पात	2.3	3.6	3.4	2.2	1.0	-2.8	-6.5	-10.4	-9.2	-9.2	-10.6	-9.8	-9.3
अन्य धातुएँ और धातु उत्पाद	-10.9	-10.1	-9.8	-11.8	-7.3	-6.4	-2.2	-1.2	-2.9	-3.4	-2.6	-2.9	-3.6
सभी अभियांत्रिकी	-4.3	-1.7	3.0	3.8	4.4	4.8	4.3	4.3	6.0	3.8	4.6	5.1	6.7
इलेक्ट्रॉनिक्स	-15.6	-1.9	2.7	2.3	3.9	7.1	5.9	6.6	11.9	2.8	0.4	6.5	6.9
अन्य	-0.6	-1.7	3.0	4.2	4.5	4.2	3.8	3.7	4.4	4.1	5.9	4.7	6.6
वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	3.0	-2.6	2.0	7.0	3.8	0.5	6.0	6.0	6.7	9.1	10.6	10.2	10.8
रत्न और आभूषण	-0.8	4.0	0.7	5.3	-1.4	0.5	-1.3	0.1	-2.3	-3.7	-0.3	-0.2	-1.5
निर्माण	12.4	5.7	8.9	9.5	10.6	8.3	7.3	10.5	8.4	8.7	9.6	8.8	7.8
इन्फ्रास्ट्रक्चर	-2.5	-1.0	-0.7	-1.7	-1.3	-0.7	0.0	2.2	4.3	4.7	8.0	8.9	9.2
ऊर्जा	-1.6	-0.7	-1.5	-1.1	-0.8	-1.0	-1.2	0.4	1.6	1.1	3.5	5.4	5.3
दूरसंचार	-9.1	13.2	6.9	-0.6	4.2	5.3	6.8	9.5	10.5	5.5	12.6	6.6	6.0
सड़कें	-6.5	-6.5	-5.3	-7.5	-8.0	-4.9	-5.7	-5.4	0.0	1.6	3.6	6.8	9.8
अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	5.6	-2.9	4.9	3.7	2.8	2.9	8.7	16.8	18.9	26.0	32.9	29.9	28.7
अन्य उद्योग	5.1	-3.3	1.4	-4.2	-1.1	-2.4	-5.0	-11.0	-3.4	-1.8	-1.3	-2.5	-0.3
उद्योग	-1.1	-0.4	2.1	0.7	1.0	1.4	0.9	0.3	1.9	2.3	3.7	4.0	4.4

टिप्पणी : 1. डाटा अनंतिम है और चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों के उप क्षेत्र को दिए गए विस्तारित ऋण से संबंधित है।

2. टाइम सीरीज डाटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस पर और <https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publication> पर भी उपलब्ध है।

स्रोत : भारिबैंक और लेखक द्वारा गणना।

अनुबंध सारणी V: गैर खाद्य ऋण के लिए दीर्घकालिक एआरडीएल रिग्रेशन

व्याख्यात्मक चर	मॉडल : एआरडीएल (1, 0, 3, 0, 3, 4) आश्रित चर : गैर खाद्य ऋण वृद्धि (अवधि: 2008 की पहली तिमाही से 2018 की तीसरी तिमाही तक)	
	गुणांक	टी-सांख्यिकी
अचल	-253.47	-3.55***
जीवीए	0.44	2.48**
आईआरएसपीडी(-1)	7.17	2.22**
एनपीए(-1)	-0.50	-1.42
जमाराशियां(-1)	0.66	2.92***
बीईआई का लॉग	50.78	3.79***
आर ²		0.94
डीडब्ल्यू स्टैटिस्टिक्स		2.06
एफ-स्टैटिस्टिक्स बाउंड टेस्ट		5.58***
समायोजन की गति / कोइंट्रेशन पैरामीटर	-0.96	-6.38***

टिप्पणी : ***, ** तथा * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर का महत्व दर्शाते हैं।
स्रोत : लेखक का अनुमान।

अनुबंध सारणी VI: कृषि ऋण वृद्धि के लिए दीर्घकालिक एआरडीएल रिग्रेशन

व्याख्यात्मक चर	मॉडल : एआरडीएल (1, 4, 4, 3, 2) आश्रित चर : कृषि ऋण वृद्धि (अवधि : 2008 की पहली तिमाही से 2018 की तीसरी तिमाही तक)	
	गुणांक	टी-सांख्यिकी
अचल	24.64	2.65***
आईएनडी_जीवीए(-2)	-1.16	-4.21***
एजीआर_जीवीए(-1)	0.80	2.40**
डब्ल्यूएएलआर	-2.71	-2.13**
जमाराशियां(-1)	0.85	3.18***
आर ²		0.93
डीडब्ल्यू स्टैटिस्टिक्स		2.07
एफ-स्टैटिस्टिक्स बाउंड टेस्ट		9.18***
समायोजन की गति / कोइंट्रेशन पैरामीटर	-0.77	-7.39***

टिप्पणी : ***, ** तथा * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर का महत्व दर्शाते हैं।
स्रोत : लेखक का अनुमान।

अनुबंध सारणी VII: उद्योगों को ऋण के लिए दीर्घकालिक एआरडीएल रिग्रेसन

व्याख्यात्मक चर	मॉडल : एआरडीएल (1, 0, 3, 0, 0) आश्रित चर : उद्योगों को ऋण (अवधि: 2008 की पहली तिमाही से 2018 की तीसरी तिमाही तक)	
	गुणांक	टी-सांख्यिकी
अचल	-232.00	-2.03**
आईएनडी_जीवीए	0.17	0.80
लॉग ऑफ सीयू	117.17	2.56**
डब्ल्यूएएलआर	-4.13	-2.11**
एनपीए	-1.94	-4.12***
आर ²		0.96
डीडब्ल्यू स्टैटिस्टिक्स		2.01
एफ-स्टैटिस्टिक्स बाउंड टेस्ट		6.96***
समायोजन की गति / कोइंट्रेशन पैरामीटर	-0.51	-6.31***

टिप्पणी : ***,** तथा * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर का महत्व दर्शाते हैं।

स्रोत : लेखक का अनुमान।

अनुबंध सारणी VIII: परिवहन परिचालक, पर्यटन, होटल और रेस्तरां तथा व्यापार हेतु ऋण के लिए दीर्घकालिक एआरडीएल रिग्रेसन

व्याख्यात्मक चर	मॉडल : एआरडीएल (1, 1, 3, 1, 3, 3) आश्रित चर : टीटीटीएच को ऋण (अवधि: 2008 की पहली तिमाही से 2018 की तीसरी तिमाही तक)	
	गुणांक	टी-सांख्यिकी
अचल	0.59	0.03
टीएचटीसी_जीवीए	0.71	2.93***
डब्ल्यूएएलआर(-4)	-0.67	-0.30
आरएआईएलएफ	0.72	2.06*
सीवीएसएएलई (-3)	0.10	1.85*
एफटीए	-0.40	-1.95*
आर ²		0.91
डीडब्ल्यू स्टैटिस्टिक्स		2.21
एफ-स्टैटिस्टिक्स बाउंड टेस्ट		6.24***
समायोजन की गति / कोइंट्रेशन पैरामीटर	-0.66	-6.78***

टिप्पणी : ***,** तथा * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर का महत्व दर्शाते हैं।

स्रोत : लेखक का अनुमान।

अनुबंध सारणी IX : पेशेवर सेवाएँ, वाणिज्यिक स्थावर संपदा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, आवास और स्थावर संपदा को ऋण के लिए दीर्घकालिक एआरडीएल रिग्रेसन

व्याख्यात्मक चर	मॉडल : एआरडीएल (2, 3, 4, 2, 4) आश्रित चर : सेवाओं को ऋण (अवधि: 2008 की पहली तिमाही से 2018 की तीसरी तिमाही तक)	
	गुणांक	टी-सांख्यिकी
अचल	-430.91	-5.85***
डब्ल्यूएलआर	-9.07	-5.89***
जमाराशि	1.45	9.40***
सीडी_अनुपात	3.45	9.69***
बीईआई का लॉग(-1)	63.86	6.37***
आर ²		0.95
डीडब्ल्यू स्टैटिस्टिक्स		2.15
एफ-स्टैटिस्टिक्स बाउंड टेस्ट		15.36***
समायोजन की गति / कोइंट्रेशन पैरामीटर	-0.94	-9.64***

टिप्पणी : ***, ** तथा * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर का महत्व दर्शाते हैं।

स्रोत : लेखक का अनुमान

चलनिधि प्रबंधन का स्वरूप: 2018-19 के दौरान आए बदलाव*

मौद्रिक नीति की परिचालन पद्धति में मूलभूत बदलावों एवं पिछले दशक में बाज़ार को दुरुस्त करने के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 2018-19 में चलनिधि में आए बदलावों की समीक्षा दर्शाती है कि अंतर-बैंक कॉल मनी मार्केट में नीतिगत रिपो दर में किए गए परिवर्तनों को सुचारू रूप से अमल में लाया गया। प्रयोगसिद्ध निष्कर्ष, अल्पावधि वित्तीय बाज़ार स्पेक्ट्रम में नीति को अमल में लाने के लिए दर एवं मात्रा दोनों चैनलों की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं।

परिचय

केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि प्रबंधन आम तौर पर मौद्रिक नीति के परिचालनात्मक फ्रेमवर्क को दर्शाता है जो अल्पावधि मार्केट स्पेक्ट्रम में प्रचलित ब्याज दर को - जो परिचालन लक्ष्य है - नीतिगत ब्याज दर के रूप में खड़ा करते हुए ट्रान्समिशन का पहला चरण सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क में चलनिधि की स्थितियों का प्रगतिशील आकलन, बाज़ारों के साथ कुशल संप्रेषण, लिखत/तों का समुचित विकल्प और मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप चलनिधि परिचालन को अंजाम देना शामिल है। यद्यपि चलनिधि प्रबंधन का वित्तीय बाज़ारों पर अल्प-कालिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में खपत, निवेश एवं पूंजी निर्माण पर उसके असर के संदर्भ में प्रभाव चिरस्थायी है। इस दृष्टिकोण से साफ़ है कि केंद्रीय बैंक की चलनिधि प्रबंधन कार्यनीति दैनिक मौद्रिक नीति परिचालनों को, परिचालन लक्ष्य के जरिए, ब्याज दरों की मीयादी संरचना को प्रभावित करते हुए संपूर्ण समष्टिआर्थिक गतिविधियों से जोड़ती है (बिंदसील, 2004)।

मौद्रिक नीति के परिचालन के लिए कुशल चलनिधि प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, “प्लम्बिंग इन इट्स आर्किटेक्चर” (पात्रा,

* यह आलेख मौद्रिक एवं चलनिधि विश्लेषण प्रभाग, मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के इंद्रनील भट्टाचार्य, समीर रंजन बेहरा और भीमप्पा तलवार द्वारा तैयार किया गया है। इसमें व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं और वह भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाता।

और अन्य, 2016)। चलनिधि प्रबंधन के समक्ष मुख्य चुनौती यह है कि नीतिगत लिखत में परिवर्तनों को त्वरित एवं सहज रूप से परिचालन लक्ष्य में सतत आधार पर स्थानांतरित करना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार, केंद्रीय बैंक अपने रिज़र्व के लिए, बाज़ार में, आम तौर पर अंतर-बैंक बाज़ार में आपूर्ति की स्थितियों को प्रभावित करते हुए चलनिधि की स्थितियों को साथ-साथ व्यवस्थित करता है। चलनिधि प्रबंधन परिचालन की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह चलनिधि एवं बाज़ार की स्थितियों को आंकने और लिखतों को लाभकारी ढंग से प्रयोग करने में, अकेले एवं/या संयुक्त रूप से, कितनी भविष्यदर्शी है। परिणामस्वरूप, इन परिचालनों से रिज़र्व को नियंत्रण में रखा जाना, भुगतान और निपटान आर्किटेक्चर की अखंडता एवं सुचारू कार्यकरण तथा ब्याज दर संरचना का क्रमिक विकास सुनिश्चित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क 1999 से बदलती घरेलू एवं वैश्विक स्थितियों के प्रतिक्रियास्वरूप उत्तरोत्तर शोधन के जरिए विकसित हुआ है। 2011 से, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निर्धारित एकदिवसीय पुनः क्रय (रिपो) दर को औपचारिक रूप से एकल मौद्रिक नीति दर के रूप में तथा भारत औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) को मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य (आरबीआई, 2011) के रूप में घोषित किया गया है। चलनिधि प्रबंधन का लक्ष्य डब्ल्यूएसीआर को नीतिगत दर के साथ मिलाना है। इस फ्रेमवर्क की वैधता के साथ-साथ पूर्ण संस्थागत संरचना, जवाबदेही प्रक्रियाएं एवं संप्रेषण आवश्यकताओं को 2016 में संशोधित आरबीआई अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आरबीआई और भारत सरकार (जीओआई) के बीच हुए मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क करार (एमपीएफए) में दर्शाया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ फरवरी 2015 में आरबीआई के लिए मध्यमावधि में 4 प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) का मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करता है (पात्रा, 2017)। एमपीएफए आरबीआई के साथ मिलकर चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के संबंध में परिचालन पद्धति निर्दिष्ट करता है एवं उसमें समय-समय पर किए गए परिवर्तनों को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करता है। इस आवश्यकता को मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) के जरिए पूरा किया जाता है।

यह आलेख उन परीक्षाओं और मुसीबतों का समाधान करता है जिनका सामना आरबीआई को 2018-19 में करना पड़ा था और वह भी तब जब घरेलू चलनिधि स्थितियों को अधिशेष एवं घाटों के बीच बड़े एवं आकस्मिक उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ा था, जिसका कारण है, संयुक्त राज्य की मौद्रिक नीति का क्रमिक रूप से सामान्य होना, वैश्विक ब्याज दरों में दृढ़ता, भू-राजनीतिक गतिविधियों में अस्थिरता, व्यापार में तनाव की स्थिति एवं कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता। ऐसे में, चलनिधि प्रबंधन के उद्देश्यों को पूरा करने में आरबीआई के प्रदर्शन का एक विश्लेषणात्मक आकलन करने की जरूरत महसूस होती है। इस आकलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मुद्राओं में अत्यधिक अस्थिरता तथा घरेलू मुद्रा की मांग में असामान्य उछाल के संदर्भ में एक स्थायी चलनिधि का प्रबंध किया जाए जिसमें प्रचुर विदेशी मुद्रा के उपयोग पर जोर दिया जाए। आलेख के बाकी हिस्सों को चार भागों में विभाजित किया गया है। भाग 2 में वर्तमान चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई है। भाग 3 में वर्ष के दौरान के घटनाक्रम एवं अधिदेश की तुलना में नतीजों की चर्चा की गई है। भाग 4 में पालिसी इम्पल्स को परिचालन लक्ष्य में ट्रान्समिट करने के संबंध में प्रयोगसिद्ध मूल्यांकन किया गया है। अंतिम भाग में निष्कर्ष दिया गया है।

2. चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क का उद्भव

भारत में बदलते मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के अनुरूप मौद्रिक नीति की परिचालन पद्धति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अप्रैल 1999 में, अंतरिम चलनिधि समायोजन सुविधा (आईएलएएफ) शुरू की गई जिसके अंतर्गत भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर चलनिधि पेश की गई थी, लेकिन निर्धारित (रिवर्स) रिपो दर पर अवशोषित की गई थी। संपार्श्विक उधार सुविधा (सीएलएफ) के साथ-साथ एक अतिरिक्त संपार्श्विक उधार सुविधा (एसीएलएफ) की स्थापना की गई थी, जिसमें निर्यात ऋण पुनर्वित्त एवं प्राथमिक विक्रेताओं (पीडी) को चलनिधि समर्थन, सभी को बैंक दर के साथ जोड़ा गया है। जून 2000 में आईएलएएफ का एक संपूर्ण चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) में रूपांतरण हुआ।

एलएएफ शुरू करने के साथ ही चलनिधि प्रबंधन के दैनिक परिचालनों में एकदिवसीय मुद्रा बाजार दरों को संचालित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरा है। एलएएफ का परिचालन कार्य अक्टूबर 2004 से एकदिवसीय निर्धारित दर रिपो (चलनिधि पहुंचाने की दर) एवं रिवर्स रिपो (चलनिधि अवशोषण दर) के जरिए किया गया था ताकि मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप ब्याज दरों की मीयादी संरचना के विकास को राह दिखाई जा सके (पात्रा एवं कपूर, 2012)। एलएएफ चलनिधि प्रबंधन का एक मूल लिखत बन गया है जिसमें ब्याज दर का कॉरिडार (जिसमें रिपो दर अधिकतम सीमा है और रिवर्स रिपो दर न्यूनतम) इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि वह 100 आधार अंक से 300 आधार अंक के बीच घटती-बढ़ती रहती है। अप्रैल 2004 में, एक अतिरिक्त लिखत के रूप में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) शुरू की गई थी ताकि एलएएफ को शुद्धिकरण कार्य के भार से मुक्त किया जा सके (मोहन, 2006)।

बाद के वर्षों में, सक्रिय नीति दर, रिपो एवं रिवर्स रिपो दरों के बीच बारी-बारी से बदलती रही जो मुद्रा बाजार में चलनिधि की स्थितियों - घाटा एवं अधिशेष पर निर्भर करती है और परिणामस्वरूप वह पूंजी अंतर्वाहों/ बहिर्वाहों में आकस्मिक उतार-चढ़ावों से प्रभावित थी। ऐसी उतार-चढ़ाव वाली चलनिधि स्थितियों से मांग मुद्रा दर के संचलनों में अत्यधिक अस्थिरता पैदा होती है, जो प्रायः, या तो उस दायरे की अधिकतम सीमा को पार कर जाती है या न्यूनतम सीमा के नीचे रह जाती है। तदनुसार, मई 2011 में परिचालन फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया था। मौद्रिक नीति के संवेगों के कुशल ट्रान्समिशन के लिए प्रणाली को घाटे में रखने के आधार पर रिपो दर को एकल स्वतंत्र परिवर्तनीय नीति दर बनाया गया ताकि नीति के संकटों को ट्रान्समिट किया जा सके (आरबीआई 2011)।¹ सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) शुरू की गई जिसके अंतर्गत बैंक अपने विवेक पर रिपो दर से 100 बेसिस प्वाइंट्स (बीपीएस) अधिक पर सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में 1 प्रतिशत तक की कटौती करते हुए एकदिवसीय उधार ले सकते हैं ताकि चलनिधि संबंधी अप्रत्याशित सदमों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच की व्यवस्था की जा सके (पात्रा एवं अन्य, 2016)। कॉरिडार को पुनः परिभाषित करते हुए एक-सा किया गया जिसमें उसका दायरा 200बीपीएस निर्धारित किया गया। रिपो दर को कॉरिडार के मध्य में रखा गया जबकि रिवर्स रिपो दर एवं एमएसएफ को क्रमशः 100बीपीएस नीचे एवं 100 बीपीएस ऊपर रखा गया।

¹ तथापि, इसका नतीजा यह निकला कि नीति में उदारता बरतने के चरण में नीति दर में कटौती का ट्रान्समिशन अधूरा रह जाता है (पात्रा एवं अन्य, 2016)।

फिर भी, वैश्विक वित्तीय संकट के तुरंत पश्चात इस फ्रेमवर्क की कई कमियां सामने आईं और वह भी विशेष रूप से मई 2013 के टेपर टैन्ट्रम के दौरान। मौद्रिक नीति के फ्रेमवर्क में संशोधन करने एवं उसको सुदृढ़ बनाने को लेकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आरबीआई को मुद्रा बाजार के एकदिवसीय पहलू पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहिए जिसके लिए एकदिवसीय रिपो पर जोर देने के बजाय भिन्न-भिन्न अवधि के मीयादी रिपो के जरिए चलनिधि प्रबंधन परिचालन किए जाने चाहिए। तदनुसार, समिति ने परिचालन फ्रेमवर्क में सुधार तथा उसके डिजाइन में परिवर्तन की सिफारिश की जो लिखतों के उपयोग के मामले में लचीला हो लेकिन मौद्रिक नीति के संपूर्ण उद्देश्यों के अनुकूल हो। संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के कुछ तत्वों को सितंबर 2014 में शामिल किया गया था।

इस फ्रेमवर्क में किया गया महत्वपूर्ण परिवर्तन था निर्धारित एलएएफ रिपो दर पर चलनिधि जरूरतों की असीमित सुविधा को समाप्त करना। संशोधित फ्रेमवर्क के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं: (i) मीयादी रिपो नीलामियों के जरिए केन्द्रीय बैंक की चलनिधि के प्रमुख भाग का प्रावधान; (ii) इन्ट्रा-डे से 28 दिनों की परिपक्वता वाली रिपो/ रिवर्स रिपो नीलामियों के जरिए परिचालनों को दुरुस्त करने की शुरुआत जिसमें सतत आधार पर चलनिधि का आकलन किया जाए; (iii) निर्यात ऋण पुनर्वित्त को समाप्त करना; और (iv) सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में उत्तरोत्तर कटौती।

इस प्रकार, चलनिधि नियंत्रण, पूर्व के फ्रेमवर्क की अपेक्षा बहुत कुछ आरबीआई के विवेक पर रह गया। चलनिधि प्रावधान के मुख्य लिखत – 14-दिन के मीयादी रिपो – को रिजर्व को बनाए रखने की अवधि के समकाल किया गया है जिससे बाजार के प्रतिभागी केन्द्रीय बैंक की चलनिधि को अपेक्षाकृत रूप से अधिक अवधि के लिए धारण कर सकते हैं। इससे अंतरबैंक बाजार के मीयादी मुद्रा खंड में उधार देने में सुविधा होगी और मीयादी लेनदेनों के लिए बाजार खंड एवं बेंचमार्क विकसित होने का आसार है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मीयादी रिपो, आरबीआई पर बाजार प्रतिभागियों की नकदी/ ट्रेजरी प्रबंधन संबंधी निष्क्रीय निर्भरता को दूर करता है।²

अप्रैल 2016 में मौद्रिक नीति के रुख में उदारता को देखते हुए चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क को और दुरुस्त किया गया। रिजर्व बैंक ने यह संकेत भी दिया कि वह आवश्यकतानुसार आरिस्त क्रय व विक्रय के जरिए साल भर में स्थायी चलनिधि³ की आपूर्ति में सहजता लाएगा। 2017-18 के दौरान, चलनिधि प्रबंधन परिचालनों का मूल लक्ष्य, मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप, प्रणाली की चलनिधि में परिवर्तन करते हुए उसे अधिशेष की स्थिति से तटस्थता के करीब लाना था। चलनिधि में पूरे साल अधिशेष की स्थितियां बनी रहने की आशंका के मद्देनजर रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 2017 में चलनिधि के संबंध में पहले से ही मार्गदर्शन दिया गया, जब उसके द्वारा यह संकेत दिया गया कि वह (i) रिवर्स रिपो की नीलामी परिवर्तनीय दर पर करेगा जिसमें दीर्घ परिपक्वता काल को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि विमुद्रीकरण पश्चात की बची अधिशेष चलनिधि को खपाया जा सके; (ii) बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत ट्रेजरी बिल (टी-बिल) एवं दिनांकित प्रतिभूति जारी करेगा जिससे अन्य स्रोतों से आने वाली चलनिधि को नियंत्रित किया जा सके; (iii) भारत सरकार (जीओआई) के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुरूप समुचित परिपक्वता काल के नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी) जारी करेगा ताकि सरकारी परिचालनों की बंदौलत हुए चिरस्थायी अधिशेष को नियंत्रित किया जा सके; (iv) प्रणाली स्तर की चलनिधि को तटस्थता की ओर ले जाने की दृष्टि से खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) करेगा ताकि स्थायी चलनिधि को नियंत्रित किया जा सके; और (v) परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो/ रिपो परिचालनों को दुरुस्त करेगा जिससे दैनंदिन चलनिधि को नियंत्रित किया जा सके (आरबीआई, 2018)। इसके अतिरिक्त, मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क में संशोधन और उसे सुदृढ़ करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप नीतिगत दर के कॉरिडार की चौड़ाई को एक-समान तरीके से अप्रैल 2016 में 100बीपीएस से घटाते हुए अप्रैल 2017 में 50बीपीएस कर दिया था। तदनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिवर्स रिपो दर को नीतिगत रिपो दर से 25बीपीएस कम रखा गया था, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को नीतिगत रिपो दर से 25बीपीएस अधिक रखा गया था। परिणामस्वरूप, मांग मुद्रा बाजार में अस्थिरता (मानक विचलन) 2016-17 में 0.19 से घटकर 2017-18 में 0.10 रह गई, वहीं कुल एकदिवसीय बाजार की मात्रा लगभग अपरिवर्तित रही।

² मीयादी रिपो बाजार में अंतर्निहित चलनिधि स्थितियों के कुशल संकेतक भी हैं।

³ अर्थव्यवस्था में ऐसी चिरस्थायी चलनिधि जो मौद्रिक नीति के रुख में मददगार होते हुए वृद्धि में सहायक होगी (आरबीआई, 2016)।

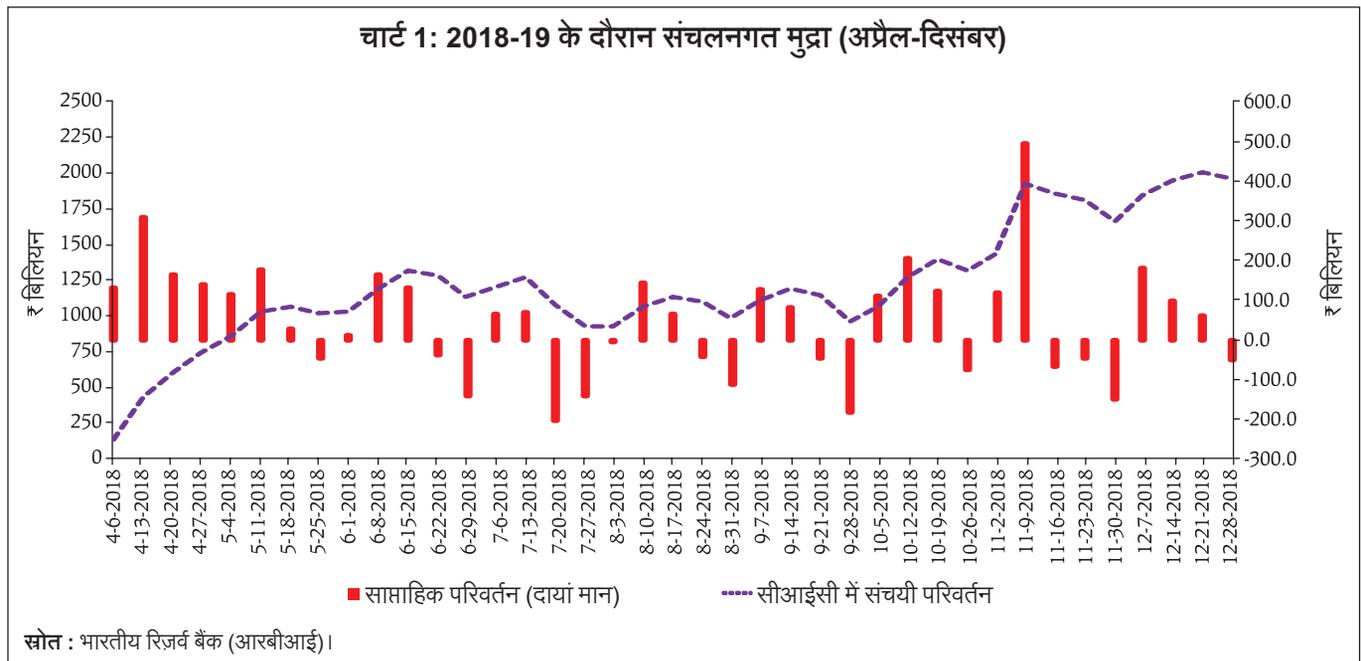
अनेक विनियामकीय परिवर्तनों की बदौलत 2018-19 के दौरान चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में और सुविधा हुई। वित्तीय बाज़ार की स्थितियों के आकलन के आधार पर, आरबीआई ने चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाया (एफएएलएलसीआर) जिससे बैंकों को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के अनुसार उपलब्ध सांविधिक चलनिधि अनुपात (एलएलआर) दिसंबर 2018⁴ तक घटकर 15.5 प्रतिशत रह गया। एफएएलएलसीआर में वृद्धि से प्रत्येक बैंकों की रिपो बाज़ार से उच्च-गुणवत्ता वाले संपार्श्विक के बदले में चलनिधि, यदि आवश्यकता हो, प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे, समय के साथ-साथ, वित्तीय प्रणाली में चलनिधि के संवितरण में सुधार आया। इसके अतिरिक्त एसएलआर को एलसीआर आवश्यकताओं के अनुरूप करने की दृष्टि से दिसंबर 2018 में यह प्रस्ताव रखा गया कि एसएलआर में प्रत्येक कैलन्डर तिमाही में 25बीपीएस की कटौती की जाए - इस प्रकार की पहली कटौती जनवरी 2019 से प्रारंभ होने वाली तिमाही में अमल में लाई गई - जब तक कि एसएलआर एनडीटीएल का 18 प्रतिशत नहीं हो जाता। इतना ही नहीं, ओएमओ नीलामियों के संबंध में किसी माह हेतु निर्धारित परिचालनों की मात्राओं का उल्लेख करते हुए अग्रिम समय-सारणी जारी करने के जरिए पूर्व मार्गदर्शन प्रदान करने से

बाज़ार की प्रत्याशाओं को अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क में इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में यह आवश्यक है कि अगले भाग में 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान आए बदलावों का विश्लेषण किया जाए।

3. 2018-19 के दौरान चलनिधि में आए बदलाव

ए. चलनिधि के संचालक एवं उसका प्रबंधन

2018-19 की पहली तीन तिमाहियों में प्रणालीगत चलनिधि में महत्वपूर्ण बदलाव आए जो वित्त बाज़ार की घरेलू एवं वैश्विक स्थितियों को दर्शाता है। वैश्विक व्यापार में तनाव की बढ़ती आशंका एवं संयुक्त राज्य की मौद्रिक नीति आशा से अधिक तेजी से सामान्य होने के परिणामस्वरूप वर्ष के प्रारंभ से पूंजी बहिर्वाह होने लगा जिसके कारण घरेलू मुद्रा पर मूल्यहास का दबाव आया। परिणामतः, आरबीआई को विदेशी आस्तियां बेचनी पड़ीं जिसके कारण घरेलू चलनिधि कम हो गई (अनुबंध सारणी 1)। मुद्रा में बड़ा विस्तार, जो वित्तीय प्रणाली से चलनिधि के रिसाव को दर्शाता है, 2018-19 के दौरान की विशेषता बनी रही जिससे प्रणाली स्तर की चलनिधि पर दबाव और तीव्र हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, दीवाली के दौरान (7 नवंबर 2018), संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में साप्ताहिक विस्तार रुपये 494 बिलियन पर अप्रत्याशित था (चार्ट 1)।



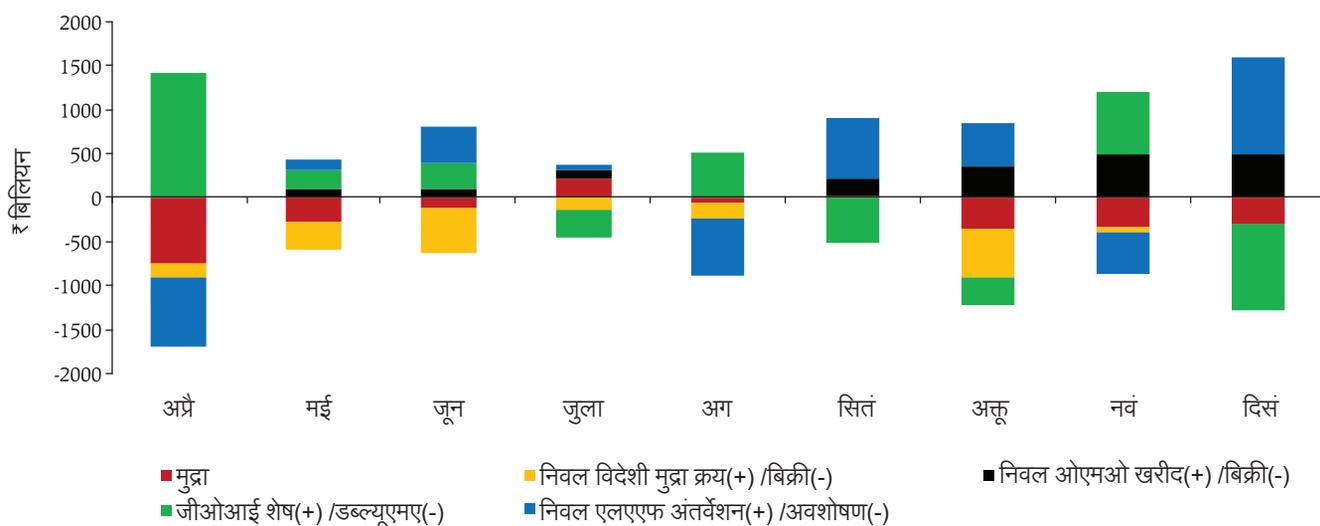
⁴ इसमें एफएएलएलसीआर (13 प्रतिशत), एमएसएफ (2 प्रतिशत) एवं बैंक द्वारा गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को प्रदान की जाने वाली वृद्धिशील बकाया ऋण राशि के समतुल्य धारित सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो एनबीएफसी एवं एचएफसी को प्रदान की जाने वाली ऋण राशि के अतिरिक्त है और जो 19 अक्टूबर 2018 को यथास्थिति उनकी बहियों में बकाया है तथा बैंक के एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक सीमित है।

2018-19 की पहली तीन तिमाहियों में प्रणालीगत चलनिधि में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखते हुए यह उपयोगी होगा कि वर्ष के दौरान त्रैमासिक बदलावों को लेकर आत्मविश्लेषण किया जाए। 2018-19 की पहली तिमाही में, चलनिधि स्थितियां सामान्यतः अधिशेष में रहीं, जो अप्रैल में केंद्र द्वारा राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राप्तियों के अंतरण एवं जून 2018 तक अधिकाधिक खर्च करने के अधिकार को दर्शाता है। प्रणाली में परिणामी चलनिधि प्रवाह (अप्रैल में रु.1.4 ट्रिलियन) चलनिधि में दो स्वायत्त कारणों⁵ – माह के दौरान मुद्रा में रु.743 बिलियन विस्तार और रु.140 बिलियन की विदेशी मुद्रा बिक्रियों - से आई कमी की अच्छी खासी भरपाई करता है। मई और जून में विदेशी मुद्रा की बिक्रियों का अनुपात बढ़ा एवं मुद्रा में विस्तार सामान्य मौसमी उछाल की अपेक्षा अधिक रहा, परिणामस्वरूप प्रणाली में जून के मध्य से जुलाई 2018 की संक्षिप्त अवधि के लिए चलनिधि घाटे में रहा (जो अग्रिम कर बहिर्वाह की वजह से और बढ़ गया)। तदनुसार, आरबीआई ने चलनिधि में तंगी को काबू में करने के लिए नियमित 14-दिवसीय रिपो के अतिरिक्त विभिन्न परिपक्वता काल के परिवर्तनीय दर रिपो के जरिए प्रणाली में चलनिधि डाला। इसके अलावा, आरबीआई ने प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि डालने के लिए मई और जून 2018 में प्रत्येक

रु.100 बिलियन के दो ओएमओ की खरीद की (चार्ट 2)। संपूर्ण रूप से, एलएएफ के अंतर्गत निवल चलनिधि अवशोषण अप्रैल में रु.496 बिलियन की औसत दैनिक निवल स्थिति से उत्तरोत्तर रूप से घटकर जून में रु.140 बिलियन रह गया।

2018-19 की दूसरी तिमाही में, चलनिधि में वृत्ताकार की स्थिति पाई गई। जुलाई में, सरकारी खर्चों में कमी (विशेषतः उत्तरार्ध में) एवं आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्रियों की वजह से एलएएफ के अंतर्गत रु.107 बिलियन की औसत दैनिक निवल चलनिधि डालना अनिवार्य हो गया; साथ ही माह के दौरान रु.100 बिलियन राशि की ओएमओ खरीद करनी पड़ी। केन्द्र का खर्चा बढ़ जाने से प्रणाली अगस्त में अवशोषण अवस्था में लौट गई जिसे आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) का भी सहारा लेना पडा, यद्यपि अप्रत्यक्ष कर भुगतान ने चलनिधि आधिक्य को संक्षिप्त अवधि के लिए कम कर दिया था। माह के दौरान आरबीआई ने औसत दैनिक निवल आधार पर रु.30 बिलियन का अवशोषण किया, वहीं प्रणालीगत चलनिधि अगस्त 20 से 30 के बीच घाटे में चली गई जिसके चलते प्रणाली में चलनिधि डालना अनिवार्य हो गया। 31 अगस्त से 10 सितंबर के दौरान प्रणाली अधिशेष की स्थिति में लौट गई थी क्योंकि माह के उत्तरार्ध में सरकारी खर्चें बढ़ गए थे, फिर भी, अग्रिम कर बहिर्वाहों

चार्ट 2: 2018-19 के दौरान चलनिधि के संचालक एवं उसका प्रबंधन



स्रोत : आरबीआई।

⁵ चलनिधि के स्वायत्त संचालक हैं – मुद्रा प्राधिकार एवं बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक के नियमित कार्यों की बदौलत बैंकों को उपलब्ध प्राथमिक चलनिधि। विशिष्ट स्वायत्त कारक हैं - संचलन में बैंक नोट, विदेशी मुद्रा आस्तियां एवं सरकारी जमा राशियों की मात्रा। ये केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र की मदद हैं जो किसी ऋण संस्थाओं की चालू खाता धारिताएं नहीं हैं।

की वजह से प्रणाली की चलनिधि घाटे में चली गई। आरबीआई ने टिकाऊ चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सितंबर के उत्तरार्ध में रु.200 बिलियन की दो ओएमओ खरीद के साथ-साथ एलएएफ के अंतर्गत प्रणाली में रु.406 बिलियन की दैनिक निवल चलनिधि डाली। प्रणालीगत चलनिधि में दैनिक अधिशेष को काबू में करने के लिए आरबीआई द्वारा परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो नीलामी की जाती है और चलनिधि में कदाचित व अनित्य घाटों की पूर्ति के लिए नियमित 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर मीयादी रिपो एवं अन्य परिपक्वता काल का सहारा लिया जाता है (चार्ट 3)।

2018-19 की तीसरी तिमाही में, चलनिधि स्थितियां आम तौर पर घाटे में रहीं। अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से, त्योहार के चलते मुद्रा की अत्यधिक मांग एवं आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्रियों, दोनों के परिणामस्वरूप प्रणालीगत चलनिधि घाटे में चली गई जो उस माह में बाकी दिनों में भी जारी रहा। केंद्र द्वारा खर्च में वृद्धि करने की वजह से नवंबर की शुरुआत में घाटा कम हो गया, लेकिन वह बाद में बढ़ गया क्योंकि त्योहार के मौसम में मुद्रा विस्तार में स्थिरता आ गई थी और उसमें दिसंबर के उत्तरार्ध में वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण था। चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आरबीआई ने विभिन्न परिपक्वता काल की परिवर्तनीय दर रिपो नीलामी की जिसमें नियमित 14-दिवसीय रिपो के अतिरिक्त दीर्घावधि (28 दिन एवं 56 दिन) नीलामी शामिल

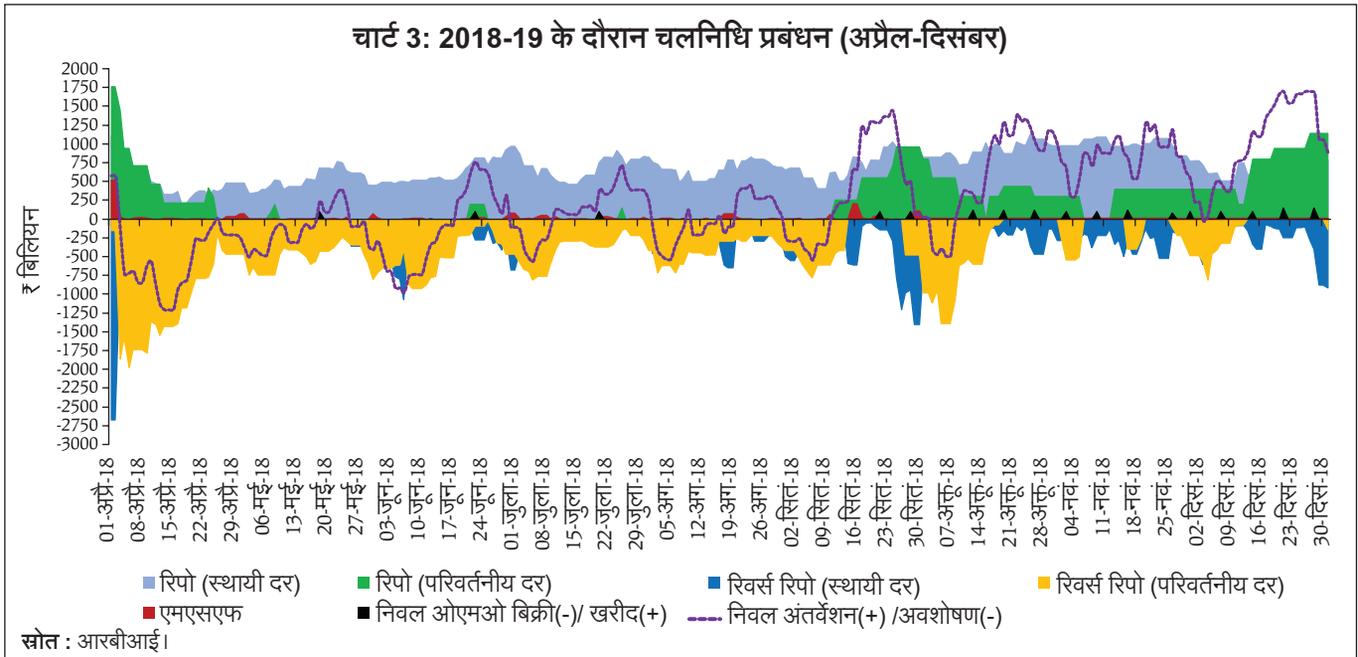
सारणी 1: 2018-19 के दौरान ओएमओ खरीद की नीलामियां
(अप्रैल-दिसंबर)

(रु बिलियन)			
नीलामी की तारीख	राशि	माह-वार	तिमाही
मई 17, 2018	100	मई - 100	
जून 21, 2018	100	जून - 100	ति1 - 200
जुलाई 19, 2018	100	जुलाई - 100	
सितंबर 19, 2018	100	सितंबर - 200	ति2 - 300
सितंबर 27, 2018	100		
अक्तूबर 11, 2018	120		
अक्तूबर 17, 2018	120	अक्तूबर - 360	
अक्तूबर 25, 2018	120		
नवंबर 01, 2018	100		
नवंबर 06, 2018	100	नवंबर - 500	ति3 - 1,360
नवंबर 15, 2018	120		
नवंबर 22, 2018	80		
नवंबर 29, 2018	100		
दिसंबर 06, 2018	100		
दिसंबर 13, 2018	100	दिसंबर - 500	
दिसंबर 20, 2018	150		
दिसंबर 27, 2018	150		
कुल (17 नीलामियां)	1,860	1,860	1,860

स्रोत: आरबीआई।

हैं। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर में ओएमओ के जरिए प्रणाली में रु.360 बिलियन की टिकाऊ चलनिधि डाली गई जिसे तत्पश्चात बढ़ाकर नवंबर और दिसंबर दोनों में रु.500 बिलियन कर दिया गया था। इस प्रकार तिमाही के दौरान प्रणाली में रु.1.36 ट्रिलियन कुल टिकाऊ चलनिधि डाली गई (सारणी 1)।

चार्ट 3: 2018-19 के दौरान चलनिधि प्रबंधन (अप्रैल-दिसंबर)



आरबीआई द्वारा परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो नीलामी भी की गई ताकि चलनिधि आधिक्य के छिटपुट उदाहरणों को समाप्त किया जा सके।

संक्षेप में कहें तो, 2018-19 में आरबीआई का विदेशी मुद्रा परिचालन एवं मुद्रा विस्तार बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि के मुख्य संचालक साबित हुए, जबकि सरकारी खर्चों में उतार-चढ़ाव चलनिधि के संचलनों में संघर्ष का मुख्य कारण था। परिणामस्वरूप, निवल एलएएफ स्थितियां वर्ष के दौरान सरकार के नकदी शेष में संचलन दर्शाती हैं (चार्ट 4)। जून माह से सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) एवं ओवरड्राफ्ट (ओडी) के जरिए किए गए खर्चों का असामान्य स्तर एवं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए निवल एलएएफ स्थितियों में उतार-चढ़ाव 2018-19 के दौरान चलनिधि के बदलते परिदृश्य को स्पष्ट करते हैं (सारणी 2)। सरकार की प्राप्तियां और भुगतान आपस में अस्थायी रूप से बेमेल होने के कारण उसे ठीक करने के लिए अप्रैल-दिसंबर के दौरान सीएमबी का छह बार सहारा लिया गया, जो कुल मिलाकर रु.1.3 ट्रिलियन होता है। प्रणाली में दीर्घ परिपक्वता काल (21, 28 और 56 दिनों) की अत्यधिक मात्रा में चलनिधि डालना 2018-19 में चलनिधि प्रबंधन की एक और निर्धारक विशेषता थी, जबकि उपयोग करने की बारंबारता के लिहाज से चलनिधि के अवशोषण के लिए 7 दिन के परिपक्वता वाले रिवर्स

सारणी 2: 2018-19 के दौरान महत्वपूर्ण चलनिधि संकेतक
(दिनों की संख्या*)

माह	निवल एलएएफ		जीओआई नकदी शेष	
	घाटा	अधिशेष	डब्ल्यूएमए/ओडी	अधिशेष
अप्रैल	1	18	0	19
मई	5	17	4	18
जून	10	11	17	4
जुलाई	16	6	16	6
अगस्त	10	10	14	6
सितंबर	12	6	9	9
अक्तूबर	17	4	12	9
नवंबर	18	0	14	4
दिसंबर	19	1	7	13

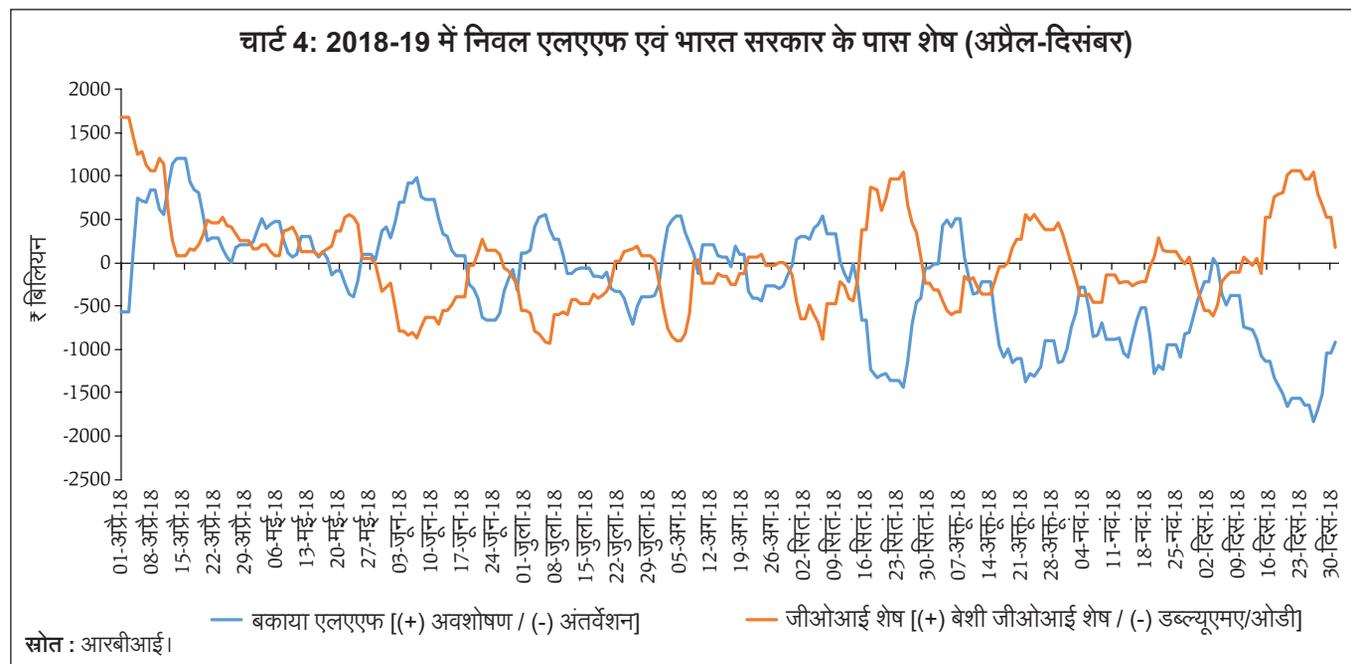
*: कार्य दिवस, शनिवार को छोड़कर।

स्रोत : मुद्रा बाजार परिचालनों के संबंध में दैनिक प्रेस विज्ञप्ति एवं आरबीआई अभिलेख।

रिपो लिखत को प्राथमिकता दी गई थी – अवशोषण के लिखतों के लिए अपेक्षाकृत रूप से कम परिपक्वता अवधि, हालांकि अधिशेष चलनिधि की उन घटनाओं के महत्व को दर्शाना विशेष नहीं था (सारणी 3)।

चलनिधि स्थितियों का उद्भव एवं आरबीआई द्वारा उसके प्रबंधन की जानकारी बैंक रिजर्व के संचलन से प्राप्त किया जा सकता है। बैंक रिजर्व के लिए बाजार का उद्भव मुख्य रूप से केन्द्रीय बैंक और निक्षेपागार संस्थाओं के बीच सक्रिय पारस्परिक क्रिया से होता है। यदि चलनिधि के स्वायत्त संचालकों की वजह से

चार्ट 4: 2018-19 में निवल एलएएफ एवं भारत सरकार के पास शेष (अप्रैल-दिसंबर)



सारणी 3: परिवर्तनीय दर नीलामियों के जरिए परिचालनों को दुरुस्त करना (अप्रैल-दिसंबर)

	रिपो (परिपक्वता)						रिवर्स रिपो (परिपक्वता)							
	7	8	14	21	28	56	2	3	4	6	7	11	13	14
बारंबारता (दिनों की संख्या)	3	1	1	2	3	2	3	7	5	2	95	1	1	13
औसत मात्रा (₹ बिलियन)	165	250	142	325	250	225	456	344	249	186	140	41	26	44

स्रोत : आरबीआई।

चलनिधि में आई कमी की आपूर्ति चलनिधि प्रबंधन उपायों के जरिए पूरी तरह से नहीं की जाती है तो वह या तो बैंक रिज़र्व में गिरावट या संचयन में दिखाई देता है। चलनिधि संचालकों की विश्लेषणात्मक संवीक्षा एवं 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) में उसका प्रबंधन रोचक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। पहली तिमाही के दौरान (1 अप्रैल से 29 जून 2018), स्वायत्त संचालकों के कारण चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के जरिए जितनी चलनिधि डाली गई थी उससे भी अधिक आहरित की गई, तदुपरांत घाटे की आपूर्ति के लिए बैंक रिज़र्व का एक बड़ा हिस्सा आहरित किया गया (सारणी 4)। एलएएफ के अंतर्गत रिपो एवं साथ ही ओएमओ खरीद के जरिए बड़ी राशि डालने की वजह से तीसरी तिमाही में बैंकिंग प्रणाली में अत्यधिक चलनिधि डाली गई, जो बैंक रिज़र्व के संचयन में दिखाई देता है। अतः,

बैंक रिज़र्व (अप्रैल-दिसंबर) की समग्र छवि वर्ष के दौरान चलनिधि संचालनों का रहस्य खोलने में कुछ-कुछ भ्रामक हो सकती है।

बी. परिचालन लक्ष्य एवं कुशलता

चलनिधि प्रबंधन की प्रभावशीलता इस यथार्थ में निहित है कि डब्ल्यूएसीआर – जो एक परिचालन लक्ष्य है –को एलएएफ कॉरिडार के अंतर्गत नीतिगत रिपो दर के साथ जोड़ा जा सके। 2018-19 के दौरान (अप्रैल-दिसंबर), डब्ल्यूएसीआर आम तौर पर रिपो दर से नीचे रहा जबकि चलनिधि की स्थितियां अधिशेष और घाटे की स्थितियों के बीच डोलती रहीं (चार्ट 5)।

डब्ल्यूएसीआर संचालनों की एक उल्लेखनीय विशेषता थी कि उसने 2018-19 की पहली तिमाही में अधिशेष की स्थितियां

सारणी 4: चलनिधि और बैंक रिज़र्व **

{(+) अंतर्वेशन/(-) बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि का अवशोषण}

(₹ बिलियन)

	अप्रैल 1- जून 29	जून 29-सितं 28	सितं 28-दिसं 28	कुल
	(1)	(2)	(3)	4 = (1+2+3)
ए. चलनिधि के स्वायत्त संचालक (1+2+3+4)	-696	-113	-1915	-2725
1. प्राधिकृत विक्रेताओं (एडी) से निवल खरीद #	-976	-313	-591	-1881
2. संचलनगत मुद्रा	-1138	179	-997	-1956
3. भारत सरकार के पास नकदी शेष	1930	-319	-603	1007
4. अन्य*	-512	340	276	104
बी. चलनिधि प्रबंधन (5+6+7+8)	293	256	2195	2744
5. निवल चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) @	-259	90	1113	944
6. खुला बाज़ार क्रय	207	300	1360	1867
7. प्राथमिक विक्रेताओं (पीडी) के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं	-1	-5	2	-4
8. सीआरआर शेष \$	347	-129	-280	-63
सी. बैंक रिज़र्व (ए + बी)	-403	142	280	18

** : गणना माह के अंतिम शुक्रवार से संबंधित आंकड़ों पर आधारित हैं; पहली तिमाही के उतार-चढ़ाव की गणना 31 मार्च 2018 की तुलना में की गई है।

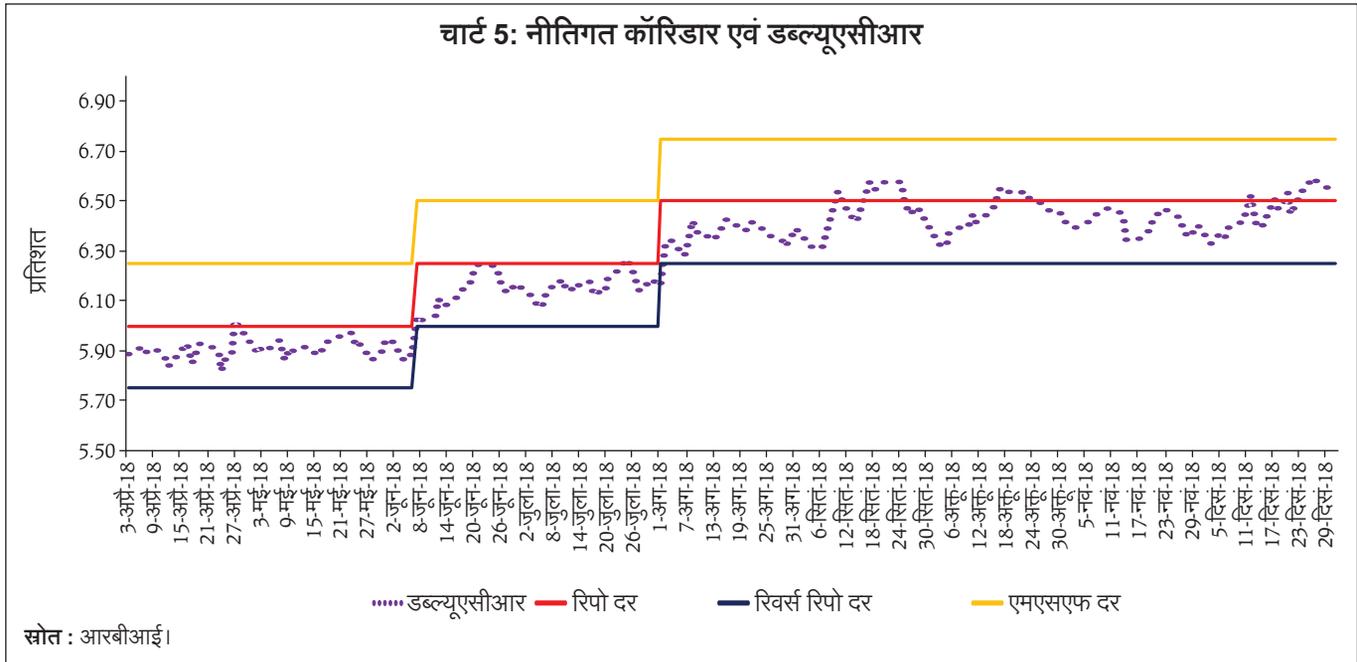
: ओएमओ खरीद में एकमुश्त के साथ-साथ एनडीएस-ओएम परिचालन भी शामिल हैं।

* : मूल्यांकन परिवर्तन, परिचालनों में हेयर कट इत्यादि शामिल हैं।

@ : निवल एलएएफ, रिवर्स रिपो परिचालनों से स्थायी दर एवं परिवर्तनीय दर रिपो तथा एमएसएफ को घटाने के उपरांत की चलनिधि स्थिति दर्शाती है।

\$: एनडीटीएल में वृद्धि के कारण (बैंक द्वारा बरकरार रखे गए सीआरआर आधिक्य में परिवर्तन के लिए समायोजित)।

स्रोत : आरबीआई एवं लेखकों की गणनाएं।



कमजोर पड़ने एवं प्रणालीगत चलनिधि में तंगी के बावजूद रिपो दर से कम में कारोबार किया, जिसके लिए रिपो के जरिए निवल अंतर्वेशन की दरकार है (सारणी 5 एवं चार्ट 6)।

इस अनोखे व्यवहार के कई कारण हैं:

- (i) अधिकांश सहकारी बैंक एनडीएस-कॉल ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म में प्रतिभागी नहीं हैं। गैर-अधिसूचित सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक कारोबार के समय – संपार्श्विकीकृत बाज़ार खंडों के बंद होने के बाद - अंतर-बैंक मांग मुद्रा बाज़ार में प्रवेश करते हैं और उनकी ऋण

गतिविधि दिन के उत्तरार्ध में बढ़ती है, अतएव दरें रिपो दर से कम हो जाती हैं;

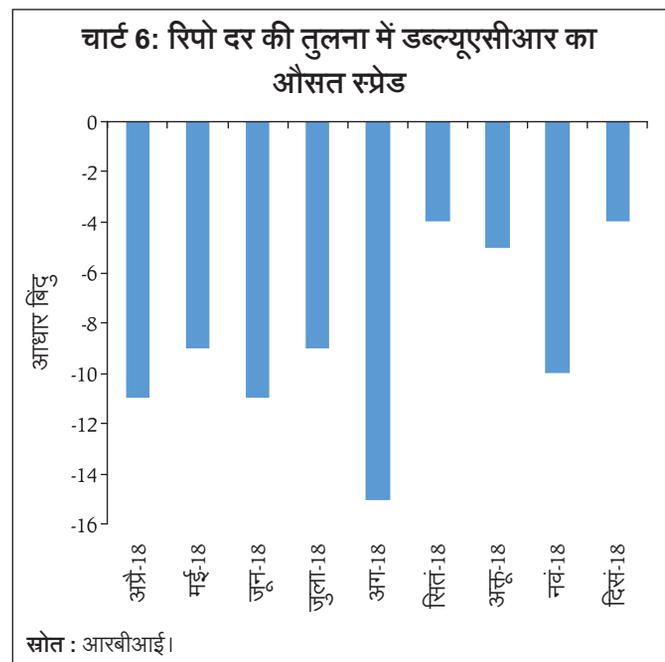
- (ii) आम तौर पर अंतर-बैंक मांग मुद्रा बाज़ार में कारोबार के प्रथम घंटे में दिन के कारोबार का लगभग 75-80 प्रतिशत कारोबार किया जाता है क्योंकि अधिकांश बाज़ार प्रतिभागी एक मजबूत चलनिधि पूर्वानुमान फ्रेमवर्क के अभाव में अपने दिन भर के अंतर्वाहों/

सारणी 5: डब्ल्यूएसीआर, रिपो एवं निवल एलएएफ

माह	डब्ल्यूएसीआर < रिपो दर	डब्ल्यूएसीआर > रिपो दर	औसत निवल एलएएफ घाटा (-) / अधिशेष (+)
दिनों की संख्या*			(₹ बिलियन)
अप्रैल	18	1	496
मई	22	0	142
जून	20	1	140
जुलाई	22	0	-107
अगस्त	20	0	30
सितंबर	11	7	-406
अक्तूबर	15	6	-560
नवंबर	18	0	-806
दिसंबर	12	8	-996

*: कार्य दिवस, शनिवार को छोड़कर।

स्रोत : आरबीआई।



बहिर्वाहों का आकलन नहीं कर पाते हैं और इसके परिणामस्वरूप निम्न मांग दरें देर-समय की मांग आपूर्ति में असंतुलन दर्शाती हैं;

- (iii) सभी मुद्रा बाज़ार खंडों (संपार्श्विकीकृत खंडों को शामिल करते हुए) में बाज़ार समय में असमानता होने की वजह से, जो तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के समय से मेल नहीं खाता है, प्रायः पाया गया है कि बाज़ार बंद होते समय डब्ल्यूएसीआर में अस्थिरता पैदा होती है।

4. नीति को अमल में लाना – प्रयोगसिद्ध मूल्यांकन

हम पात्रा एवं अन्य (2016) के प्रयोगसिद्ध फ्रेमवर्क में समुचित संशोधन के जरिए उसे बेहतर करते हुए डब्ल्यूएसीआर में संचलन निर्धारित करने वाले कारकों की जांच करते हैं। व्याख्यात्मक वेरिअबल अर्थात्, डब्ल्यूएसीआर में परिवर्तन को डब्ल्यूएसीआर, नीतिगत रिपो दर (आरआर), एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयता के अनुपात के रूप में निवल एलएएफ के अंतर्गत बकाया शेष (आरएनएलएएफ) के स्तर एवं अंतराल दोनों बदलावों के जरिए स्पष्ट किया गया है। जहां डब्ल्यूएसीआर पर आरआर का असर नीतिगत परिवर्तनों के घोषणा प्रभाव को दर्शाता है वहीं डब्ल्यूएसीआर पर आरएनएलएएफ का असर चलनिधि प्रभाव दर्शाता है (भट्टाचार्य और साहू, 2011)।

प्रयोगसिद्ध विश्लेषण 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान के दैनिक आंकड़ों पर आधारित है। यूनिट रूट टेस्ट बताते हैं कि डब्ल्यूएसीआर एवं आरआर के मामले में गैर-स्थिरता की शून्य परिकल्पना को खारिज नहीं किया जा सकता है। तथापि, आरएनएलएएफ के मामले में इसे खारिज किया गया है। बाउंड टेस्ट से पता चलता है कि ये तीनों वेरिअबल (डब्ल्यूएसीआर, आरआर एवं आरएनएलएएफ) एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए, ये उचित है कि आंकड़ों को अलग करने एवं बहुमूल्य सिलेसिलेवार सूचना/आंकड़े के गुणों को खोने के बजाय आटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग (एआरडीएल) दृष्टिकोण को अपनाएं और वह भी तब जब उनके एकीकरण का प्रकार भिन्न-भिन्न हों। अल्पकालिक गतिशीलता दर्शाने के लिए आधार रेखा के विशेष लक्षण यहां प्रस्तुत हैं:

$$\Delta (WACR)_t = a * (WACR - b * RR - c * RNLF)_{t-1} + \sum d_i * \Delta (WACR_{t-i}) + \sum e_i * \Delta (RR_{t-i}) + \sum f_i * \Delta (RNLF_{t-i}) + \varepsilon_t \dots \dots \dots (Eq. 1)$$

अगले कदम में, हम बाज़ार के संबंध में विशेष प्रकृति के कारकों को दर्शाने के लिए डमी के सहारे समीकरण 1 को आगे रखते हैं। यह देखा गया है कि जब बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपार्श्विक रहित खंड में उधार देने को लेकर उच्चतर जोखिम भार से बचने के उद्देश्य से मांग मुद्रा बाज़ार में सामान्य रूप से उधार देना कम कर देते हैं तब मांग मुद्रा दरें तिमाही के अंत में बढ़ने लगती हैं। इस घटना को तिमाही के अंत में डमी के जरिए दर्शाया गया है (डी_ तिमाही)। इतना ही नहीं, रिज़र्व आवश्यकताओं को बनाए रखना दिन की समाप्ति पर दैनिक न्यूनतम एवं पाक्षिक औसत का विषय है – अर्थात्, बैंक पाक्षिक रिज़र्व बनाए रखने की अवधि के प्रथम सप्ताह में अत्यधिक रिज़र्व धारण करता है जबकि दूसरे सप्ताह में आहरण के कारण धारिता घट जाती है। चलनिधि की कमी वाले बैंकों के पास पात्र संपार्श्विक की कमी होने की वजह से उन्हें रिज़र्व बनाए रखने की अवधि के कुछ-कुछ दिनों में आरबीआई की स्थायी सुविधाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिणामस्वरूप दैनिक मांग दरों में उतार-चढ़ाव भी आ सकता है। तदनुसार, यह माना गया है कि इन प्रभावों को आधार रेखा के विशेष लक्षण में दैनिक डमी (डी_दैनिक – जिसे डी2 से डी10 डमी के जरिए दर्शाया गया है)⁶ के जरिए दर्शाया जा सकता है। अतः, विशेष लक्षण में इस प्रकार विस्तार किया गया है:

$$\Delta(WACR)_t = a * (WACR - b * RR - c * RNLF - \sum d * D_quarter - \sum e_j * D_daily)_{t-1} + \sum f_i * \Delta (WACR_{t-i}) + \sum g_i * \Delta (RR_{t-i}) + \sum h_i * \Delta (RNLF_{t-i}) + \sum j_i * \Delta (D_quarter_{t-i}) + \sum j_i * \Delta (Dum_daily_{t-i}) + \varepsilon_t \dots \dots \dots (Eq. 2)$$

आधार रेखा के आकलनों एवं वर्धित मॉडल को अनुबंध सारणी 2 में दर्शाया गया है। नतीजे गुणात्मक रूप से समान होने के कारण, हम इसका वर्णन करने के लिए वर्धित विशेष लक्षण (मॉडल 3) पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नीतिगत रिपो दर का दीर्घकालिक गुणांक एकता का विषय है जो एक मजबूत घोषणा प्रभाव की ओर संकेत करता है, अर्थात्, औसतन, मांग दर चलनिधि नियंत्रण संबंधी परिचालनों से पहले करीब-करीब

⁶ डमी डी1, डी2, डी3, डी4 एवं डी5, 14-दिवसीय रिज़र्व बनाए रखने की अवधि के प्रथम सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को दर्शाता है, जबकि डी6, डी7, डी8, डी9 एवं डी10 रिज़र्व बनाए रखने की अवधि के दूसरे सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को दर्शाता है। मल्टीकोलीनिएरिटी से बचने के लिए, हम प्रथम सप्ताह के सोमवार के लिए अनुमानित समीकरण में डमी (डी1) को शामिल नहीं करते।

नीतिगत दर के समान हो जाती है। साथ ही चलनिधि प्रभाव विशेष करके कम हो जाता है (आरएनएलएफ में 100बीपीएस के बदलाव से डब्ल्यूएसीआर में विपरीत दिशा में 7बीपीएस का बदलाव आता है), अर्थात्, प्रणाली में चलनिधि अधिशेष (घाटा) से डब्ल्यूएसीआर में घाटा (वृद्धि) होता है। इतना ही नहीं, डी_तिमाही में उच्च गुणांक मूल्य (धनात्मक एवं सांख्यिकीय तौर पर महत्वपूर्ण) के अनुसार डब्ल्यूएसीआर पर प्रत्येक तिमाही के अंत में पर्याप्त दबाव पड़ता है। फिर भी, डी_दैनिक का गुणांक रिपोर्टिंग पखवाड़े के लिए सीमांत रूप से धनात्मक (साप्ताहिक रूप से पर्याप्त) निकला। अंततः, एरेर करेक्शन टर्म द्वारा प्रस्तुत अल्पकालिक गतिशीलता संकेत देती है कि किसी आघात के अनुरूप ढलने की गति पर्याप्त है – अर्थात्, लगभग 37 प्रतिशत विचलन का समायोजन अगले ट्रेडिंग दिन में हो जाता है।

चालू वर्ष के दौरान आए बदलावों के साथ दीर्घावधि सैम्पल (5 वर्ष) के लिए लगाए गए अनुमान के नतीजे भिन्न-भिन्न हैं। चलनिधि प्रभाव के लिहाज से, अनुमान के मुताबिक चलनिधि की स्थितियों और डब्ल्यूएसीआर के बीच ऋणात्मक संबंध है अर्थात्, चलनिधि में तंगी (उदारता) के परिणामस्वरूप डब्ल्यूएसीआर रिपो दर से अधिक (हास) होनी चाहिए। इसके ठीक विपरीत, चालू वर्ष के दौरान आए बदलाव दर्शाते हैं कि जब प्रणालीगत चलनिधि घाटे में था तब डब्ल्यूएसीआर रिपो दर से कम था। इससे बाज़ार की वर्तमान सूक्ष्म संरचना – पूरे क्षेत्रों में बाज़ार बंद होने के समय में असमानता; शुरू के घंटों में अधिकाधिक ट्रेडिंग करने एवं बाज़ार और निपटान दोनों के समय में असमानता - को लेकर हमने जिन मुद्दों की परिकल्पना की थी उसकी पुष्टि होती है। ट्रान्समिशन को बेहतर करने के लिए चल रहे प्रयासों में ये कारक अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं।⁷

5. निष्कर्ष

2018-19 में जब वातावरण वैश्विक स्पिलओवर, पुनर्मुद्रीकरण में तीव्रता और बजट व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण असामंजस्य से ग्रस्त था तब चलनिधि प्रबंधन को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप, प्रणाली में

⁷ 01 अगस्त 2018 को जारी तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति संबंधी वक्तव्य में विभिन्न बाजारों के समय को लेकर व्यापक रूप से समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक दल गठित करने एवं बाजार के समय में संस्तुत संशोधनों का समर्थन करने के लिए आवश्यक भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की गई है।

चलनिधि को अत्यंत संघर्ष करना पड़ा जिससे उसके हाल के स्वरूप को हानि पहुंची और आरबीआई के लिए आवश्यक हो गया कि वह मिश्रित लिखत चुनने एवं उसे प्रयोग में लाने के समय के लिहाज से असामान्य कदम उठाए – पहली बार, पूर्व-घोषित ओएमओ अधिसूचित राशियों ने आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन लिखतों के संसाधनों में स्थान पाया। 2018-19 से प्राप्त अनुभव की एक और निर्धारक विशेषता है कि अल्प-कालिक (4-7 दिन) रिवर्स रिपो के जरिए चलनिधि अवशोषण किया गया जबकि चलनिधि अंतर्वेशन मुख्य रूप से दीर्घ-कालिक (28-56 दिन) रिपो के माध्यम से किया गया था, जो दर्शाता है कि प्रणाली में अधिशेष चलनिधि की घटनाएं अस्थायी हैं। इस हालत में, एक-पक्षीय ओएमओ (क्रय) एवं दीर्घ-कालिक रिपो ने संयुक्त रूप से डब्ल्यूएसीआर में गिरावट लाई जो साल भर नीतिगत दर से कम ही रही, इसलिए निशानेबाजी उद्देश्य, जिसे एलएफ कॉरिडार को उत्तरोत्तर रूप से कम करने के लक्ष्य से अपनाया गया है, के लिहाज से फ्रेमवर्क के प्रदर्शन की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना अनिवार्य बन जाता है।

प्रयोगसिद्ध नतीजे बताते हैं कि घोषणा प्रभाव चलनिधि प्रभावों पर भारी पड़ता है ताकि नीतिगत पहल के प्रति बाज़ार की प्रतिक्रियाएं नीतिगत परिवर्तनों से उत्पन्न प्रणालीगत चलनिधि में बदलावों के प्रति निधि की वास्तविक लागत की प्रतिक्रिया की अपेक्षा दृढ़ एवं तेज हों। परिणाम बाज़ार की सूक्ष्म संरचना में सुधार को प्राथमिकता देने की जरूरत पर भी बल देता है, यदि निशानेबाजी एवं ट्रान्समिशन की प्रभावशीलता के लिहाज से चलनिधि प्रबंधन रूपरेखा के कायापलट के पूरे प्रभाव का लाभ उठाया जाना हो। तथापि, डब्ल्यूएसीआर में उतार-चढ़ाव पर्याप्त रूप से घटा जिससे बाज़ार की प्रत्याशाओं में स्थिरता आई।

चलनिधि फ्रेमवर्क के उद्भव को लेकर एक कार्य अधूरा रह गया है। 14-दिवसीय रिपो, जिसके जरिए रिज़र्व की मांग को पूरी तरह से तृप्त करने के लिए प्राथमिक चलनिधि थोक में उपलब्ध कराई जाती है, एकमात्र नीतिगत दर के रूप में स्थायी दर एकदिवसीय रिपो का स्थान लेना चाहता है। बाज़ार-आधारित फ्रेमवर्क में दुतरफा ओएमओ की जरूरत है ताकि मात्रात्मक परिवर्तन घोषणा प्रभावों पर निर्भर होने के बजाय निर्बाध रूप से हो सके। 2018-19 के अनुभव यह भी बताते हैं कि परिचालनों को दुरुस्त करने का कार्य अल्प-कालिक और आसानी से रद्द करने योग्य होना चाहिए, न कि स्थायी चलनिधि परिचालनों को अत्यधिक तीव्र

बनाने वाला। चलनिधि जरूरतों का अधिक सटीक आकलन महत्वपूर्ण है, जिसके लिए टॉप-डाउन कार्यप्रणाली एवं बॉटम-अप दृष्टिकोण का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाना है। चलनिधि प्रबंधन में सुधार करने के लिए विस्तृत योजना निर्धारित की गई है (आरबीआई, 2014) एवं यह उचित है कि इसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएं। चलनिधि प्रबंधन की सफलता उसके उद्देश्यों के संदर्भ में प्रयोजन, विषय-वस्तु, समय-सीमा तथा लक्ष्य(यों) के स्पष्ट एवं पारदर्शी संप्रेषण पर निर्भर करती है।

संदर्भ

- Bindseil, U. (2004), "The Operational Target of Monetary Policy and the Rise and Fall of Reserve Position Doctrine", *Working Paper No. 372, European Central Bank*.
- Bhattacharyya, I. and Sahoo, S. (2011) "Comparative Statics of Central Bank Liquidity Management: Some Insights," *Economics Research International*, vol. 2011, Article ID 930672, available at <https://doi.org/10.1155/2011/930672>.
- Mitra, A.K., and Abhilasha, (2012), "Determinants of Liquidity and the Relationship between Liquidity and Money: A Primer", *RBI Working Paper, WPS (DEPR):14/2012*.
- Mohan, R. (2006), "Coping with Liquidity Management in India: A Practitioner's View", *Reserve Bank of India Bulletin*, April.
- Patra, M. D., and Kapur, M. (2012), "A Monetary Policy Model for India", *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, 5(1), 16–39.
- Patra M.D., Kapur M., Kavediya R., and Lokare S.M. (2016), "Liquidity Management and Monetary Policy: From Corridor Play to Marksmanship", in Ghate C., and Kletzer K. (eds) *Monetary Policy in India*, Springer, New Delhi, 257-296.
- Patra M.D. (2017), "One Year in the Life of India's Monetary Policy Committee", *Reserve Bank of India Bulletin*, December.
- Pesaran, M., Shin, Y., & Smith, R. (2001), "Bounds testing approaches to the analysis of level Relationships", *Journal of Applied Econometrics*, 16, 289–326.
- Reserve Bank of India, (2011), "Report of the Working Group on Operating Procedure of Monetary Policy" (Chairman: Deepak Mohanty).
- Reserve Bank of India, (2014), "Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework" (Chairman: Dr. Urjit R Patel).
- Reserve Bank of India, (2016), "First Bi-monthly Monetary Policy Statement 2015-16", April 5.
- Reserve Bank of India, (2018), "Annual Report 2017-18", August.

अनुबंध
सारणी 1: प्रमुख चालकों में गतिविधियां और प्रणालीगत चलनिधि पर उसका प्रभाव

परिचालन / लिखत / चर	(1) में परिवर्तन	बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि पर प्रभाव
(1)	(2)	(3)
स्वायत्त कारक		
संचलन में मुद्रा	बढ़ घट	↓ ↑
भारत सरकार के पास नकदी शेष	बढ़ाना घटाना	↓ ↑
भारिबैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में हस्तक्षेप	क्रय विक्रय	↑ ↓
बैंकों द्वारा भारिबैंक के पास रखी अतिरिक्त आरक्षित निधि	बढ़ाना घटाना	↓ ↑
नीति चालित (विवेकाधीन) कारक		
भारिबैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन	क्रय विक्रय	↑ ↓
नकदी आरक्षित निधि आवश्यकताएँ (सीआरआर)	बढ़ाना घटाना	↓ ↑
निवल एलएएफ स्थिति	अंतर्वेशन* अवशोषण#	↑ ↓

*: (रिपो + एमएसएफ – रिजर्व रिपो) > 0; #: (रिपो + एमएसएफ – रिजर्व रिपो) < 0; वृद्धि (↑); घट (↓)

स्रोत : मित्रा और अभिलाषा से लेखक का अनुरूपण, 2014.

सारणी 2: नीति दर, चलनिधि और डब्ल्यूएसीआर – वैकल्पिक विनिर्देश

चर	बेस लाइन - मॉडल 1	संवर्धित – मॉडल 2 (तिमाही डमी के साथ)	संवर्धित – मॉडल 3 (तिमाही और दैनिक दोनों डमी के साथ)
चुनिंदा मॉडल ^a	एआरडीएल(5, 1, 1)	एआरडीएल(5, 1, 1)	एआरडीएल(5, 1, 1)
<i>दीर्घकालिक समीकरण : निर्भर चर: डब्ल्यूएसीआर</i>			
आरआर	1.05 (0.00)	1.06 (0.00)	1.06 (0.00)
आरएनएलएएफ	-0.08 (0.00)	-0.07 (0.00)	-0.07 (0.00)
डी_तिमाही	-	1.33 (0.00)	1.32 (0.00)
डी_दैनिक10	-	-	0.03 (0.08)
त्रुटि संशोधन (-1)	-0.34 (0.00)	-0.37 (0.00)	-0.37 (0.00)
समायोजित आर ^b	0.94	0.95	0.95
एफ-सांख्यिकी	37.75	50.51	50.81
निम्नतर और उच्चतर बाउंड क्रिटिकल मूल्य	1% [4.13, 5.00]	1% [4.13, 5.00]	1% [4.13, 5.00]
क्यू- सांख्यिकी	5.52 (0.85)	21.99 (0.15)	21.71 (0.17)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े पी-मूल्य को दर्शाते हैं। एकाइक सूचना मानदंड (ए आई सी) का प्रयोग करते हुए लैंग लेख का चयन किया गया है।

स्रोत : लेखक का अनुमान।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	71
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	72
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	73
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	74
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	75
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	75
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	76
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	77
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	78
9	कुल चलनिधि राशियां	78
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	79
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	79
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	80
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	80
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	81
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	82
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	83
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	84
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	85
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	85
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	85
21	थोक मूल्य सूचकांक	86
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	89
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	89
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	90
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	90
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	91
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	92
28	वाणिज्यिक पत्र	92
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	92
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	93

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	94
32	विदेशी मुद्रा भंडार	94
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	94
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	95
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	95
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	96
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	96
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	97
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	98
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	99
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹ में)	100
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	101
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	102
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	103
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	104
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	105
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	106
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	107
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	108

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2017-18	2017-18		2018-19	
		ति1	ति2	ति1	ति2
		1	2	3	4
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.9	5.6	6.1	8.0	6.9
1.1.1 कृषि	5.0	3.0	2.6	5.3	3.8
1.1.2 उद्योग	6.1	-0.4	7.1	10.8	6.5
1.1.3 सेवाएं	7.8	8.5	6.4	7.5	7.5
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.6	8.7	6.3	8.4	8.0
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	9.3	0.8	6.1	10.0	12.5
	2017-18	2017		2018	
		नवंबर	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	4.4	8.5	7.3	0.5	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	6.2	3.0	3.6	10.8	8.9
2.1.2 ऋण	10.0	9.3	10.4	16.2	13.9
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10.2	9.6	11.2	16.3	13.8
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9.5	3.6	-6.7	2.0	-0.5
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	27.4	30.4	55.9	18.9	17.0
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	9.2	8.4	10.0	10.4	10.2
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.7	5.1	4.8	5.1
3.4 ऋण-जमा अनुपात	75.5	73.5	74.7	77.1	78.2
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	117.3	250.9	173.7	111.6	139.2
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.0	31.0	30.5	28.5	27.9
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	43.0	853.3	159.9	17.8	1.1
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.00	6.00	6.00	6.50	6.50
4.2 रिवर्स रिपो दर	5.75	5.75	5.75	6.25	6.25
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.25	6.25	6.25	6.75	6.75
4.4 बैंक दर	6.25	6.25	6.25	6.75	6.75
4.5 आधार दर	8.65/9.45	8.95/9.45	8.85/9.45	8.95/9.45	8.95/9.45
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.80/7.95	7.70/8.05	7.65/8.05	8.15/8.45	8.15/8.55
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/6.75	6.00/6.75	6.00/6.75	6.25/7.50	6.25/7.50
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.15	5.89	5.99	6.39	6.57
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.11	6.15	6.19	6.77	6.65
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.33	6.25	6.33	7.06	6.84
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.49	6.28	6.42	7.22	6.94
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.42	7.25	7.51	7.64	7.36
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	65.04	64.73	63.93	69.66	69.98
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	80.62	76.72	76.39	79.36	80.18
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमेरिकी डालर					
1-माह (%)	4.61	4.26	4.32	4.31	4.37
3-माह (%)	4.37	4.08	4.44	4.02	3.97
6-माह (%)	4.21	4.39	4.47	4.13	4.09
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.6	4.9	5.2	2.3	2.2
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.1	4.0	4.0	4.9	5.2
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	2.9	4.0	3.6	4.6	3.8
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.3	5.6	3.9	0.9	2.3
6.3.2 ईंधन और पावर	8.2	8.4	8.0	16.3	8.4
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.7	2.7	2.8	4.2	3.6
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	20.9	23.7	21.5	4.3	-2.4
7.2 निर्यात	10.0	31.0	15.7	0.7	0.3

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआईएडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रकाशन शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2017-18	2018		2019			
		जनवरी	दिसंबर 28	जनवरी 4	जनवरी 11	जनवरी 18	जनवरी 25
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	18,044.20	17,129.62	19,992.41	20,030.20	20,285.00	20,392.60	20,359.57
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.15	0.17	0.13	0.11	0.09	0.12	0.12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	18,044.35	17,129.79	19,992.54	20,030.31	20,285.09	20,392.72	20,359.69
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	733.81	683.75	719.43	736.93	736.93	736.93	736.93
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	17,303.70	16,438.93	19,264.84	19,285.17	19,540.04	19,647.71	19,614.75
1.2.3 रुपया सिक्का	6.84	7.11	8.27	8.21	8.13	8.08	8.01
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	9,854.76	8,124.68	7,050.87	6,981.57	6,499.89	6,312.66	6,185.26
2.1.1.1 केंद्र सरकार	68.08	1.01	1.00	1.01	1.01	1.01	1.00
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	946.73	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	6.51	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,256.86	4,566.12	5,331.73	4,824.90	4,906.90	5,016.46	4,931.14
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	48.28	38.83	34.42	34.26	36.21	34.20	34.45
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	25.49	18.91	21.42	21.94	22.50	22.30	22.54
2.1.1.7 अन्य बैंक	305.66	264.03	286.12	281.43	283.70	281.83	283.25
2.1.1.8 अन्य	4,143.88	2,288.63	1,375.75	1,810.55	1,249.15	956.43	912.46
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	-	-	-	7.07	-	-	-
2.1.2 अन्य देयताएं	9,141.27	8,675.15	10,559.47	10,777.68	11,102.55	11,343.32	11,431.07
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	18,996.03	16,799.84	17,610.34	17,759.26	17,602.45	17,655.97	17,616.33
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.15	0.17	0.13	0.11	0.10	0.12	0.12
2.2.2 विदेश में रखे शेष	8,887.95	8,798.57	6,748.99	6,841.30	6,891.20	6,987.18	7,107.52
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केंद्र सरकार	-	-	-	532.93	331.24	171.06	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	7.39	31.80	7.62	38.28	73.61	56.43	9.19
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2,739.78	756.72	1,881.09	1,174.74	1,017.86	1,049.95	999.49
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.35	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एकिजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	106.75	41.17	59.71	44.60	50.77	48.98	47.98
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	7.07	-	-	-
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	6,369.76	6,469.59	8,070.78	8,233.05	8,336.47	8,440.46	8,541.94
2.2.6 अन्य आस्तियां	883.90	701.82	842.02	887.18	901.21	901.79	910.09
2.2.6.1 सोना	673.37	621.75	759.11	776.86	787.65	787.65	793.12

* डाटा अंतिम है।

सं. 3: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
दिसं. 1, 2018	10.20	221.28	-	-	-	-	-	-	-	-211.08
दिसं. 3, 2018	36.21	601.62	-	177.59	1.77	-	-	-	-	-741.23
दिसं. 4, 2018	31.41	163.24	126.50	368.86	0.50	-	-	-	-	-373.69
दिसं. 5, 2018	27.16	192.77	-	8.00	22.25	-	-	-	-	-151.36
दिसं. 6, 2018	36.11	114.99	-	84.34	1.05	-	-	-	-	-162.17
दिसं. 7, 2018	101.26	228.46	66.15	38.48	24.50	-2.19	-	-	100.00	22.78
दिसं. 10, 2018	115.96	100.33	-	-	27.30	-	-	-	-	42.93
दिसं. 11, 2018	201.37	90.92	235.02	-	5.87	-	-	-	-	351.34
दिसं. 12, 2018	212.71	92.86	-	-	0.02	2.01	-	-	-	121.88
दिसं. 13, 2018	59.71	160.18	250.02	-	0.50	-	-	-	-	150.05
दिसं. 14, 2018	35.46	340.08	469.37	-	29.21	-4.54	-	-	100.00	289.42
दिसं. 15, 2018	106.27	62.55	-	-	26.87	-	-	-	-	70.59
दिसं. 17, 2018	60.76	83.24	-	-	10.01	-	-	-	-	-12.47
दिसं. 18, 2018	60.87	95.03	230.05	-	0.65	4.05	-	-	-	200.59
दिसं. 19, 2018	43.58	126.40	142.00	-	1.35	-1.20	-	-	-	59.33
दिसं. 20, 2018	184.34	136.34	-	-	15.05	1.65	-	-	-	64.70
दिसं. 21, 2018	136.58	255.15	123.24	-	32.05	-	-	-	150.00	186.72
दिसं. 24, 2018	209.03	122.87	146.67	-	-	-	-	-	-	232.83
दिसं. 26, 2018	227.86	108.20	-	-	158.10	-	-	-	-	277.76
दिसं. 27, 2018	205.37	288.25	200.01	-	7.10	-0.90	-	-	-	123.33
दिसं. 28, 2018	41.24	401.11	235.02	-	1.26	1.30	-	-	150.00	27.71
दिसं. 29, 2018	-	476.99	-	-	-	-	-	-	-	-476.99
दिसं. 31, 2018	41.38	916.88	-	137.50	57.35	-	-	-	-	-955.65

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में परिचालन

मद	2017-18	2017	2018	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	33,689.00	5,647.00	-644.00	607.00
1.1 क्रय (+)	52,068.00	6,008.00	3,127.00	837.00
1.2 विक्रय (-)	18,379.00	361.00	3,771.00	230.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	2,228.28	371.46	-55.62	40.09
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डालर)	33,689.00	23,664.00	-26,510.00	-25,903.00
(बिलियन ₹)	2,228.27	1,555.71	-1,880.87	-1,840.76
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	20,853.00	29,099.00	-1,924.00	-2,426.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2017-18	2017	2018	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	3,935.00	0.00	51.00	0.00
1.2 विक्रय (-)	3,935.00	0.00	51.00	0.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	0.00	0.00	0.00	0.00

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	31 दिसंबर 2018 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	1,025	419	606
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	1,984	1,182	802
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	5,453	9,287	-3,834
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	8,462	10,888	-2,426

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2017-18	2018					2019	
		जनवरी 19	अगस्त 31	सितंबर 28	अक्टूबर 26	नवंबर 23		दिसंबर 21
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	—	—	1.3	42.0	—	7.5	32.1	5.0
2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 बकाया	—	—	—	—	—	—	—	—
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3.2 बकाया	25.4	9.8	23.9	19.0	20.3	21.2	20.8	17.0
4 अन्य								
4.1 सीमा	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 बकाया	—	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	25.4	9.8	25.1	61.0	20.3	28.7	52.9	22.1

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2017-18	2017	2018		
		दिसंबर 22	नवंबर 23	दिसंबर 7	दिसंबर 21
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	17,597.1	16,164.2	19,244.5	19,316.9	19,509.1
1.1 संचलन में नोट	18,037.0	16,717.7	19,850.1	19,881.9	20,041.8
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	249.1	248.5	249.5	249.5	249.5
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	696.4	809.4	862.6	822.0	789.7
2 जनता की जमा राशियां	15,076.2	12,699.0	13,640.3	13,389.2	13,276.7
2.1 बैंकों के पास मांग जमा राशियां	14,837.1	12,470.1	13,382.7	13,135.5	13,026.0
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशियां	239.1	228.9	257.6	253.8	250.7
3 एम₁ (1+2)	32,673.3	28,863.2	32,884.7	32,706.1	32,785.8
4 डाकघर बचत बैंक जमा राशियां	1,092.1	1,028.0	1,256.2	1,256.2	1,256.2
5 एम₂ (3+4)	33,765.4	29,891.2	34,140.9	33,962.3	34,042.0
6 बैंकों के पास मीयादी जमा राशियां	106,952.6	103,223.6	112,303.0	113,279.5	112,710.3
7 एम₃ (3+6)	139,625.9	132,086.8	145,187.7	145,985.6	145,496.1
8 कुल डाकघर जमा राशियां	3,008.1	2,881.4	3,372.6	3,372.6	3,372.6
9 एम₄ (7+8)	142,633.9	134,968.2	148,560.4	149,358.3	148,868.7

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 / माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2018			
		दिसंबर 22	नवंबर 23	दिसंबर 7	दिसंबर 21
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	40,014.0	39,285.9	43,445.9	44,382.1	42,346.7
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	4,759.6	3,868.4	7,127.2	7,812.2	6,830.1
1.1.1 सरकार पर दावे	6,435.6	6,552.1	7,251.6	7,813.6	7,899.0
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	6,418.4	6,531.3	7,251.6	7,743.6	7,893.4
1.1.1.2 राज्य सरकारें	17.2	20.8	0.0	70.0	5.7
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	1,676.0	2,683.7	124.4	1.4	1,069.0
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,675.6	2,683.3	123.9	1.0	1,068.5
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	35,254.4	35,417.5	36,318.7	36,570.0	35,516.6
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	92,137.2	86,419.3	97,243.0	98,009.5	98,770.5
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	140.3	86.9	93.2	88.3	92.8
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	91,996.9	86,332.3	97,149.8	97,921.2	98,677.7
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	86,254.2	80,682.7	91,326.3	92,062.5	92,876.4
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,666.0	5,562.2	5,737.8	5,769.7	5,712.3
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	76.7	87.5	85.8	88.9	88.9
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	29,223.0	27,284.0	29,297.1	29,047.4	28,826.0
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	27,607.8	25,945.6	27,975.2	27,725.5	27,504.0
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	27,609.9	25,947.5	27,977.5	27,727.8	27,506.3
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.1	1.9	2.3	2.3	2.3
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,615.1	1,338.4	1,321.9	1,321.9	1,321.9
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	256.0	257.0	257.0	257.0
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	22,004.8	21,158.3	25,055.2	25,710.4	24,704.0
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	9,069.9	8,557.9	10,899.7	10,751.0	10,503.4
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	12,934.9	12,600.4	14,155.5	14,959.4	14,200.6
एम₃ (1+2+3+4-5)	139,625.9	132,086.8	145,187.7	145,985.6	145,496.1

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017	2018		
		दिसंबर 22	नवंबर 23	दिसंबर 7	दिसंबर 21
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम ₁ (1.1 + 1.2.1+1.3)	32,673.3	28,863.2	32,884.7	32,706.1	32,785.8
एन एम ₂ (एन एम ₁ + 1.2.2.1)	80,142.1	74,683.5	82,729.5	83,002.3	82,835.7
एन एम ₃ (एन एम ₂ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	141,816.7	133,905.3	147,140.8	147,890.5	147,582.8
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	17,597.1	16,164.2	19,244.5	19,316.9	19,509.1
1.2 निवासियों की कुल जमा राशियां	120,323.4	114,292.9	124,148.8	124,904.7	124,248.0
1.2.1 मांग जमा राशियां	14,837.1	12,470.1	13,382.7	13,135.5	13,026.0
1.2.2 निवासियों की सावधि जमा राशियां	105,486.3	101,822.8	110,766.1	111,769.2	111,222.0
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमा राशियां	47,468.8	45,820.2	49,844.8	50,296.1	50,049.9
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,931.1	1,281.5	1,687.0	1,705.0	1,835.4
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमा राशियां	58,017.4	56,002.5	60,921.4	61,473.1	61,172.1
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	239.1	228.9	257.6	253.8	250.7
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,657.1	3,219.3	3,490.0	3,415.1	3,575.0
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	139,941.3	132,916.6	148,987.5	150,731.4	149,452.4
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	40,014.0	39,285.9	43,445.9	44,382.1	42,346.7
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	4,759.6	3,868.4	7,127.2	7,812.2	6,830.1
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	35,254.4	35,417.5	36,318.7	36,570.0	35,516.6
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	99,927.3	93,630.7	105,541.6	106,349.2	107,105.8
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	140.3	86.9	93.2	88.3	92.8
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	99,787.1	93,543.8	105,448.5	106,260.9	107,013.0
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	7,728.5	7,108.2	8,187.6	8,201.2	8,242.4
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	256.0	257.0	257.0	257.0
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,931.6	25,495.2	26,900.8	27,443.4	26,490.3
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,607.8	25,945.6	27,975.2	27,725.5	27,504.0
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-676.2	-450.4	-1,074.4	-282.0	-1,013.7
2.4 पूंजी खाता	20,705.2	19,510.2	23,516.2	23,004.4	22,953.6
2.5 अन्य मदें (निवल)	4,607.6	5,252.3	5,488.3	7,536.9	5,663.3

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2017-18	2017	2018		
		दिसंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	141,816.7	133,905.3	146,312.1	147,140.8	147,582.8
2 डाकघर जमा राशियां	3,008.1	2,881.4	3,372.6	3,372.6	3,372.6
3 एल₁ (1 + 2)	144,824.7	136,786.7	149,684.7	150,513.4	150,955.4
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमा राशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एल₂ (3 + 4)	144,854.0	136,816.0	149,714.0	150,542.8	150,984.8
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमा राशियां	319.1	316.0
7 एल₃ (5 + 6)	145,173.1	137,132.0

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017	2018		
			दिसंबर 22	नवंबर 23	दिसंबर 7
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	18,293.5	16,973.6	20,107.0	20,138.8	20,298.8
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,655.3	4,790.6	5,103.6	5,082.7	5,155.6
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,269.1	4,476.7	4,765.7	4,743.2	4,821.1
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	228.9	257.6	253.8	250.7
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	24,187.8	21,993.1	25,468.2	25,475.3	25,705.2
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	5,393.4	4,349.5	8,135.8	8,243.9	8,447.6
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	4,759.6	3,868.4	7,127.2	7,812.2	6,830.1
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	4,742.9	3,848.0	7,127.6	7,742.6	6,824.8
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	—	—	—	106.1	—
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	—	—	—	—	—
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6,411.5	6,523.9	7,243.1	7,629.2	7,885.1
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	6,411.5	6,523.9	7,243.1	7,629.2	7,885.1
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	6.9	7.4	8.5	8.4	8.3
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	1,675.6	2,683.3	123.9	1.0	1,068.5
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	16.8	20.4	-0.4	69.6	5.3
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	493.5	394.2	915.4	343.4	1,524.7
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	493.5	394.2	915.4	343.4	1,524.7
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	140.3	86.9	93.2	88.3	92.8
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	25.4	20.8	21.2	18.9	20.8
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	—	—	—	—	—
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	256.0	257.0	257.0	257.0
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,607.8	25,945.6	27,975.2	27,725.5	27,504.0
2.3.1 सोना	1,397.4	1,334.8	1,553.6	1,473.3	1,478.5
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,210.6	24,610.9	26,421.8	26,252.4	26,025.7
2.4 पूंजी खाता	8,584.3	7,890.8	10,488.5	10,153.8	9,871.3
2.5 अन्य मदें (निवल)	485.6	667.1	411.2	597.2	632.1

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2017-18	2017	2018				
			दिसंबर 29	नवंबर 30	दिसंबर 7	दिसंबर 14	दिसंबर 21
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	24,187.8	22,375.9	25,568.7	25,476.2	26,293.2	25,706.0	26,180.2
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	18,293.5	16,932.7	19,959.0	20,139.7	20,239.0	20,299.7	20,250.4
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,655.3	5,198.0	5,353.2	5,082.7	5,776.0	5,155.6	5,673.7
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	245.2	256.6	253.8	278.3	250.7	256.1
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	4,759.6	4,276.0	7,857.7	7,812.2	7,937.9	6,830.1	7,382.9
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	493.5	158.6	389.7	343.4	1,036.2	1,524.7	1,480.0
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	140.3	91.3	89.8	88.3	85.3	92.8	93.2
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,607.8	26,185.5	27,386.5	27,725.5	28,117.5	27,504.0	27,490.2
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	256.0	257.9	257.9	257.9	257.9	258.0
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	9,069.9	8,591.4	10,412.7	10,751.0	11,141.6	10,503.4	10,524.0

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017	2018		
		दिसंबर 22	नवंबर 23	दिसंबर 7	दिसंबर 21
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	112,794.2	106,808.0	116,598.9	117,336.0	116,674.5
1.1.1 मांग जमाराशियां	13,702.8	11,339.6	12,259.6	12,008.5	11,899.1
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	99,091.4	95,468.3	104,339.2	105,327.5	104,775.3
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	44,591.1	42,960.8	46,952.7	47,397.4	47,148.9
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,931.1	1,281.5	1,687.0	1,705.0	1,835.4
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	54,500.3	52,507.6	57,386.6	57,930.1	57,626.4
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,657.1	3,219.3	3,490.0	3,415.1	3,575.0
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	127,142.0	121,142.2	133,799.5	134,833.9	134,603.9
2.1.1 सरकार को ऋण	33,174.1	33,317.1	34,250.9	34,506.5	33,465.7
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	93,967.9	87,825.1	99,548.7	100,327.4	101,138.2
2.1.2.1 बैंक ऋण	86,254.2	80,682.7	91,326.3	92,062.5	92,876.4
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	85,834.4	80,018.2	90,603.4	91,268.1	92,103.0
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	64.3	105.9	113.7	141.2	95.5
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	10.5	18.1	10.7	12.1	13.5
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	7,638.9	7,018.6	8,098.0	8,111.6	8,152.7
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-676.2	-450.4	-1,074.4	-282.0	-1,013.7
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2,018.0	1,840.4	1,784.5	2,516.0	1,783.6
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,466.3	1,400.8	1,536.9	1,510.3	1,488.2
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	1,227.9	890.0	1,322.1	1,287.7	1,309.1
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	5,321.8	4,794.0	4,612.8	5,125.1	3,988.6
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,256.9	4,476.7	4,765.7	4,743.2	4,821.1
2.3.2 उपलब्ध नकदी	600.6	711.5	762.4	725.3	692.2
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	535.7	394.2	915.4	343.4	1,524.7
2.4 पूंजी खाता	11,879.3	11,377.7	12,786.0	12,609.0	12,840.5
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	3,457.1	4,080.9	4,463.1	6,316.7	4,488.7
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	4,360.8	4,081.6	3,812.7	3,794.6	4,061.8
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-268.2	-64.2	-506.9	-444.0	-471.6

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	30 मार्च, 2018 की स्थिति	2017	2018		
		दिसंबर 22	नवंबर 23	दिसंबर 7	दिसंबर 21
		1	2	3	4
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	33,184.5	33,335.1	34,261.6	34,518.6	33,479.2
2 वाणिज्यिक पत्र	1,159.4	1,103.2	1,076.9	937.5	948.2
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	118.7	115.6	117.0	116.8	117.3
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	745.3	728.0	731.1	721.9	723.3
3.3 अन्य	42.1	42.9	62.0	58.0	64.2
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	1,399.7	1,130.2	1,255.1	1,275.0	1,269.6
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	2,222.3	2,026.3	2,268.4	2,267.9	2,277.8
4.3 अन्य	994.6	621.3	1,267.4	1,283.1	1,266.4
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	177.3	586.6	470.7	565.6	564.3
5.2 वित्तीय संस्थाएं	895.8	787.3	849.3	885.6	921.5

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2017-18	2017	2018		2017-18	2017	2018	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	223	223	223	223	149	149	149	150
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	2,344.9	2,142.1	2,357.2	2,630.4	2,282.0	2,090.7	2,309.7	2,583.3
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमा राशियां	1,667.5	1,531.1	1,552.1	1,632.8	1,615.6	1,481.6	1,509.2	1,590.1
1.2 बैंकों से उधार राशि	611.7	550.4	670.8	912.2	601.2	550.4	667.4	909.3
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	65.7	60.5	134.2	85.5	65.2	58.7	133.1	84.0
2 अन्य के प्रति देयताएं	126,658.9	121,238.7	131,366.7	131,275.8	123,506.3	118,133.1	128,208.5	128,096.5
2.1 कुल जमा राशियां	117,285.4	112,475.6	122,625.3	122,292.0	114,260.5	109,521.9	119,602.9	119,248.0
2.1.1 मांग	13,994.8	12,280.6	13,204.8	12,900.3	13,702.8	12,013.1	12,929.2	12,617.0
2.1.2 मीयादी	103,290.6	100,195.0	109,420.5	109,391.8	100,557.7	97,508.8	106,673.7	106,631.1
2.2 उधार	3,693.9	3,664.2	3,572.0	3,702.3	3,657.1	3,617.7	3,529.9	3,660.5
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	5,679.7	5,098.9	5,169.3	5,281.5	5,588.7	4,993.5	5,075.6	5,188.1
3 रिजर्व बैंक से उधार	2,740.1	869.7	1,133.0	1,881.1	2,739.8	869.7	1,133.0	1,881.1
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अन्य	2,740.1	869.7	1,133.0	1,881.1	2,739.8	869.7	1,133.0	1,881.1
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	6,029.2	5,698.3	5,920.0	6,217.6	5,857.5	5,558.1	5,778.8	6,072.9
4.1 उपलब्ध नकदी	616.3	692.9	779.8	762.8	600.65	674.7	761.0	741.2
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	5,412.9	5,005.4	5,140.2	5,454.8	5,256.9	4,883.3	5,017.8	5,331.7
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	3,011.8	2,700.1	3,209.7	3,685.9	2,614.6	2,280.8	2,846.8	3,296.6
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	2,041.9	1,851.5	2,196.3	2,579.2	1,860.5	1,695.7	2,022.6	2,369.5
5.1.1 चालू खाते में	156.0	175.4	119.7	176.5	123.1	148.0	93.1	153.4
5.1.2 अन्य खातों में	1,885.9	1,676.1	2,076.6	2,402.7	1,737.4	1,547.7	1,929.5	2,216.1
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	360.5	336.8	384.8	451.5	182.4	130.5	234.3	319.8
5.3 बैंकों को अग्रिम	284.1	258.5	322.3	318.2	282.0	257.3	321.5	311.9
5.4 अन्य आस्तियां	325.3	253.3	306.3	337.1	289.6	197.3	268.4	295.5
6 निवेश	34,124.7	34,383.7	35,071.1	34,161.1	33,184.5	33,420.0	34,137.5	33,236.6
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	34,067.4	34,322.5	35,002.7	34,097.8	33,174.1	33,408.0	34,126.9	33,229.0
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	57.3	61.3	68.5	63.3	10.5	12.0	10.6	7.6
7 बैंक ऋण	88,785.3	84,299.3	96,039.4	95,952.7	86,254.2	81,794.6	92,219.0	93,197.2
7क खाद्यान्न ऋण	611.4	776.1	1,028.6	987.1	419.9	584.6	798.3	756.9
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	86,451.5	81,974.2	93,847.7	93,684.8	83,984.8	79,527.5	90,073.0	90,976.3
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	230.3	276.8	208.5	217.9	203.9	257.3	195.1	204.3
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,417.3	1,365.8	1,397.3	1,422.6	1,387.5	1,334.0	1,373.6	1,397.9
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	266.0	258.7	237.2	227.4	263.0	256.3	234.3	224.2
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	420.3	423.9	348.6	400.1	415.0	419.5	343.0	394.5

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 30, 2018	2017	2018		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			दिसंबर 22	नवंबर 23		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	77,303	73,055	81,652	82,413	6.6	12.8
1.1 खाद्यान्न ऋण	419	662	721	771	84.2	16.4
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	76,884	72,393	80,931	81,642	6.2	12.8
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	10,302	9,981	10,648	10,821	5.0	8.4
1.2.2 उद्योग	26,993	26,341	27,084	27,494	1.9	4.4
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,730	3,683	3,630	3,650	-2.1	-0.9
1.2.2.2 मझौले	1,037	957	1,051	1,046	0.9	9.2
1.2.2.3 बड़े	22,226	21,701	22,403	22,798	2.6	5.1
1.2.3 सेवाएं	20,505	18,119	22,538	22,330	8.9	23.2
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,213	1,152	1,292	1,303	7.5	13.1
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	186	179	191	191	2.8	6.7
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	365	367	384	388	6.3	5.6
1.2.3.4 नौवहन	63	73	64	62	-1.1	-14.4
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,554	1,422	1,685	1,717	10.5	20.7
1.2.3.6 व्यापार	4,669	4,406	4,795	4,860	4.1	10.3
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	2,052	1,935	2,116	2,140	4.3	10.6
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,618	2,471	2,679	2,719	3.9	10.1
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,858	1,825	1,877	1,899	2.2	4.1
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	4,964	3,682	5,663	5,709	15.0	55.1
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	5,633	5,013	6,587	6,200	10.1	23.7
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	19,085	17,952	20,662	20,997	10.0	17.0
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	197	182	33	33	-83.4	-82.0
1.2.4.2 आवास	9,746	9,362	10,774	10,966	12.5	17.1
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	725	557	682	693	-4.4	24.5
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	56	58	60	62	11.1	6.9
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	686	642	853	845	23.2	31.7
1.2.4.6 शिक्षा	697	704	692	691	-0.9	-1.8
1.2.4.7 वाहन ऋण	1,898	1,831	1,987	1,992	5.0	8.8
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	5,080	4,617	5,582	5,714	12.5	23.8
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	25,532	24,224	26,041	26,279	2.9	8.5
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	10,216	9,932	10,587	10,750	5.2	8.2
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	9,964	9,066	9,957	10,047	0.8	10.8
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,730	3,683	3,630	3,650	-2.1	-0.9
1.2अ.2.2 सेवाएं	6,234	5,383	6,327	6,397	2.6	18.9
1.2अ.3 आवास	3,756	3,727	4,043	4,085	8.8	9.6
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	264	169	230	239	-9.4	41.3
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	607	592	568	567	-6.6	-4.2
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	3	3	3	3	14.2	20.3
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	5,690	5,493	5,986	6,019	5.8	9.6
1.2अ.8 निर्यात ऋण	283	409	185	185	-34.7	-54.8

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 30, 2018	2017	2018		वित्तीय वर्ष में अब तक 2018-19	वर्ष-दर-वर्ष 2018
			दिसंबर 22	नवंबर 23		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	26,993	26,341	27,084	27,494	1.9	4.4
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	413	334	430	417	0.8	24.9
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	1,554	1,439	1,407	1,478	-4.8	2.8
1.2.1 चीनी	290	270	239	249	-14.1	-7.8
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	211	194	208	214	1.3	10.2
1.2.3 चाय	45	48	54	53	19.0	10.7
1.2.4 अन्य	1,008	927	906	963	-4.5	3.8
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	156	170	140	142	-8.7	-16.3
1.4 वस्त्र	2,099	2,007	1,984	1,999	-4.8	-0.4
1.4.1 सूती वस्त्र	1,057	1,002	987	1,000	-5.5	-0.2
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	22	25	21	21	-5.0	-14.8
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	243	235	237	241	-0.7	2.5
1.4.4 अन्य वस्त्र	776	745	740	737	-5.1	-1.1
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	113	109	111	107	-5.0	-1.6
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	109	106	114	115	5.7	8.4
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	306	310	303	300	-2.2	-3.2
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन	651	471	536	568	-12.8	20.7
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,630	1,598	1,692	1,774	8.8	11.0
1.9.1 उर्वरक	306	244	268	272	-10.9	11.7
1.9.2 औषधि और दवाइयां	484	474	508	510	5.3	7.6
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	387	443	395	463	19.6	4.5
1.9.4 अन्य	453	438	521	529	16.7	20.9
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	424	408	436	447	5.4	9.5
1.11 कांच और कांच के सामान	85	82	102	101	19.7	23.3
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	526	531	556	550	4.6	3.7
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	4,160	4,132	3,792	3,799	-8.7	-8.1
1.13.1 लोहा और स्टील	3,262	3,223	2,908	2,922	-10.4	-9.3
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	898	910	884	877	-2.4	-3.6
1.14 सभी अभियांत्रिकी	1,553	1,514	1,580	1,615	4.0	6.7
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	344	350	369	374	8.8	6.9
1.14.2 अन्य	1,210	1,164	1,211	1,241	2.6	6.6
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	787	730	785	808	2.6	10.8
1.16 रत्न और आभूषण	727	690	680	680	-6.5	-1.5
1.17 निर्माण	901	862	930	928	3.1	7.8
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	8,909	8,898	9,579	9,719	9.1	9.2
1.18.1 पावर	5,196	5,200	5,397	5,476	5.4	5.3
1.18.2 दूरसंचार	846	854	900	906	7.1	6.0
1.18.3 सड़क	1,665	1,703	1,822	1,870	12.3	9.8
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,202	1,140	1,460	1,467	22.0	28.7
1.19 अन्य उद्योग	1,890	1,952	1,928	1,947	3.0	-0.3

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2017-18	2017		2018					
		नवंबर 24	सितंबर 14	सितंबर 28	अक्टूबर 12	अक्टूबर 26	नवंबर 09	नवंबर 23	नवंबर 30
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	31	32	31	31	30	31	31	31	30
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	540.9	568.3	547.9	556.6	513.5	543.6	565.3	554.8	537.8
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	158.0	203.0	190.4	174.8	160.9	160.4	172.0	166.5	162.5
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	41.7	78.5	51.2	51.4	53.7	46.4	50.1	47.9	49.1
2.1.1.2 अन्य	89.9	95.1	79.5	88.2	79.1	83.9	86.1	86.8	83.3
2.1.2 बैंकों से उधार	1.2	0.0	11.5	7.5	3.1	3.2	3.5	4.6	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	25.2	29.3	48.2	27.8	25.0	27.0	32.3	27.2	30.2
2.2 मीयादी देयताएं	797.9	886.0	876.6	878.8	842.8	865.5	869.5	854.5	855.5
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	336.5	405.4	394.5	397.1	399.5	392.5	383.8	380.0	393.7
2.2.1.2 अन्य	451.0	473.1	468.4	468.4	434.5	459.7	479.2	468.0	454.6
2.2.2 बैंकों से उधार	3.1	0.0	6.0	7.3	2.6	6.2	0.0	0.2	0.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	7.3	7.4	7.7	6.1	6.3	7.1	6.5	6.4	7.2
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	404.8	472.6	439.1	447.6	486.1	487.4	516.1	516.3	520.2
4.1 मांग	112.3	155.7	146.3	151.5	157.0	156.2	168.5	170.0	168.3
4.2 मीयादी	292.5	317.0	292.8	296.1	329.1	331.2	347.5	346.3	351.9
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	55.6	46.3	60.4	46.2	46.0	44.8	44.0	44.2	42.6
5.1 उपलब्ध नकदी	2.8	3.1	3.2	3.3	2.6	3.1	3.0	3.0	3.1
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	52.8	43.3	57.2	42.9	43.4	41.7	41.0	41.2	39.4
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	15.0	7.8	9.5	10.9	7.2	9.0	9.4	40.4	11.0
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	295.6	315.7	322.4	316.9	310.8	316.4	314.0	317.7	310.0
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	208.8	229.2	161.0	155.5	180.0	164.3	178.0	181.2	166.6
9 बैंक ऋण (10.1+11)	434.4	463.0	545.7	543.2	530.3	544.0	533.2	543.0	550.2
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	434.4	463.0	545.7	543.2	530.3	543.9	533.2	543.0	550.2
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	668.5	736.8	737.1	762.0	783.0	788.6	792.6	798.7	812.4
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2017-18			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	दिसं. 17	नवं. 18	दिसं. 18	दिसं. 17	नवं. 18	दिसं. 18	दिसं. 17	नवं. 18	दिसं. 18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	138.6	137.4	138.1	141.5	140.0	138.8	138.8	139.1	137.6	140.5	139.7	138.4
1.1 अनाज और उत्पाद	135.2	133.7	134.7	136.4	137.1	137.1	134.4	138.1	138.5	135.8	137.4	137.5
1.2 मांस और मछली	142.7	143.8	143.1	143.7	150.8	152.0	142.6	146.3	147.8	143.3	149.2	150.5
1.3 अंडा	134.4	134.1	134.3	144.8	136.7	137.5	145.9	137.8	141.0	145.2	137.1	138.9
1.4 दूध और उत्पाद	140.3	138.6	139.6	141.9	141.9	142.5	139.5	141.6	141.6	141.0	141.8	142.2
1.5 तेल और चर्बी	121.7	114.8	119.2	123.1	122.8	124.5	115.9	118.1	118.2	120.5	121.1	122.2
1.6 फल	146.2	137.0	141.9	147.2	143.9	140.4	135.0	141.5	138.5	141.5	142.8	139.5
1.7 सब्जी	146.8	154.3	149.3	161.0	147.5	137.3	163.2	145.2	132.4	161.7	146.7	135.6
1.8 दाल और उत्पाद	136.4	123.6	132.1	133.8	121.0	121.1	119.8	115.3	117.5	129.1	119.1	119.9
1.9 चीनी और उत्पाद	119.8	120.2	119.9	121.9	111.6	110.0	120.7	112.5	111.0	121.5	111.9	110.3
1.10 मसाले	135.0	139.2	136.4	135.8	140.6	140.7	139.7	141.4	141.5	137.1	140.9	141.0
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	131.1	125.0	128.5	131.1	137.5	138.0	125.7	128.0	128.1	128.8	133.5	133.9
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	149.4	145.1	147.4	151.4	156.1	156.2	146.3	152.6	152.9	149.0	154.5	154.7
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	150.0	153.8	151.0	153.2	161.9	162.5	157.0	164.4	164.6	154.2	162.6	163.1
3 कपड़ा और जूते	145.3	132.4	140.2	147.2	150.8	151.0	134.0	140.5	140.8	142.0	146.7	147.0
3.1 कपड़ा	146.1	133.8	141.3	148.0	151.7	151.8	135.6	142.4	142.7	143.1	148.0	148.2
3.2 जूते	140.0	124.7	133.7	141.9	145.5	146.1	125.6	130.2	130.3	135.1	139.1	139.5
4 आवास	--	136.4	136.4	--	--	--	139.1	146.9	146.5	139.1	146.9	146.5
5 ईंधन और लाइट	138.6	123.0	132.7	142.6	150.3	149.2	126.8	136.7	132.4	136.6	145.1	142.8
6 विविध	130.4	124.4	127.5	131.9	140.1	141.8	125.1	132.2	131.7	128.6	136.3	136.9
6.1 घरेलू सामान और सेवा	137.7	128.2	133.2	139.5	148.0	149.7	129.3	135.8	136.2	134.7	142.2	143.3
6.2 स्वास्थ्य	133.9	126.6	131.1	136.1	145.4	149.9	128.2	136.8	137.3	133.1	142.1	145.1
6.3 परिवहन और संचार	121.2	115.3	118.0	122.0	130.3	128.9	115.3	121.2	118.8	118.5	125.5	123.6
6.4 मनोरंजन	132.1	124.6	127.9	133.4	143.1	143.4	125.6	131.3	131.7	129.0	136.5	136.8
6.5 शिक्षा	139.7	135.9	137.4	141.1	150.2	155.1	136.7	146.1	146.5	138.5	147.8	150.1
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	126.5	124.1	125.5	127.8	133.1	133.4	124.6	130.5	130.8	126.5	132.0	132.3
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	137.2	132.5	135.0	139.8	142.4	142.1	134.1	139.0	138.0	137.2	140.8	140.2

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष		2017-18	2017	2018	
	योगक कारक	दिसंबर			नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	284	286	302	301
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	889	900	914	913
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	895	906	921	921

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2017-18		2017		2018	
			दिसंबर		नवंबर	
	1	2	3	4	5	6
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)		29,300	28,763		31,010	31,251
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)		39,072	37,270		36,879	37,095

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2017-18	2017	2018		
			दिसंबर	अक्टूबर	नवंबर (अ)	दिसंबर (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	114.9	115.7	122.0	121.8	120.1
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	130.6	131.7	137.2	137.2	134.7
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.2	144.1	145.9	146.1	144.0
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	142.6	140.6	146.7	148.6	149.9
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	155.9	162.1	157.8	155.2	142.9
1.1.1.3 दूध	4.440	139.7	140.2	144.1	144.1	143.6
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	135.7	134.2	135.3	137.4	140.3
1.1.1.5 मसाले	0.529	125.2	128.2	131.7	131.6	129.1
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.0	142.6	143.1	143.8	145.5
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	119.6	119.2	123.4	124.6	124.5
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.0	119.4	130.1	130.9	128.6
1.1.2.2 तिलहन	1.115	129.9	129.3	137.6	140.7	140.9
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	110.9	106.6	108.1	108.1	107.8
1.1.2.4 फूल	0.204	148.7	184.0	166.7	169.3	177.7
1.1.3 खनिज	0.833	122.5	122.2	140.4	130.4	140.4
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	109.1	109.3	128.1	116.1	128.1
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	169.3	167.7	183.6	180.5	183.6
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	73.0	78.5	104.1	104.1	91.7
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	93.3	95.5	111.3	110.0	103.5
1.2.1 कोयला	2.138	118.7	117.0	123.4	123.4	123.4
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	134.1	131.7	133.3	133.3	133.3
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	112.5	110.4	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	104.2	113.5	120.0	120.0	120.0
1.2.2 खनिज तेल	7.950	82.5	87.0	107.6	105.5	94.7
1.2.3 बिजली	3.064	103.7	102.4	112.4	112.4	112.4
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	113.8	114.2	118.9	118.8	118.3
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	127.4	127.4	129.7	129.0	127.7
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	134.4	133.7	138.1	138.1	136.5
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	128.1	133.1	140.6	135.2	134.8
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	119.1	119.7	114.1	114.0	113.7
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	109.4	111.5	118.8	116.7	114.1
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	142.1	141.7	136.0	135.7	133.4
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	137.4	137.3	143.0	142.9	143.3
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	112.6	112.0	113.3	115.3	119.4
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	128.8	128.1	129.8	129.5	128.9
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	128.0	124.1	113.2	112.8	110.3
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.1	126.9	129.2	126.9	126.6
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	131.4	132.2	133.5	136.3	137.0
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	129.1	128.7	138.5	138.3	137.3
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	118.2	121.3	120.5	122.6	122.9
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.2	127.6	126.6	128.8	125.3
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	141.1	139.1	139.6	142.3	145.9
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	153.0	149.8	159.4	160.9	159.0
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	118.9	119.9	121.4	121.7	122.0
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	113.4	114.8	115.0	115.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	117.9	118.2	121.4	121.7	121.2
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोटलबन्ध पानी के अन्य उत्पाद	0.275	127.4	130.7	131.1	131.7	132.9
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	148.4	151.8	149.9	149.7	149.5
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	148.4	151.8	149.9	149.7	149.5
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	113.4	113.2	119.2	119.1	119.2
1.3.4.1 धागों की कटाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.2	105.5	112.6	112.1	111.3
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	122.0	122.4	127.8	128.4	128.8
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	108.6	108.1	113.6	113.8	113.8
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	124.6	124.7	129.1	129.1	134.6
1.3.4.5 जोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	141.7	138.5	140.7	142.7	141.3
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	117.5	117.9	120.4	118.6	120.4
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	136.9	138.8	138.4	138.1	138.4
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	137.8	138.7	139.3	138.7	139.0
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	134.5	139.1	136.2	136.7	136.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारंकांक	2017-18	2017	2018		
			दिसंबर	अक्टूबर	नवंबर (अ)	दिसंबर (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	120.1	121.2	121.9	121.5	121.1
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	110.9	111.6	110.7	110.1	108.5
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	131.2	132.7	137.4	135.5	134.5
1.3.6.3 जूते चप्पल	0.318	121.6	122.8	123.2	123.3	123.6
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	131.5	131.4	132.5	133.5	133.9
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.5	121.2	123.6	125.5	127.6
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॉमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड	0.493	131.5	133.0	135.9	136.9	136.5
1.3.7.3 बिल्डिंग की बड़ईगीरी	0.036	159.8	155.7	158.5	156.9	157.0
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	134.5	128.3	119.8	120.4	122.7
1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	118.9	118.6	124.7	125.3	125.2
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	122.3	122.9	131.9	132.8	132.2
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.1	113.2	116.0	117.0	118.4
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	116.2	117.1	121.8	121.6	120.8
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	143.7	143.5	146.7	146.5	147.5
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	143.7	143.5	146.7	146.5	147.5
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	112.5	113.2	120.5	120.8	120.0
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	111.2	114.3	127.6	128.2	126.5
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	117.1	116.8	121.6	122.8	123.4
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	113.0	113.0	120.3	119.2	117.2
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	115.3	114.8	119.9	121.0	119.4
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	108.6	107.5	112.4	113.1	112.4
1.3.10.6 साबुन और डिटरजेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	115.2	115.4	116.7	117.7	117.5
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	110.1	110.0	118.7	117.9	117.3
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	97.5	99.7	107.0	107.0	105.9
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	121.2	123.2	123.2	124.3	124.1
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	121.2	123.2	123.2	124.3	124.1
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	107.6	106.9	109.9	110.4	110.2
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	100.3	98.3	99.0	99.3	99.6
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.0	90.2	91.6	91.9	92.0
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	113.9	113.8	118.2	118.6	118.3
1.3.13 अन्य अघाटिक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	112.7	113.3	115.5	115.6	115.2
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	117.2	116.3	122.0	121.5	121.3
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	113.2	108.2	111.5	112.4	110.7
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	94.0	94.3	95.8	96.5	97.2
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.5	112.3	112.2	112.3	112.3
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	113.8	113.6	113.0	112.9	112.8
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	118.9	119.1	120.5	121.4	120.6
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	117.2	117.9	118.7	119.5	118.8
1.3.13.8 अन्य अघाटिक खनिज उत्पाद	0.169	89.9	109.9	139.5	139.5	136.5
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	101.4	102.9	114.8	113.9	112.5
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	98.2	97.7	119.0	117.1	114.5
1.3.14.2 मेटलिक आयरन	0.653	99.4	100.8	121.6	119.5	117.5
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	93.2	94.5	101.2	100.2	98.8
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	95.6	98.5	111.5	112.1	110.4
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	104.9	106.2	123.0	122.4	119.6
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	97.3	97.9	114.3	113.8	110.3
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	98.2	100.8	114.1	113.2	112.8
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	116.1	118.8	127.6	127.0	126.2
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	107.9	109.3	112.9	112.8	111.6
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	104.8	106.8	110.7	109.1	109.9
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	118.4	119.6	136.7	134.5	136.2
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	109.5	110.9	116.0	116.2	116.1
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	105.9	106.2	114.2	113.5	113.6
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	122.6	126.0	129.6	129.7	127.3
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	109.0	109.4	103.8	108.6	103.8
1.3.15.4 धातु की फॉर्जिंग, दबाना, स्टैमिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	90.7	93.0	93.8	96.7	100.2
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.3	99.4	99.5	99.8	100.1
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	114.8	116.9	125.1	124.2	125.0
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	110.1	110.5	113.1	113.0	112.3
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	103.7	101.7	101.3	102.4	101.7
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	127.4	127.4	135.1	135.1	135.1

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2017-18	2017	2018		
			दिसंबर	अक्टूबर	नवंबर (अ)	दिसंबर (अ)
			1	2	3	4
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	110.6	116.0	117.3	116.5	116.8
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.1	102.9	105.5	104.9	102.8
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	106.9	108.4	111.2	111.2	110.6
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.8	136.1	138.5	138.6	138.6
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.9	100.5	101.9	99.8	105.4
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.0	113.1	107.2	107.2	105.3
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	109.6	109.7	111.7	112.1	112.0
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	105.8	105.3	106.7	108.7	108.5
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.4	116.5	118.3	118.3	118.0
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	116.5	112.8	128.5	126.3	128.4
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	105.7	107.5	112.3	111.9	111.7
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	109.9	111.3	109.8	105.9	106.0
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.3	121.5	121.0	121.9	120.8
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	107.2	108.6	108.9	108.4	108.9
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	108.9	108.9	111.5	111.7	111.7
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	102.3	101.8	102.5	103.3	102.9
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	115.3	115.3	118.8	118.8	118.5
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.6	109.0	109.0	109.1	109.3
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	109.0	113.6	110.2	111.3	110.1
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	78.5	79.3	77.4	77.4	77.4
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	105.8	107.0	110.0	110.3	111.2
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	127.3	127.0	130.2	129.9	129.8
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	112.8	112.8	117.6	117.8	117.9
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	99.6	97.3	102.5	102.6	103.3
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.0	74.0	76.5	76.5	76.4
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	121.1	121.9	128.0	128.0	127.7
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	117.4	112.5	118.9	119.3	118.3
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	119.5	119.7	123.2	122.8	124.3
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.4	70.3	67.0	67.0	67.0
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	110.7	110.2	113.4	113.7	112.8
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	112.6	112.0	114.0	114.3	113.9
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	108.6	108.3	112.8	113.1	111.5
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	110.2	111.5	111.8	112.1	112.4
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.7	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.0	105.2	103.6	103.4	103.4
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	105.3	107.0	106.8	107.0	107.4
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	121.3	120.1	128.7	129.0	129.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	119.9	119.7	124.8	124.8	124.9
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	120.3	120.6	127.7	128.4	127.5
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	120.3	120.6	127.7	128.4	127.5
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	109.2	106.1	107.6	107.1	114.6
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	106.7	103.1	104.5	104.0	111.9
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	171.0	181.3	167.5	177.1	172.0
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	126.0	125.2	128.8	128.6	131.6
1.3.22.4 खेल और खेलौने	0.005	128.2	128.9	131.1	132.4	132.1
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	151.9	157.6	160.6	160.7	160.3
2 खाद्य सूचकांक	24.378	137.3	137.8	139.9	139.7	137.9

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2016-17	2017-18	अप्रैल-नवंबर		नवंबर	
				2017-18	2018-19	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	120.0	125.3	121.6	127.7	125.8	126.4
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	102.5	104.9	98.4	102.0	107.7	110.6
1.2 विनिर्माण	77.63	121.0	126.6	123.0	129.1	127.7	127.2
1.3 बिजली	7.99	141.6	149.2	150.5	160.5	140.1	147.2
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	117.5	121.8	118.6	124.3	120.9	124.8
2.2 पूंजीगत माल	8.22	101.5	105.6	99.5	106.7	104.3	100.8
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	122.3	125.1	122.2	123.0	125.4	119.7
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	125.0	132.0	128.2	138.8	129.3	135.8
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	122.6	123.6	122.3	132.3	122.0	120.9
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	126.5	139.9	133.8	139.0	149.1	148.2

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नजर में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - दिसंबर			
	2018-19 (संशोधित अनुमान)	2018-19 (वास्तविक)	2017-18 (वास्तविक)	संशोधित अनुमान का प्रतिशत	
				2018-19	2017-18
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	17,296.8	10,840.4	10,136.2	62.7	67.3
1.1 कर राजस्व (निवल)	14,844.1	9,363.3	9,001.2	63.1	70.9
1.2 करेतर राजस्व	2,452.8	1,477.1	1,135.0	60.2	48.1
2 पूंजीगत प्राप्तियां	7,275.5	7,479.9	6,853.3	102.8	96.2
2.1 ऋण की वसूली	131.6	123.2	106.4	93.6	60.9
2.2 अन्य प्राप्तियां	800.0	342.2	537.4	42.8	53.7
2.3 उधारियां और अन्य देयताएं	6,344.0	7,014.6	6,209.5	110.6	104.4
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	24,572.4	18,320.3	16,989.6	74.6	76.6
4 राजस्व व्यय	21,406.1	16,202.1	14,623.6	75.7	75.2
4.1 ब्याज भुगतान	5,875.7	4,211.9	3,739.6	71.7	70.4
5 पूंजी व्यय	3,166.2	2,118.2	2,366.0	66.9	86.5
6 कुल व्यय (4+5)	24,572.4	18,320.3	16,989.6	74.6	76.6
7 राजस्व घाटा (4-1)	4,109.3	5,361.7	4,487.4	130.5	102.2
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}	6,344.0	7,014.6	6,209.5	110.6	104.4
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	468.3	2,802.6	2,469.9	598.5	385.9

स्रोत : महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिशन बजट 2018-19।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2017		2018				
		दिसंबर 29	नवंबर 23	नवंबर 30	दिसंबर 7	दिसंबर 14	दिसंबर 21	दिसंबर 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	323.7	274.3	311.0	340.0	315.9	319.4	390.5	380.1
1.2 प्राथमिक व्यापारी	243.5	182.7	203.4	174.8	163.9	160.9	152.2	173.3
1.3 राज्य सरकारें	146.2	1,022.0	751.0	779.0	789.0	708.8	768.8	748.3
1.4 अन्य	343.4	589.3	673.4	643.8	638.8	606.6	522.4	481.8
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	216.2	361.4	371.9	375.3	362.7	393.8	415.3	404.0
2.2 प्राथमिक व्यापारी	316.5	193.2	477.1	471.5	450.8	426.2	415.4	428.1
2.3 राज्य सरकारें	193.6	61.2	344.5	344.5	344.5	344.5	344.5	344.5
2.4 अन्य	120.9	108.7	170.4	172.4	205.8	199.8	189.3	187.8
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	512.3	339.8	566.7	535.1	572.0	595.8	572.3	529.3
3.2 प्राथमिक व्यापारी	551.8	606.0	759.4	779.9	761.3	781.3	787.1	815.5
3.3 राज्य सरकारें	26.3	29.7	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9
3.4 अन्य	326.4	341.2	541.3	572.2	573.4	551.8	589.8	624.4
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 प्राथमिक व्यापारी	—	—	—	—	—	—	—	—
4.3 राज्य सरकारें	1,560.6	1,564.5	1,361.8	1,276.3	800.4	762.2	1,359.8	1,406.2
4.4 अन्य	5.1	4.7	6.3	4.9	18.3	18.0	5.5	4.8
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	3,320.8	4,109.3	5,351.1	5,369.4	5,359.1	5,269.9	5,328.6	5,298.0

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खज़ाना बिल												
2018-19												
नवंबर 28	70	68	345.86	148.01	38	69.99	148.01	218.00	98.34	6.7706		
दिसंबर 5	70	61	520.80	30.01	31	69.99	30.01	100.00	98.35	6.7292		
दिसंबर 12	70	45	276.65	12.01	23	69.99	12.01	82.00	98.36	6.6877		
दिसंबर 19	70	78	409.08	68.01	30	69.99	68.01	138.00	98.38	6.6048		
दिसंबर 26	70	54	340.46	56.51	30	69.99	56.51	126.50	98.37	6.6462		
182-दिवसीय खज़ाना बिल												
2018-19												
नवंबर 28	40	60	231.36	0.02	23	39.98	0.02	40.00	96.60	7.0587		
दिसंबर 5	40	50	170.18	0.03	24	39.98	0.03	40.01	96.62	7.0157		
दिसंबर 12	40	44	182.56	69.12	19	39.98	69.12	109.10	96.65	6.9513		
दिसंबर 19	40	52	277.87	53.50	10	40.00	53.50	93.50	96.69	6.8654		
दिसंबर 26	40	52	162.41	25.00	27	40.00	25.00	65.00	96.70	6.8440		
364-दिवसीय खज़ाना बिल												
2018-19												
नवंबर 28	40	80	249.74	0.09	22	39.91	0.09	40.00	93.28	7.2239		
दिसंबर 5	40	74	189.77	0.09	15	39.91	0.09	40.00	93.34	7.1548		
दिसंबर 12	40	74	192.38	0.08	16	39.92	0.08	40.00	93.44	7.0398		
दिसंबर 19	40	67	269.98	0.03	13	39.97	0.03	40.00	93.50	6.9710		
दिसंबर 26	40	61	122.51	0.00	28	40.00	0.00	40.00	93.53	6.9366		
नकद प्रबंधन बिल												
2018-19												
जून 11	250	86	1,598.72	—	47	250.00	—	250.00	98.74	6.6538		
जून 25	200	62	1,647.38	—	39	200.00	—	200.00	99.20	6.5412		
जुलाई 10	200	75	2,068.86	—	25	200.00	—	200.00	98.77	6.4934		
अक्टूबर 15	150	77	1,295.13	—	26	150.00	—	150.00	98.91	6.8175		
दिसंबर 5	300	44	1,365.88	—	24	300.00	—	300.00	99.78	6.7064		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
दिसंबर	1, 2018	5.05-6.50	6.18
दिसंबर	3, 2018	5.00-6.55	6.33
दिसंबर	4, 2018	5.00-6.50	6.35
दिसंबर	5, 2018	5.00-6.80	6.37
दिसंबर	6, 2018	5.00-6.75	6.35
दिसंबर	7, 2018	5.00-6.60	6.41
दिसंबर	10, 2018	5.00-6.55	6.42
दिसंबर	11, 2018	5.00-6.60	6.48
दिसंबर	12, 2018	5.00-6.70	6.52
दिसंबर	13, 2018	5.00-6.85	6.41
दिसंबर	14, 2018	5.00-6.55	6.39
दिसंबर	15, 2018	4.10-6.65	6.49
दिसंबर	17, 2018	5.00-6.75	6.51
दिसंबर	18, 2018	5.00-6.62	6.47
दिसंबर	19, 2018	5.00-7.00	6.47
दिसंबर	20, 2018	5.00-6.75	6.53
दिसंबर	21, 2018	5.00-6.65	6.44
दिसंबर	24, 2018	5.00-7.25	6.55
दिसंबर	26, 2018	5.00-7.36	6.59
दिसंबर	27, 2018	5.00-6.80	6.58
दिसंबर	28, 2018	5.00-7.20	6.56
दिसंबर	29, 2018	4.10-6.40	6.00
दिसंबर	31, 2018	5.00-6.85	6.54
जनवरी	1, 2019	5.00-6.55	6.34
जनवरी	2, 2019	5.00-6.60	6.33
जनवरी	3, 2019	5.00-6.60	6.32
जनवरी	4, 2019	5.00-6.70	6.29
जनवरी	5, 2019	4.10-7.00	6.10
जनवरी	7, 2019	5.00-6.55	6.37
जनवरी	8, 2019	5.00-6.60	6.35
जनवरी	9, 2019	5.00-6.80	6.36
जनवरी	10, 2019	5.00-6.55	6.36
जनवरी	11, 2019	5.00-6.52	6.34
जनवरी	14, 2019	5.00-6.70	6.36
जनवरी	15, 2019	5.00-6.60	6.42

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाणपत्र

मद	2017	2018			
	दिसंबर 22	नवंबर 9	नवंबर 23	दिसंबर 7	दिसंबर 21
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	1,269.8	1,312.0	1,485.1	1,556.7	1,806.6
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	185.2	128.8	279.7	310.8	322.2
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.21-7.75	7.12-8.50	6.92-8.50	6.99-9.37	6.83-9.02

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2017	2018			
	दिसंबर 31	नवंबर 15	नवंबर 30	दिसंबर 15	दिसंबर 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	4,090.5	5,847.2	5,606.1	5,460.8	4,987.3
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	916.0	1,066.2	1,300.6	1,036.5	957.8
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.22-10.76	6.69-11.73	6.63-11.09	6.51-11.18	6.78-10.29

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2017-18	2017	2018					
		दिसंबर 29	नवंबर 23	नवंबर 30	दिसंबर 7	दिसंबर 14	दिसंबर 21	दिसंबर 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	245.5	300.7	342.2	267.6	358.1	350.8	372.0	306.7
2 नोटिस मुद्रा	36.6	50.0	9.6	97.1	5.0	83.7	60.1	236.6
3 मीयादी मुद्रा	9	5.3	4.0	9.4	4.6	6.8	2.0	6.5
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	2,130.1	2,691.9	2,300.0	2,917.6	2,514.8	3,128.2	2,518.7	2,950.4
5 बाजार रिपो	1,921.8	2,345.3	1,748.6	2,188.8	1,861.6	2,100.0	1,733.0	2,171.0
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	3.8	1.2	8.4	45.2	41.5	47.5	59.2	66.0
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	55,345	69,022	55,903	76,552	68,026	61,119	65,507	65,175
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	808.7	760.2	507.8	951.1	1,187.7	1,114.5	884.6	646.2
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	45.3	19.7	32.6	80.0	57.0	43.6	79.3	77.7
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	35.5	44.9	49.4	36.0	31.9	18.6	69.2	73.1
10.2 182-दिवसीय	10.2	4.4	19.4	16.9	36.1	17.0	21.9	32.3
10.3 364-दिवसीय	10.3	11.7	27.8	31.8	32.2	20.6	47.5	31.0
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	13	—	1.4	1.9	66.1	35.4	—	—
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	923.0	840.9	638.3	1,117.7	1,411.0	1,249.7	1,102.5	860.4
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	—	0.6	27.6	22.3	23.4	20.8	30.7	37.7

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2017-18		2017-18 (अप्रैल-दिसंबर)		2018-19 (अप्रैल-दिसंबर)*		दिसंबर 2017		दिसंबर 2018 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	214	679.9	143	369.7	106	145.2	18	22.4	4	7.7
1ए प्रीमियम	211	657.8	142	356.7	104	140.1	18	20.7	4	7.0
1.1 पब्लिक	193	466.0	130	324.5	100	126.8	16	13.9	2	0.5
1.1.1 प्रीमियम	190	448.7	129	313.8	98	123.1	16	13.1	2	0.4
1.2 राइट्स	21	213.9	13	45.1	6	18.4	2	8.5	2	7.2
1.2.1 प्रीमियम	21	209.1	13	42.9	6	17.1	2	7.6	2	6.6
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 डिबेंचर	7	49.5	5	41.2	15	285.7	1	2.3	1	2.6
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	7	49.5	5	41.2	15	285.7	1	2.3	1	2.6
3.2.1 पब्लिक	7	49.5	5	41.2	15	285.7	1	2.3	1	2.6
3.2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल (1+2+3+4)	221	729.5	148	410.9	121	430.8	19	24.7	5	10.3
5.1 पब्लिक	200	515.6	135	365.8	115	412.4	17	16.2	3	3.1
5.2 राइट्स	21	213.9	13	45.1	6	18.4	2	8.5	2	7.2

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2017-18	2017		2018			
		1	दिसंबर	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर
			2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	बिलियन ₹	19,565.1	1,788.0	1,938.3	2,018.2	1,986.6	1,901.5	1,975.4
	अमेरिकी मिलियन डालर	303,526.2	27,832.6	27,871.0	27,946.8	26,980.4	26,463.0	27,927.7
1.1 तेल	बिलियन ₹	2,414.3	238.8	263.5	318.1	334.5	370.3	297.6
	अमेरिकी मिलियन डालर	37,465.1	3,717.8	3,789.5	4,404.3	4,542.7	5,153.1	4,207.8
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	17,150.8	1,549.2	1,674.8	1,700.1	1,652.1	1,531.2	1,677.7
	अमेरिकी मिलियन डालर	266,061.1	24,114.8	24,081.5	23,542.5	22,437.7	21,309.9	23,719.9
2 आयात	बिलियन ₹	30,010.3	2,700.2	3,147.6	3,031.7	3,248.5	3,102.4	2,900.3
	अमेरिकी मिलियन डालर	465,581.0	42,030.8	45,258.3	41,981.7	44,117.2	43,176.9	41,005.0
2.1 तेल	बिलियन ₹	7,003.2	664.6	830.5	790.9	1,049.2	969.6	754.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	108,658.7	10,345.0	11,941.4	10,951.3	14,249.3	13,493.4	10,672.3
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	23,007.1	2,035.6	2,317.1	2,240.9	2,199.2	2,132.9	2,145.5
	अमेरिकी मिलियन डालर	356,922.3	31,685.8	33,316.9	31,030.4	29,867.9	29,683.5	30,332.7
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	-10,445.2	-912.1	-1,209.2	-1,013.5	-1,261.8	-1,201.0	-925.0
	अमेरिकी मिलियन डालर	-162,054.8	-14,198.2	-17,387.3	-14,034.9	-17,136.8	-16,713.9	-13,077.3
3.1 तेल	बिलियन ₹	-4,588.9	-425.7	-566.9	-472.8	-714.7	-599.3	-457.2
	अमेरिकी मिलियन डालर	-71,193.6	-6,627.2	-8,151.8	-6,547.0	-9,706.6	-8,340.3	-6,464.5
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	-5,856.3	-486.4	-642.3	-540.7	-547.1	-601.7	-467.7
	अमेरिकी मिलियन डालर	-90,861.2	-7,571.0	-9,235.5	-7,487.9	-7,430.2	-8,373.6	-6,612.8

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2018				2019		
		जनवरी 19	दिसंबर 14	दिसंबर 21	दिसंबर 28	जनवरी 4	जनवरी 11	जनवरी 18
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	बिलियन ₹	26,431	28,157	27,537	27,523	27,671	27,988	28,191
	अमेरिकी मिलियन डालर	414,785	393,121	393,288	393,404	396,085	397,352	396,681
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	बिलियन ₹	24,896	26,389	25,772	25,758	25,871	26,173	26,374
	अमेरिकी मिलियन डालर	390,769	367,866	367,971	368,077	370,292	371,379	370,726
1.2 स्वर्ण	बिलियन ₹	1,306	1,476	1,479	1,479	1,514	1,525	1,525
	अमेरिकी मिलियन डालर	20,422	21,187	21,224	21,224	21,690	21,844	21,844
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1,061	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052
	बिलियन ₹	98	104	102	102	102	104	104
	अमेरिकी मिलियन डालर	1,531	1,450	1,459	1,463	1,463	1,472	1,465
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	बिलियन ₹	131	188	184	185	184	187	188
	अमेरिकी मिलियन डालर	2,063	2,618	2,634	2,640	2,640	2,656	2,645

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2017-18	2017	2018		2017-18	2018-19
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	126,182	123,315	125,685	125,772	5,040	6,975
1.1 एफसीएनआर (बी)	22,026	21,808	20,433	20,840	806	-1,185
1.2 एनआर (ई) आरए	90,035	88,135	90,515	90,254	3,703	6,604
1.3 एनआरओ	14,121	13,372	14,737	14,678	531	1,556

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	2017-18	2017-18	2018-19	2017	2018	
		अप्रैल-दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	30,286	23,879	24,808	2,736	851	2,657
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	39,431	30,825	33,087	3,285	1,225	3,620
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	60,974	47,877	46,624	6,057	3,269	5,664
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45,521	36,425	33,988	4,875	1,795	4,447
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	7,797	6,488	2,033	55	210	1
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिजर्व बैंक	29,569	22,663	27,820	2,995	1,378	4,264
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7,491	6,789	3,640	1,769	151	126
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	664	485	495	56	56	56
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	12,542	9,149	9,973	1,061	1,061	1,061
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	2,911	2,303	2,663	121	413	157
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	21,544	17,052	13,537	2,772	2,044	2,044
1.1.1.2.1 ईक्विटी	21,325	16,867	13,314	2,762	2,022	2,022
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	219	185	223	10	22	22
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	9,144	6,947	8,279	549	375	963
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	5,254	3,991	5,043	383	226	722
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	2,853	2,139	2,189	238	238	238
1.1.2.3 अन्य पूंजी	4,525	3,561	2,867	252	211	303
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	3,487	2,744	1,820	323	300	300
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	22,115	19,839	-11,875	-120	1,707	1,107
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	22,165	19,789	-13,694	-84	1,758	1,159
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	50	-50	-1,819	36	51	51
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	52,401	43,718	12,933	2,615	2,557	3,765

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	2017-18	2017	2018		
		दिसंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	11,333.6	981.4	1,093.6	996.8	1,093.1
1.1 जमाराशियां	414.9	31.6	29.7	29.4	31.6
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	89.6	10.9	9.0	6.6	5.4
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	441.8	31.0	29.7	24.9	34.3
1.4 उपहार	1,169.7	107.9	90.9	102.2	110.4
1.5 दान	8.5	0.4	0.3	0.6	1.3
1.6 यात्रा	4,022.1	361.6	373.8	339.7	386.2
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,937.4	255.3	192.9	208.0	223.3
1.8 चिकित्सा उपचार	27.5	2.7	2.6	3.4	1.9
1.9 विदेश में शिक्षा	2,021.4	147.0	344.0	267.7	277.9
1.10 अन्य	200.6	32.9	20.8	14.2	21.0

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2016-17	2017-18	2018		2019
			जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	74.65	76.94	76.81	72.89	72.32
1.2 रीर	114.52	119.71	120.35	115.02	114.12
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	76.38	78.89	78.94	74.34	73.88
2.2 रीर	116.45	121.94	122.59	117.21	116.49
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	66.86	68.13	67.57	63.44	62.97
1.2 रीर	125.17	129.87	129.68	123.46	121.59
2 आधार : 2016-17 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	101.90	101.07	94.89	94.18
2.2 रीर	100.00	103.75	103.61	98.63	97.14

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार — पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

मद	2017-18	2017	2018	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	769	56	78	66
1.2 राशि	20,397	905	1,296	3,332
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	38	1	2	1
2.2 राशि	8,471	400	770	474
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	807	57	80	67
3.2 राशि	28,868	1,305	2,066	3,806
4 भारत ओसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.10	6.20	6.20	5.50
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत ओसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	2.39	0.92	1.15
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-12.25	0.00-10.50	0.00-15.00	0.00-12.00

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जुलाई-सितंबर 2017 (आं.सं)			जुलाई-सितंबर 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	292,554	283,055	9,499	290,177	292,044	-1,868
1 चालू खाता (1.1+1.2)	145,498	152,454	-6,956	160,007	179,119	-19,112
1.1 पण्य	76,082	108,536	-32,455	83,399	133,432	-50,034
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	69,417	43,918	25,499	76,609	45,687	30,922
1.2.1 सेवाएं	47,409	29,032	18,377	50,094	29,844	20,250
1.2.1.1 यात्रा	6,962	5,332	1,630	7,038	5,813	1,225
1.2.1.2 परिवहन	4,206	4,175	31	4,641	5,086	-446
1.2.1.3 बीमा	635	542	92	646	396	250
1.2.1.4 जीएनआई	126	145	-19	140	261	-122
1.2.1.5 विविध	35,479	18,837	16,642	37,629	18,287	19,342
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	19,295	1,325	17,969	20,755	1,472	19,283
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9,084	9,559	-475	9,408	9,690	-282
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1,321	1,574	-253	1,311	1,132	180
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	536	215	321	606	278	328
1.2.2 अंतरण	17,522	1,850	15,672	20,891	1,560	19,331
1.2.2.1 आधिकारिक	108	212	-104	35	215	-180
1.2.2.2 निजी	17,414	1,638	15,776	20,856	1,346	19,511
1.2.3 आय	4,486	13,036	-8,550	5,623	14,282	-8,659
1.2.3.1 निवेश आय	3,456	12,472	-9,016	4,549	13,691	-9,141
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	1,030	564	466	1,074	592	482
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	147,055	130,165	16,890	129,255	112,925	16,330
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	87,191	72,714	14,477	75,386	69,132	6,254
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	20,046	7,635	12,411	14,997	7,126	7,872
2.1.1.1 भारत में	18,979	4,288	14,692	14,246	4,055	10,191
2.1.1.1.1 इक्विटी	15,107	4,253	10,854	10,185	3,894	6,291
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3,043	-	3,043	3,456	-	3,456
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	829	34	795	606	161	445
2.1.1.2 विदेश में	1,067	3,347	-2,281	751	3,071	-2,320
2.1.1.2.1 इक्विटी	1,067	1,041	26	751	1,112	-361
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	713	-713	0	747	-747
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1,593	-1,593	0	1,212	-1,212
2.1.2 संविभाग निवेश	67,145	65,079	2,066	60,388	62,006	-1,618
2.1.2.1 भारत में	67,016	64,579	2,437	59,216	61,616	-2,400
2.1.2.1.1 एफआईआई	67,016	64,579	2,437	59,216	61,616	-2,400
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	52,492	55,924	-3,432	50,860	52,179	-1,319
2.1.2.1.1.2 ऋण	14,524	8,655	5,869	8,356	9,436	-1,081
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	128	500	-372	1,173	391	782
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	33,438	30,582	2,857	23,120	16,933	6,187
2.2.1 बाह्य सहायता	1,259	1,176	82	1,216	1,264	-48
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	31	-17	12	30	-18
2.2.1.2 भारत को	1,245	1,145	100	1,204	1,234	-30
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	8,156	9,376	-1,220	8,494	7,047	1,447
2.2.2.1 भारत द्वारा	2,964	2,672	292	1,515	1,349	166
2.2.2.2 भारत को	5,192	6,704	-1,512	6,979	5,698	1,281
2.2.3 भारत को अल्पावधि	24,023	20,029	3,994	13,411	8,622	4,789
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	23,614	20,029	3,585	7,392	8,622	-1,230
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	409	0	409	6,019	0	6,019
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	16,876	16,702	174	21,194	20,672	522
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	16,790	16,702	88	21,194	20,670	524
2.3.1.1 आस्तियां	2,566	4,936	-2,370	5,370	5,638	-268
2.3.1.2 देयताएं	14,224	11,766	2,458	15,823	15,031	792
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	12,187	11,476	711	15,402	12,075	3,326
2.3.2 अन्य	86	0	86	0	2	-2
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	2	-2	0	1	-1
2.5 अन्य पूंजी	9,549	10,166	-616	9,555	6,187	3,368
3 भूल-चूक	-	436	-436	914	-	914
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	9,499	-9,499	1,868	0	1,868
4.1 आईएमएफ	0	0	0	-	-	-
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	-	9,499	-9,499	1,868	0	1,868

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

मद	जुलाई-सितंबर 2017 (आं.सं)			जुलाई-सितंबर 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	18,808	18,197	611	20,356	20,487	-131
1 चालू खाता (1.1+1.2)	9,354	9,801	-447	11,225	12,566	-1,341
1.1 पण्य	4,891	6,978	-2,086	5,851	9,361	-3,510
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	4,463	2,823	1,639	5,374	3,205	2,169
1.2.1 सेवाएं	3,048	1,866	1,181	3,514	2,094	1,421
1.2.1.1 यात्रा	448	343	105	494	408	86
1.2.1.2 परिवहन	270	268	2	326	357	-31
1.2.1.3 बीमा	41	35	6	45	28	18
1.2.1.4 जीएनआईई	8	9	-1	10	18	-9
1.2.1.5 विविध	2,281	1,211	1,070	2,640	1,283	1,357
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,240	85	1,155	1,456	103	1,353
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	584	615	-31	660	680	-20
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	85	101	-16	92	79	13
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	34	14	21	43	20	23
1.2.2 अंतरण	1,126	119	1,008	1,466	109	1,356
1.2.2.1 आधिकारिक	7	14	-7	2	15	-13
1.2.2.2 निजी	1,120	105	1,014	1,463	94	1,369
1.2.3 आय	288	838	-550	394	1,002	-607
1.2.3.1 निवेश आय	222	802	-580	319	960	-641
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	66	36	30	75	42	34
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9,454	8,368	1,086	9,067	7,922	1,146
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	5,605	4,675	931	5,288	4,850	439
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	1,289	491	798	1,052	500	552
2.1.1.1 भारत में	1,220	276	945	999	284	715
2.1.1.1.1 इक्विटी	971	273	698	714	273	441
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	196	0	196	242	0	242
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	53	2	51	43	11	31
2.1.1.2 विदेश में	69	215	-147	53	215	-163
2.1.1.2.1 इक्विटी	69	67	2	53	78	-25
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	46	-46	0	52	-52
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	102	-102	0	85	-85
2.1.2 संविभाग निवेश	4,317	4,184	133	4,236	4,350	-113
2.1.2.1 भारत में	4,308	4,152	157	4,154	4,322	-168
2.1.2.1.1 एफआईआई	4,308	4,152	157	4,154	4,322	-168
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	3,375	3,595	-221	3,568	3,660	-93
2.1.2.1.1.2 ऋण	934	556	377	586	662	-76
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8	32	-24	82	27	55
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	2,150	1,966	184	1,622	1,188	434
2.2.1 बाह्य सहायता	81	76	5	85	89	-3
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	2	-1	1	2	-1
2.2.1.2 भारत को	80	74	6	84	87	-2
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	524	603	-78	596	494	101
2.2.2.1 भारत द्वारा	191	172	19	106	95	12
2.2.2.2 भारत को	334	431	-97	490	400	90
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,544	1,288	257	941	605	336
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,518	1,288	231	519	605	-86
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	26	0	26	422	0	422
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	1,085	1,074	11	1,487	1,450	37
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	1,079	1,074	6	1,487	1,450	37
2.3.1.1 आस्तियां	165	317	-152	377	396	-19
2.3.1.2 देयताएं	914	756	158	1,110	1,054	56
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	783	738	46	1,080	847	233
2.3.2 अन्य	6	0	6	0	0	-
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	0	-	0	0	-
2.5 अन्य पूंजी	614	654	-40	670	434	236
3 भूल-चूक	0	28	-28	64	0	64
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	611	-611	131	0	131
4.1 आईएमएफ	-	-	-	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	611	-611	131	0	131

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जुलाई-सितंबर 2017 (आ.सं.)			जुलाई-सितंबर 2018 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	145,490	152,435	-6,944	160,007	179,098	-19,091
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	123,491	137,568	-14,078	133,493	163,277	-29,784
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	76,082	108,536	-32,455	83,399	133,432	-50,034
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	75,534	102,823	-27,289	83,400	124,201	-40,801
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	548	0	548	-1	-	-1
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	5,714	-5,714	-	9,231	-9,231
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	47,409	29,032	18,377	50,094	29,844	20,250
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	32	9	24	58	8	50
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	52	109	-58	43	259	-216
1.अ.ख.3 परिवहन	4,206	4,175	31	4,641	5,086	-446
1.अ.ख.4 यात्रा	6,962	5,332	1,630	7,038	5,813	1,225
1.अ.ख.5 निर्माण	517	366	152	766	635	131
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	635	542	92	646	396	250
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1,321	1,574	-253	1,311	1,132	180
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	142	1,290	-1,147	162	1,942	-1,780
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	19,985	1,653	18,332	21,425	1,869	19,557
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9,084	9,559	-475	9,408	9,690	-282
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	371	723	-353	447	774	-328
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	126	145	-19	140	261	-122
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	3,974	3,555	420	4,008	1,978	2,031
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	4,486	13,036	-8,550	5,623	14,282	-8,659
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1,030	564	466	1,074	592	482
1.आ.2 निवेश आय	2,727	12,350	-9,623	3,474	13,397	-9,923
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,418	5,905	-4,487	1,777	6,220	-4,443
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	70	3,442	-3,372	53	3,516	-3,463
1.आ.2.3 अन्य निवेश	153	2,995	-2,842	135	3,648	-3,513
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1,086	8	1,078	1,508	13	1,495
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	728	122	607	1,075	293	782
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	17,514	1,830	15,684	20,891	1,539	19,352
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तोत्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	17,414	1,638	15,776	20,856	1,346	19,511
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	16,854	1,352	15,502	20,224	991	19,233
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	560	286	274	633	354	278
1.इ.2 सामान्य सरकार	100	193	-93	35	193	-159
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	83	115	-31	75	96	-21
2.1 अनुयादित वित्तोत्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	20	41	-22	2	4	-2
2.2 पूंजी अंतरण	64	73	-10	72	92	-19
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	146,980	139,569	7,411	131,048	112,851	18,198
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	20,046	7,635	12,411	14,997	7,126	7,872
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	18,979	4,288	14,692	14,246	4,055	10,191
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	18,150	4,253	13,897	13,640	3,894	9,747
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	15,107	4,253	10,854	10,185	3,894	6,291
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3,043	-	3,043	3,456	-	3,456
3.1.अ.2 ऋण लिखत	829	34	795	606	161	445
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	829	34	795	606	161	445
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1,067	3,347	-2,281	751	3,071	-2,320
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1,067	1,754	-687	751	1,859	-1,108
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1,067	1,041	26	751	1,112	-361
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	-	713	-713	-	747	-747
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1,593	-1,593	0	1,212	-1,212
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	1,593	-1,593	0	1,212	-1,212
3.2 संविभाग निवेश	67,145	65,079	2,066	60,388	62,006	-1,618
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	67,016	64,579	2,437	59,216	61,616	-2,400
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	52,492	55,924	-3,432	50,860	52,179	-1,319
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	14,524	8,655	5,869	8,356	9,436	-1,081
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	128	500	-372	1,173	391	782
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	4,617	5,670	-1,053	5,623	4,344	1,278
3.4 अन्य निवेश	55,172	51,686	3,486	48,172	39,374	8,798
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमा राशियां	12,273	11,476	797	15,402	12,078	3,324
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	86	0	86	0	2	-2
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमा राशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमा राशियां)	12,187	11,476	711	15,402	12,075	3,326
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	14,018	15,779	-1,761	15,502	16,905	-1,403
3.4.3अ भारत को ऋण	11,040	13,076	-2,036	13,975	15,526	-1,551
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2,978	2,703	275	1,527	1,379	147
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	42	203	-161	36	142	-106
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	24,023	20,029	3,994	13,411	8,622	4,789
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	4,815	4,199	616	3,822	1,626	2,196
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	9,499	-9,499	1,868	0	1,868
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	9,499	-9,499	1,868	-	1,868
4. कुल आस्तियां / देयताएं	146,980	139,569	7,411	131,048	112,851	18,198
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	76,497	68,305	8,193	72,083	62,810	9,273
4.2 ऋण लिखत	65,668	57,566	8,101	53,276	48,415	4,861
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	4,815	13,698	-8,883	5,690	1,626	4,063
5. निवल भूल-चूक	-	436	-436	914	-	914

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(बिलियन ₹)

मद	जुलाई-सितंबर 2017 (आ.सं)			जुलाई-सितंबर 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	9,353	9,800	-446	11,225	12,564	-1,339
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	7,939	8,844	-905	9,365	11,454	-2,089
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	4,891	6,978	-2,086	5,851	9,361	-3,510
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	4,856	6,610	-1,754	5,851	8,713	-2,862
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	35	0	35	-0	0	-0
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	367	-367	0	648	-648
1.अ.ख. सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	3,048	1,866	1,181	3,514	2,094	1,421
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इन्पुट पर विनिर्माण सेवाएं	2	1	2	4	1	4
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	3	7	-4	3	18	-15
1.अ.ख.3 परिवहन	270	268	2	326	357	-31
1.अ.ख.4 यात्रा	448	343	105	494	408	86
1.अ.ख.5 निर्माण	33	24	10	54	45	9
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	41	35	6	45	28	18
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	85	101	-16	92	79	13
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	9	83	-74	11	136	-125
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,285	106	1,179	1,503	131	1,372
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	584	615	-31	660	680	-20
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	24	47	-23	31	54	-23
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	8	9	-1	10	18	-9
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	256	229	27	281	139	142
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	288	838	-550	394	1,002	-607
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	66	36	30	75	42	34
1.आ.2 निवेश आय	175	794	-619	244	940	-696
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	91	380	-288	125	436	-312
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	5	221	-217	4	247	-243
1.आ.2.3 अन्य निवेश	10	193	-183	10	256	-246
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	70	1	69	106	1	105
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	47	8	39	75	21	55
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	1,126	118	1,008	1,466	108	1,358
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्ततार निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,120	105	1,014	1,463	94	1,369
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	1,084	87	997	1,419	70	1,349
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	36	18	18	44	25	20
1.इ.2 सामान्य सरकार	6	12	-6	2	14	-11
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	5	7	-2	5	7	-1
2.1 अनुत्पादित वित्ततार आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	1	3	-1	0	0	-0
2.2 पूँजी अंतरण	4	5	-1	5	6	-1
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	9,449	8,973	476	9,193	7,917	1,277
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	1,289	491	798	1,052	500	552
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	1,220	276	945	999	284	715
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1,167	273	893	957	273	684
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	971	273	698	714	273	441
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	196	0	196	242	0	242
3.1.अ.2 ऋण लिखत	53	2	51	43	11	31
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	53	2	51	43	11	31
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	69	215	-147	53	215	-163
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	69	113	-44	53	130	-78
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	69	67	2	53	78	-25
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	46	-46	0	52	-52
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	102	-102	0	85	-85
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	102	-102	0	85	-85
3.2 संविभाग निवेश	4,317	4,184	133	4,236	4,350	-113
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	4,308	4,152	157	4,154	4,322	-168
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	3,375	3,595	-221	3,568	3,660	-93
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	934	556	377	586	662	-76
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8	32	-24	82	27	55
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	297	365	-68	394	305	90
3.4 अन्य निवेश	3,547	3,323	224	3,379	2,762	617
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	789	738	51	1,080	847	233
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट म्यूटेट; एनआरजी)	6	0	6	0	0	-0
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	783	738	46	1,080	847	233
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	901	1,014	-113	1,087	1,186	-98
3.4.3अ भारत को ऋण	710	841	-131	980	1,089	-109
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	191	174	18	107	97	10
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	3	13	-10	3	10	-7
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,544	1,288	257	941	605	336
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	310	270	40	268	114	154
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	611	-611	131	0	131
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	611	-611	131	0	131
4. कुल आस्तियां / देयताएं	9,449	8,973	476	9,193	7,917	1,277
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	4,918	4,391	527	5,057	4,406	651
4.2 ऋण लिखत	4,222	3,701	521	3,737	3,396	341
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	310	881	-571	399	114	285
5. निवल भूत-वृक	-	28	-28	64	-	64

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2017-18		2017		2018			
			सितंबर		जून		सितंबर	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	157,373	378,965	153,514	363,949	160,717	372,393	163,036	362,164
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	103,734	363,190	101,566	347,959	106,443	356,627	107,551	346,526
1.2 अन्य पूंजी	53,640	15,775	51,947	15,991	54,274	15,766	55,486	15,638
2 संविभाग निवेश	2,665	272,418	2,456	253,966	1,704	254,519	922	238,093
2.1 इक्विटी	1,246	155,106	2,408	150,074	1,477	144,433	696	135,249
2.2 ऋण	1,418	117,312	48	103,892	227	110,086	227	102,843
3 अन्य निवेश	48,235	401,286	44,679	380,428	41,332	393,031	41,530	397,640
3.1 व्यापार ऋण	1,696	103,156	1,263	93,590	1,357	99,586	904	104,172
3.2 ऋण	8,225	159,939	5,952	156,397	7,023	157,611	7,073	158,345
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	20,790	126,456	19,175	118,266	16,294	124,506	16,628	122,137
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	17,524	11,736	18,288	12,175	16,658	11,328	16,925	12,986
4 रिज़र्व्स	424,545	–	400,205	–	405,740	–	400,525	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	632,818	1,052,669	600,854	998,343	609,493	1,019,943	606,014	997,897
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-419,851		-397,489		-410,450		-391,883

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2017-18	2018			2017-18	2018		
		अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर		अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	124.46	11.86	10.97	11.32	1,467,431.99	142,152.55	130,030.07	145,830.04
1.1 ग्राहक लेनदेन	120.71	11.58	10.70	11.05	1,036,698.74	97,944.08	91,162.92	101,338.56
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	3.72	0.28	0.27	0.27	130,426.03	13,912.67	11,922.19	15,085.17
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.024	0.002	0.002	0.002	300,307.22	30,295.81	26,944.96	29,406.31
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	3.50	0.32	0.25	0.32	1,074,802.02	115,017.56	89,962.85	102,273.20
2.1 सीबीएलओ	0.204	0.022	0.002	—	283,307.58	32,597.57	2,693.59	—
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.12	0.09	0.09	0.12	370,363.78	39,571.40	53,489.45	63,213.83
2.2.1 एकमुश्त	0.92	0.07	0.06	0.09	113,998.80	7,701.86	7,378.19	11,377.50
2.2.2 रिपो	0.199	0.021	0.016	0.017	256,364.98	31,869.53	22,603.13	21,654.73
2.2.3 त्रिपक्षीय रिपो	—	—	0.01	0.02	—	—	23,508.13	30,181.60
2.3 विदेशी समाशोधन	2.17	0.21	0.16	0.20	421,130.66	42,848.59	33,779.81	39,059.37
3 पेपर समाशोधन	1,171.31	98.91	86.66	92.52	81,934.93	7,026.39	6,229.28	6,687.42
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	1,138.05	97.80	85.67	91.71	79,451.24	6,948.47	6,153.57	6,626.42
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.2 अन्य केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	33.27	1.11	0.99	0.81	2,483.68	77.92	75.71	61.00
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	5,467.29	612.11	591.65	620.10	192,017.98	22,035.92	21,034.97	22,268.70
4.1 ईसीएस नामे	1.54	0.04	0.03	0.03	9.72	0.25	0.25	0.16
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	6.14	0.66	0.47	0.50	118.64	16.03	12.14	10.80
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	1,946.36	209.04	194.21	194.78	172,228.52	19,227.03	18,246.68	19,570.40
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	1,009.80	154.62	149.94	176.93	8,924.98	1,403.07	1,347.57	1,468.99
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	2,503.46	247.75	246.99	247.86	10,736.12	1,389.55	1,428.33	1,218.35
5 कार्ड	13,358.62	1,424.97	1,363.39	1,462.09	38,214.64	4,042.86	3,839.04	4,220.92
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,412.97	161.97	146.65	159.22	4,626.33	565.96	519.94	546.38
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	7.81	0.91	0.80	0.88	36.68	4.18	3.76	4.03
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,405.16	161.06	145.85	158.34	4,589.65	561.78	516.18	542.35
5.2 डेबिट कार्ड	11,945.65	1,263.00	1,216.74	1,302.88	33,588.31	3,476.90	3,319.10	3,674.54
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	8,602.26	869.61	840.17	915.34	28,987.61	2,933.92	2,778.69	3,143.12
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	3,343.39	393.39	376.57	387.54	4,600.70	542.98	540.41	531.42
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	3,459.05	420.20	394.17	441.77	1,416.34	221.28	185.19	189.22
6.1 एम-वॉलेट	3,025.98	368.45	347.32	392.99	1,086.75	187.86	161.08	163.68
6.2 पीपीआई कार्ड	432.63	51.75	46.84	48.77	310.41	33.42	24.11	25.54
6.3 पेपर वाउचर	0.44	0.00	0.00	0.00	19.19	—	—	—
7 मोबाइल बैंकिंग	1,872.26	559.48	575.80	661.06	14,738.54	2,480.17	2,490.97	2,771.48
8 कार्ड बकाया	898.56	1,041.28	1,035.64	1,002.36	—	—	—	—
8.1 क्रेडिट कार्ड	37.48	42.68	43.24	44.21	—	—	—	—
8.2 डेबिट कार्ड	861.08	998.61	992.40	958.15	—	—	—	—
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	222247	220154	220114	220051	—	—	—	—
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	3083067	3450355	3510859	3592424	—	—	—	—
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	23,584.20	2,568.38	2,447.07	2,628.12	2,555,510.68	260,200.76	224,336.42	252,063.19

टिप्पणी: पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2.1: 5 नवंबर 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को समाप्त कर दिया है।

2.2.3: 5 नवंबर 2018 से सिक्युरिटीज सेगमेंट के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत की गई है।

अवसरिक शृंखलाएं

सं. 44: लघु बचत

(बिलियन ₹)

योजना		2017-18	2017	2018		
		1	मई	मार्च	अप्रैल	मई
			2	3	4	5
1. लघु बचत		728.98	48.03	119.83	67.14	89.35
	प्राप्तियां					
	बकाया	8,039.71	7,387.84	8,039.71	8,106.68	8,196.24
1.1 कुल जमाराशियां		583.32	37.33	75.38	65.83	72.65
	प्राप्तियां					
	बकाया	5,273.10	4,755.02	5,273.10	5,338.93	5,411.58
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	171.45	4.43	25.16	25.85	20.52
	बकाया	1,092.10	935.69	1,092.10	1,117.95	1,138.47
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-1.62	-0.32	1.06	-0.43	-0.28
	बकाया	31.38	32.33	31.38	30.95	30.67
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0.05	-0.04	0.03	-0.06	-0.06
	बकाया	-0.43	-0.58	-0.43	-0.49	-0.55
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16.25	-1.19	8.90	7.04	9.21
	बकाया	1,816.91	1,795.24	1,816.91	1,823.95	1,833.16
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	122.64	12.01	11.28	10.88	12.29
	बकाया	417.18	314.94	417.18	428.06	440.35
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	196.33	15.26	19.02	15.74	20.53
	बकाया	992.92	821.58	992.92	1,008.66	1,029.19
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	598.18	527.91	598.18	605.02	614.56
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	45.97	38.38	45.97	46.45	47.63
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	61.40	52.64	61.40	62.23	63.23
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	287.37	202.65	287.37	294.96	303.77
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	78.68	7.18	9.63	6.81	10.44
	बकाया	923.20	855.52	923.20	930.01	940.45
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	-0.45	0.00	0.31	0.00	0.00
	बकाया	-0.37	0.08	-0.37	-0.37	-0.37
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
	बकाया	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21
1.2 बचत प्रमाणपत्र		79.43	7.32	7.32	3.83	14.13
	प्राप्तियां					
	बकाया	2,066.76	1,996.49	2,066.76	2,070.42	2,084.76
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	-0.65	-5.04	9.69	1.92	3.59
	बकाया	871.74	860.23	871.74	873.66	877.25
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-9.56	0.02	-11.75	0.00	1.17
	बकाया	-0.71	8.87	-0.71	-0.71	0.46
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-155.92	-11.88	-8.96	-11.87	-12.57
	बकाया	379.81	513.30	379.81	367.94	355.37
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	245.88	24.27	18.29	13.89	22.02
	बकाया	706.12	502.21	706.12	720.01	742.03
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-0.29	-0.05	0.05	-0.06	0.03
	बकाया	-1.40	-1.18	-1.40	-1.46	-1.43
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-0.03	0.00	0.00	-0.05	-0.11
	बकाया	-0.64	-0.62	-0.64	-0.69	-0.80
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	111.84	113.68	111.84	111.67	111.88
1.3 लोक भविष्य निधि		66.23	3.38	37.13	-2.52	2.57
	प्राप्तियां					
	बकाया	699.85	636.33	699.85	697.33	699.90

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अंतर है।

स्रोत : महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2017		2018		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	51451.83	52813.50	53967.78	54556.81	56028.30
1. वाणिज्यिक बैंक	40.37	41.40	42.68	41.84	41.41
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.33	0.33	0.29	0.33	0.37
3. बीमाकृत कंपनियां	23.49	23.63	23.49	24.24	24.61
4. म्यूच्युअल फंड	1.86	1.33	1.00	1.13	1.41
5. सहकारी बैंक	2.62	2.69	2.57	2.59	2.51
6. वित्तीय संस्थाएं	0.78	0.82	0.90	0.93	0.97
7. कॉरपोरेट	1.04	1.09	0.91	1.09	1.01
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	4.58	4.53	4.35	3.84	3.65
9. भविष्य निधियां	5.99	5.32	5.88	5.79	5.71
10. भारतीय रिजर्व बैंक	12.84	11.94	11.62	11.63	11.76
11. अन्य	6.11	6.92	6.30	6.58	6.58
11.1 राज्य सरकार	1.92	1.91	1.91	1.97	1.99

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2017		2018		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	22488.35	23329.53	24288.29	24954.61	25668.33
1. वाणिज्यिक बैंक	37.64	38.13	35.79	35.02	34.66
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.38	0.51	0.51	0.75	0.58
3. बीमाकृत कंपनियां	34.00	33.35	34.13	34.24	33.74
4. म्यूच्युअल फंड	1.92	1.68	1.64	1.20	1.05
5. सहकारी बैंक	4.82	4.78	4.78	4.79	4.75
6. वित्तीय संस्थाएं	0.22	0.22	0.35	0.35	0.43
7. कॉरपोरेट	0.11	0.13	0.15	0.16	0.17
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.16	0.21	0.23	0.15	0.10
9. भविष्य निधियां	18.37	17.05	19.67	20.34	21.04
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	2.37	3.94	2.76	2.99	3.48
11.1 राज्य सरकार	0.00	0.01	0.05	0.06	0.07

खजाना बिल					
श्रेणी	2017		2018		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	5704.50	5102.82	3798.76	5280.07	5657.50
1. वाणिज्यिक बैंक	52.15	48.40	60.74	55.30	47.84
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.38	1.67	2.17	1.41	1.86
3. बीमाकृत कंपनियां	4.32	5.22	4.17	3.66	4.55
4. म्यूच्युअल फंड	12.44	10.40	2.27	7.03	10.69
5. सहकारी बैंक	2.33	2.05	2.42	1.29	1.20
6. वित्तीय संस्थाएं	3.54	3.97	3.55	2.36	1.67
7. कॉरपोरेट	1.64	2.12	2.45	1.88	6.67
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.20	0.02	0.11	0.21	0.01
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	22.01	26.17	22.12	26.87	25.50
11.1 राज्य सरकार	18.73	21.81	16.35	23.11	21.36

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(बिलियन ₹)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18, (स.अ.) ²	2018-19, (ब.अ.) ²
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	30,002.99	32,852.10	37,606.11	42,659.69	48,579.90	53,611.81
1.1 गतिविधियां	17,142.21	18,720.62	22,012.87	25,379.05	29,324.08	32,025.64
1.1.1 राजस्व	13,944.26	14,830.18	16,682.50	18,784.17	22,525.73	24,390.87
1.1.2 पूंजी	2,785.08	3,322.62	4,120.69	5,012.13	5,857.77	6,745.79
1.1.3 ऋण	412.88	567.82	1,209.68	1,582.75	940.58	888.98
1.2 गैर गतिविधियां	12,427.83	13,667.69	15,108.10	16,726.46	18,542.53	20,762.79
1.2.1 राजस्व	11,413.65	12,695.20	13,797.27	15,552.39	17,684.36	19,839.32
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	5,342.30	5,845.42	6,480.91	7,244.48	8,166.36	8,851.50
1.2.2 पूंजी	990.37	946.87	1,273.06	1,157.75	844.41	909.08
1.2.3 ऋण	23.81	25.63	37.77	16.32	13.76	14.40
1.3 अन्य	432.95	463.79	485.14	554.17	713.29	823.38
2. कुल प्राप्तियां	30,013.72	31,897.37	37,780.49	42,884.32	47,718.59	52,780.35
2.1 राजस्व प्राप्तियां	22,114.75	23,876.93	27,483.74	31,322.01	35,923.82	41,185.41
2.1.1 कर प्राप्तियां	18,465.45	20,207.28	22,971.01	26,221.45	30,132.23	34,941.02
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	11,257.81	12,123.48	14,409.52	16,523.77	18,296.56	22,138.76
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	7,176.34	8,051.76	8,522.71	9,656.22	11,802.47	12,775.14
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	31.30	32.04	38.78	41.46	33.20	27.12
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	3,649.30	3,669.65	4,512.72	5,100.56	5,791.59	6,244.38
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	401.62	396.22	357.79	332.20	316.10	368.35
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	391.13	609.55	598.27	690.63	1,651.83	1,428.43
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	93.85	220.72	165.61	209.42	648.80	616.50
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	297.28	388.83	432.66	481.22	1,003.03	811.93
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	7,497.11	8,365.63	9,524.10	10,647.04	11,004.25	10,997.97
उक वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
उक.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
उक.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,358.58	-374.76	2,310.90	6,171.23	1,447.92	..
उक.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	1,081.30	-3,341.85	604.72	1,958.16	-1,448.47	..
उक.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	4,065.61	8,611.06	7,085.72	4,295.85	9,532.16	..
उक.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
उख वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
उख.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
उख.1.1 बाजार उधार (निवल)	6,391.99	6,640.58	6,732.98	6,898.21	7,951.99	8,398.36
उख.1.2 लघु बचत (निवल)	-142.81	-565.80	-785.15	-1,050.38	-1,653.29	-1,434.61
उख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	312.90	343.39	352.61	456.88	406.13	474.19
उख.1.4 आरक्षित निधियां	34.63	51.09	-33.22	-64.36	6.70	31.14
उख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	255.45	275.45	134.70	177.92	168.45	159.10
उख.1.6 नकद शेष	-10.72	954.74	-174.38	-224.63	861.31	831.46
उख.1.7 अन्य	582.75	536.84	3,169.08	4,273.43	3,238.79	2,564.21
उख.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.7	26.3	27.3	28.0	29.0	28.6
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	26.7	25.6	27.4	28.1	28.4	28.2
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.7	19.2	20.0	20.5	21.4	22.0
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.4	16.2	16.7	17.2	18.0	18.7
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.7	6.9	7.0	6.6	5.9

...: उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2018 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	5.76	19	14.92	19	5.71	17
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	0.39	21	1.58	19	0.42	14
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	6.42	25	0.22	1
11	झारखंड	-	-	3.32	18	1.66	2
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	0.27	10	0.35	8	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नागालैंड	0.41	21	1.07	16	0.16	4
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	0.07	26	5.98	26	2.79	13
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	2.56	19	8.65	19	4.31	9
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	-	-	3.87	17	0.89	7
29	पश्चिम बंगाल	3.69	11	11.81	11	2.17	6

- टिप्पणीयां :**
- राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
 - राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
 - प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
 - : नाग्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2018 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	72.96	7.18	0.02	0
2	अरुणाचल प्रदेश	9.51	0.01	--	0
3	असम	45.84	0.42	0	40.00
4	बिहार	54.66	--	0	0
5	छत्तीसगढ़	36.67	--	0.01	2.17
6	गोवा	5.06	2.54	--	0
7	गुजरात	120.77	4.24	0	0
8	हरियाणा	18.39	10.54	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	8.00
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	0	--	0	0
12	कर्नाटक	27.37	--	0	225.00
13	केरल	18.97	--	0	0
14	मध्य प्रदेश	--	8.14	0.00	0
15	महाराष्ट्र	308.52	--	--	400.00
16	मणिपुर	3.33	0.88	0	0
17	मेघालय	5.41	0.23	0.09	0
18	मिज़ोरम	4.77	0.22	--	0
19	नगालैंड	13.10	0.28	--	0
20	उड़ीसा	118.19	12.74	0.74	242.50
21	पुदुचेरी	2.82	--	--	8.97
22	पंजाब	0	0	0.08	0
23	राजस्थान	--	--	1.29	43.92
24	तमिलनाडु	58.55	--	0.46	303.15
25	तेलंगाना	42.42	6.19	0.01	0
26	त्रिपुरा	2.90	0.04	--	0
27	उत्तरप्रदेश	--	--	1.87	0
28	उत्तराखंड	26.49	0.70	0	0
29	पश्चिम बंगाल	93.57	3.71	2.14	0
	कुल	1090.31	58.07	6.71	1273.71

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19						2018-19 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	195.00	177.06	228.00	189.22	45.43	39.60	20.00	14.17	15.00	6.25	246.60	217.44
2	अरुणाचल प्रदेश	4.53	2.87	8.88	7.03	-	-	-	-	-	-	4.00	4.00
3	असम	30.90	19.94	77.60	67.97	-	-	5.00	5.00	10.00	10.00	59.00	59.00
4	बिहार	177.00	168.15	100.00	89.08	-	-	-	-	-	-7.50	-	-7.50
5	छत्तीसगढ़	42.00	38.98	81.00	81.00	15.00	15.00	10.00	10.00	-	-	25.00	25.00
6	गोवा	13.20	11.71	18.00	14.00	1.00	1.00	2.00	-	2.50	2.50	15.00	13.00
7	गुजरात	247.20	209.44	240.00	157.85	35.88	35.88	37.08	27.08	38.75	26.25	196.71	164.21
8	हरियाणा	158.00	153.59	166.40	158.40	15.00	15.00	30.00	30.00	-	-	110.25	105.25
9	हिमाचल प्रदेश	34.00	21.63	46.00	25.51	5.00	3.00	5.00	3.00	-	-	25.00	17.98
10	जम्मू और कश्मीर	27.90	18.99	62.00	39.74	3.25	1.13	8.75	6.75	-	-	42.00	32.24
11	झारखंड	51.54	47.25	60.00	48.07	-	-	-	-	10.00	8.05	20.00	18.05
12	कर्नाटक	280.07	240.26	220.98	173.48	75.00	67.00	76.00	76.00	60.00	60.00	211.00	203.00
13	केरल	173.00	146.86	205.00	162.03	15.00	15.00	15.00	11.50	18.00	10.00	163.00	139.65
14	मध्य प्रदेश	161.00	145.51	150.00	131.25	20.96	20.96	26.00	19.75	16.00	16.00	122.96	116.71
15	महाराष्ट्र	400.00	364.72	450.00	364.80	-	-20.00	-	-	20.00	20.00	128.69	108.69
16	मणिपुर	6.30	4.78	5.25	2.78	-	-	0.50	0.50	1.00	-1.00	5.00	3.00
17	मेघालय	10.01	7.18	11.16	9.20	1.50	1.50	2.50	1.30	2.50	2.50	6.50	5.30
18	मिज़ोरम	1.70	-0.35	4.24	2.77	-	-	-	-	-	-	-	-0.27
19	नगालैंड	10.70	7.33	11.35	7.66	-	-	-	-	1.50	1.50	5.00	3.40
20	उड़ीसा	76.20	69.90	84.38	84.38	-	-	-	-	-	-	45.00	45.00
21	पुदुचेरी	5.25	5.25	8.25	4.88	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	3.50	2.50
22	पंजाब	136.00	121.44	174.70	133.49	23.00	18.00	10.00	10.00	23.26	16.24	160.80	128.78
23	राजस्थान	160.54	143.25	249.14	167.77	15.00	15.00	27.00	12.00	23.70	12.08	266.00	211.26
24	सिक्कीम	7.44	5.74	9.95	7.45	1.25	1.25	1.00	1.00	-	-2.93	7.25	4.32
25	तमिलनाडु	372.50	349.94	409.65	360.23	35.00	22.50	40.00	32.50	42.50	25.00	298.90	261.40
26	तेलंगाना	218.61	205.79	246.00	218.28	30.00	25.83	30.00	25.83	15.00	8.75	199.68	178.84
27	त्रिपुरा	9.90	7.53	11.37	11.37	-	-	-	-	2.43	2.43	11.43	11.43
28	उत्तरप्रदेश	410.50	369.05	416.00	371.78	85.00	75.00	20.00	10.00	45.00	35.00	230.00	170.00
29	उत्तराखंड	54.50	50.81	66.60	58.30	2.50	2.50	5.50	5.50	6.00	3.85	53.50	46.85
30	पश्चिम बंगाल	344.31	312.30	369.11	253.04	40.00	34.00	20.00	5.00	84.83	75.95	209.83	117.42
	कुल	3819.79	3426.92	4191.00	3402.81	465.77	390.15	391.84	307.39	438.96	331.91	2871.59	2405.94

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7: माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.10 से 4.12: माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
 4.13: माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2: चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2: नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2: आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5: बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्यतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2: आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4: अनुमान

1.1.1.2: नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10: जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 29 राज्यों से संबंधित हैं।

2015-16 से जीडीपी डाटा 28 फरवरी 2018 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम से संबंधित है।

जीडीपी के लिए 2016-17 (आरई) और 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 से लिए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपार्श्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज़ डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2019	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [@]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [@])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹700 (सामान्य) ₹750 (डाक प्रभार सहित) ₹525 (रियायती) ₹575 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 37, 2016	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियाः

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, मुम्बई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए।
एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8691632-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।